राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तीसवां दिवस [संख्या: 15

गुरुवार,

10 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न संख्या 63, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

अनुरोध एवं मांग

माननीय मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों ने तो वाकआउट कर दिया और वाकआउट के बाद...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय कटारियाजी, प्लीज। क्वेश्चन आवर की गरिमा को, इतने सीनियर आदमी हैं आप, मेरी बात सुन लें आप। मैं फिर आपकी भावना को सुन लूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको जीरो आवर में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड आप मुझे मौका दो। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं कहूंगा जिससे सदन का सम्मान न रहे। ऐसा मेरे जीवन में नहीं होगा। हम लोग वाकआउट कर गये, उसके बाद मंत्री महोदय ने जिन शब्दों में कहा, राजस्थान नम्बर वन पर है। इसमें किसी को एतराज नहीं, पर चूंकि नम्बर वन पर इसलिए है कि +++

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप वाकआउट करिये। प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। श्री कालीचरण सराफ। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

माननीय कटारियाजी, बहुत गलत परम्परा डाल रहे हो आप। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। यह तरीका नहीं है। मैंने आपको मौका दिया। कटारियाजी, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, लेकिन बोलने के बीच में इस तरह से नहीं। आप बोलो न, मैं सुन रहा हूं। मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपकी बात बैठकर सुन रहा था, पर उप नेता प्रवोक करके कहें, यह तरीका ठीक नहीं है। पूरा हाउस आपके पास था। आप बोल रहे थे। बिलकुल गलत बात है। माननीय सदस्य, आप अपने नेता को नहीं मान रहे हो। नेता बोल रहे हैं। आप जाइये, अपनी जगह पर जाइये आप। नेता बोल रहे हैं। आप अपनी जगह पर जाइये। अपनी जगह पर जाइये। मैं कटारियाजी को बोलने का पूरा मौका दे रहा था, मैं तो सुन रहा था उनकी बात। नेतागीरी में ऐसे थोड़े ही होता है। माननीय कटारियाजी को आप सुनना ही नहीं चाहते। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आसन का पूरा सम्मान रखते हुए कल हम लोगों ने तो वाकआउट कर लिया और उसके बाद जो वक्तव्य हो रहा था, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ कि राजस्थान रेप केसेज में हिन्दुस्तान में प्रथम है, यह आपने स्वीकार किया और उसके आगे आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, चूंकि +++ इससे क्या है कि उन +++ का भी अपमान हुआ जो देश के लिए लड़े और मरे। राजस्थान जाना जाता है तो उसकी बहादुरी के कारण से जाना जाता है। +++ इस कारण से नहीं जाने जाते हैं कि +++ यह दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग हुआ है न, उससे राजस्थान की जनता को बहुत आक्रोश है। मैं तो बहुत जल्दी, 9 बजे ही सो गया था, लेकिन बाद में टेलीफोन आना शुरू हुए। उनका कहना था कि 72 लोग वहां झक मारने के लिए बैठे हो क्या, एक आदमी ने इन शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कहा कि हमें ध्यान नहीं, जब हम थे तब तक यह विषय नहीं आया, बाद में आया है और मैंने स्वयं ने यू-ट्यूब देखा है। आपने स्वयं ने देखी होगी। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह राजस्थान की उन नारियों का भी अपमान है और राजस्थान की सारी जनता का और बहादुर लोगों का भी अपमान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने लीडर को भी नहीं मानते। बैठे-बैठे बोल रहे हैं। सीनियर लीडर हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि आप सामान्य घटना के रूप में मत लो। यह जो कुछ भी कमेंट्स हैं, मजाक करते हैं हम आपस में, एक दूसरे की छींटाकशी करते हैं, समझ में आ सकता है लेकिन इतनी घटिया स्तर की बात कह जाएं और सारे नारी समाज को जिस प्रकार से हम अपमानित करें और राजस्थान के बहादुर लोगों को जिस ढंग से आपने उनके साथ मिलाकर अपमान किया है, आखिर इसका कोई हल तो हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, Please, I am on the Chair. कम्पीटिशन है क्या, यहां पर। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपकी भावना से सहमत हूं। कल ही सदन की कार्यवाही से इसको निकाल दिया गया है। डीपीआर को निर्देश दे दिये गये हैं कि इस तरह की कार्यवाही को पत्रकार नहीं छापें। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि निर्देश के बाद भी अख़बार में यह बात छपी, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मंत्रीजी मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा और सदन की कार्यवाही में भी कहा है कि मेरे से अन-इंटेंशनली शब्द निकल गये, उनको निकाला जाए। उन्होंने स्वयं ने कहा है और मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय मंत्रीजी की यह भावना नहीं थी और आप सुनना चाहें तो मैं संसदीय मंत्रीजी से कहूंगा कि वह अपनी बात कह दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप बैठें। इस्तीफा, यह क्या तरीका है? आपकी समझ में नहीं आ रहा है। I will not allow it. I will not allow it. Mr Rathore, I will not allow it. I will not allow it. I said I will call him. Please be seated. माननीय राठौड़ साहब, गलत बात है। आप मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते। आप मंत्रीजी को सुनना ही नहीं चाहते। यह कौनसा तरीका है? आप प्रस्ताव लाइये, बाहर निकालने का, सदन से बाहर निकालने का। बात खतम करिये। यह क्या तरीका बना रखा है। क्या रखा है, इसमें क्या तकलीफ है। यह तरीका है सदन चलाने का?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इस सदन को इस तरह से नहीं चलने दूंगा। मैं सदन को नहीं चलने दूंगा। आपके मन में आये जो करो। करते रहिये यहां पर। माननीय मंत्रीजी बोलें। अंकित नहीं होगा।

खेद प्रकट

दिनांक 09 मार्च, 2022 की बैठक में स्लिप-आफ-टंग की वजह से उच्चारित शब्द/अभिव्यक्ति के लिए खेद प्रकटीकरण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभागों की अनुदान मांगों पर कल मैं सदन में जब जवाब दे रहा था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गये, जिसका अहसास होते ही मैंने अपने सम्बोधन के दौरान ही इन शब्दों को कार्यवाही से हटाने का माननीय सभापति से अनुरोध कर दिया था। मेरे मुंह से ये निकले गलत शब्द स्लिप-आफ-टंग थे, जिसका मुझे बेहद खेद है। दरअसल राजस्थान मरु प्रदेश है, जिसके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्लिप-आफ-टंग के कारण गलत शब्द निकल गये। मैं व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं का बेहद सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। मेरे द्वारा कहे गये इन शब्दों से यदि किसी को ठेस लगी है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इससे ज्यादा और क्या होगा। इससे क्या होगा? काहे का इस्तीफा देंगे। हो गया। माफी मांगने के बाद भी नहीं। माफी मांग ली, उसके बाद भी नहीं है। यह कौनसा तरीका है?

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 63

माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न संख्या 63, चन्द्रभान सिंह आक्या।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

(कृपया आगे देखें।)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 235

नगरीय निकायों में डेयरी बूथों का आबंटन

अगला प्रश्न संख्या 235, श्री कालीचरण सराफ।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): जी, हां। बजट 2021-22 की अनुपालना में प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा आबंटित 2,338 डेयरी बूथों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 236, श्री राजकुमार।

चौरासी की ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय

236. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर रा.उ.मा. विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ऐसी कितनी ग्राम पंचायत हैं जहां एक भी रा.मा.वि. व रा.उ.मा.वि. नहीं है? ग्राम पंचायत के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिस ग्राम पंचायत स्तर पर एक भी रा.उ.मा.वि. नहीं है, वहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के रा.मा.वि. व रा.उ.मा.वि. में ब्लाकवार बालिकाओं की संख्या कितनी है? क्या सरकार सबसे अधिक लिंगानुपात वाले उक्त क्षेत्र में बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 28 के उप बिन्दु III के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र चौरासी की 14 ग्राम पंचायतों में रा.मा.वि. एवं रा.उ.मा.वि. संचालित नहीं हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-1 के खण्ड 1 व 2 के अनुसार।

(3) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में संचालित 14 रा.मा.वि. एवं 87 रा.उ.मा.वि. में बालिका नामांकन का ब्लाकवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 28 के उप-बिन्दु iv के अनुसरण में अन्य प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र चौरासी (डूंगरपुर) के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर पात्र प्रस्तावों के अनुसार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने बताया है कि चौरासी विधान सभा क्षेत्र में 14 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, तो मंत्रीजी से मेरा सवाल है कि नैक्स्ट सत्र, जो जुलाई में स्टार्ट होगा, उससे पहले इन सभी 14 ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो जाएंगे या नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि चौरासी विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला आता है और इसमें चौरासी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला विधान सभा क्षेत्र है। इसमें मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस विधान सभा क्षेत्र में बालिका विद्यालय खोलने के लिए सरकार की क्या मंशा है? क्योंकि पूरे विधान सभा क्षेत्र में 23 हजार 713 बालिकाएं वर्तमान में अध्ययनरत हैं। माननीय मंत्रीजी बताएं कि बालिका विद्यालय कब तक खोले जाएंगे? (भारी व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विधान सभा क्षेत्र चौरासी में संचालित 14 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, एड्रेस इधर करें। I will expel him. प्रोटेस्ट इधर करें। I will expel him. प्रोटेस्ट इधर करें, उधर नहीं करेंगे। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, बोलें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका पूरक प्रश्न यह है कि उसमें 14 स्कूलें ऐसी हैं, जिसमें 13 तो नई पंचायतें हैं, और एक पुरानी पंचायत है। सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए पांच किलोमीटर की दूरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिए सात किलोमीटर की दूरी आवश्यक है। जो मानदण्ड के अनुसार स्कूलें आएंगी, उनमें सैकण्डरी या

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले जाएंगे। जहां तक इन्होंने 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के बारे में बात की है, जहां लिंगानुपात ज्यादा है, वहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये जाएंगे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे, तो मंत्रीजी जवाब में यह बताएं कि जुलाई से पहले इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? दूसरा प्रश्न, कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सिर्फ प्राथमिक विद्यालय हैं। जैसे कि सुजातलाई, तो क्या उन प्राथमिक विद्यालयों को सीधा सीनियर में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा या उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको मानदण्डानुसार पहले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा और जैसे जोंतरी ब्लाक, वासुआ में छह किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकास नगर, इसको सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है, मंत्रीजी मुझे आश्वस्त करें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरासी विधान सभा क्षेत्र में खोल दिये जाएंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया कि हमारे पास इस बार 200 प्राइमरी और कुछ मिडल स्कूल मिले हैं, जो भी क्राइटेरिया में आएंगे, उनको मैं आदिवासी इलाकों को ध्यान में रखते हु ए प्राथमिकता दूंगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज, आप बैठें। (व्यवधान)

अगला प्रश्न। हमीर सिंह भायल। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 237

बाड़मेर में पुलिस थानों का सीमांकन

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) सरकार द्वारा पुलिस थानों का सीमांकन कर नये वृत कार्यालय का सृजन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

बाड़मेर जिले में पुलिस थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्रवार किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस हेतु न ही कोई समिति गठित की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बाड़मेर जिले में सिवाना मुख्यालय पर नया वृत कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

नये वृत कार्यालय का सृजन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में सिवाना पुलिस थाने में सी.आई. पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समदड़ी पुलिस थाना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खण्ड में नई चौकी खोले जाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (व्यवधान)

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

प्रश्न संख्या 238

कोटा में बायोलोजिकल पार्क का कार्य

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

वन मंत्रीजी।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क, कोटा का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है। पार्क का विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 18.12.2021 को किया जाकर उक्त पार्क दिनांक 01.01.2022 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

(वन मंत्री)

(2) जी हां। कोटा के अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क में कोटा के पुराने चिड़ियाघर के वन्यजीवों को शिफ्ट करने की कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 71 वन्यजीवों जैसे कि लैपर्ड, हायना, सियार, भेड़िया ब्लैक बक, चिंकारा, चीतल आदि शिफ्ट किये जा चुके हैं। अन्य वन्यजीवों को द्वितीय चरण में शेष एनक्लोजर बन जाने के पश्चात् शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट किये गये वन्यजीवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश एवं देश के दूसरे चिड़ियाघर जैसे कि सज्जनगढ बायोलोजिकल पार्क, उदयपुर, नाहरगढ़ बायोलोजिकल पार्क, जयपुर, नागालैण्ड जूलोजिकल पार्क एवं शक्करबाग जूलोजिकल पार्क, जूनागढ़ से वन्यजीवों की शिफ्टिंग का कार्य प्रस्तावित है। केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् शिफ्टिंग का कार्य कराया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में नहरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य

239. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सिंचाई के साधनों की कमी को देखते हुए अपरघोड़ी तालाब देवल की दायीं और बायीं मुख्य नहर की मरम्मत एवं अधूरी पड़ी नहरों को पूर्ण कराने एवं नहरों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु कोडियागुण के मेवाड़ा बांध पर स्थित दायीं और बायीं दोनों नहरों की मरम्मत एवं अधूरी नहरों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। डूंगरपुर ग्राम पंचायत देवल खास (पंचायती राज विभाग) के अधीन स्थित अपरघोड़ी बांध की जीर्ण-शीर्ण नहरों की मरम्मत एवं अधूरी नहरों के निर्माण कार्य वर्ष 2022-23 में मुख्य मंत्री की बजट घोषणाओं में सम्मिलित किया गया है, जिसकी पालना में अपरघोड़ी बांध की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति उपरान्त संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) मेवाड़ा बांध एवं इनकी नहरों की मरम्मत, जीर्णोद्वार एवं अधूरी नहरों का निर्माण का कार्य रिपेयर, रिनोवेशन एण्ड रेस्टोरेशन (RRR) मद में प्रस्तावित किया गया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति प्रक्रियाधीन है। कार्य की स्वीकृति एवं बजट उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रोटेस्ट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट कर रहे हो कि योगी-मोदी की कर रहे हो?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य को स्वीकृत कर पूर्ण करा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपरघोड़ी बांध के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही कोडियागुण, जो मेवाड़ा बांध है, उसके लिए भी लोगों की काफी मांग है, वहां पानी की समस्या है, तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा अपरघोड़ी और मेवाड़ा बांध कोडियागुण, जल्दी से जल्दी, कब तक चालू कराने की मंशा रखते हैं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता चुका हूं, इस कार्य को स्वीकृत करा लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 240

झालावाड़ में सहकारी समितियों के माध्यम से बीज वितरण

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

कोआपरेटिव मिनिस्टर। सहकारिता मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। किसानों को अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों को उन्नत/प्रमाणित बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक जिले के लिए खरीफ एवं रबी

(सहकारिता मंत्री)

मौसम पूर्व कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जोनल कान्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें प्रमाणित बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों को मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजफैड द्वारा कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अनुबन्धित कंपनियों के माध्यम से उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण किया जाता है तथा भण्डारित उर्वरक मांग के समय किसानों को उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर मांग के अनुसार बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझसे टेलीफोन करके यह भी जानकारी चाही थी कि अगले साल क्या रहेगा? अगले साल और ज्यादा संकट उत्पन्न होने की स्थिति है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पृथक प्रस्तावित बजट में से उर्वरक अनुदान हेतु प्रावधान गत वर्ष की तुलना में 24.9 प्रतिशत कम किये जाने से सम्भावना है कि आगामी वर्ष में उर्वरकों की आपूर्ति में कमी होना अपेक्षित है।

इस ओर माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से ध्यानाकर्षित किया गया है।

प्रश्न संख्या 241

डूंगरपुर में फसल खराबे का मुआवजा

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): डूंगरपुर जिले में खरीफ फसल वर्ष 2021 (संवत् 2078) में 3 तहसील साबला, सागवाड़ा एवं गलियाकोट में सूखे से फसल खराबा होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। शेष तहसीलों में सूखे से फसल खराबा नहीं होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। सूखे से प्रभावित किसानों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

प्रभावित पात्र कृषकों को राज्य आपदा मोचन निधि के मानदण्डानुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जायेगा। विभाग द्वारा किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें)

डूंगरपुर जिले में 344 गांवों में 33 परसेंट या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है तथा 109659 कृषक प्रभावित हुए हैं। सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरण करने हेतु दिनांक 09.12.2021 को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु संरक्षण गतिविधियों यथा पशु शिविर, चारा डिपो खोलने हेतु दिनांक 10.01.2022 को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं तथा पेयजल परिवहन हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को लिखा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में खरीफ फसल वर्ष 2021 में सूखे से बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, डूंगरपुर एवं चूरू जिले की 64 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से 31 करोड़ 21 लाख हैक्टेयर में 33 परसेंट या इससे अधिक फसल खराबा हुआ तथा 22.65 लाख कृषक प्रभावित हुए हैं। जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

सूखे से 10 जिलों में 6122 गांवों में 33 परसेंट या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। प्रभावित कृषकों में से 184682 कृषकों को 175.77 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान वितरित करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी। डूंगरपुर जिले में सूखे से 3 तहसीलों में खराबा होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटे से उबारने की कार्ययोजना

242. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बसों का किराया अन्य राज्यों से अधिक होने के बाद भी निगम लगातार घाटे में चल रहा है? विगत 3 वर्षों में निगम को कितना घाटा हुआ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि रोडवेज रूटों पर अवैध बसों का संचालन हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर अंकुश न लगाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अवैध बसों के संचालन पर रोक लगाने और प्राइवेट बसों द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजे जाने के बाद भी उक्त अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? यदि हां तो सरकार उक्त पर क्या कार्यवाही कर रही है? विगत 3 वर्षों में अधिकारियों को इस सम्बन्ध में भेजे गये पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र की तुलना में कम है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का विगत 3 वर्षों का घाटा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**घाटा (रुपये करोड़ में)**
2018-19	153.76
2019-20	217.06
2020-21	179.76

निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण निम्न रहे हैं:-

I. डीजल की दरों में निरन्तर बढ़ोतरी।

II. पुराना वाहन बेड़ा होने के कारण वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर अधिक व्यय।

III. निगम वाहनों के समानान्तर निजी बसों का प्रतिस्पर्धात्मक संचालन।

IV. विगत 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण संचालन में कमी।

V. निगम कार्मिकों के वेतन एवं मानदेय वेतन आयोगों की अनुशंषानुसार नियत होना।

(2) रोडवेज रूटों पर अवैध बसों के संचालन को रोकने के लिए

(राज्य मंत्री, परिवहन)

विभागीय उड़नदस्तों द्वारा समय-समय पर उक्त श्रेणी के वाहनों की जांच/कार्यवाही की जाती है। विगत तीन वर्षों में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अवैध बसों के संचालन को रोकने/अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर विभागीय उड़नदस्तों द्वारा प्रभावी जांच एवं कार्यवाही की जाती है। विगत तीन वर्षों में की गयी कार्यवाही का विवरण उपरोक्तानुसार खण्ड 2 के उत्तर मे वर्णित परिशिष्ट "1" में सम्मिलित है। विभाग द्वारा अवैध बसों के संचालन पर विगत तीन वर्षों में प्रसारित दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अपने प्रश्न में माना है कि रोडवेज रूट्स पर अवैध बसों का संचालन होता है। आपने उसी में यह कहा है कि समय-समय पर उड़न दस्ते द्वारा कार्यवाही की जाती है। जब आप ही इस चीज को मान रहे हो कि अवैध बसों का संचालन हो रहा है तो समय-समय पर ही क्यों, नियमित रूप से क्यों नहीं उड़न दस्तों का संचालन किया जाये, जिससे रोडवेज घाटे में नहीं आये?

साथ ही, आज तक ऐसी कितनी बसों को जब्त किया गया तथा कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गयी?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि अवैध बसें नहीं चल रही हैं। लेकिन पिछली सरकार के समय में रोडवेज के रूट्स को डिनोटिफाइड किया था। लोक परिवहन की सेवाओं को परमिट दिये गये थे। उस वजह से भी घाटे में वृद्धि हुई है। अभी तक 12656 प्रकरणों में हमने कार्यवाही की है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रोडवेज कर्मचारियों की लम्बे समय से भुगतान की मांग चल रही है। क्या सरकार उनका भुगतान करने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): कुछ को भुगतान कर दिया गया है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में सातवें वेतन आयोग को भी लागू करने की घोषणा की है। वह प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही उस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन डिपो अधिकारियों के अधीन सबसे ज्यादा राजस्व घाटा हुआ है, वहां पर कितने कर्मचारियों को नोटिस दिये गये? उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कृपया माननीय मंत्री महोदय बताने का श्रम करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): डिपो के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। डिपो का घाटे में कोई योगदान नहीं है। जहां-जहां अवैध बसें या अन्य वाहन चले हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 243

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त युवाओं को देय सुविधाएं

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा पुरस्कार का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष 2017-18 में श्री मनिष कुमार दवे (व्यक्तिगत श्रेणी)

वर्ष 2018-19 में सुश्री दिव्या कुमारी जैन (व्यक्तिगत श्रेणी)

वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गयी।

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गयी।

वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गयी।

(2) विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है एवं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अभिशंषा नहीं की जाती है। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाकर युवा पुरस्कार दिये जाते हैं।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी श्रेणी में मैं बताना चाहता हूं कि पुरस्कार के उद्देश्य हैं-

(1) राष्ट्रीय विकास या समाज के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए युवा व्यक्तियों, 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को दिया जाता है।

(2) युवाओं को समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करना और इस प्रकार अच्छे नागरिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार करना।

(3) राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा के लिए युवाओं के साथ कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करना।

पुरस्कार का विवरण निम्न प्रकार है-

ये पुरस्कार स्वास्थ्य, अनुसंधान और नवाचार, संस्कृति, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, कला और साहित्य, परम्परागत चिकित्सा, पर्यटन, सक्रिय नागरिक एवं सामुदायिक सेवाएं जैसी विकास गतिविधियों और सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए पहचाने जाने योग्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जायेगा।

खेल और अकादमिक उत्कृष्टता और स्मार्ट लर्निंग, व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों की संख्या 25, युवा संगठन और संस्थाओं के पुरस्कारों की संख्या 10, व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार संख्या 50,000, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। युवा संगठन एवं संस्थानों को पुरस्कारों की राशि 2 लाख रुपये, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है।

पात्रता की शर्तें व्यक्तिगत के लिए निम्न हैं-

भारत का नागरिक होना चाहिए। 01 जनवरी, 2022 को आयु 15 से

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

29 के बीच होनी चाहिए। साधारण पहचान योग्य सामाजिक कार्य करना चाहिए, यथा यह पुरस्कार जीवन में एक बार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Mr. Beniwal, what is this? बाहर निकालो, क्या कर रहे हैं? I will ask the Marshal. मैं आपको बोल चुका हूं। बैनर नहीं बतायेंगे। मिस्टर पुखराज, यह क्या कर रखा है आपने? I will call the Marshal. मैं मना कर चुका हूं कि आप डिस्प्ले नहीं करेंगे। यह क्या कर रखा है आपने? आप नीचे कीजिये इसको। नहीं सुन रहे हैं क्या मिस्टर बेनीवाल? मिस्टर बेनीवाल। आप सुन नहीं रहे हैं क्या? Mr. Beniwal, I will name you. Mr. Beniwal and Mr. Pukhraj, I will name you. Mr. Pukhraj and Mr. Beniwal, I will name you. Mr. Marshal, ...(interruptions) What is this? यह क्या बना रखा है ...(व्यवधान) Mr. Chandrabhan, I will name you. यह क्या तरीका लगा रखा है? यह क्या बना रखा है? आप नीचे कीजिये इसको। बाहर फैंकिये इसको। Mr. Pukhraj, I will name you. Mr. Pukhraj and Mr. Beniwal, I will name you. Mr. Beniwal, I will name you. Mr. Beniwal, I will name you. Marshal...Marshal... नीचे करिये कागज को। मिस्टर बेनीवाल, नीचे करिये कागज को। कागज नीचे करिये, मिस्टर बेनीवाल। (व्यवधान)

माननीय कटारियाजी, कटारियाजी, कटारियाजी। नीचे, नीचे करिये। मार्शल रुकिये। नीचे करिये इसको। कटारियाजी, नीचे करवाइये इनको, गलत बात है। यह गलत बात है। यह क्या तरीका है कटारियाजी? यह क्या तरीका है? (व्यवधान) यह क्या तरीका है, आप अपना प्रोटेस्ट कीजिये। यह यहां अलाउ नहीं है। आज आप इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, मैंने खुद ने आर्डर दिया है कि हाउस के अन्दर कोई डिस्प्ले नहीं करेगा। आप प्रोटेस्ट कीजिये न। प्रोटेस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप नियम को तोड़ें।

Mr. Beniwal and Mr. Pukhraj, I will name you. मैंने उस दिन कहा था कि कोई इस तरह का यहां पर लाकर नहीं बतायेगा। आप प्रोटेस्ट कीजिये। प्रोटेस्ट करने का मतलब यह नहीं है।

माननीय मंत्रीजी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में राजस्थान ने अनेकों बार भारत सरकार को लिखा, अनेकों प्रदेशों की सरकारों को लिखा। भारत सरकार को राजस्थान राज्य के

(श्री अशोक)

समस्त पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं की सूची उपलब्ध कराने हेतु 12 जुलाई, 2021 व 14 दिसम्बर, 2021 को संयुक्त सचिव ...(व्यवधान)

सदस्य का निष्कासन

राजस्थान विधान सभा के कतिपय माननीय सदस्यों का निष्कासन

श्री अध्यक्ष: Mr. Kataria Ji, It will be a limit. I will not tolerate it. I will not tolerate it. मैं इस तरह का नहीं हूं। Mr. Beniwal and Mr. Garg, I will not tolerate it. हाउस चले या नहीं चले पर नियमों का यदि पालन नहीं होगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। प्रोटेस्ट कीजिये लेकिन यह तरीका नहीं है। (व्यवधान) नहीं सुन रहे हैं अभी भी? नहीं सुन रहे हैं? Marshal, come up and throw them out. Throw them out. (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.36 बजे 12.36 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 12.36 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए अपने स्थान पर। (व्यवधान) अपने स्थान पर तो पधारिये। प्लीज, प्लीज, सहयोग करें, माननीय सदस्य। विराजिए, अपने स्थानों पर विराजिए। (व्यवधान)

सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.37 बजे 13.07 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 13.07 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अनुरोध एवं मांग

माननीय मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय को लेकर के हाउस में एक गतिरोध पैदा हुआ है उस गतिरोध के समय में आरएलपी के मेरे सभी सहयोगी विधायकों ने अख़बार की कटिंग को लेकर दिखाने का प्रयास किया। आपकी मंशा, पिछली बार की जो घटना हुई थी उसके आधार पर आपने कहा था कि इस प्रकार के फ्लैग वगैरह को मैं हाउस में अलाउ नहीं करूंगा। उसके कारण से आपने माननीय सदस्यों को कहा कि बाहर जाओ और मार्शल को भी आपने बुलाया कि इनको बाहर निकालें, पर मैं सोचता हूं कि यह अनहोनी घटना न हो, मैं तीनों माननीय सदस्य जो उनकी पार्टी के हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक बार ना पक्ष की लॉबी में बैठें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वास्तव में इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि उनको सदन से बाहर निकालें और निकलने की आपने व्यवस्था कर दी, तो उस व्यवस्था में मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन तीनों माननीय सदस्यों को भी वापस सदन में बुलायें।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो कुछ भी हुआ है वह शोभाजनक नहीं है। उसका आपको दु:ख है और आपने यहां बोला है पर हम सब लोग सुन नहीं पाये कि आपने किस भाषा में अपने इन शब्दों के ऊपर दु:ख जाहिर किया। मैं आसन से भी व्यवस्था चाहूंगा कि मंत्री जी उसके बारे में अपना ठीक प्रकार से कहें ताकि केवल मैं और यहां के सदस्य ही नहीं, राजस्थान की 7 करोड़ जनता भी इस बात को सुने क्योंकि इससे हरेक के मन को काफी पीड़ा हुई है। मैं सोचता हूं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम जनता के हर सम्मान को बनाये रखने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम अच्छी तरह से निभायें।

भाई पुखराज जी और उनके तीनों सदस्य, दो मिनट आप ना पक्ष की लॉबी में जाएं। अभी आपको वापस ससम्मान अध्यक्ष जी व्यवस्था देकर बुलायेंगे और एक तरह से अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद फिर से सदन चले तभी माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य उसके बाद ही पढ़ें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय पुखराज जी गर्ग और आपके साथियों से निवेदन है कि अध्यक्ष के डायरेक्शन के अनुसार, जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, आप एक बार सदन से बाहर प्रस्थान करें। उसके बाद हम आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण, मैं प्रतिपक्ष के नेता को और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि अध्यक्ष की व्यवस्था के सम्बन्ध में आपने अपने विचार व्यक्त किये। मैं आशा करता हूं कि सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष को अनप्लेजेंट निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रतिपक्ष के नेता ने इस भावना को अपने आप में सम्मिलित किया।

मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में अध्यक्ष के जो निर्णय हैं, उनका पालन किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। एक मिनट, धारीवाल साहब।

सदस्य का निष्कासन

राजस्थान विधान सभा के कतिपय सदस्यों के निष्कासन की निरस्ती

माननीय संसदीय मंत्री जी अपनी बात कहें। मैं आपकी भावना से सहमत होते हुए माननीय सदस्यों को कहूंगा कि वे सदन के अन्दर आ जायें। माननीय धारीवाल साहब।

खेद प्रकट

दिनांक 09 मार्च, 2022 की बैठक में स्लिप-आफ-टंग की वजह से उच्चारित शब्द/अभिव्यक्ति के लिए खेद प्रकटीकरण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं करीब पौने 11 बजे के लगभग आपके चैम्बर में आया था और आकर के मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कल यहां पर जो घटना घटी है और मेरे मुंह से जो स्लिप-आफ-टंग की वजह से कुछ शब्द निकल गये, उसके लिए मैं सदन से माफी मांगना चाहता हूं।

आपने उस वक्त यह व्यवस्था दी कि एक बार हाउस होने दीजिये, हाउस होने पर आपका स्टेटमेन्ट दिलवा देंगे, लेकिन हाउस में जिस प्रकार से गतिरोध पैदा हुआ और जिस प्रकार से शोर-शराबा होता रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपना स्टेटमेन्ट पूरा पढ़ा, लेकिन वह आप लोगों के शायद, जैसा अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम सुन नहीं पाये, तो मैं दुबारा से आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पुलिस विभाग की अनुदान मागों पर कल मैं सदन में जब जवाब दे रहा था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से गलत निकल गये, जिसका अहसास होते ही मैंने अपने सम्बोधन के दौरान ही इन शब्दों को कार्यवाही से हटाने के लिए माननीय सभापति से अनुरोध किया। मेरे मुंह से निकले ये गलत शब्द स्लिप-आफ-टंग थे, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, बेहद खेद है।

दरअसल, राजस्थान मरु प्रदेश है, जिसके बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन स्लिप-आफ-टंग के कारण गलत शब्द निकल गये। मैं व्यक्तिगत तौर पर महिलाओं का बेहद सम्मान करता आया हूं और करता रहूंगा।

मेरे द्वारा कहे गये इन शब्दों से यदि किसी को ठेस लगी है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और माफी भी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। आज के स्थगन प्रस्ताव, 295, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, वार्षिक प्रतिवेदन पर जो व्यवस्था थी, वह कल के लिए स्थगित की जाती है और हम सीधे आय-व्ययक पर डिस्कशन प्रारम्भ करेंगे। माननीय मंत्री जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,20,90,50,000/- (एक सौ बयालीस अरब बीस करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 01 देखें)

मांग संख्या 13 - आबकारी की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13 - आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री परसादी लाल)

1,80,82,55,000/- (एक अरब अस्सी करोड़ बयासी लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 02 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रथम वक्ता को पार्टी ने समय दिया उसमें बोलेंगे, बाकी सब सदस्य 7-7 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें जिससे हम डिबेट को आगे बढ़ा सकें। श्री कालीचरण सराफ।

मांग संख्या 26 एवं 13 पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा हो रही है और मांग संख्या 13- आबकारी पर चर्चा हो रही है। मैं मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

मैं मेरी बात प्रारम्भ करूं, उससे पहले देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। देश के नागरिकों के लिए नि:शुल्क 175 करोड़ वैक्सीन लगाकर जो कीर्तिमान विश्व में स्थापित किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ धन्यवाद देना चाहूंगा, यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान, जो हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे थे, वहां से उनको सफलतापूर्वक सकुशल हमारे देश में वापस लाये। इसके साथ-साथ जो मेडिकल विद्यार्थी वहां से आये हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) कोविड और युद्ध के कारण इन्टर्नशिप पूरी नहीं कर पाये, ऐसे भारत के छात्र जो विदेशों में पढ़ रहे थे, उनके लिए इन्टर्नशिप की व्यवस्था हमारे देश में करने का आदेश उन्होंने प्रदान किया है। इसके लिए भी मैं मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

एनएमसी ने यह भी निर्णय किया है कि भारत में इन्टर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल छात्रों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जिस ध्येय वाक्य "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" को लेकर आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम हमारे सामने आये हैं। उसमें चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बहुमत के साथ वापसी हासिल की है और मैं क्या कहूं, कांग्रेस का सभी 5 राज्यों में सूपड़ा साफ हो गया है।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज यहां मांग संख्या 26 पर चर्चा हो रही है, पर मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन की पहली डोज भी पूरी नहीं लग पायी है, जो शत-प्रतिशत डोज का लक्ष्य था, वह भी पूरा नहीं हो पाया है।

उदाहरणार्थ, मैं आपको बताऊंगा जयपुर जिले में जहां 6 मार्च तक 4 लाख 62 हजार 338 बच्चों को पहली डोज लगनी थी, अभी तक केवल 2 लाख 91 हजार 592 लोगों को ही डोज लगी है। 1 लाख 70 हजार से ज्यादा बच्चे आज पहली डोज से वंचित हैं। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो यह बतायें कि जब आपको केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है तो क्या कारण रहा, किसकी ढिलाई रही कि आपके बार -बार निर्देश के बावजूद भी अभी तक वैक्सीनेशन का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है?

(समय: 13.18 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद 2013 तक हमारे राज्य में केवल 7 मेडिकल कालेज थे। एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक अजमेर में, एक जोधपुर में, एक झालावाड़ में, एक कोटा में और एक बीकानेर में। सबसे पहले जब देश के प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली। उन्होंने घोषणा की कि हिन्दुस्तान के हर जिले में मेडिकल कालेज होगा। और उसी के अनुरूप 2013 से 2018 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी का राज था राजस्थान में तो आठ मेडिकल कालेजेज की स्वीकृति दी और आज हमें खुशी है इस बात की कि सभी जिलों में मेडिकल कालेज स्थापित किए जायेंगे, इसकी घोषणा आदरणीय मोदी जी ने की है। अच्छा होता कि मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में यह कहते कि 60 प्रतिशत पैसा केन्द्रीय सरकार का और 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार का, तो एक शब्द वो यह कह देते कि मोदी जी के आदेश से हमें फख्र है इस बात का कि पूरे हिन्दुस्तान के हर जिले में मेडिकल कालेज हो रहे हैं और उसी के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के यहां कांग्रेस की सरकार होते हुए भी और

(श्री कालीचरण सराफ)

मोदी जी क्योंकि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' इस आधार पर चल रहे हैं, इसलिए यहां भी मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति दी, तो कम से कम उनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे राजस्थान के सामाजिक न्याय विभाग ने यह कहा कि यहां केवल 192 लोग अनाथ हुए हैं और 5,640 सिंगल पैरेंट के भरोसे यहां पर बच्चे रह रहे हैं और उसी के आधार पर आपने उनको सहायता भी दी पर केन्द्रीय सरकार की जो संख्या है उसके आधार पर 714 बच्चे अनाथ हुए और 6,098 के माता-पिता में से एक को उन्होंने खोया है, परन्तु यदि वास्तविक रूप से आप इसका सर्वे करेंगे तो यह संख्या जो बतायी जा रही है, चाहे केन्द्र सरकार की तरफ से बतायी जा रही है या राज्य सरकार की तरफ से, इससे तीन-चार गुना ज्यादा है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें उस समय निश्चित रूप से यह घोषणा करें कि आपके विभाग द्वारा पूरे राजस्थान का पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जायेगा और उस सर्वे में जितने बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके मां-बाप दोनों काल कवलित हो गये या किसी के माता की मृत्यु हो गयी, किसी के पिता की मृत्यु हो गयी, पूरा सर्वे कराकर और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जो अनाथ हुआ हो और वह सरकारी सहायता से महरूम हो जाये और जो आपने सहायता राशि दी है, उसके बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों के मां-बाप दोनों चले गये उनको कम से कम दस लाख रुपया एकमुश्त और जिनके माता-पिता में से एक चला गया उसको कम से कम पांच लाख रुपया एकमुश्त निश्चित रूप से दें और पेन्शन के रूप में जब तक वह 18 साल का नहीं होता, जिनके दोनों चले गये उनको दस हजार रुपये प्रति माह और जिनके एक चला गया उनको पांच हजार रुपये प्रति माह देने की आप निश्चित रूप से घोषणा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हुई हमारे जिम्मेदार पद पर स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति कैंसर दिवस पर स्टेटमेंट देते हैं कि तम्बाकू खाने से, तम्बाकू का सेवन करने से कोई कैंसर से मौत नहीं होती और उन्होंने यहां तक कहा कि जो तम्बाकू नहीं पीते, जो तम्बाकू का सेवन नहीं करते, उनके तो निश्चित रूप से कैंसर हो सकता है परन्तु जो

(श्री कालीचरण सराफ)

तम्बाकू का सेवन करते हैं उनके कैंसर नहीं होता। आप अब एक साधारण एमएलए नहीं हैं, आप राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके मुंह से इस प्रकार के शब्द निश्चित रूप से जनता को भ्रमित करने वाले शब्द हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने सबने यह कहा कि नहीं, जितनी भी मौतें होती हैं कैंसर से उनमें से अधिकांश मौतें तम्बाकू के सेवन से होती हैं, जिसने कभी न कभी तम्बाकू का सेवन किया है, ऐसे लोगों की मौत होती है तो मैं यह चाहूंगा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया हो सकता है कि इससे आपके वोटों में कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी, गांव के लोग आपसे खुश हो गए होंगे, परन्तु यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। आप जब अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से मैं यह चाहूंगा कि आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दें जनता से माफी मांगें और जनता को जो गुमराह करने का प्रयास आपने जिस स्टेटमेंट के माध्यम से किया है, निश्चित रूप से इससे लोगों को निजात मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारे प्रदेश में डाक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का सवाल है, हमारे राजस्थान में 43 हजार डाक्टर्स अभी पंजीकृत हैं और 1700 लोगों पर प्रदेश में एक डाक्टर है और सरकारी हास्पिटल में 11,000 पद स्वीकृत हैं और उनमें से 9,000 डाक्टर्स कार्यरत हैं और 2,000 डाक्टर्स के पद अभी भी रिक्त हैं और 34 हजार डाक्टर अभी निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 3 हजार छोटे-बड़े सरकारी अस्पतालों में से 2500 छोटे जिलों या दूरदराज गांवों में स्थित हैं, जहां करीब 75 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी चाहे वो डाक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो वो कोई भी वहां जाना नहीं चाहता और राजनीतिक रसूखों से वो शहरों में लग जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में मरीजों को जब कोई भी बीमार होता है तो उसको या तो जिला अस्पताल में आना पड़ता है या जो सम्भाग केन्द्रों पर कालेजेज हैं मेडिकल कालेज, वहां पर उनको आना पड़ता है। आपने कुछ दिन पहले एक अच्छा निर्णय किया कि जितने भी डेपुटेशन पर लगे हुए थे स्वास्थ्यकर्मी चाहे वो डाक्टर्स थे, नर्सेज थी या पैरामेडिकल स्टाफ के लोग थे, उनका आपने सबका डेपुटेशन समाप्त कर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं परन्तु इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आप पर जब दबाव पड़ेगा एमएलए साहेबान और कई लोग आयेंगे कि नहीं, साहब, यह तो मेरा रिश्तेदार है, इसको तो आप जयपुर में ही रखिये, मेरा

(श्री कालीचरण सराफ)

रिश्तेदार है इसको तो आप अजमेर में ही रखिये। आप यदि वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना चाहते हैं तो जो आपने निर्णय किया है उसकी आप सख्ती से पालन करियेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम जब भी नये डाक्टर्स की नियुक्ति करते हैं तो एक-दो महीने तो वह वहां पर जाता है, या तो ज्वाइन ही नहीं करता और यदि ज्वाइन कर भी लेता है तो वह कोई न कोई सिफारिश लगा करके और जयपुर में या बड़े शहरों में अपना डेपुटेशन करवा लेता है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, कम से कम जो भी डाक्टर नियुक्त होते हैं उनसे बोण्ड भरवाइये। 25 लाख रुपये और 50 लाख रुपये के बोण्ड भरवाने की व्यवस्था हम लोगों ने भी की थी और उसमें यह बताइये कि जहां आपकी नियुक्ति हुई है वहां यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा। परन्तु होता क्या है नियम तो बने हुए हैं परन्तु उसकी पालना नहीं होती है। दबाव पड़ता है हम लोगों पर और इसलिए आज चाहे पद 2 हजार ही खाली हैं डाक्टर्स के पर आप चले जाइये दूरदराज के इलाकों में, कहीं पर भी डाक्टर अवेलेबल नहीं हैं। सारे डाक्टर किसी न किसी राजनीतिक अप्रोच से सारा नर्सिंग स्टाफ, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, यह सब शहरों के आस-पास लगे हुए रहते हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप जब अपना जवाब दें तो सख्ती के साथ इस बात की आप घोषणा करें कि निश्चित रूप से जिन डाक्टर्स की नियुक्ति होगी, उनको जहां नियुक्त किया जायेगा वहां पर वो कम से कम पांच साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगा और दूसरा मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि आज हमारे कई डाक्टर मित्रों से बात होती है तो वह कहते हैं कि प्राइवेट होस्पिटल्स में हमको ज्यादा तनख्वाह मिलती है इसलिए हम लोग प्राइवेट होस्पिटल्स में जाना ज्यादा पसन्द करते हैं, एक तो शहर में रहते हैं और प्राइवेट होस्पिटल में तनख्वाह ज्यादा मिलती है तो आप विचार करिये, मुख्य मंत्री जी से बात करिये...

और जो आपका सपना है 'नीरोगी राजस्थान', इसको यदि वास्तव में सही करना चाहते हैं तो यदि इनका पैकेज बढ़ाने की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से इनका पैकेज भी बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं एक बात और कहूंगा कि जो डाक्टर शहरों में लगते हैं उनको हम

(श्री कालीचरण सराफ)

लोग शहरी भत्ता देते हैं, मकान किराया देते हैं। इसको बन्द कर दीजिए और जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहते हैं, यदि आवश्यकता हो तो उनको ग्रामीण भत्ता भी दीजिए और वहां रहने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा भी मुहैया कराइये। यदि आप यह करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से इसका फायदा होगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे से ईसीजी टेक्निशियंस संवर्ग के लोग मिले थे। आज ईसीजी टैस्ट, सीटी एमटी टैस्ट, 2D ईको टैस्ट, थ्रीडी ईको रिपोर्टिंग, हाल्टर मानिटर टैस्ट, टीआरओपी टैस्ट, बीटी टैस्ट, कार्डियोलाजी की जांच का कार्य, आरपीएमसी में रजिस्टर्ड दक्ष एवं प्रशिक्षित ईसीजी टेक्निशियंस के द्वारा किया जाता है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हर पीएचसी पर हम नि:शुल्क जांच करवायेंगे, किससे करवाओगे? आज ईसीजी टेक्निशियंस के 50 परसेंट से ज्यादा पद रिक्त हैं। यदि यह पद रिक्त रहेंगे तो मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की कि पीएचसी, सीएचसी पर हम जांच की सुविधा देंगे, कहां से जांच कराओगे? अप्रशिक्षित व्यक्ति वहां पर जांच करेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी को अगर ईसीजी जांच करानी है तो वह जिला हैडक्वार्टर पर जाता है, संभागीय केन्द्र पर जाता है, बड़े हास्पिटल में जाता है। आप देखिए कि 77282 बैड पर 1840 टेक्निशियंस चाहिये और आज हमारे 177 हैं, यानी 10 परसेंट। हमारे जयपुर शहर के एसएमएस हास्पिटल की स्थिति बताऊं, एसएमएस में सात सरकारी अस्पतालों में 223 पद ही भरे हुए हैं और उसमें केवल 8 महिलाएं हैं। जो बाकी हास्पिटल हैं, चाहे कांवटिया हास्पिटल हो, चाहे जयपुरिया हास्पिटल हो, चाहे आरयूएचएस हास्पिटल हो, वहां पर महिला ईसीजी टेक्निशियंस तो है ही नहीं। अब किसी महिला को अगर जांच करानी है तो वह पुरुष करता है। मैं यह चाहूंगा कि आप प्राथमिकता के आधार पर ईसीजी टेक्निशियंस की नियुक्ति करने का आदेश प्रदान करें जिससे लोगों को जांच की सुविधा मिल सके और जो मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि पीएचसी और सीएचसी पर जांच की सुविधा हम मुहैया करायेंगे, उसको हम पूरा कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, हम यह देख रहे हैं कि मेडिकल कालेजेज में चिकित्सा शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद रिक्त रहते हैं। आरपीएससी से भर्तियां की जाती हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है। हमने हमारे समय में एक प्रयोग किया था कि जो नये मेडिकल कालेज खुले थे, उनमें हमने

(श्री कालीचरण सराफ)

डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से डाक्टर्स की नियुक्ति की थी और उसके परिणामस्वरूप डाक्टर्स की नियुक्ति में जो समय लगता है, आरपीएससी में जाते हैं, फिर वहां लिखित एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसमें साल भर लग जाता है। मैं चाहूंगा कि चाहे पुराने मेडिकल कालेज हो, चाहे जो नये मेडिकल कालेज खुल रहे हैं, वह मेडिकल कालेज हो, सबमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू करो क्योंकि आपका एमबीबीएस यहीं से किया है, एमएस यहीं से किया है, पीजी यहीं से किया है, तो उसका डायरेक्ट इंटरव्यू करके जो-जो भी लगना चाहते हैं, उनको आप डायरेक्ट अपाइंटमेंट दीजिए, जिससे कि समय की बचत हो।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आये दिन यह सुनने को मिलता है कि मरीजों के परिजनों के द्वारा डाक्टर्स से मारपीट की घटनाएं। कभी एसएमएस में हो जाती हैं, कभी जयपुरिया में होती हैं, कभी कांवटिया में होती हैं, कभी जोधपुर के हास्पिटल में हो जाती हैं, कभी अजमेर के हास्पिटल में। यह नहीं हों, इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े हास्पिटल हैं वहां पुलिस चौकी का इंतजाम होना चाहिये और वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिये। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा। आपने तो चुनाव घोषणा पत्र में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की बात कही थी। आप जब जवाब दें तो यह भी बताएं कि आप यह एक्ट कब लागू करेंगे, इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है?

माननीय सभापति महोदय, एसएमएस हास्पिटल हो या अन्य हास्पिटल हो, यहां करोड़ों रुपये की मशीनें खरीदकर डिब्बों में बन्द पड़ी है। क्यों पड़ी है, कहते हैं खराब हैं, यह ठीक नहीं हुई। यह स्थिति क्यों होती है, क्योंकि डाक्टर्स का कमीशन होता है। आज यदि प्राइवेट जगह पर वह भेजेंगे तो उसमें 40-50 परसेंट कमीशन होता है। जब करोड़ों रुपये की मशीनें हमारे पास सरकार ने खरीदकर यहां पर रखी हुई हैं तो उस पर कुछ खर्चा कर के अगर ठीक कराने की आवश्यकता है तो ठीक कराई जाय। इससे निश्चित रूप से जनता को कमीशन खोरों से निजात मिलेगी।

एक बात मैं और ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारा जो एसएमएस हास्पिटल है, वह 80 साल पुराना है और यहां पर कभी किसी कमरे में शार्टसर्किट हो जाता है, कभी कहीं पर प्लास्टर गिर जाता है, कहीं पर कोई

(श्री कालीचरण सराफ)

दीवार गिर जाती है। आये दिन यह घटनाएं होती हैं। मैंने जानकारी ली तो पता लगा कि केवल 2 करोड़ रुपया सालाना हम वहां मेंटीनेंस के लिए देते हैं। एसएमएस हास्पिटल हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा हास्पिटल है, दिल्ली के एम्स हास्पिटल से भी बड़ा है। मैं यह चाहूंगा कि यहां मेंटीनेंस के नाम पर जो दो करोड़ रुपये दिये जाते हैं इसकी जगह पर्याप्त बजट उपलब्ध करायें और परमानेंट किसी एजेंसी के द्वारा मोनिटरिंग हो।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने एसएमएस हास्पिटल और ट्रोमा सेंटर के बीच में जो टोंक रोड पड़ता है, वहां अंडरपास बनवाया था। आप देखिए कि जब अंडरपास बनवाया तो उसमें लगा कि करोड़ों रुपये खर्च होंगे। वहां जब दुकानें आक्शन हुईं तो जितना पैसा उस अंडरपास में लगा उससे ज्यादा पैसा एसएमएस हास्पिटल के पास आ गया। मैं यह चाहूंगा कि जैसे यहां सुविधा मिली आज चाहे मरीज हो, चाहे डाक्टर हो, उनको अब सड़क पार नहीं करनी पड़ती। हमारी योजना भी थी, सरकार चली गई, आपकी सरकार आ गई। मेडिकल कालेज एसएमएस हास्पिटल के बीच में जेएलएन मार्ग पड़ता है, वहां भी यदि अंडरपास बन जाये तो जो हमारे रेजीडेंट डाक्टर मेडिकल हास्टल में रहते हैं, डाक्टर्स भी आते-जाते रहते हैं, उनकी दुर्घटनाएं नहीं हो और आना-जाना सुविधाजनक हो जाये और उसमें आप दुकानें भी बना दें और दुकानों का अगर आप आक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा मिल सकता है।

यह बात भी सही है कि एसएमएस हास्पिटल इतना बड़ा हास्पिटल होने के बाद भी, इतनी ओपीडी होने के बाद भी आज वहां जगह कम पड़ रही है। मेरा एक सुझाव और है कि हमारे डीजी साहब का बंगला और सीएस का बंगला, यह दोनों हास्पिटल के पास में है और 6-6, 7-7 हजार गज में यह बने हुए हैं। अब कभी सीएम साहब को सीएस साहब की आवश्यकता पड़ती है तो उनको टाइम लगता है तो वहां सीएम साहब के बगल में ही आमने-सामने इनको बंगला दे दो। डीजी साहब को भी वहां बंगला दे दो और यह जो जमीन है, इसको यदि आप खाली करवाकर हास्पिटल के लिए दे देंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको सालों साल याद करेगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज केवल कंस्ट्रक्टिव सुझाव दूंगा, मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा। सभापति महोदय, हमारा एमएमएस हास्पिटल है, उसकी प्रतिदिन की ओपीडी लगभग 10 हजार की है। जब हमारी सरकार

(श्री कालीचरण सराफ)

थी तो हमने मरीजों का दबाव कम करने के लिए बिना किसी भेदभाव के जयपुरिया हास्पिटल दक्षिण में, कांवटियां हास्पिटल पश्चिम में, गणगौरी हास्पिटल उत्तर में और सेठी कालोनी का सैटेलाइट हास्पिटल पूर्व में, इनमें हमने सुविधाएं उपलब्ध करवायी थीं। जयपुरिया में सीटी स्कैन, एमआरई, 2D ईको, टीएमटी व अन्य सुविधाओं के साथ सुपर स्पेशिलिटी उपचार भी प्रारम्भ किया था। जहां पहले तीन सौ का आउटडोर था, वह बढ़कर ढाई-तीन हजार का हो गया था, परन्तु सरकार बदलते ही वहां पर सुपर स्पेशिलिटी की फैसेलिटी बन्द कर दी गयी। जयपुरिया का ईएचसीसी हास्पिटल से एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए एमओयू हुआ था। उसमें यह प्रोविजन था कि बीपीएल परिवार और वरिष्ठ नागरिकों की जांच नि:शुल्क की जाये, परन्तु क्या पता, क्या अव्यवस्था हुई कि अब तीन-तीन महीने की वेटिंग है। यदि वहां कोई वरिष्ठ नागरिक जाता है या बीपीएल परिवार का व्यक्ति जाता है तो उसको तीन-तीन महीने वेट करना पड़ता है। आज यदि आपको एमआरआई कराने की आवश्यकता है और आज आवश्यकता सीटी स्कैन कराने की है तो फिर तीन महीने वेट कौन करेगा? इसलिए इस व्यवस्था को भी सुधारा जाये। इसी प्रकार हमने कांवटियां में ब्लड बैंक, ईको कार्डियोलाजी सेन्टर, आईवीएफ सेन्टर समेत अनेक सुविधाएं दी हैं। ओपीडी 2 हजार से बढ़कर 4 हजार हो गया। सेठी कालोनी में मेडिसन, सर्जरी, शिशु रोग, कार्डियोलाजी की सुविधा, सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करायी। गणगौरी बाजार में भी हमने कई सुविधाएं मुहैया करायीं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी। हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि इन हास्पिटल को स्ट्रेन्थन करने के लिए और आरयूएचएस हास्पिटल को सुदृढ़ करने के लिए कोई घोषणा करेंगे। उन्होंने अपनी बजट घोषणा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोती डूंगरी रोड पर एक मोबाइल हास्पिटल को सैटेलाइट हास्पिटल करने की घोषणा की है, यह तो आपने अच्छा किया। मैं यह चाहूंगा कि जयपुरिया हास्पिटल जो कि विकल्प बन सकता है, वहां पर आज भी सुपर स्पेशिलिटी की व्यवस्था नहीं है और वहां पर कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो उसको हाथों-हाथ एसएमएस रेफर कर दिया जाता है। वहां पर जो एक्सीडेंटल केस आते हैं, उनकी भी व्यवस्था हो। जो आरयूएचएस हास्पिटल है,

(श्री कालीचरण सराफ)

वह बहुत बढ़िया हास्पिटल बन गया। वहां पर 1200 की कैपेसिटी है। कोविड के अन्दर शानदार काम आरयूएचएस के डाक्टर्स ने किया। परन्तु वहां भी इस हास्पिटल में मेडिकल टीचर्स की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। सुपर स्पेशिलिटी की सुविधाओं का भी अभाव है। न्यूरो सर्जरी, ट्रोमा सेन्टर, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी के बड़े सेन्टर्स के रूप में तैयार करने के लिए गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है। बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह चाहूंगा कि ये व्यवस्थाएं भी हों, इसके बारे में भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो-तीन मिनट और लूंगा। सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में Rajasthan University for Health and Science को खुले 16 साल हो गये। इससे जुड़े मेडिकल, डेन्टल और नर्सिंग कालेज भी खुल गये, परन्तु अभी भी सरकारी फार्मेसी कालेज का इन्तजार है। आरयूएचएस का सरकारी संघटक फार्मेसी कालेज नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्राइवेट कालेजों में जाना पड़ता है और महंगी फीस देनी पड़ती है और वहां से फार्मेसी का कोर्स करने को मजबूर होना पड़ता है। जयपुर में सालों से मात्र एक डिप्लोमा कालेज है। मैं यह चाहूंगा कि जब आप हर जिले में नर्सिंग कालेज खोल रहे हैं, उसी प्रकार से कम से कम हर सम्भाग केन्द्र पर एक-एक सरकारी फार्मेसी कालेज खोलेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि नर्सिंग ट्यूटर के समकक्ष शैक्षणिक योग्यताओं और वेतन श्रृंखला वाले राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों को तो आपने राजपत्रित संवर्ग में लाने का ऐलान कर दिया, परन्तु नर्सिंग ट्यूटर्स के बारे में आपने कुछ नहीं किया। इससे आपके ऊपर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। यदि इनको भी आप राजपत्रित संवर्ग में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से यह फायदे की बात होगी। मैं निजी अस्पताल के बारे में भी दो मिनट कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: अब और नहीं, समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट में कर रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करिये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये निर्देश दिये हैं कि सब सात-सात मिनट बोलेंगे, आपको तीस मिनट बोलना था। आप बोल चुके हैं। प्लीज सहयोग कीजिये, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दो मिनट और दे दीजिये, प्लीज दो मिनट।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, आसन की व्यवस्था, प्लीज सहयोग करें, आप समय क्यों खराब कर रहे हैं? आपने दो मिनट के लिए कहा, मैंने आपको दो मिनट दे दिये। दो-दो मिनट करने का कोई अर्थ तो है नहीं। डा. राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद।

'सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु,
सर्वेषां पूर्णम् भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।

"सबका कल्याण हो, सबमें शान्ति हो, सबके कार्य सिद्ध हों, सबका मंगल हो, पूरा संसार सुखी हो।" यह श्लोक मैंने इसलिए बोला है, क्योंकि आज मांग संख्या 26, राजस्थान की सात करोड़ की जनसंख्या के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण मांग है। उस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। ईश्वर से यह मंगल कामना करते हुए कि आज राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में हम लोग एक ट्रस्टी के रूप में बैठे हैं और हम सब ट्रस्टियों के मुख्य ट्रस्टी हमारे सदन के नेता, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने चिकित्सा से लेकर हर विभाग में इस बजट में जो जन कल्याणकारी घोषणा की है। मैं जहां तक समझता हूं, मैं मेरी शुभकामनाओं के साथ इस रूप में आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि राजस्थान की जनता मुख्य मंत्री जी के आवास पर, 36 कौम की जनता और कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए सभी संगठन किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां पर आ रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान की जनता माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों पर कितना भरोसा करती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार का नारा है, निरोगी राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। प्राचीन कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया और जान है तो जहान है। राजस्थान की चिकित्सा सेवाओं में जो विस्तार हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को भूल नहीं सकती, चाहे हमने कितने अस्पताल खोले हों,

(डा. राजकुमार शर्मा)

सीएचसी खोली हो, पीएचसी खोली, रिकार्ड उप स्वास्थ्य केन्द्र, नि:शुल्क दवा योजना हो, नि:शुल्क जांच योजना, घातक बीमारियों के बचाव के लिए योजनाओं का विस्तार हो। मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आयुर्वेद एवं योग कालेज खोलने से संबंधित सभी चिकित्सा क्षेत्रों में जनोपयोगी कार्यक्रम प्रारम्भ किये और उन्हें लगातार बढ़ाने का कार्य किया।

माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व चिकित्सा मंत्री तीन साल पहले थे, तीन साल पहले इन्होंने चिकित्सा विभाग में ऐसा राम राज्य ला रखा था। (व्यवधान) राम को ही भूल गये, अभी तो आप लोग नारे लगा रहे थे। ऐसा राम राज्य था कि उस समय सारे पद भरे हुए थे, सारी जांचें चल रही थीं, सारे अस्पताल फुल थे। हमारे आने के बाद वे पद भी समाप्त हो गये और उन पदों पर जो लोग काम कर रहे थे, वे लोग भी छोड़-छोड़कर भाग गये। सुझाव वे व्यक्ति दे रहे हैं जिन्होंने पांच साल चिकित्सा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। ताज्जुब होता है जब वे अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि 2013 से पहले 7 मेडिकल कालेज थी। मनमोहन सिंह जी ने, आप उठा लें, यह तो सारा डाक्यूमेंट्स में है। आजकल तो बटन दबाते हैं तो सब कुछ आ जाता है। मनमोहन सिंह जी के समय, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि उस समय मैं अशोक गहलोत सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा था, सर्वे हुआ था। एक पीडीकोर कम्पनी थी, उसने सर्वे करना शुरू कर दिया था। आपको पता है कि सीकर के अन्दर जमीन भी चिह्नित कर ली थी। बाद में वह कालेज कहां गया? हालांकि हम तो चाहते थे कि चूरू में खुले, झुंझुनूं में भी खुले, सीकर में खुले, लेकिन चलो आपको मौका मिला और आप उसको लेकर दौड़ पड़े वहां पर, कोई बात नहीं, आदमी के समय-समय की बात होती है। रख-रखाव की बात करें, 2 करोड़ रुपये एस.एम.एस. के अन्दर बढ़ा दो, किसने बढ़ाए? उस समय की आप हालत सोचिए, हालत ऐसी थी कि एस.एम.एस. के अन्दर कोई पेशेंट अगर 70 परसेंट बीमार जा रहा है तो 100 परसेंट तो बैड तक पहुंचतेपहुंचते हो जाता। हम लोगों ने कितनी सफाई की व्यवस्था की, हम लोगों ने खुद रात भर जाग-जाग कर वहां पर मानिटरिंग की।

आज वह डेपुटेशन की बात कर रहे हैं। हमारे चिकित्सा मंत्री जी की भावनाओं को भड़का रहे हैं। परसादी लाल जी, हमारे चिकित्सा मंत्री जी, एक ऐसा दिमाग बनाकर बैठे हैं, वह खुद समझते हैं इस बात को। मुझे आज भी

(डा. राजकुमार शर्मा)

याद है कि जब वह चिकित्सा मंत्री जी थे, माननीय सभापति महोदय, मैं उनके ऑफिस में गया, उनके कार्यालय के अन्दर, मैंने कहा कि यहां पर 7 डाक्टर काम कर रहे थे, आपने वहां से 6 कैसे उठा लिए? वह खुद बोल रहे थे कि क्या करें, दबाव है, सारे आई.ए.एस. जयपुर में बैठते हैं, सारे उद्योगपति जयपुर में बैठते हैं, सारे नेता जयपुर में बैठते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? आज वह ज्ञान दे रहे हैं। उनका ज्ञान सुनकर ताज्जुब हुआ मुझे।

आज एक नई चीज और बोली उन्होंने। आज एक बात और बोली कि यह एमओज का पैसा क्यों नहीं बढ़ाते, पैकेज क्यों नहीं बढ़ाते? माननीय सभापति महोदय, 16 हजार रुपये के अन्दर हमारा एमओ काम करता था, 2008 से पहले, 16,000 रुपये में मात्र। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी को और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे दुर्रू मियां जी को, कि हमारी एक रिक्वेस्ट के ऊपर 30 हजार रुपये उन एमओज के किये गये। पहली बार 30 हजार रुपये। हमें पता था कि 16 हजार के अन्दर हमारा एम.बी.बी.एस. किया हुआ डाक्टर कैसे गांव के अन्दर अपनी सेवाएं दे सकता है? आपने 5 साल में एक रुपया भी बढ़ाया क्या उनका? एक रुपया भी नहीं बढ़ाया। आज वह पैकेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

अभी इन्होंने एक भी उपलब्धि नहीं बतायी। शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने की, एक उपलब्धि नहीं बताई और उपलब्धि थी भी नहीं तो बता भी क्या सकते थे? एक उपलब्धि मुझे जरूर ध्यान में है कि हमारी मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसका नाम इन्होंने जरूर चेंज किया, भामाशाह योजना। उस योजना का नाम चेंज किया जो पूरे देश के अन्दर नहीं, देश के बाहर भी लोगों ने तारीफ की, उसको सराहा।

अभी बात मशीनों की कर रहे थे कि बहुत सारी मशीनें हैं जो वहां पर धूल फांक रही हैं। उनका यूज नहीं आ रहा है, कमीशन का खेल होता है। मैं जहां तक समझता हूं कि जितनी स्टडी हमारे माननीय सदस्य मालवीय नगर से आने वालों ने कर रखी है इस मामले पर, वे लगा ल्यो भाई साहब, क्योंकि थांको मामलो वन-वे है, मनै पतो है, सभापति महोदय, अब ये बोल तो गये लेकिन सुनेंगे नहीं क्योंकि वन-वे है मामला इनका। इनको कहिए प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने दोनों तरफ लगा लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): दोनों तरफ लगा लिए, धन्यवाद साहब। इसके बारे में, इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कमीशन का खेला। मैं जहां तक समझता हूं कि वह मशीनें क्यों बेकार पड़ी हैं? क्यों नहीं पड़ी हैं? आप सब समझते हैं लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि तीन साल पहले जिस महकमे को आपने चलाया और जो महकमा 2013 में हम छोड़कर गये थे आपके पास में, उसके बाद की आपकी सरकार ने चिकित्सा विभाग का भट्ठा बैठाने का काम किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप उन्हें इन्वाइट नहीं करें। आसन को सम्बोधित करें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिए हैं वे माननीय नेता प्रतिपक्ष और सबसे वार्ता करके दिए हैं। अब आप यदि बीच में इस तरह से इंटरवीन करेंगे तो जो बोलने वाले वक्ता बैठे हैं, जिनको मात्र सात-सात मिनट दिया जा रहा है, उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्या? आप तो जो है ट्यूरिस्ट आते हैं। मैं आपसे मुखातिब हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरी ओर इंगित करते हुए बात कही है।

श्री सभापति: आप विराजिये। आप एज ट्यूरिस्ट आते हैं यहां पर, बोले और गये। ये लोग सुबह से आकर शाम तक बैठते हैं, इनका क्या होगा? मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया इंटरवीन नहीं करें और समय का ध्यान रखें। जो वक्ता बोलने के लिए सुबह से शाम तक यहां पर बैठे रहते हैं, उनका सम्मान करें। वह नये-नये वक्ता आए हुए हैं, नये-नये विधायक बने हैं, उनको आप कुछ सीखने दें। मैं आप दोनों से मुखातिब हूं, कृपया इंटरवीन नहीं करेंगे आप दोनों। उनको भी कह दिया। आप उनको इन्वाइट मत कीजिए। आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, हम कब किसी को इन्वाइट कर रहे हैं? जब वह बोल रहे थे, तब हम तो कुछ नहीं बोले। हम तो सुन रहे थे। सब चुपचाप बैठे थे। एक सामान्य स्टूडेंट की तरह सुन रहे थे। ये संवेदनशील बताने वाले उपनेता जी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तय कर देते हैं, हम नये लड़कों को बोलने का मौका ही नहीं देते। सुनने का मौका नहीं देते। अब रवाना हो रहे हैं। मैं तो इन्वाइट कर ही सकता हूं कि बैठकर सुनें।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख और अब इसमें 10 लाख रुपये तक की

(डा. राजकुमार शर्मा)

सीमा तक नि:शुल्क उपचार होगा। यह जनता के लिए संजीवनी की तरह सिद्ध होगा जिसमें कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा जैसी सैकड़ों बीमारियों का इलाज होगा। कृषि बजट में भी औषधीय खेती व जैविक खेती को माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐतिहासिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। जब बजट के ऊपर माननीय सभी सदस्य बोल रहे थे विपक्ष के, सब एक ही चिन्ता कर रहे थे कि ये घोषणाएं तो हो गयीं चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर, कृषि बजट के अन्दर, सड़कों के ऊपर लेकिन ये बजट की घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? पैसा कहां से आएगा? सब एक बात पर चिन्ता कर रहे थे, चाहे प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित नेता जी हो। मेरा यह मानना है कि आप लोगों को सुझाव देने चाहिए थे। ये तो बात वैसे ही हो गयी कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है काम्पीटिशन की और गांव वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले उसको यह ताना दे कि तू कैसे आई.ए.एस. बनेगा? कैसे डाक्टर बनेगा? हम देखेंगे तू कैसा बनेगा? लास्ट के अन्दर वह बच्चा ये कहता है कि जिस दिन रिजल्ट आए, उस दिन देख लेना। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन योजनाएं पिछले तीन साल के अन्दर जितनी धरातल के ऊपर हम लोग लेकर आए हैं, हमारी सरकार लेकर आई है, आने वाले वक्त के अन्दर पर जब यह धरातल पर आकर लोगों को फायदा देगी, उस समय आपको अहसास होगा। वरना आपके पास में दो साल बाद में चुनाव है, निश्चित रूप से जनता की अदालत में आप और हम जाएंगे तो जनता फैसला करेगी।

भाई, बधाई हो, उसके लिए, आपको बधाई हो। बहुत-बहुत बधाई, आपको जीत की बधाई। लोकतंत्र के अन्दर यह सब चीजें चलती हैं। पंजाब के लिए भी आपको विशेष बधाई, 4-5 सीटों के लिए। वहां भी आपके ही लोग थे। पंजाब के अन्दर भी तो 4-5 सीटें गिनती की आयी हैं, वह भी कैप्टेन साहब से मिलकर। आप इस बात को छोड़िए, हमने भी बहुत अच्छी-अच्छी जीत देखी हैं, हार भी देखी है। लोकतंत्र के अन्दर हार और जीत, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार-जीत चलती रहती है। हम लोग आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित जरूर हैं लेकिन निराश नहीं हैं। आने वाले वक्त के अन्दर सब चीजें आएंगी, चिन्ता मत कीजिए।

मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के उस कथन को सार्थक किया है, जो आप लोगों की एक क्वेरी चल रही थी बार-बार, मैं कहना चाहता हूं मंडेला जी का एक कोट है, वह आपके सामने बताना चाह

(डा. राजकुमार शर्मा)

रहा हूं कि 'जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असम्भव ही लगता है।' मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुझे आज भी याद है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी 2008 से 2013 के बजट में घोषणा कर रहे थे, तब पूरे विपक्षी सदस्यों ने एक ही बात कही कि क्या संभव है? क्या सरकारी अस्पतालों के अन्दर फ्री इलाज मिल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जांचें फ्री हो जाएंगी? लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर वह व्यक्ति, वह परिवार जिनके घर में बेटा और बेटी दोनों बीमार हो जाते थे, ऐसे इलाके, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, इलाकों के अन्दर प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम किया है, वहां पर देखा है कि बेटा-बेटी बीमार है। बेटे का इलाज पहले माता-पिता करा रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? बोले कि पैसा हमारे पास इतना ही है कि बेटे का इलाज करा पाएंगे। बेटी तो अपने आप ठीक हो जाएगी।

हमने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया। वह योजना चालू हुई। योजना चालू होने के बाद में उसका रिजल्ट पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। इस बजट में भी आपने, मैं समझता था कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी बहुत अच्छे सुझाव देकर, यह बजट कैसे सफल हो, कैसे जनता का काम हो, यह बात जरूर बताएंगे। लेकिन सारे सदस्यों ने नकारात्मक बातें कीं। इसके अन्दर ऐसी-ऐसी बातें की कि आदमी उत्साह के रूप में कोई काम करे तो वह वैसे ही सोचे कि अब कैसे हो पाएगा? इतने सारे एक साथ हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आपने जितने भी हमले किये, हमारे मुख्य मंत्री जी के ऊपर, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि घोषणा मैंने सोच-समझकर की है। वे जितनी भी घोषणाएं करते हैं, वे खुद उसको मानिटर करते हैं। आप पैसे की चिन्ता मत कीजिए, मैं हूं न, यह बात किसने कही? यह हमारे सदन के नेता ने। केन्द्र सरकार के अन्दर हमारे प्रधान मंत्री जी, आपके नेता मोदी जी, उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया, सदन के अन्दर विपक्षी सदस्यों ने पूछ लिया कि नोटबंदी की विफलता, जी.एस.टी. की विफलता, कोविड के समय जो आप लोगों ने, जिस प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर रात को अचानक लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद उपजे हालात के बाद जिस प्रकार से आपका फेल्योर जनता ने पूछा, विपक्षी सदस्यों ने पूछा, समाचार पत्रों ने पूछा।

(समय: 14.00 बजे)

तो आपके प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि आप चिन्ता मत कीजिये, मैं

(डा. राजकुमार शर्मा)

बैठा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। मुझे पता है, उन्होंने एक भाषण में कहा कि यह सारी समस्याएं निपटेंगी तो ठीक है, वरना मेरा क्या है, मैं तो संन्यासी हूं, झोला उठाऊंगा और हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा। एक प्रधान मंत्री जी, एक जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति, अगर यह बात कहे, तो आप सोचिये, कितने करोड़ यानी डेढ़ सौ करोड़ देशवासियों को भ्रम में डालने वाला बयान था यह। बेरोजगारों को सकते में डालने वाला बयान था, उनके सपने तोड़ने वाला बयान था। यह तो वही बात हो गई, एक बस चलाने वाला व्यक्ति, बस में 50 सवारियां बैठी हैं, वह बस चला रहा है, सवारियां कह रही हैं कि आगे टूटा हुआ पुल है, कैसे निकालोगे, जब गाड़ी बीच में चली जाती है, तो वह कहता है आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो कूद रहा हूं और वह छलांग लगा देता है। इस देश को आपने इस स्थिति में डाल दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी सरकार का हौसला बढ़ाइये। जो अच्छे काम करते हैं, उनकी बातों को आपको सपोर्ट करना चाहिये। आपको सुझाव देकर, इन योजनाओं को बढ़ाने का काम करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आज भी याद है, उस समय मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का अध्ययन करने के लिए भारत के 16 राज्यों के प्रतिनिधि आये थे, जिसमें इनका गुजरात भी शामिल था। तब भी हमने इस पवित्र सदन के अन्दर यह बात कही थी कि गुजरात की एक टीम आई है, आप लोग तो विरोध कर रहे हो, लेकिन गुजरात की टीम आकर, जिसमें विधान सभा के कई माननीय सदस्य थे और आईएएस थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने आकर हमसे एक-एक चीज पूछी कि आपने किस तरह से गांव लेवल तक, ग्राउण्ड जीरो तक ले जाकर इस योजना को सफल बना रहे हैं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मुख्य मंत्री कौन थे गुजरात के... (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): गुजरात के मुख्य मंत्री, मुझे तो पता नहीं उस समय कौन थे ... (व्यवधान) हां नरेन्द्र मोदी जी थे। वह बातें बहुत टाइम की हो गयीं, अब।

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): हिन्दुस्तान से तो लोग आये ही आये, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार पेट्रिक ग्रेसपार्ड भी, नि:शुल्क दवा योजना की जानकारी लेने के लिए हमारे जयपुर के बस्सी में आये। उन्होंने भी प्लानिंग देखी और इस योजना को सराहा।

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना और पुरानी पेंशन बहाली। चिकित्सा विभाग के बहुत सारे कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कर्मचारियों के अन्दर खुशी की लहर है। सीएमआर के अन्दर तो एक महिला कर्मचारी ने कहा कि हमें बुढ़ापे की लाठी दे दी है। चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई थी वह महिला। आप सोचिये, अगर उनको सरकार की तरफ से इतना विश्वास मिल जाये कि आप चिन्ता मत करो। जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, जो काम है, उसको करते जाइये, सरकार आपके भविष्य का, आपके परिवार का ख्याल रखेगी, ऐसी योजना को वापस बहाली करके, इस प्रदेश की जनता को, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सम्बल प्रदान किया है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 2008-13 के बीच में हमने जो सुधार किये थे और 2013-18 तक आपने उन सुधारों को किस तरह खराब किया, वह आपके सामने बताना चाहता हूं। सिर्फ तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूं। सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केन्द्र।

हमने गांव-गांव तक हास्पिटल खोले। उन अस्पतालों का भवन भी नहीं बना पाये। हमने भर्तियां उस समय 45 हजार निकाली थीं। उन भर्तियों में भी आपने कटौती करके खतम कर दिया। 2008-09 में जब आपका कार्यकाल था, उस समय पूरे राजस्थान में सीएचसी 367 थी, हमने उसको बढ़ाकर 563 किया। इन्होंने पूरे पांच साल में 563 को बढ़ाकर 606 किया यानी मात्र 43 सीएचसी आप पूरे राजस्थान में खोल पाये। ऐसे ही, 2008 में पीएचसी 1503 थी, हमने उसको बढ़ाकर 2081, यानी पांच साल के अन्दर 578 खोलीं। इन्होंने 2013-18 में मात्र 9 पीएचसी खोली हैं। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य साहब, मात्र नौ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आंकड़े कहां से लाये हो?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आंकड़े स्वास्थ्य विभाग से ही लाऊंगा और कहां से लाऊंगा। (व्यवधान) यह तो आप लोग बोलोगे, उस समय सही रख देना, अगर हम मिथ्या बोल रहे हैं तो माफी मांग लेंगे। हम तो उसी वेबसाइट से लाये हैं, कोई अलग से तो लाये नहीं हैं। माननीय कालीचरण साहब, आपने चिकित्सा मंत्री रहते हुये एक बहुत बड़ा पाप किया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): लांछन लगा रहे हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लांछन इसलिए कहना चाहता हूं, चिकित्सा विभाग के पीएचसी, सीएचसी आपने पीपीपी मोड पर दी है या नहीं, आप बता दीजिये। सभापति महोदय, इन्होंने पीपीपी मोड पर दी है। आपको ध्यान है कि उस वक्त हम लोग मात्र 21-22 लोग ही, विपक्ष के अन्दर बैठे थे। इधर 163 लोग थे। इन्होंने चिकित्सा संसाधन पीपीपी मोड पर दे दिये। पीपीपी मोड, उन-उन व्यक्तियों को, जिनको खुद का हास्पिटल चलाने का अनुभव नहीं। हमारे सरकारी हास्पिटल, जो जनता के विश्वास के प्रतीक होते हैं, उस अस्पताल को इन्होंने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया।

मुझे तो ताज्जुब हुआ, जब उप नेता कल-परसों प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बिल आ रहा था, उस पर इन्होंने कहा कि निजीकरण कर रहे हो, निजीकरण कर रहे हो। आपने उस समय स्कूलों का निजीकरण करने का असफल प्रयास किया। उस समय आपने अस्पतालों को भी पीपीपी मोड पर दे दिया। धीरे-धीरे आपके द्वारा किये गये कांट्रेक्ट खतम हो रहे हैं, हम वापस लेकर आ रहे हैं। सरकार के अन्दर वापस उन अस्पतालों को ले रहे हैं। लोगों के अन्दर खुशी की लहर है, इस बात के लिए।

माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस संजीवनी बनकर उभरी है, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अन्दर। राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार का ज्वाइंट वेंचर है, इसको दोनों मिलकर चलाते हैं। मुझे कहते हुए दु:ख है। चिकित्सा मंत्री जी, मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहूंगा। 108 एम्बुलेंस उन लोगों के लिए जो तुरन्त कोई गाड़ी किराये नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, हमारी 108 एम्बुलेंस बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के, उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाती है। आज निजी कम्पनियां 2008 से, जब से यह योजना चालू हुई है हम निजी कम्पनियों को ठेका दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं सब विधायक महोदय, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आप अपनी आत्मा से सोच लेना। 108 एम्बुलेंस के कहीं पर टायर नहीं है, कहीं उनमें डीजल के पैसे नहीं है। हद तो तब हो गयी, जब इन्होंने एक नवाचार किया। एक कम्पनी है जीवीके, यह जीवीके भ्रष्ट कम्पनी है, इसने एक नवाचार किया है, माननीय सभापति महोदय। इन्होंने कहा कि हमें वह कम्पाउण्डर चाहिये, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। क्यों? क्योंकि दोनों काम वह एक व्यक्ति से कराना चाहते हैं, जबकि नियम यह है कि एक एम्बुलेंस के अन्दर पांच लोग रहने चाहिये। दो ईएमटी

(डा. राजकुमार शर्मा)

और दो पायलट और एक रिलीवर, ऐसे करके पांच का स्टाफ होना चाहिये। यह कहीं पर एक व्यक्ति से, कहीं पर दो व्यक्ति से। आपको पता है, कुछ ज़िलों में तो, नागौर जैसे ज़िले के सीएमएचओ ने तो इनका पेमेंट भी रोक दिया। अपने से यह पूरा पैसा उठाते हैं। पैसा भी कितना, 2021-22 में इन एम्बुलेंस के संचालन में करीब 199.68 करोड़ खर्च हुआ है। जिसमें एनएचएम से 88 करोड़ और राज्य सरकार से करीब 111 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की, पक्ष,विपक्ष, निर्दलीय, सबको मिलाकर, एक कमेटी बना दीजिये। एक बार हम लोग जाकर इनकी ऑडिट तो करें, हम एक बार जाकर जांच तो करें। किस कदर इन लोगों ने राज्य सरकार से, केन्द्र सरकार से, यह पैसा तो जीवीके वाले उठाते हैं, लेकिन वह पैसा आगे कितना दे रहे हैं, कितना स्टाफ रखे हुए हैं, स्टाफ के नाम पर यह कितना पैसा उठा रहे हैं, इसकी ऑडिट होनी चाहिये।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी, हो सकता है कुछ लोग यह समझें कि हमारा कोई व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं होता है। हम सब ट्रस्टी हैं। एक मांग भी करना चाहूंगा आप जब जवाब दें, माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो भी हो, इस राजस्थान पर एक भला कर दो। पूरे देश के अन्दर नई परम्परा शुरू कर दो कि एनआरएचएम से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वह ड्राइवर हो, चाई ईएमटी हो, चाहे आफिस का पूरा स्टाफ जो उनको सम्भालता है, उस योजना में जो लोग लगे हुए हैं, इनको परमानेंट करो। परमानेंट करने से क्या होता है, क्योंकि यह लाला की नौकरी करते हैं, उसकी मर्जी होती है उसको निकाल देता है, मर्जी हो उसको रख लेता है। इसमें नौकरी लगाने के अन्दर कोई मेरिट की आवश्यकता नहीं है। इनके पास यह बारगेनिंग करते हैं कि हम आठ हजार रुपये आपको देंगे, काम करना है क्या? दूसरा आदमी आ गया, वह सात हजार में तैयार है तो उसको काम दे देंगे। आप यह सोचिये कि सात हजार रुपये के अन्दर वह ड्राइवर उस एम्बुलेंस को चलायेगा 24 घंटे तो लास्ट के अन्दर वह क्या करेगा? आप खुद समझ जाइये, मैं कहना नहीं चाहता कि वे किस कदर से टायर उठा ले जाते हैं, उसमें से डीजल निकालकर ले जाते हैं तो एक बार आपका यह स्टाफ परमानेंट हो जायेगा 108 का तो वह व्यक्ति रुचि लेकर

(डा. राजकुमार शर्मा)

उसमें काम करेगा, उसकी जवाबदेही भी तय हो जायेगी कि हां, मैं परमानेंट नौकर हूं, मैं परमानेंट काम करता हूं इसलिए मेरी नौकरी जा सकती है। वे लोग तो वह हैं, उनको तो कभी भी हटा दो और कभी भी लगा लो इसलिए मेरी आपसे यह मांग है कि 108 एम्बुलेंस के अन्दर जितने भी यह staffing में जितने भी वर्ग हैं उन सबको परमानेंट करने की एक चिट्ठी केन्द्र सरकार को जानी चाहिए और केन्द्र सरकार से यह भी निवेदन करना चाहिए कि यह सब काम राज्यों को सौंप दे तो राज्यों को अपने-अपने स्तर के ऊपर यह एम्बुलेंस को चलाना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, कोविड, कोरोना, नाम सुनकर भी वह समय याद आता है जब हमने इतनी लाशों को देखा और इतने अपने लोगों को मरते हुए देखा। वह समय, कोरोना का नाम सुनते ही शरीर में एक अलग से डर और कम्पन सा महसूस होता है। हम लोगों ने पिछले दो वर्षों में कोविड का एक भयानक रूप देखा है, आम जनता के कष्ट को अनुभव किया है, उनकी वेदनाओं को समझा है। कुछ परिवारों ने अपने प्रियजन खोये हैं तो बहुत से परिवारों ने अपनी आजीविका खो दी। जो लोग गल्फ कंट्री में काम करते थे, जो लोग सूरत, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद, हैदराबाद यानी, यह जहां-जहां भी काम करते थे उनके सबके सब रोजगार छिन गये हैं। कुछ परिवारों ने अपनी खुशियां खो दीं।

राजस्थान में भी जिस प्रकार से कोरोना से मुकाबला करने के लिए नीति और व्यवस्था की गयी, वह राजस्थान की जनता के लिए वरदान साबित हुई है। जहां एम.पी. और यू.पी. जैसे राज्यों ने अपने ही राज्यों के लोगों को खुद के घरों में ही जाने से बोर्डर पर ही रोक दिया गया वहीं राजस्थान में दूसरे राज्यों से अपने राज्य में लाने के लिए नि:शुल्क बसें चलायी गयीं।

आप सब लोग भी उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी की वीडियो कांफ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे, आप विपक्ष के लोग भी जुड़े हुए थे। आप सबको यह पता है कि खूब लम्बी चर्चा चली। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर वह मंजर याद करते हुए बता रहा हूं तो इतनी तकलीफ होती है कि लाखों लोग सड़कों के ऊपर, माताएं-बहनें अपने बच्चों को सिर पर लेकर और हाथ के अन्दर सामान लेकर किस कदर देश की सड़कों के ऊपर लोग चल-चलकर भूखे प्यासे दम तोड़ रहे थे, उस समय राजस्थान की सरकार ने, जब हमने माननीय मुख्य

(डा. राजकुमार शर्मा)

मंत्रीजी से यह निवेदन किया तो उन्होंने हाथों-हाथ दरियादिली दिखाते हुए राजस्थान के अन्दर किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राज्य का हो, अगर वह पैदल चल रहा था, भूखे-प्यासे चल रहा था तो उस व्यक्ति तक गाड़ी पहुंचायी, और उस व्यक्ति तक राशन पहुंचाया और उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य देखिये कि उत्तर प्रदेश के अन्दर तो हमारी राजस्थान की पुलिस को, हमारे प्रशासन को उत्तरप्रदेश के प्रशासन से लड़ना पड़ा और लड़ाई इस बात की हुई कि हमने यहां तक छोड़ दिया, आपके उत्तर प्रदेश के यह लोग रहने वाले हैं, इनके आप आधार कार्ड देख लीजिए, इनको आप प्रवेश तो करा दीजिए, लेकिन संवेदनहीन यू.पी. की सरकार ने उनको यू.पी. में प्रवेश नहीं करने दिया। यह सब लोग इस बात को जानते हैं।

बड़े ताज्जुब की बात है कि प्रधान मंत्रीजी ने संसद के अन्दर कोविड का विस्तार, कोविड का जिस प्रकार से यह संक्रमण फैला उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दिया। भूल गये वे लोग जब पूरे राजस्थान की ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान की मीडिया यह कह रही थी कि Howdy Modi, नमस्ते ट्रम्प मत करवाओ। देश-विदेश से बहुत लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन आपने उस मोटेरा स्टेडियम को, आजकल शायद वह मोटेरा स्टेडियम नहीं रहा, वह मोदी स्टेडियम हो गया।

माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार देखा है कि जब किसी जिंदा व्यक्ति के नाम से कोई स्टेडियम का नाम पड़ा हो। हमने महापुरुषों का नाम सुना है, लेकिन जीते-जी अपने आपको कोई व्यक्ति महापुरुष घोषित कर दे, यह तो हमने पहली बार सुना है। उस स्टेडियम को खचाखच भर दिया गया और उसके बाद ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): यह मेडिकल से जुड़ा हुआ है क्या?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेडिकल से ही जुड़ा हुआ है कोविड पर ही तो बोल रहा हूं कि वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं करते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): भीड़ इकट्ठी नहीं करते। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता, देश के प्रधान मंत्रीजी को यह कोई हक नहीं बनता...., हमने उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया, हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि सड़कों पर जो दम तोड़ रहे थे उनको खाना खिलाया। सड़कों पर जो पैदल

(डा. राजकुमार शर्मा)

चलकर दम तोड़ रहे थे, उनको बसों में बैठाकर उनके राज्यों की सीमा तक छोड़ा। आपको जितना आरोप लगना है आप लगाइये, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकारों ने, जहां-जहां भी हमारी सरकारें थीं, हमने यह पूरी कोशिश की कि उन व्यक्तियों की हम लोग मदद करें।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): फिर भी आपको मंत्री तो नहीं बनाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? कृपया, शांत रहें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपसे दो-तीन मांग करना चाहूंगा।

एक तो नव-नियुक्त जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी परिवीक्षा काल की असमानता को दूर करें क्योंकि मेरे को याद है कि वर्ष 2008 से 2013 में हम लोगों ने एक साल एम.बी.बी.एस. के बराबर क्योंकि बी.ए.एम.एस. का कोर्स भी उतना ही होता है जितने वर्ष इनको लगते हैं तो जब एम.बी.बी.एस. में एक वर्ष का है इनका परिवीक्षा काल तो इनका दो वर्ष कर दिया गया है तो मेरा यह निवेदन है कि यह एक वर्ष ही वापस किया जाये ताकि उनको फायदा मिले क्योंकि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार खूब काम करती है और जो गौ-माता और आयुर्वेद का नाम लेकर, आप सबको पता है कि वे किस तरह की बात करते हैं लेकिन आयुर्वेद को हमें जिंदा रखना है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

ऐसे ही होम्योपैथिक विभाग से भेजे गये, होम्योपैथिक विभाग ने 656 पदों को सृजित करने का एक पत्र आपको लिखा है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि वर्षों से संविदा के ऊपर होम्योपैथिक चिकित्सक अपने यहां पर काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को नियमित करें। वह 571 की संख्या है और टोटल 656 पदों की विभाग ने अपनी आवश्यकता बतायी है तो मुझे यह उम्मीद है कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करेंगे।

तीसरी एक मांग और है कि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अन्दर पंचायत हैडक्वार्टर पर या जितनी भी दसवीं की स्कूलें थीं, उनको हमने बारहवीं तक किया है तो मैं यह मांग करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से, चिकित्सा मंत्रीजी, कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जो सब सेंटर है उसको पी.एच.सी. के अन्दर क्रमोन्नत कर दिया जाये ताकि लोगों को इलाज सुलभ हो सके। यह एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो जायेगा, प्रत्येक हैडक्वार्टर पर

(डा. राजकुमार शर्मा)

क्योंकि 2011 की जनसंख्या से हम लोग यह तुलना कर रहे हैं, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है तो अगर आज की तारीख में देखा जाए तो कितनी जनसंख्या के अन्दर बढ़ोतरी हो गयी है तो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर अगर पी.एच.सी. खोल दी जाये तो उसका बहुत फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बार सदन में और सदन के बाहर यानी, पूरे प्रदेश में एक बात की चर्चा रही इस बजट के बाद और वह भी नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया। नॉन इश्यू को इश्यू बनाया गया और वह नॉन इश्यू क्या था? मोबाइल फोन। चर्चा तो यह होनी चाहिए थी कि करोड़ों महिलाएं जो चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई हैं उनको हमारी सरकार ने मोबाइल दिये हैं और जैसे कि परम्परा है कि माननीय विधायकों को भी मोबाइल फोन दिये गये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मोबाइल फोन दिये गये और जब घोषणा कर रहे थे माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस समय विपक्ष के सब साथी मेज को थपथपा रहे थे। फिर पता नहीं कि शाम को क्या हुआ कि सब लोगों का एक मैसेज मीडिया के ऊपर आने लगा कि हम लोग मोबाइल लौटा रहे हैं और पूरे राजस्थान के अन्दर विधायकों की जिस प्रकार से, मैं यह कह रहा हूं कि एक खिल्ली उड़ायी गयी, लोगों में सोशल मीडिया के अन्दर विधायकों के खिलाफ एक मोबाइल को लेकर, एक 80 हजार रुपये का मोबाइल लेकिन माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मोबाइल वाली बात जरा अच्छी नहीं लगी क्या? माननीय सभापति महोदय, मेरे को तो अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह लो।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री संदीप शर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदय, कल विधान सभा में मेरे विधान सभा

(श्री खुशवीरसिंह)

क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना को लेकर उसकी पहचान को जाहिर किया गया है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि भविष्य में, माननीय सदस्यों ने कल जो बात कही है, उसकी पहचान को छुपाकर रखा जाए, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री संदीप शर्मा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे बात करने के दो घंटे के अन्दर पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज सहयोग करें। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 एवं 13 पर विचार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना की गयी है और उसमें सरकार का लोगों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर और साथ ही साथ जो चिकित्सकीय बजट है, उसकी प्राथमिकता को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन उस बजट की घोषणा के साथ-साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन और ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि जिस बजट की हम घोषणा कर रहे हैं, धरातल तक क्रियान्वयन हो जाए और नीचे तक के लोगों को उसका लाभ मिले। यह प्रयास बजट घोषणाओं से पूर्व तय कर लेना चाहिए। हम जैसा देखते आ रहे हैं कि तीन बार से बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुईं जो धरातल पर नजर आती नहीं।

सभापति महोदय, जिस तरह वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को झकझोर दिया और इस कोरोना महामारी से विश्व के लगभग 50 लाख

(श्री संदीप शर्मा)

लोग अपनी जान गंवा बैठे और आज भी बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड से पीड़ित होकर परेशान हैं। हमारे देश और प्रदेश में भी कोरोना महामारी का ताण्डव हुआ, जिसमें लाखों लोग संक्रमित हुए और बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई। परिवार के परिवार तबाह हो गये। बच्चे अनाथ हो गये। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सूझबूझ के साथ सार्थक प्रयासों के चलते, कुशल प्रबन्धन को एग्जीक्यूट करते हुए कोरोना महामारी को वर्तमान में नियंत्रण की ओर ले जाने का प्रयास केन्द्र सरकार ने किया है। इन सराहनीय प्रयासों की विश्व के सम्पूर्ण देशों ने सराहना की। हमारे प्रदेश में भी हमने कोरोना के इस काल को देखा है। उस पीड़ा को हमने महसूस किया है। उस समय भी केन्द्र की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में राजस्थान के प्रदेशवासियों को खुले दिल से जिसको जो आवश्यकता थी, जब चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता थी या आक्सीजन सिलेण्डर्स की आवश्यकता थी, अन्य आर्थिक अपेक्षायें थीं, दवाइयों की आवश्यकता थी, हमारे प्रदेश में उपलब्ध कराया।

सभापति महोदय, यही नहीं, वैक्सीनेशन नि:शुल्क करवाकर पूरे प्रदेशवासियों को, आज बिना मास्क के हम सब लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं कि एक संकट मोचक की भूमिका के रूप में हमारी केन्द्र सरकार के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने निभाया। अभी इस कोरोना महामारी का खतरा गया नहीं है। नये वेरिएंट के रूप में हमारे सिर पर खतरा मंडरा रहा है। सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि वह कंपा देने वाला दृश्य दूसरी पीक में देखा था, जिसमें हमारी सरकार और सब हाथ पर हाथ धर कर बैठ गये थे और अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं थी, दवाइयां नहीं थीं। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अभी भी दूसरा वेरिएंट कभी भी प्रभावी हो सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान में चिकित्सकीय तंत्र की वर्तमान में जो स्थिति है, उसको लेकर जरूर आप लोग अपनी पीठ थपथपा लेते हो लेकिन बड़ी आवश्यकता है कि आज इस चिकित्सकीय तंत्र को निचले स्तर तक सुदृढ़ चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से लेस करने की। प्रभावी कदम उठाने होंगे और सरकार को प्रयास करना होगा कि प्रदेश के आमजन को चिकित्सा में राहत भी मिले। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं दायित्व भी है। प्रदेश में आज मात्र 53 हजार से लेकर 54 हजार रजिस्टर्ड डाक्टर 9 करोड़ लोगों का इलाज कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी कहते हैं कि चिकित्सक और होने चाहिए परन्तु

(श्री संदीप शर्मा)

दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यह तय करके कि और मेडिकल कालेज खोले जाएं। मेडिकल कालेजेज में छात्रों की संख्या बढ़ायी जाए। छोटे मेडिकल कालेज में वर्तमान में सौ छात्र संख्या है। बड़े मेडिकल कालेज में 250 छात्र संख्या है। संख्या को हम बढ़ा सकें, राजस्थान में और चिकित्सक हम बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार को महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे।

सभापति महोदय, जिस तरीके से नीरोगी राजस्थान का संकल्प 2021-22 में सरकार ने लिया था, वह संकल्प बेबुनियाद निकला, सिर्फ कागजी संकल्प निकला। राजस्थान प्रबन्ध कोष की 100 करोड़ की घोषणा सिर्फ प्रचार-प्रसार और संगोष्ठियों में सिमट कर रह गई। प्रत्येक संभाग पर आपने वादा किया कि हैल्थ कालेजेज बनायेंगे। यह घोषणा भी आपकी कहीं फलीभूत होती हुई नजर नहीं आती।

कोरोना में जिन सरकारीकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी, उनके लिए आपने जो मुआवजे की घोषणा की थी, उसमें 120 शिक्षक और 118 विद्युत कर्मियों को आप कोरोना वॉरियर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लीनिक कुछ मोहल्लों में खुले, फिर बन्द हो गये। कोटा में जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई थी। अभी वहां एक ईंट भी नहीं लगी। कोई कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। पुरानी बजट घोषणाओं को तो आप साकार रूप नहीं दे पाये। 2022-23 में घोषणाओं का अम्बार लगा दिया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, एक दो मिनट तो और दे दो। बस समाप्त कर रहा हूं सर।

जिस तरीके से केन्द्रीय सरकार आज प्रदेश में जन्म देने वाली जन्मदात्री मां की हम स्थिति अगर देखें...

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

जिस तरीके से जन्मदात्री मां 3200 छोटे अस्पतालों में, मात्र 2 हजार अस्पतालों में प्रसव सुविधा है। सालाना 25 हजार नवजात शिशु मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं सिर्फ कुपोषण के कारण, उनकी और मां की प्रसव पूर्व जांच नहीं होने के कारण 25 हजार बच्चों की दर 30 परसेंट है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए अब आप। माननीय उप नेता महोदय, अपने लोगों से कहिए कि वह सहयोग करें। प्लीज विराजिए। विराजिए। प्लीज सहयोग करें। समय मत खराब करिये। अच्छा नहीं लगता। विराजिए आप। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए अब आप। सहयोग करिये। माननीय उप नेता महोदय, आपने व्यवस्था बनाने और सहयोग करने की बात की थी। प्लीज सहयोग करें। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: कोई टेबिल नहीं होगा। विराजिए अब आप। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि 'doctor is a half God, half pagan' लेकिन मैंने डाक्टर्स से भी निवेदन किया है, जैसा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था, उसका पालन करें। कोरोना पर बहुत लम्बी चर्चा हो गयी। बहुत बड़ा कोहराम था पूरे विश्व में। स्पेनिश फ्लू आया था सौ साल पहले। पूरे विश्व में 5 करोड़ लोगों की डैथ हुई थी। अभी जो कोविड़ आया, भयंकर कोहराम था विश्व में। यूरोप में करीब 54 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत में करीब साढ़े 4 लाख और राजस्थान में करीब साढ़े 8 हजार लोगों की मृत्यु हुई। बहुत बड़ा कोहराम था। जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, माननीय सभापति महोदय, बिलकुल वह दृश्य था जो विभाजन के समय 1947 में ट्रेनें लदी हुई थीं, लोग सड़कों पर जा रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मैनेजमेंट किया, वह अद्भुत था और आज की तारीख में राजस्थान के अन्दर करीब-करीब 95 परसेण्ट को वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लग गयी है और करीब 75 परसेंण्ट को सैकण्ड डोज लग गयी है। बूस्टर डोज भी लग रही है, 18 वर्ष से अधिक वालों को भी लग रही है, बहुत शानदार मैनेजमेंट है। ऑक्सीजन की भारी कमी थी, माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में बड़े-बड़े टैंकर्स भरकर जा रहे थे, लोग लूट रहे थे। मुख्य मंत्रीजी ने सबसे बड़ा काम किया, वह ऑक्सीजन मैनेजमेंट का राजस्थान में आज साढ़े 400 सी.एच.सी. पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए हैं। यह कोई बहुत छोटा काम नहीं है। एकएक, डेढ़-डेढ़ करोड़ से भी ऊपर का प्लांट है। खुद मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हैं और बाकी की जो पी.एच.सीज. थीं, वहां ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर भेजे गये। फ्री खाना

(श्री जितेन्द्र सिंह)

था, सब कुछ व्यवस्थाएं थीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का मैनेजमेंट था।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मॉडल का एप्रीसिएशन पूरी दुनिया में हुआ। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबन्धन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अपने मेडिकल कालेज खुल रहे हैं 33 जिलों में, और मेडिकल कालेज खुलेंगे तो उनके डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल अपग्रेड होंगे। आज सारा लोड एस.एम.एस. हास्पिटल के ऊपर है। पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, एशिया का सबसे बड़ा आउट-डोर है एस.एम.एस. हास्पिटल का, पर-डे 10 हजार पेशेंट वहां पर आते हैं। एट-ए-टाइम 50 हजार लोग उस कैम्पस में रहते हैं। आप कल्पना करिए, यह जो मेडिकल कालेजेज खुलेंगे, आपके सीकर में खुल गया, चूरू में खुल गया, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, तो मैं इस तरह से समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या के अन्दर जिला हैडक्वार्टर के वह हास्पिटल अपग्रेड होंगे और जिले के जो बाकी के बचे हुए हास्पिटल्स हैं, उससे एस.एम.एस. का लोड कम होगा और जो बाकी के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं, वह अपग्रेड होंगे और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत खतरनाक स्थिति है, हमारे 1700 पेशेंट पर एक डाक्टर है और गवर्नमेंट डाक्टर 9 हजार पर एक है, 2 हजार की और वेकेंसी है, 43 हजार टोटल डॉक्टर्स हैं, 34 हजार प्राइवेट सैक्टर में हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. ने नर्सेज का स्टैण्डर्ड रखा है एक हजार पर तीन। उसमें भारत के अन्दर 1.7 है, राजस्थान में 1.3 हैं हजार पर और मैं समझता हूं कि यह मेडिकल सैक्टर के अन्दर बहुत बड़ा काम हुआ है यह छोटा काम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे चिरंजीवी योजना में पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख किया, यह सिर्फ राजस्थान में है, अन्य राज्यों में नहीं है। इसमें और बाकी की बीमारी कवरेज हों, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलग से किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर को भी उससे जोड़ दिया, यह बहुत बड़ा काम किया है। चिरंजीवी योजना का लाभ हरेक तक पहुंचे, इसको हमको बहुत प्रमोट करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं एस.एम.एस. मेडिकल कालेज पर आता हूं। यह एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर का हास्पिटल है। यहां सबसे

(श्री जितेन्द्र सिंह)

पहले मैं न्यूरो साइंस सेंटर के बारे में बताना चाहूंगा। स्व डाक्टर अशोक पानगड़िया, पद्मश्री ने बहुत बड़ा काम किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं चिकित्सक हूं और जो लैप्सेज होते हैं हमारे नर्व सेंटर में, वह सबसे बड़ा होता है कि अगर किसी को लकवे का अटैक आ गया। लकवे का अटैक आ गया तो वहां गांव में वैद्य जी के पास रहता है और उसके बाद में जब कम्प्लीट पैरेलाइसिस हो जाता है, तब वह हास्पिटल में आता है। तब तक वह लेट हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ चार घंटे ऐसे होते हैं लकवे के अटैक में, जैसे हार्ट अटैक आता है, उस वक्त जो खून पतला करने की दवा है, वह अगर दे दी जाए तो उसकी जिन्दगी खराब नहीं हो। इसके अलावा चार दिन ऐसे बचते हैं उसके पास, उन चार दिनों में भी एस.एम.एस. हास्पिटल में पहुंच जाए तो यह अलग से व्यवस्था होती है, जैसे हार्ट को साफ करते हैं, जैसे ब्रेन को कैथेटर के माध्यम से एण्डोवेसकुलर न्यूरोइंटरवेंशन कहते हैं, वह उस थक्के को निकाल देते हैं तो उसकी जिन्दगी खराब नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, मैंने मेरी स्वयं की आंखों से देखा है, राजस्थान में लाखों लकवे के ऐसे पेशेंट हैं, जो बैड पर पड़े-पड़े अपनी जान देते हैं। यह बड़ा दर्दनाक सीन है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 250 करोड़ रुपया न्यूरो साइंस सेंटर के लिए दिया है। मैं मांग करूंगा हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय से, पद्मश्री डा. अशोक पानगड़िया ने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया है, इसलिए इस सेंटर का नाम उनके नाम से किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कार्डियोलाजी की बात करना चाहूंगा। माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन बैठे हैं, मैं 1993 में एम.एल.ए.था तीसरी बार और मदेरणा जी ने कहा था कि डाक्टर साहब बोलिए। उस समय हमारे देवराज हर्ष थे कर्नाटक के, उनकी सिस्टर के हार्ट अटैक हुआ और उनकी एस.एम.एस. की इमरजेंसी में डैथ हो गयी। माननीय Leader of the Opposition was a Health Minister, उन्होंने बहुत बेहतरीन, मैं बधाई दूंगा, उस समय की सबसे बेस्ट इमरजेंसी आपने बनायी। उसके बाद में जो डवलप हुआ, माननीय मैं उस समय हाउस में बोला था और उस समय आनरेबल लेट चीफ मिनिस्टर भैरोंसिंहजी शेखावत ने मेडिसिन से कार्डियोलोजी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

को अलग किया, हार्ट को अलग किया, उससे डिपार्टमेंट बना। न्यूरोलोजी को अलग किया, कार्डियो-न्यूरो सेंटर बना और आज जो Denton Cooley ने जितने ऑपरेशन नहीं किये होंगे, उससे ज्यादा आपरेशन एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर हो गये। यह बहुत बड़ा काम कार्डियोलोजी में हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अलग से घोषणा की है कार्डियक टावर बनाने की और उसके अन्दर मेरा आपसे आग्रह है कि एक ओ.सी.टी. मशीन, उससे एंजियोप्लास्टी करते हैं, यह कई बार फेल होती है। ओ.सी.टी. मशीन से जो ब्लाक्स होते हैं, उनका पता लग जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस वक्त स्वयं ने कहा था कि आई.सी.यू. इम्प्रूव होना चाहिए। आई.सी.यू. में, माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. में 25 बैड हैं, उसमें कम-से-कम 50 बैड होने चाहिए। 50 बैड उनके पास जनरल वार्ड में हैं, वह 150 बैड होने चाहिए। पूरे उत्तरी भारत और सारे-के-सारे वहां आ रहे हैं और आपके पास 50 बैड हैं, मैं समझता हूं कि इनको बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब किडनी के ऊपर आता हूं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे इण्डिया में 2 लाख वेटिंग में हैं। होती है 6 प्रतिशत, 1200 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट होती है। डोनर नहीं मिलते हैं। राजकुमार जी चले गये, वह ब्लड डोनेशन कैम्प लगाते हैं। हमारे लोगों में भय है। सिर्फ एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर पांच साल के अन्दर साढ़े चार सौ तो आपके लिव, जिन्होंने अपने खुद की जीवित रहते हुए किडनी दान किया है। मात्र 50 जो हमारे डोनर थे, जिनका मृत्यु के बाद शिफ्ट हुआ। यह नितान्त आवश्यक है। लोगों में जागरूकता स्कूल टाइम से लानी पड़ेगी वरना, माननीय सभापति महोदय, 30 प्रतिशत किडनी डोनर होते हैं अमेरिका में, 40 प्रतिशत स्पेन में, जो डैथ के बाद अपने अंगदान कर देते हैं। मैं समझता हूं कि इसको बहुत प्रोपोगेट करना चाहिए स्कूल टाइम से लेकर।

माननीय सभापति महोदय, गायनोकोलोजी में, स्त्री रोगों में यह 'उड़ान' बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। हमारे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कामन हैं। अब वह 'उडान' के माध्यम से सेनेटरी पैड्स दे रहे हैं, यह बहुत बड़ा काम है। इनीशियएली स्टेज पर जो हमारे सब-सेंटर्स हैं 14 हजार, उनको अपग्रेड करना चाहिए और जो भी महिला आती है

(श्री जितेन्द्र सिंह)

कि ब्रेस्ट में उसके छोटी-सी गांठ है, इमिजिएटली उसकी टाइमली सर्जरी हो जानी चाहिए, उनकी जान बच जाएगी। जो गायनी है, उनमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी चाहिए और उन सब-सेंटर्स को स्ट्रेन्थन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आता हूं एण्डोक्रोनोलोजी पर, डायबिटीज पर and seven percent of the population is diabetic. हमारे बहुत से साथी भी डायबिटिक हैं, मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा यह है कि अगर कोई बच्चा हमारे विकलांग पैदा हो गया तो वह अभिशाप है, पूरे समाज के लिए और घर के लिए। बहुत बड़ी परेशानी है। इसका पता समय रहते जेनेटिक डिस-आर्डर से पता लगाया जा सकता है। मां के पेट में बच्चा होता है तो पेरेसेंटिटी से एमेनिटिक फ्लूड की जांच कर सकते हैं और तीन महीने में अगर पता लग गया कि बच्चा विकलांग होगा या मेंटली रिटायर्ड होगा तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. हास्पिटल का एण्डोक्राइन लैब इण्डिया में सबसे बेस्ट लैब है। माननीय सभापति महोदय, भारत का सर्वश्रेष्ठ है और अभी उन्होंने, मैं अभी धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को, हमारे आफिसर्स को, कि जापान के माध्यम से कोलोबरेशन से सारा पैसा जापान दे रहा है। उसके अन्दर जो जेनेटिक डिसआर्डर्स हैं, उनके लिए अलग से जेनेटिक लैब बन रही है। डायबिटीज जेनेटिक डिसआर्डर है। स्टैम सैल्स को इंजेक्ट करके वह ठीक हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं अब रेस्पिरेटरी डिजीज पर आता हूं। कोरोना में सबसे ज्यादा सांस रोग हुआ। ब्रेन इफेक्टेड हुआ, मेंटल हो गये केसेज। आज राजस्थान के अन्दर एक भी डाक्टर डीएम नहीं है रेस्पिरेटरी में। मंत्री महोदय, आप भी सुनें। एक भी डीएम नहीं है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। आपने रेस्पिरेटरी मेडिसिन के जो एमडी हैं, उनको टीबी हास्पिटल में पटककर टीबी का डाक्टर बना रखा है। उनको एसएमएस हास्पिटल में लाइये। यह पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि मेडिसिन वाले करेंगे। उन जिम्मेदार लोगों को टीबी हास्पिटल में कर रखा है। आप रोटेशन में रखिये। जब आपने न्यूरोलोजी, कार्डियोलोजी बना दी, व्हाई नाट रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डाक्टर्स को, उनको एसएमएस में लाइये। वह डीएम की बात करते हैं। एक डीएम नहीं है राजस्थान के अन्दर। एक गुप्ता थे वह रिटायर हो गये। यह आपको अपग्रेड करना चाहिए।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

दूसरा, सिलिकोसिस में मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ दे रखा है। जो हमारे पोल्यूशन, कैंसर में हैं, वह सब हो रहा है।

सभापति महोदय, ईएनटी में अभी काक्लियर इंप्लांट के लिए पैसा दिया है। ब्लैक फंगस के आपरेशन किये हैं। मैं बधाई दूंगा डा. सतीश जैन को, he is a private doctor, but he is a leading doctor in the Country जिन्होंने ब्लैक फंगस को आपरेट किया और पूरे हिन्दुस्तान में नाम किया। He is an excellent personality.

सभापति महोदय, मैं अब आफ्थोमोलोजी, आंख के लिए आ रहा हूं। आंख शरीर के अन्दर सबसे कीमती चीज है। आंख के 7 हजार आपरेशन होते हैं। यह कैटरेक्ट तो बहुत कामन है। आप तो खुद जानते हैं लेकिन सबसे खतरनाक है डिटेचमेंट आफ रेटिना, डायबिटीज में रेटिना गिर गया और 24 घण्टे में आपरेट नहीं हुआ तो ब्लाइंड हो जायेगा। खुद मेरे परिवार का भतीजा ब्लाइंड हो गया डिटेचमेंट आफ रेटिना से। इसके सिर्फ गुजरात में डाक्टर थे। एसएमएस में भी इम्प्रूव करें। दूसरा, अंधा होने का रीजन है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में आई प्रेशर बढ़ जाता है। समय-समय पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, डेंटल के अन्दर डाक्टरों की बहुत बुरी पोजिशन है। सिर्फ 450 सरकारी नौकरी में हैं। सैकड़ों लोग बैठे हैं। हर सीएचसी पर एक डेंटल डाक्टर होना चाहिए ताकि जो वेटिंग में हैं, वो हो सकें। मंत्री महोदय, अन्य डाक्टरों की तो वांट्स निकालते हैं लेकिन डेंटल डाक्टर्स की बहुत बड़ी त्रासदी है। उन्होंने मुझे रिप्रजेंटेशन दिया है कि हमें भी सरकारी नौकरी में लो।

सभापति महोदय, कैंसर सबसे ज्यादा जान लेवा है। ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक शानदार कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया है। उसमें अब बहुत अपग्रेड हो रहा है। बहुत एफिशिएंसी हो रही है। कैंसर का बहुत महंगा इलाज है। एक-एक इंजेक्शन लाख-लाख रुपये का है। मैं मुख्य मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, मेंटल केसेज पूरे वर्ल्ड के अन्दर 10 परसेंट साइकाइट्री के केसेज हैं। उनके अन्दर यह अत्यन्त आवश्यक है कि डिप्रेशन में जाने के पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाये।

सभापति महोदय, बच्चों के लिए जेकेलोन इम्पोर्टेंट हास्पिटल है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इंस्टीट्यूट आफ रेयर डिजीज और जेनेटिक टेस्टिंग की फेसेलिटी इसमें डाली जाये। आरयूएचएस यहां का लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। आरयूएचएस हास्पिटल जो 400 बैड्स का था, उसको बढ़ाकर 1500 बैड्स का किया। मेडिकल कालेज में उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आरयूएचएस को जैसा होना चाहिए, उस स्थिति में यह नहीं है।

सभापति महोदय, लास्ट है, आप मेडिकल कालेजेज खोल रहे हो। डाक्टर्स की भर्ती कर रहे हो। सिर्फ 2 हजार डाक्टर्स कम हैं। आप 33 मेडिकल कालेज लाओगे। लेकिन बिना नर्सेज के हास्पिटल नहीं होता है। आपके प्राइवेट सेक्टर में 16-17 कालेज खुले हैं। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो प्राइवेट नर्सिंग कालेज वहां खोले जायें जिनके पास 100 बैड का हास्पिटल हो। अभी भी राजस्थान में बहुत सारे 100 बैड के हॉस्पिटल्स हैं। झुंझुनूं में हैं, सीकर में है, जिन्होंने नर्सिंग कालेज के लिए एप्लाई किया हुआ है। यह बिलकुल जिनाइन मैटर है। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि वहां उनकी सम्बद्धता की जाये। यह रिप्रजेंटेशन किया है नर्सेज ने और जो कोविड सहायक हैं उन्होंने।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): सभापति महोदय, अन्त में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, today is World Kidney Day. सबसे बड़ा क्राइसिस है, हमारे लोग भयभीत हैं। मैं राजस्थान पत्रिका को बधाई दूंगा कि उन्होंने लोगों में जागरूकता की। डाक्टर्स और लेडी डाक्टर्स की रैली निकाली लेकिन जागरूकता ऐसे नहीं होगी। मैं इस सदन में मेरे जीवन की सबसे बड़ी घोषणा करता हूं कि मेरी मृत्यु के उपरान्त मैं अपने हार्ट, किडनी और लीवर को कामन मैन के लिए डोनेट करता हूं। यह डाक्टर जितेन्द्र सिंह करेगा, तब आम लोगों की आंखें खुलेंगी। ऐसे नहीं खुलने वाली। जिस तरह से ब्लड बैंक का है।

सभापति महोदय, अन्त में मैं, हमारे मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि सर्वाधिक सैनिक नालपुर, खेतड़ी में हैं। इंडियन आर्मी का 10 परसेंट झुंझुनूं में है। उसके अन्दर पीएचसी खोली जाये और सीएचसी शिमला को।

सभापति महोदय, अन्त में, मेडिकल कालेज झुंझुनूं खोल रहे हैं। झुंझुनूं के हमारे बहुत सारे जन प्रतिनिधि विधायक बैठे हैं। जिस स्थान का चयन हुआ है, वह बिलकुल गली में ले जाकर कर दिया। वहां कोई मतलब नहीं है। हाईवे पर मेडिकल कालेज होना चाहिए। हास्पिटल होना चाहिए। मेरा

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आपसे आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करें। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल चौधरी।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 13 और 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने नीरोगी राजस्थान का सपना देखा है। जितनी भी योजनाएं हैं, उनको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री महोदय का मैं ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना तो कर दिया लेकिन जिस तरह से पहले भामाशाह कार्ड के जरिये गरीब आदमी कहीं भी जाता था, उसका सीधा इलाज हो जाता था। बाकी जन आधार कार्ड बनने के बाद में अभी भी वह गरीब आदमी भटकता रहता है। हर विधायक से पूछता है कि मेरा इलाज किस तरह से होगा। आप इसको सरल बनाने का काम करें। इसकी पूरी जानकारी लोगों को दें।

सभापति महोदय, समय की कमी है। 5-7 मिनट ही आपने बोलने का मौका दिया है तो मैं, मेरे क्षेत्र की विशेष मांगें रखता हूं। टोडारायसिंह उपखण्ड में ढाई से 3 लाख जनसंख्या है। वहां पर 50 बैड का हास्पिटल है। उसको 100 बैड का करें जिससे लोगों को सारी सुविधा मिल सके। वहां डॉक्टर्स की जो कमी है, उसकी भी पूर्ति करें।

इसके साथ-साथ मालपुरा जिससे 2 स्टेट हाई-वे निकलते हैं, सांगानेर से माण्डल और दूदू से छान। उस पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहां पर केवल 75 बैड का हास्पिटल है, उसको 150 बैड का किया जाये। उसको ट्रोमा हास्पिटल में क्रमोन्नत किया जाये, जिससे लोगों को समय पर इलाज मिल सके। जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनको अगर समय पर इजाज मिल जायेगा तो वह मृत्यु होने से बच जायेंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मालपुरा हास्पिटल में वार्ड की कमी है। वहां पर अभी केवल 50 लोगों को ही बैड पर रख सकते हैं। वहां पर डेली ओपीडी 700 से 800 है। मरीज वहां नीचे ही पड़े रहते हैं। वहां पर वार्ड बनाये जायें। जो डाक्टर्स क्वार्टर्स हैं, वह भी कम हैं। वह भी बनाये जायें।

दूसरा, मेरे मालपुरा हास्पिटल में सोनोग्राफी मशीन पड़ी हुई है, लेकिन

(श्री कन्हैया लाल)

वह कार्य नहीं कर रही है। उसको चालू किया जाये। जिससे लोगों का भला हो सके। इसके साथ-साथ टोडारायसिंह हास्पिटल में भी सोनोग्राफी मशीन दिलाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 108, 104 एम्बुलेंस सेवा है, वहां पर कोई भी मरीज को लेकर जाते हैं तो पहले मालपुरा से टोंक रैफर करते हैं। उसके बाद टोंक से जयपुर आते हैं। मालपुरा से जयपुर की दूरी 70-80 किलोमीटर है और टोंक की भी इतनी ही दूरी है। यह निर्देशित किया जाये कि वह मालपुरा से टोंक जायेगा और फिर वहां से जयपुर रैफर करते हैं, तब तक मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है, उनको सीधे जयपुर रैफर करने की कोशिश करें। इसके साथ 104, 108 पर नर्सिंग कर्मियों की भी कमी है। वह भी पूर्ति की जाये।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में काफी बड़े पंचायत हैडक्वार्टर संवारिया, पतराज, बासेड़ा हैं। इनके अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें। इसके साथ-साथ कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें।

अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि हमने 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो 2013 में कर दिये। वह आपने जाते हुए घोषणा की थी। आपने एक रुपये का भी बजट नहीं दिया था। उन सारे ही स्वास्थ्य केन्द्रों की 2013 से 2018 के बीच हमारी सरकार ने बिल्डिंग्स बनायी। उसके बाद में वह चालू हुए। घोषणा जो करें, उनको कंपलीट करें। केवल घोषणा करने से ही काम नहीं चलेगा। आप कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत कम घोषणाएं कीं। आपकी की हुई घोषणाओं को भी पूरा किया। इनमें से 300 तो हमने ही बनाये।

इसके साथ ही मेरे यहां काफी बड़े कस्बे लाम्बा हरिसिंह, पचेवर, टोरड़ी और लावा हैं। यहां पर भी कम से कम 200 से 300 ओपीडी हैं। इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें ताकि इनका भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जहां एएनएम के पद नहीं हैं वहां पद बढ़ाये जायें और जो भी पद खाली हैं वो सारे एएनएम के पद हैं जिनसे रोजाना आम जो महिलाएं होती हैं उनका एएनएम से काम पड़ता है बाकी 50 परसेंट से ज्यादा एएनएम के पद खाली हैं, यही स्थिति शायद पूरे राजस्थान की है। आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हमने जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य

(श्री कन्हैया लाल)

केन्द्र, सबको हमने पिछले कोविड के समय में तीन करोड़ से ज्यादा विधायक मद से पैसा दिया। फिर भी कई जगह पर, कहीं वार्डों की कमी है, कहीं कुछ मैटेरियल की कमी रह गयी है तो उसकी भी पूर्ति की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, टोंक में मेडिकल कालेज बन रहा है। मेडिकल कालेज के साथ-साथ जो पुराना हास्पिटल वहां पर 200 बैड का सैंक्शन किया है। अब वो हास्पिटल वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है और वहां पर मेडिकल कालेज में काफी बड़ी जगह है जो नया हास्पिटल बने तो वह नये मेडिकल कालेज में ही बनाया जाये तो वहां सारी सुविधाएं और सारे प्रोफेसर भी मिल जायेंगे, इस पर आप ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मालपुरा उप खण्ड के अन्दर से दोनों स्टेट हाईवे जाने की वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहां पर ब्लड बैंक की कमी है तो वहां पर ब्लड बैंक भी बनाया जाये। इससे लोगों को समय पर ब्लड मिलेगा तो उनका समुचित इलाज हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फ्री वैक्सीन 130 करोड़ लोगों को लगायी, कोविड की वजह से लोगों की काफी जानें तो गयीं, लेकिन वैक्सीन से बहुत सारी जानें बची भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, बातें तो बहुत सारी कहनी थीं, लेकिन समय की कमी है, मैं आप लोगों से कहना चहता हूं कि आप सब मिलकर ऐसे प्रधान मंत्री को धन्यवाद दें, जिन्होंने पहली स्वदेशी वैक्सीन, आजादी के बाद पहली बार निश्चित टाइम पीरियड में बनाकर हमारी पूरी जनता को लगायी तो वह जनता भी उनको धन्यवाद दे रही है, आप अपने मुंह से भी उनको धन्यवाद दें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 - चिकित्सा सेवाओं पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

आज के अख़बार में एक बहुत शानदार खबर थी कि जैसे कई निजी चिकित्सालय बिल बहुत भारी कर देते थे, व्यक्ति मर जाता था, डैथ हो जाती

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

थी तो उसकी बॉडी को रोक लेते थे कि पहले पेमेंट करें और फिर बॉडी ले जाने देंगे। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है, जो व्यवस्था की गयी है और जो आदेश निकाले गये हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, बिल की पेंडेंसी के लिए किसी प्रकार की बॉडी को कोई नहीं रोक सकता। यह एक बहुत संवेदनशील विषय है और बहुत जोरदार बात है और इस बात को हम सभी को, पक्ष और विपक्ष को एप्रिशिएट करना चाहिए कि कितना अच्छा निर्णय हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय के माध्यम से लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, 2022-23 का बजट हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य की जनता को दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी कम है और विशेषकर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम बात करें तो बहुत कुछ दे दिया और इतना दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को चाहे पंक्ति में खड़ा अन्तिम व्यक्ति हो, उसको भी इस बात की चिन्ता नहीं करनी कि अगर वह बीमार हो जायेगा या उसके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जायेगा तो वह कहां से दवा-दारू की व्यवस्था करेगा, कहां से चिकित्सक की व्यवस्था करेगा, पैसों की व्यवस्था करेगा, कहां से चिकित्सा करायेगा, सब कुछ दे दिया गया है। चिकित्सा के पेमेंट के अभाव में किसी भी गरीब आदमी को बायें-दायें नहीं देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि आज ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा लेकिन चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपये तक के ट्रीटमेंट की सुविधा देना बहुत बड़ी बात है सोचा ही नहीं जा सकता था। यहां बैठे हम विधायक खुद नहीं सोच सकते थे, कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय 5 लाख से 10 लाख रुपये की व्यवस्था चिकित्सा के लिए हर व्यक्ति के लिए, इस राज्य के हर नागरिक के लिए कर देंगे और उसके साथ-साथ 5 लाख रुपये का बीमा भी देंगे। अब तो सारे ही हास्पिटल जो गवर्नमेंट सैक्टर में हैं, चाहे वो सब सेंटर्स हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, जिला हास्पिटल हैं, राज्य स्तर का एसएमएस हास्पिटल है, वहां पर किसी भी प्रकार का इलाज बिलकुल कैशलेस इलाज है इसके लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री महोदय बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

एक्सीलेंट कोविड मैनेजमेंट की बात मैं अगर कहूं तो रिपीटेशन होगा

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

लेकिन जो अच्छी बात है उसको बार-बार कहना भी अच्छा लगता है। जो एक्सीलेंट मैनेजमेंट कोविड का राजस्थान की सरकार द्वारा किया गया, हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा किया गया, उस समय उनकी जो टीम थी उसके द्वारा किया गया, हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे चिकित्सा कर्मी हैं उनके द्वारा किया गया, वह बहुत सराहनीय बात है और जो व्यवस्था थी राजस्थान का जो कोविड मैनेजमेंट था इससे देश के अन्य राज्यों ने भी प्रेरणा ली और देश के प्रधान मंत्री ने भी प्रेरणा ली और विश्व स्तर पर इस बात की सराहना की गयी। इस बात से हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम उस राज्य के निवासी हैं और हम उस मुख्य मंत्री के साथ हैं जिस मुख्य मंत्री ने इतना शानदार काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय का अभाव है इसलिए अपने विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं। हर विधान सभा क्षेत्र का सुधार होगा तभी राज्य का सम्पूर्ण विकास होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने मांग की थी कि लाम्बा व गोठड़ा, डुलानिया में और साथ ही खुडानिया में भी पीएचसी खोली जाये क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी नहीं हैं। इसलिए लाम्बा के लिए मैंने नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी प्रकार लाम्बा गोठड़ा, डुलानिया के लिए भी 131 में मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषकर लाम्बा के लिए लाम्बा में देखिये कुछ गांव हैं, दिलावरपुर, नालवा, कुरेशीनगर, काजियों की ढाणी, गोविन्दपुरा, जाखड़ा, बुडानिया, खूमनसर खुर्द, नारनोद, मालीगांव, बाघपुरा, इन गांवों में चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है इसलिए मैंने निवेदन किया था कि लाम्बा में एक पीएचसी अवश्य खोली जाये। मैं इतना यहां कमिट करता हूं कि वहां की व्यवस्था, भवन की व्यवस्था, हम वहां करवा देंगे, राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, भवन की व्यवस्था वहां पर है और करवा देंगे, और कमरे बनवाने हों तो मैं भामाशाहों से बनवा दूंगा, लेकिन लाम्बा में पीएचसी खोली जानी चाहिए ताकि इतने सारे गांवों को उचित चिकित्सा व्यवस्था मिल जाये। इसी प्रकार से लाम्बा गोठड़ा में भी भवन का जो भामाशाह तैयार है, भवन बना पड़ा है, पीएचसी के लिए भवन बनाया है, एक महिला है, उसके जवान बेटे की डैथ हो गयी, उसकी स्मृति में उन्होंने भवन

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

बना दिया और कमिट कर दिया है, दे दिया है भवन, पंचायत को हैंडओवर कर दिया है कि आप इसमें पीएचसी खुलवा दो, हम यह भवन उसके लिए दे देंगे। अभी जो चल रहा है उसमें सब सेंटर चल रहा है, उस सब सेंटर को कृपया अपग्रेड कर दीजिये ताकि लाम्बा गोठड़ा के साथ-साथ अलीपुर, खुडिया, बदनगढ़, गोठड़ी, इस्माइलपुर, श्योपुरा, भोमपुरा, शेखपुरा, हरिपुरा, अजीतपुरा और कुड़ियों की ढाणी, इतने गांवों को उचित चिकित्सा सुविधा मिलेगी। डुलानिया वो गांव है, जो बिलकुल हरियाणा की सीमा पर है, वहां भी पीएचसी नहीं है, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं और खुडानिया गांव के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जो तीन-चार पीएचसी हैं, ये आप करायें ताकि लोगों को वहां पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदय, पिलानी रोड पर 2400 स्क्वायर मीटर का एक नि:शुल्क भूखण्ड मैंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को अभी कुछ महीने पहले दिलवाया है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए उसका म्यूटेशन भी हो चुका है, जमाबन्दी में नाम आ चुका है, मेन रोड पर है, पिलानी की सीएचसी अब तो उप जिला हास्पिटल है, उस उप जिला हास्पिटल की अगर आप भीड़ देख लें तो इतनी भीड़ होती है कि व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर चलता है, इसलिए ये 2400 स्क्वायर मीटर का भूखण्ड मैंने नि:शुल्क राज्य सरकार को, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिलाया है। उसमें मातृ और शिशु अस्पताल के लिए मैंने नेशनल हैल्थ मिशन को प्रस्ताव भिजवाया है, एनआरएचएम के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। मैं निवेदन करता हूं कि आपके प्रभाव का उपयोग करते हुए एनआरएचएम के माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से वहां पर मातृ और शिशु अस्पताल बनवाया जाये। इसके प्रस्ताव आलरेडी जा चुके हैं। यहां के मिशन डाइरेक्टर को भी मैंने अपने व्यक्तिगत पत्र से निवेदन कर दिया है और प्रोजेक्ट भी इसका बनकर जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेरे सीएचसी में 80 लाख रुपये महिलाओं के लिए डिलिवरी सेंटर के माडर्नाइजेशन के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा हुआ है वो भी एनआरएचएम के माध्यम से भेजा हुआ है उसमें भी मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं। आपके सकारात्मक हस्तक्षेप से ये दोनों परियोजनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र को मिल सकती हैं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय सभापति महोदय, अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि सभी एमएलए को नर्सिंग कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के माध्यम से काम कर रहे हों, टेम्परेरी रूप से या संविदा के माध्यम से, चाहे स्टेट स्पोंसर्ड स्कीम के माध्यम से काम कर रहे हों, चाहे और किसी स्कीम के माध्यम से काम कर रहे हों, वो इधर-उधर घूमते रहते हैं, और उनके लिए आपने कमेटी भी बना दी है, मैं निवेदन करता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण और उनके भविष्य के कैरियर के लिए जो कमेटी राज्य सरकार ने बनायी है उसकी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र आये।

(समय: 15.00 बजे)

उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ये जो नर्सिंग कर्मचारी विभिन्न स्रोतों से अपनी समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये। अन्त में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो बातें मैंने आज अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए कही हैं उन पर आप अवश्य गौर करें और ये सब चीजें मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिलाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank You very much.

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 - चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि हमारा तीर्थराज पुष्कर एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का स्थान है और यहां पर स्थानीय लोगों के साथ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देश और विदेश से सैलानी आते हैं। वहां का जो अस्पताल है, वह बड़ी जर्जर अवस्था में है।

पुष्कर नगरपालिका ने खेरखड़ी रोड पर नये अस्पताल के लिए भूमि का आबण्टन भी कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों की आपसी लड़ाई, गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई में उस नये भवन के निर्माण का चीरहरण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे तीर्थराज पुष्कर की आवश्यकता को देखते हुए नवीन भवन के निर्माण की आज ही घोषणा करें।

इसके साथ ही, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़, खरखेड़ी, पुष्कर, भदूल, ऊंटड़ा, घगवाणा, गुढा, मदारपुरा, हटूण्डी, सराणा, नान्द, कड़ेल आदि

(श्री सुरेश सिंह रावत)

सामुदायिक अस्पतालों के साथ ही उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक उपकरणों सहित भवनों की मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे काफी उप-स्वास्थ्य केन्द्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। हमारे उप-खण्ड पुष्कर, उप-खण्ड रूपनगढ़ के अस्पतालों में ब्लड बैंक यूनिट की स्थापना के साथ ही क्रिटिकल एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

हमारे प्रत्येक गांव में जनता क्लिनिक खोलने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। इसके साथ ही पुष्कर में चूंकि यात्री भार काफी है, आस-पास के लोग भी आते हैं, नागौर जिला भी सटा हुआ है, इसलिए हमारे पुष्कर अस्पताल को क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल में तब्दील करने की कृपा करें। इसके साथ ही, अभी हमारे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्राम पंचायतें खुली हैं, उनमें हमारे उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुले हैं। वे भी खुलें। साथ ही, हमारे यहां मायापुर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है, जो कि वर्षों से बिना उप-स्वास्थ्य केन्द्र के ही चल रहा है, वहां भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलें।

हमारे तीर्थराज पुष्कर का अन्तरराष्ट्रीय मेला प्रतिवर्ष भरता है और वहां लाखों लोग आते हैं। इसके साथ ही, प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। हमारे अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। वहां भी जायरीनों के साथ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। वहां भी बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अजमेर में एक विश्वस्तरीय मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने का भी आप विचार करें तो यह भी हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा।

अभी विधान सभा में जब मैं आया था तो नर्सिंगकर्मी और कम्प्यूटर आपरेटर धरना दे रहे थे। मेरी आपसे मांग है कि आप धरना स्थल पर जाकर लोगों की समस्या सुनें और आज ही उन्हें नियमित करने की घोषणा करें। इसके साथ ही, कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर संविदाकर्मियों ने लोगों को सुविधा देने का काम किया, लेकिन आज तक उन्हें वेतन नहीं दिया गया। मेरी आपसे मांग है कि उन्हें वेतन दिया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई, जो कि एक महत्त्वपूर्ण विषय है, उस पर आज चर्चा हो रही है। नीरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के

(श्री मेवाराम जैन)

लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने जिस तरह से आम गरीब, जिन्हें इलाज के लिए पैसे नहीं मिलते थे, अपने गहने, जमीन बेचकर अपना इलाज करवाते थे, उनकी यह पीड़ा देखते हुए उन्होंने नि:शुल्क दवा योजना की शुरुआत की, वह पूरे भारत में सराही गयी, लोकप्रिय हुई।

यही नहीं, इससे आगे बढ़कर माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी योजना अभी पांच लाख से दस लाख की। उसमें कैसी भी बीमारी हो, उसका मुफ्त इलाज करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे राजस्थान में लागू किया। इसके साथ-साथ एक्सीडेंट का क्लेम भी पांच लाख तक का इसमें जोड़ा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, जिस तरह से शानदार बजट राजस्थान की जनता के लिए दे रहे हैं, जिस तरह से कर्मचारियों को तोहफा दिया है और जिस तरह से प्रत्येक वर्ग के लिए इतना शानदार बजट दिया है, अब हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को चिन्ता हो गयी कि ये खर्च कैसे करेंगे। आप इसकी चिन्ता छोड़ें। बजट अभी पास भी नहीं हुआ, उससे पहले डायरेक्शंस चले गये कि तुरन्त आप सैंक्शन होने वाले स्कूलों की लिस्ट बनाएं।

मेरे यहां बाड़मेर में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल, जिसकी घोषणा इस बजट में हुई, उसके लिए चार विभाग और 24 पोस्टें भी सैंक्शन हो गयीं। इस प्रकार आप चिन्ता नहीं करें। बजट के लिए आप पैसों की जो चिन्ता कर रहे हैं, बिलकुल निश्चिन्त रहें और आप आज जो रिजल्ट आये, इसके लिए थोड़े उत्साहित हो रहे हैं, आप चिन्ता ही मत करें, आप 2023 में देखेंगे कि राजस्थान में क्या आपका हश्र होगा। आप इस बात की चिन्ता करनी छोड़ दें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से, चाहे पूरे राजस्थान में पीएचसी, सीएचसी, सब-सेंटर और एडिशनल जिला अस्पताल, इस तरह से जो मेरे से पूर्व राजकुमार जी ने पूरी डिटेल्स बतायी थीं कि राजस्थान में किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में शानदार काम किया, कोई ढाणी, कोई पंचायत, कोई ऐसी जगह नहीं जहां सब-सेंटर या पीएचसी और सीएचसी खोलने में कोई कोताही बरती गयी हो।

माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 200 करोड़ का सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल सैंक्शन किया, उसका शिलान्यास कर दिया और उसका कार्य भी शुरू कर दिया, इसलिए मैं माननीय

(श्री मेवाराम जैन)

मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा। चिकित्सा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले सात जिलों में और उसके बाद अब अठारह जिलों में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की और कार्य भी शुरू करवा दिया। मेरे बाड़मेर में नर्सिंग महाविद्यालय स्वीकृत कराया और चालू भी कराया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे चिकित्सा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेडिकल क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोरोना काल में शानदार काम किया है। कोई भूखा नहीं सोये और जिस तरह से शानदार व्यवस्था अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर की गयी है, राजस्थान सारे भारतवर्ष में एक मॉडल बना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रात और दिन एक करके लोगों की जिस प्रकार से जान बचायी है, मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार काम इस कार्यकाल में किया।

माननीय सभापति महोदय, आप ज्यादा समय नहीं देंगे, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेडिकल के अन्दर, चाहे हमारे बाड़मेर की मैं बात करूं, बाड़मेर अस्पताल में साठ आईसीयू वार्ड, बीस-बीस के तीन वार्ड, जिनकी कोस्ट चार-चार करोड़ है, उनकी सैंक्शन ही नहीं की, बल्कि वे बन चुके हैं। एक हमारे भामाशाह पृथ्वी सिंह जी कोल्हू ने दो करोड़ का बीस बैड का आईसीयू वार्ड बनाकर दिया है, उसका भी लोकार्पण हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाड़मेर में खूब काम हुआ और कुछ पीएचसी के लिए कह रहा था कि बाड़मेर में एक जसाई और मूण्डों की ढाणी दो पीएचसी की माननीय मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दो पीएचसी स्वीकृत करें। मेरे यहां एक सीएचसी स्वीकृत की, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा की है और हमारे जो पंचायत मुख्यालय हैं उनके अन्दर जहां पर सब-सेंटर नहीं हैं, वहां खोलने की मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे यहां 13 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पंचायत मुख्यालय पर सब-सेंटर नहीं है तो वहां सब-सेंटर खोलें। पीएचसी और सीएचसी के लिए तो सभी विधायक

(श्री मेवाराम जैन)

भी मांग कर रहे हैं, इन सबको आप दें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक उप स्वास्थ्य केन्द्र सुजाननगर में जरूरी है। इसके अलावा ईश्वरपुरा और तिरसिंगड़ी में सब-सेंटर खोलने के लिए मैं कहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि परिसीमन 2007-08 में हुआ, पर मेडिकल के ब्लाक उसी हिसाब से बने हुए हैं जबकि दूसरे सभी विभागों में पानी का, बिजली का, पीडब्ल्यूडी, सारे विभाग हैं उनमें अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रवाइज ब्लाक हुए हैं। मैं मेरा उदाहरण देना चाहता हूं कि बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के जो पुराने परिसीमन के हिसाब से बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में चार ब्लाक सीएमएचओ में बंटे हुए हैं इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको एक ही ब्लाक बनाओ पर जो टुकड़े हैं कि सिणधरी में आठ पंचायतें डाली हुई हैं बायतू में अलग डाली हुई हैं शिव में अलग डाली हुई हैं।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो ब्लाक हैं इनमें कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक मिनट ही। इसलिए आप ये ब्लाक अच्छी तरह बना दें ताकि लोगों को इसमें सुविधा हो सकेगी। हमारे यहां साजटा, दूदाबेरी और बालेरा पीएचसी के लिए भवन सैंक्शन करना है। पीएचसी भी कभी की सैंक्शन हो चुकी थी, इसलिए इसके लिए आप भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान करावें। एनआरएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं उन सबकी मांगें हैं....

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): हमने घोषणा भी कर रखी है तो आप उनको जल्दी से जल्दी नियमित करने का प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 13 एवं 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार ने 2021-22 के बजट भाषण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक आदर्श सीएचसी, मॉडल सीएचसी बनाने की घोषणा की थी। उसमें सभी विधायकों से प्रस्ताव भी मांग लिए, पर आज हम देखते हैं कि उस आदर्श सीएचसी के नाम से सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन इनमें जो सुविधा होनी चाहिए, उस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हुई हैं। विधायकों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा में राशि खर्च करनी चाहिए थी, वह आदर्श मॉडल चिकित्सालय में खर्च की, लेकिन सरकार के द्वारा उसके ऊपर गाइडलाइन तैयार कर उसमें जो डिजिटल एक्स-रे है, डाक्टरों के पद हैं, इस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए, ये सुविधाएं अभी तक मॉडल सीएचसी में नहीं की गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में सीएचसी परतापुर के अन्दर कुल 12 डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं जिनमें मात्र चार डाक्टर ही कार्यरत हैं। गायनाकोलोजिस्ट एवं सर्जन वहां नहीं है। सीएचसी में आईसीयू वार्ड, डिजिटल एक्स-रे आदि की सुविधा नहीं है।

(समय : 15.14 बजे)

(जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

65 बैडेड जो अस्पताल है उसको 100 बैडेड होना चाहिए था, पर उसको भी घोषणा में लेकर उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी घोषित करने की घोषणा कर दी, परन्तु आदर्श सीएचसी में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं की है। इस सम्बन्ध में सरकार हर विभाग के नाम से 2019 और 2022 में बजट में घोषणा का ही काम किया है, परन्तु हमारे टीएसपी क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में किसी प्रकार की विशेष कोई सुविधा हमें उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्या के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सगवाड़िया व रोहिड़ा में पीएचसी खोलना आवश्यक है। कुमजी का पारड़ा, लालपुरा, भरकरिया पाड़ा कुवालिया, टोरी बड़ी गुसाई का पाड़ा, चिकनपाड़ा, मण्डेलापाड़ा, मालपुर भीमसौर, नथैली भाणतलाई, झालो का गड़ा, तली सरेड़ी छोटी, चिम्बोली, पिछोड़ा बड़ा, नवापादर नगरपालिका क्षेत्र के गांवों में सब सेंटर खोलना आवश्यक था परन्तु सरकार ने टीएसपी क्षेत्र को

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

नजरअंदाज किया है। टीएसपी क्षेत्र को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष दर्जा मिलना चाहिए था, परन्तु सरकार ने टीएसपी क्षेत्र के बारे में किसी तरह से कोई विशेष पैकेज बनाकर घोषणा नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कौड़ी का काम नहीं किया गया। टीएसपी क्षेत्र में आआजना पीएचसी को सीएचसी और बोरी पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करना आवश्यक था पर हमारे निवेदन करने के उपरान्त भी उसको क्रमोन्नत नहीं किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अवलपुरा, झड़स, बिलोदा, मण्डेलापाड़ा और ऐसे कई गांव हैं जहां पर सब सेंटर और पीएचसी, सीएचसी के भवन नहीं बने हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में परतापुर, तलवाड़ा, अरथूना, गढ़ी, पालोदा, जोलाना, सरेड़ी बड़ी सीएचसी हैं उनमें डाक्टरों के काफी पद रिक्त हैं और मात्र एक-एक डाक्टर इन सीएचसी में कार्यरत है जिसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सभी सीएचसी में आप पद भरने का आदेश फरमायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि केन्द्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के नाम से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी राज्यों में, भारत के किसी भी कोने में जाकर एक गरीब आदमी इलाज कराता था, लेकिन राज्य सरकार ने और आपने इस चिरंजीवी योजना में इस आयुष्मान भारत योजना को सम्मिलित करने से हमारा जो बीपीएल, गरीब परिवार का आदमी है उस आदमी का अन्य राज्यों में इलाज सम्भव नहीं होता है। हमारा टीएसपी क्षेत्र गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है और वहां का हर आदमी गुजरात में अपनी मजदूरी के लिए जाता है, पर उसको चिरंजीवी योजना का लाभ लेने के लिए, इलाज कराने के लिए वापस यहां पर आना पड़ता है। वह यहां नहीं आ सकता है तो अन्य राज्यों में भी इसकी सुविधा होनी चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र के अन्दर मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि अभी होम्योपैथिक के जो डाक्टर हैं, वे 571 डाक्टर 14 फरवरी से धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उनको स्थायी करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में ही समाप्त करें।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): जी साहब। होम्योपैथिक, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बाद में द्वितीय सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है और उसमें सभी मंत्री और सभी विधायकों ने अनुशंषा की है, परन्तु सरकार इसके ऊपर विचार नहीं कर रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो 571 डाक्टर हैं इनको नियमित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि टीएसपी क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानें हर गांव और मोहल्ले में चलायी जा रही हैं और वहां पर नकली शराब बेची जाती है। गरीब आदमी इस नकली शराब को लेकर पी जाता है। इससे कई मौतें भी होती हैं, कई बीमारियां भी फैलती हैं। आदिवासी क्षेत्र में हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और वहां पर आदिवासी महुआ फूल से देशी हथकढ़ शराब बनाता है। पुलिस उनको पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा भी बनाती है, उनको परेशान भी करती है जबकि वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो तस्करी का काम करते हैं और नकली इंग्लिश दारू बेचते हैं तथा गांवों में दुकान चलाते हैं। इनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हमारे महुआ फूल से शराब बनाते हैं इन लोगों को, गरीब आदिवासी जो अपने पीने के लिए शराब बनाते हैं उनको परेशान नहीं किया जाये और जो नकली शराब की दुकानें चलायी जा रही हैं, वहां पर बेचा जा रहा है उनको रोका जाये, इनके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्यवाही की जाये।

हमारा जो क्षेत्र है वह सम्पूर्ण गुजरात बोर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र से बहुत बड़ी शराब की तस्करी होती है जिसमें पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत भी होती है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र से जो तस्करी हो रही है उसको रोका जाये तथा तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सर, सर्वप्रथम मैं राज्य सरकार को, जो यह कल्याणकारी बजट लायी है और चिकित्सा सेवाओं में जो प्रावधान किये हैं, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने ऐसे प्रावधान किये हैं जो आम आदमी के जीवन को गांव-गांव तक सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, चिरंजीवी योजना में सीमा 5 लाख से 10 लाख बढ़ायी है। मैं मानता हूं कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, सी.एम. साहब की सोच को दर्शाता है कि जनता के प्रति, गरीब के प्रति उनका कितना सेवा भाव है। इसका लाभ हर आदमी को मिलेगा। इसके साथ ही आपने आउटडोर फैसिलिटी को भी नि:शुल्क किया है। सर, यह भी बहुत ही अच्छा कदम है। मैं मानता हूं लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा।

सर, राजस्थान सरकार ने बजट में हर विभाग को दिया है, पर खासतौर से आज चूंकि मांग संख्या-26 चिकित्सा सेवाओं के बारे में विचार-विमर्श है। सरकार की मंशा दर्शाती है कि सरकार गरीब के प्रति कितनी संवेदनशील है और सरकार ने कितने सकारात्मक कदम उठाये हैं।

सर, इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कस्बा देवली है, देवली चार जिलों की सीमा पर है। बून्दी की हिण्डौली लगती है, भीलवाड़ा का जहाजपुर लगता है, अजमेर का सरवाड़ और केकड़ी लगते हैं और टोंक जिला है। यह बड़ा कस्बा है, पी.जी., कालेज, तहसील, एसडीएम हैड क्वार्टर है, पर यहां का अस्पताल सिर्फ 75 बैड का है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसके महत्व देखते हुए, इस क्षेत्र से लोगों के जुड़ाव को देखते हुए इसे आप जिला अस्पताल का दर्जा दें। इसको क्रमोन्नत करें और जिला अस्पताल का दर्जा दें।

इसके साथ ही दो नेशनल हाईवे मेरे यहां से गुजरते हैं। एक तो टोंक से सवाई माधोपुर और एक एनएच जयपुर से कोटा। सर, कोटा वाले एनएच पर तो एक बहुत बड़ा कस्बा दूनी पड़ता है और जब टोंक से सवाई माधोपुर जाते हैं तो वहां उनियारा पड़ता है। सर, दोनों नेशनल हाईवेज पर तेज गति से गाड़ियां चलती हैं, अनेक एक्सीडेंट्स होते हैं। दोनों अस्पतालों में, दूनी के अस्पताल में भी ट्रोमा फैसिलिटी नहीं है और उनियारा में भी नहीं है। मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि इन रोड्स के महत्व के देखते हुए आप दोनों उनियारा अस्पताल में और दूनी अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर खोलने की व्यवस्था करावें।

इसके साथ ही इस बजट में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो सीएचसी दी गयी है, न एक भी पीएचसी दी गयी है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप जवाब दें तो मेरे दो इम्पोर्टेन्ट कस्बे हैं, जिनमें पीएचसी नहीं

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

है। एक तो उनियारा पंचायत समिति में पलाई कस्बा है। यह पंचायत मुख्यालय भी है, बड़ा कस्बा है, व्यापारिक केन्द्र है। इसमें पीएचसी नहीं है। इसमें आप पीएचसी स्वीकृत करने की कृपा करें।

इसी तरह उनियारा पंचायत समिति में एक बड़ा कस्बा देवली है। वह देवली नहीं, जो सब-डिवीजन मुख्यालय है, देवली एक कस्बा है उनियारा पंचायत समिति में, वहां भी आप एक पीएचसी देने की कृपा करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीन नयी पंचायतें बनी हैं। तीन पंचायत मुख्यालय हैं, वहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं हैं। जैसे- बिलोता, देवीखेड़ा, श्योराजपुरा, ये तीनों ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और इन पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि यहां भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें।

सर, कुछ बहुत बड़ेबड़े गांव हैं, जिनमें एक भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, न पीएचसी है, न यूपीएचसी है, जिनमें खासतौर से बिलासपुर पंचायत के देवपुरा, फूलेता पंचायत के गांव बालापुरा में, उखलाना पंचायत के आसलगांव में, बनेठा पंचायत के मीनों की झोपड़ी में, हैदरीपुरा पंचायत के लसाडिया गांव में, संथली के गांधीग्राम में, यह गांधीग्राम ग्रामधानी गांव है, पूरी बैरवा बस्ती है, 100 परसेंट दलितों की बस्ती है, यह सरकार ने बसायी है।

सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संवेदनशीलता दिखाते हुए इस गांव में एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करें। बन्थली में विजगगढ़, रामसागर के जालिमगंज, गांवडी पंचायत के ककोडिया, बीजवाड़ का मानपुरा, घाड पंचायत के डाटून्दा, देवड़ावास पंचायत के आमली गांव में अभी तक उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं। मैं आशा करता हूं कि इन सबमें आप उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे।

सर, इसी तरह से आपने जहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये, उनकी स्थिति भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सर, उप-स्वास्थ्य केन्द्र बालापुरा, चतरपुरा, समरावता, जिरोता, आमली, छान, पायगा, रोशनपुरा, मंडालिया, रमजानगंज, बिंजारी, गुमानपुरा, नयागांव, रघुनाथपुरा कलां, स्यावता, गांवडी, बोरडा, धांधोली, बालागढ़ और गोविन्दपुरा, सरकारी आंकड़ों में यहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है, पर एक में भी भवन नहीं है और जहां भवन नहीं

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

हैं, वहां कहां चल रहा होगा? कौन किराया देता है या नहीं देता है? मुझे पता नहीं है पर सरकारी भवन नहीं है तो सोच सकते हैं, वहां क्या दशा होगी मेडिकल फैसिलिटीज की? अभी तक ये भवन रहित हैं।

सर, वहीं एक घाड उप-स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां आपने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। सर, चार साल हो गये हैं, भवन का कार्य चालू नहीं हुआ, लोगों को नुकसान हो रहा है। सर, बड़े कस्बे हैं, कृपया जो भी जिला अधिकारी हैं, उनसे बात करें। सर, इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है तो भवन निर्माण शुरू होना चाहिए, चार साल से अटका हुआ है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, इसी तरह से कुछ भवन तो 30-30 साल पुराने हैं, वहां कुछ भी नहीं है, जर्जर अवस्था में हैं, कभी भी गिर जायेंगे, उस इलाके में बारिश भी ज्यादा होती है। जो भी आपके पुराने भवन हैं, आप सीएमएचओ से रिपोर्ट ले लें, उनकी रिपेयर करवायें, ताकि आवश्यकतानुसार उनकी रिपेयर की जा सके।

सर, अब मैं आखिरी चीज बता रहा हूं। मान लें, मेरे यहां हास्पिटल भी है और भवन भी है। मैं स्टाफ की पोजिशन बताता हूं। उनियारा उपखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेठा में 2 विशेषज्ञ के पद हैं और दोनों ही रिक्त हैं। देवली उपखण्ड में स्वास्थ्य केन्द्रों पर 8 विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं, 8 के 8 ही रिक्त हैं, एक भी नहीं है। सर, तो विशेषज्ञ का मतलब क्या है? भवन है, डाक्टर नहीं है। डाक्टर है, भवन नहीं है। सर, इसका मिलकर समाधान करना है।

इसी प्रकार उनियारा उपखण्ड के चिकित्सालयों में महिला स्वास्थ्य दर्शिका के कुल 14 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से मात्र 2 ही कार्यरत हैं। अब उनके अभाव में क्या काम हो रहा होगा? ये ओ-ओ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके टाइम भी ऐसी ही थी। यह राजस्थान की जनता की आवाज है। सर, इसे पार्टी की नजर से नहीं देखें।

इसी प्रकार से मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में प्रयोगशाला सहायकों के 14 पद स्वीकृत हैं और 14 के 14 ही रिक्त हैं। कृपया, इस पर ध्यान दें। एक पीएचसी धुआ कलां में चिकित्साधिकारी के अलावा समस्त पद रिक्त हैं। जब स्टाफ ही नहीं है तो क्या इलाज हो रहा होगा? महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनको देखें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, लास्ट में 108 एम्बुलेंस की जो सुविधा है, जिला मुख्यालय टोंक है, उपखण्ड मुख्यालय उनियारा और देवली है। वहां का कोई भी पेशेंट आता है तो उसको उनियारा से रैफर किया जयपुर एसएमएस के लिए या देवली से रैफर किया जयपुर के लिए, पर वह सीधा जयपुर नहीं आता, पहले टोंक जिला मुख्यालय पर जाता है। वहां से फिर उनसे परमिशन लेता है तो उसमें बहुत कीमती समय गुजर जाता है और काफी बार आदमी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि जब सीधा रैफर किया है, डाक्टर जहां भी रैफर करें, सीधे उस अस्पताल में जाएं वाया टोंक नहीं जाएं। सर, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहला सुख निरोगी काया। चिकित्सा विभाग का सीधा सम्बन्ध राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा प्रगति प्रतिवेदनों में बड़े बखान हमेशा किये जाते रहे हैं, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बावजूद सम्पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कोरोनाकाल में हमने देखा, किस प्रकार लोग डर के साये में जी रहे थे। जिस चिकित्सा विभाग को सेवा का माध्यम माना गया और सेवा करने वाले डाक्टरों को भी भगवान की संज्ञा दी गयी, किस तरह से इस विभाग के कुछ लोगों ने जीवनदायिनी ऑक्सीजन व रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खेल खेला, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह कुछ डाक्टरों ने अपने परिचितों को रेमडेसिविर पिछले दरवाजे से लाकर दिये, किस तरह गरीब के हक की ऑक्सीजन को दो नम्बर से बेचा गया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सबसे बड़े हास्पिटल की, अभी माननीय सदस्यों ने चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपने-अपने हिसाब से इसका विश्लेषण किया, लेकिन मैं दैनिक भास्कर के 8 मार्च के अख़बार की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, जिसमें मुख्य पृष्ठ पर छपा है कि वार्ड बाय खुले में कर रहे हैं महिलाओं की ईसीजी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आरयूएचएस के वार्ड में वार्ड

(श्री नारायण बेनीवाल)

बाय खुले में महिलाओं की ईसीजी कर रहे हैं जिसे देख कर शर्म के मारे महिलाएं अपनी आंखें मूंद लेती हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेंगी यह आने वाला समय ही बतायेगा। एसएमएस सहित शहर के 60 सरकारी बड़े अस्पतालों में 223 टेक्निशियन के पदों में से सिर्फ 28 ही भरे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, यहां पर 77,282 बैड पर 1840 टेक्निशियन की आवश्यकता है। और तो और माननीय सीएम साहब के क्षेत्र में भी और माननीय मंत्री जी के खुद के क्षेत्र में भी कई बार अखबारों के माध्यम से पता चला कि टेक्निशियन के काफी पद रिक्त पड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, खींवसर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, वहां पर उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा सेन्टर की मांग लम्बे समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही है क्योंकि खींवसर के लोगों को इलाज के लिए नागौर या जोधपुर जाना पड़ता है। अधिकतर देखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में जोधपुर जाते-जाते वह मरीज वहां दम तोड़ देता है तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि खींवसर के अन्दर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना की जाये।

माननीय सभापति महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात जरूर कही थी कि बजट के अन्दर आप लोग अच्छे सुझाव भी देना। सुझाव हमने दिये, लेकिन कोई हमारे सुझावों को माने तब। हमने तो यह सुझाव दिया कि किस तरह बजट की इतनी बड़ी घोषणाएं सीएम साहब ने जो कीं वह धरातल पर आयेंगी, किस तरह हमारा खजाना वापस भरा जायेगा। अगर मुख्य मंत्री जी अपने इर्द-गिर्द पच्चीस मीटर के अन्दर यदि जीरो टोलरेंस की नीति ला दें तो निश्चित रूप से राजस्थान सोने की चिड़िया वापस हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर के 46 गांवों में आज तक उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। 27 स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन ही नहीं हैं जबकि जमीन उपलब्ध है। 32 भवन जर्जर अवस्था में पड़े हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि खींवसर उपखण्ड मुख्यालय पर बीसीएमओ के कार्यालय की घोषणा भी आप करें। इसके अलावा शंखवास और खजुवाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, जनाणा के अन्दर पीएचसी की घोषणा के

(श्री नारायण बेनीवाल)

लिए माननीय चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्र शीलगांव, करनू, खरनाल, बैराथल और रिया श्यामदास को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग भी मैं करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सभी सीएचसी और पीएचसी पर सोनोग्राफी मशीन और प्रशिक्षित डाक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि जब यह कोरोना का काल आया तब यह बात सबसे प्रमुखता से उठी कि जब तक चिकित्सा सेवाओं का हम डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक ऐसी वायरस जनित बीमारियां जो आ रही हैं, जो छुआछूत की बीमारियां आ रही हैं उनसे हम निजात नहीं दिला सकते। हर व्यक्ति क्योंकि वहां छोटे केन्द्रों पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से शहर के बड़े अस्पतालों में आता है तो गम्भीर और सामान्य रोगों के अन्दर भी जो अलग-अलग विभाजन डाक्टर नहीं कर पाते हैं और बहुत बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि हनुमान सागर, रावों की ढाणी, बेरावास, बेनीवालों की ढाणी, बासनी खली, लूनावास, गोल्यासनी, काल्यास, कुड़कुड़ा कलां और गुलासर में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की मैं चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा। आज चिकित्सा सुविधाओं की धुरी समझी जाने वाली 108 एम्बुलेंस कई जगह धूल फांक रही है। मैं आपसे मांग करूंगा कि इन 108 के जो कर्मचारी हैं उनको भी आप नियमित करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कि 175 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है खींवसर क्षेत्र, उसके अन्दर कुचेरा और खींवसर में ही 108 और शंखवास और पाचोडी में 104 एंबुलेंस, कुल 4 ही एंबुलेंस मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। मैंने विधायक कोष से जो एंबुलेंस दी है उसके अन्दर सरकार के पास ड्राइवर नहीं है। आरएमआरएस के पास पैसा नहीं है तो इन सब चीजों पर हम गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तो सिर्फ बजट की घोषणाओं से जनता का भला होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी प्राचीन जो चिकित्सा विधियां हैं चाहे वह होम्योपेथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, उनके अन्दर भी हमें कोई न कोई अच्छी कार्ययोजना बनाकर क्योंकि कोरोना काल के अन्दर हमने देखा कि पूरे विश्व ने भारत की प्राचीन विधियों की बहुत बड़ी तारीफ की थी तो प्राचीन विधियों की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के खाली पड़े पदों की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के बीसीएमओ मूंडवा के अधीन आने वाले गांवों में कुल 203 जो पद हैं उनमें से 74 पद रिक्त पड़े हैं। सीएचसी पांचला में डाक्टर्स के स्वीकृत पद 5 में से 3 पद रिक्त हैं व सीएचसी पाचोडी में स्वीकृत 5 में से पूरे के पूरे 5 पद ही रिक्त हैं। इनमें से अधिकतर प्रतिनियुक्ति पर बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक मांग मैं और करूंगा चिकित्सा मंत्री जी से कि नागौर सहित तमाम जिलों में मेडिकल कालेज बन रहे हैं, इन कालेजों के निर्माण में गुणवत्ता निरीक्षण हेतु एक समिति बनायी जाये जिसमें वहां के स्थानीय सांसद और सभी विधायकों को उसमें शामिल करें क्योंकि कुछ साल पहले ही नागौर के जेएलएन में जो एमसीएच विंग बनी, वह गुणवत्ता के अभाव में उसका उद्घाटन होने से पहले ही उसकी छत का प्लास्तर गिर गया और आज भी वह जर्जर अवस्था में है। नागौर के जेएलएन अस्पताल में कार्डियोलोजिस्ट व न्यूरोलोजिस्ट के पद स्वीकृत करें। जेएलएन नागौर में वरिष्ठ विशेषज्ञ के 6 में से 5 पद और कनिष्ठ विशेषज्ञ के 22 में 8 पद रिक्त पड़े हैं। कुचेरा व खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र सहायक के पद सृजित करें और प्रदेश स्तर पर भर्ती निकालकर नेत्र सहायकों को नियुक्ति दें ताकि आये दिन बढ़ते हुए नेत्र रोगियों को समय पर इसका इलाज मिल सके।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में आयुर्वेदिक डाक्टर इंटर्नशिप के दौरान मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं उनकी मांग को भी सरकार पूरी करे। एएनएम भर्ती 2013, संविदाकर्मी एएनएम, हैल्थ मिशन के कर्मचारी, एनएचएम, एनआरएचएम, आशा सुपरवाइजर, कोविड सहायक को भी नियमित करने तथा मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मुद्दा है एक बायोमेडिकल वेस्ट का इस पर सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है। होस्पिटल का कचरा कहीं न कहीं सड़कों पर और शहर की बाहर की कालोनियों में लाकर डाल देते हैं और उससे बहुत बड़ा संक्रमण तेजी से फैलता है तो बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था के ऊपर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान

(श्री नारायण बेनीवाल)

आकर्षित करूंगा जिसके अन्दर बहुत बड़ी अनियमितता हो रही है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया, लेकिन हम सबकी यह परम जिम्मेदारी है कि जिस तरह से पहले भामाशाह कार्ड की जो दुर्गति हुई कहीं इसकी भी दुर्गति नहीं हो जाये, इसके लिए हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिये कि समाज के अन्तिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज कैसे मिले।

माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट मेरी डिमाण्ड है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि इनाणा गांव नागौर जिले का बहुत बड़ा गांव है। इसके अन्दर बहुत सुन्दर चिकित्सालय बनाया और बहुत सुन्दर रहने के लिए क्वार्टर बनाये, लेकिन आज तक भी 26 लाख रुपये उन क्वार्टर्स पर खर्च करने के बाद कोई भी चिकित्साकर्मी उसके अन्दर नहीं रह रहा है और पिछले 4-5 साल में 15 लाख रुपये का एचआरए वहां के डाक्टर्स ने और मेडिकल के कर्मचारियों ने उठाया है। यही स्थिति कमोबेश सब जगह है तो जब आप किसी पीएचसी और सीएचसी में उनके रहने के लिए क्वार्टर बनाते हैं तो यह भी आप पाबंद करें कि चिकित्सा का स्टाफ वहीं रहे ताकि सरकार का एचआरए भी बचे और गांव का गरीब व्यक्ति यदि रात को या ऐसी इमरजेंसी में आये तो उसको समय पर उसका इलाज मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द जी मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की निम्न समस्याओं की मांग रखता हूं। जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय सीएचसी जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है। नेशनल हाईवे 148डी सड़क निकल रही है। जहाजपुर शहर कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है। आये दिन दुर्घटना होती रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय से सौ किलोमीटर दूरी होने के कारण वहां ट्रोमा सेन्टर और ब्लड बैंक की स्थापना की जाये। इसी तरह कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय में ब्लड बैंक और ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति दिलायी जाये। मेरे जहाजपुर में पीएचसी और सीएचसी में डाक्टर्स के अधिकतर पद खाली हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर्स के रिक्त पद भरे जायें। जहाजपुर में सीएचसी खजूरी में दो वर्ष से सीएचसी क्रमोन्नत की गयी।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीएचसी के लिए भूमि आबंटित कर दी गयी है, भवन निर्माण के लिए आप बजट आबंटन करें। हमारे सवाईपुर कस्बा बड़ा कस्बा है, नेशनल हाईवे सड़क है, लाडपुरा से कोटा हाईवे निकल रहा है। वहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। इसी तरह लुहारीकलां जहां हमारे क्षेत्र के दस हजार से अधिक सैनिक देश की राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं वहां लुहारीकलां जो अभी पीपीपी मोड पर दे रखा है उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 15 से 20 किलोमीटर तक कोई पास में सीएचसी नहीं है, अत: मैं पीएचसी को लुहारीकलां सीएचसी क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। साथ ही शकरगढ़ कस्बा जो उपखण्ड मुख्यालय से और जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालय जो बड़े आबादी के गांव हैं दूरदराज क्षेत्र हैं बीस से तीस किलोमीटर दूर है। वहां सब सेन्टर है, ग्राम पंचायत बरोदा तलोदा, धोड़, धुंआला, अमरगढ़, बीरदोरी, टिकड़, बड़ला पंचायत में, अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना अच्छी लागू की है, लेकिन चिरंजीवी में जो अस्पताल शामिल नहीं है। उनमें अज्ञानता के कारण गरीबों ने इलाज करा लिया उनको भुगतान नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र का एक सुरेश धाकड़ है, जिसकी मौत हो गयी उसके साढ़े चार लाख रुपये बकाया है, उसको भुगतान नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गरीब लोगों को चिह्नित करके सरकार मुख्यमंत्री सहायता से या अन्य योजना से उनको लाभ दिलाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक सब सेंटर जर्जर अवस्था में हैं। जिले में डीएमएफटी में 800 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं सरकार बजट नहीं दे रही है तो जिला कलेक्टर को निर्देश दें कि हमारी विधान सभा के जर्जर भवनों को डीएमएफटी में सरकार से स्वीकृति जारी करावें।

सभापति महोदय, मैं सरकार का एक नमूना बताना चाहता हूं, मेरे

(श्री गोपी चन्द मीणा)

विधान सभा क्षेत्र में कोटडी ब्लाक सीएमएचओ कोरोना के समय पर भी मुख्यालय पर नहीं रहकर अनुपस्थित रहा। वहां के जन प्रतिनिधियों ने पंचायत समिति और जिला परिषद् की बैठक में निन्दा प्रस्ताव पास किया, उसके बाद भी वह उपस्थित नहीं रहा। मैंने माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया। मैंने भामाशाह के द्वारा 30 लाख की 108 एम्बुलेंस डोनेट कराई। उस एम्बुलेंस का भी उसने दुरुपयोग किया और दुरुपयोग इतना किया कि उसने कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर एम्बुलेंस को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा है। माननीय मंत्री महोदय ने उसकी जांच भी कराई, जांच भी यहां आई। इतना ही नहीं, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ने नेताओं के इशारे पर हमारे इस सदन के सम्माननीय सदस्यों के बारे में भी अश्लील भाषा का प्रयोग किया, जो जिला मुख्यालय के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसकी सीडी मैंने माननीय मंत्री महोदय के यहां डायरेक्टर साहब के भिजवा रखी है। उस सीडी को भी मुख्यालय में खराब कर दिया गया। मैंने दुबारा सीडी भिजवायी है। ऐसे दोषी कर्मियों के खिलाफ मैं कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): इतना ही नहीं, भीलवाड़ा जिले को सरकार ने नंबर एक के लिए अवार्ड दिया है। वहां फर्जी आंकड़े पेश किये हैं। माननीय मोदी जी के टीकाकरण योजना में मरे हुए व्यक्ति का टीकाकरण बताया गया है। यह भी 4 मार्च के समाचार पत्रों में प्रकाशित है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मैं कार्यवाही की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान जी पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 13 और 26 पर अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरी बात मांग संख्या 13 से शुरू करूंगा। प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की गारंटी राशि कम करने की मैं मांग करता हूं। मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि सरकार एक तरफ तो नीरोगी काया की बात करे और दूसरी तरफ गारंटी इतनी बढ़ाई हुई है कि इतनी दारू नहीं पिलाओगे तो आपकी गारंटी पूरी नहीं होगी। हम खुद दारू पिला-पिलाकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। उनके फेफड़े और गुर्दे खराब कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं नीरोगी

(श्री बलवान पूनियां)

काया पर बहुत सारा खर्चा करेंगे। मुख्य मंत्री जी ने गुरुशरण छाबड़ा जी की याद में एक टीम बनाई। वह टीम बिहार में जांच करने के लिए गई कि शराब पर पाबंदी कैसे लगाई जाय। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमने यह ठेकेदारों पर थोप रखी है कि इतनी तो बेचनी ही पड़ेगी, इससे बदमाशी फैलती है। एक ठेके वाले से गारंटी पूरी नहीं होती तो वह दूसरे ठेके के क्षेत्र में जाकर बेचता है तो उन लोगों में लट्ठ चलते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नोहर में मुकदमा दर्ज हुआ है। थोड़े दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में झगड़ा होने की पोजिशन आ गई थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की गंभीरता से जांच करें। दूसरा, बहुत ही सख्ताई से लागू करें कि ड्राई डे पर गेट के नीचे से, फाटक के नीचे से दारू बेचने का धंधा नहीं चले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान की जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी आबकारी पालिसी बनायेंगे।

मैं मांग संख्या-26 पर अपनी बात रखते हुए कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीएचसी अभी ट्रोमा सेंटर का इंतजार कर रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीएचसी पर एक करोड़ रुपये हमने एमएलए लैड से दिये हैं जिससे नये भवन की शुरुआत हम करेंगे। वहां डाक्टर तो ठीक है, नर्सिंग स्टाफ भी खूब है, लेकिन मरीजों को देखते हुए, 750 से लेकर 1100 तक की ओपीडी पर डे है। हमने सरकारी हास्पिटल की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया है। सब पीएचसी, सीएचसी को ठीक करने का प्रयास किया है। आपसे मेरा निवेदन है कि वहां आप ट्रोमा सेंटर उपलब्ध कराएं।

दूसरा, हर सीएचसी पर एक दंत चिकित्सक की आप व्यवस्था करें। सभापति महोदय, दंत के रोगियों को इसके लिए हरियाणा के हास्पिटलों में जाना पड़ता है, जिससे वहां लूट बढ़ती है। जब प्रशासन गांव के संग कैम्प था, वहां विकलांग लोग आ गये कि हमारा विकलांग प्रमाण पत्र बनाओ। पता नहीं यह विशेषज्ञ कैसे करते हैं, हम तो उन चीजों को जानते नहीं, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है एक आदमी एक साइड से पूरा पैरेलाइज है, वह कोई काम ही नहीं कर सकता, यह कह रहे हैं कि यह 40 परसेंट नहीं है। कितना है, 35 है। क्या फार्मूला है? हम तो यह जानते हैं कि जिस आदमी को सुनाई नहीं देता, जिसको दिखता नहीं, जिसके हाथ ठीक नहीं है, जिसका शरीर ठीक नहीं है, हम उसको विकलांग समझते हैं। उसका ब्याह भी नहीं होता। फिर विकलांग

(श्री बलवान पूनियां)

प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा निवेदन है कि चिकित्सा मंत्री महोदय, दिव्यांगों को, विकलांगों के लिए इतना हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं होना चाहिये कि 39 हो गया लेकिन 40 नहीं करेंगे। इसमें आप थोड़ी लिबर्टी बरतें।

अपन को फिजियोथैरेपिस्ट की अनदेखी नहीं करनी चाहिये। हम जितना दवाइयों पर खर्चा कर रहे हैं, आज कमर के रोग महिलाओं में ज्यादा बढ़ रहे हैं, पुरुषों में ज्यादा बढ़ रहे हैं। कमर के रोग वाले को चार व्यायाम से फिजियोथैरेपिस्ट ठीक कर सकता है। खुद मुख्य मंत्री जी के घर में फिजियोथैरेपिस्ट जाता है। मेरे पास आये कि साहब, हम मंत्री महोदय से तो निवेदन कर आएं, आप फिजियोथैरेपिस्ट की मांग कीजिए। फिजियोथैरेपिस्ट हर हास्पिटल में हो जिससे लोगों को दवाई के बजाय चार एक्सरसाइज बताकर ठीक किया जा सके। आरजीएचएस में होम्योपैथी को भी जोड़ा जाये, यह हमारा निवेदन है।

जो लड़के कम्प्यूटर पर काम करते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना में कोरोना में इतना बढ़िया काम किया। सारी की सारी जांच पर डे 3000-4000 सैम्पल उठाने का काम, कम्प्यूटर आपरेटर पूरी-पूरी रात लगे रहते। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में और जांच योजना में, दोनों में जो कम्प्यूटर आपरेटर लगे हुए हैं, उनका मानदेय सिर्फ 7000 है। सभापति महोदय, आज 7000 रुपये में कोई आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता और वो भी सुबह 9 बजे से बैठकर रात के 10-11 बजे तक काम करे। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उनका न्यूनतम मानदेय कम से कम 18,000 हो। ऐसे लोग जो मुख्य मंत्री जी के पहले कार्यकाल के समय के लगे हुए हैं, उन लोगों को स्थायी क्यों नहीं करते? जो प्लेसमेंट ऐजेंसियों के मार्फत लगे हुए हैं, आरएमआरएस से नहीं हैं, उनका तो इतना भारी शोषण है कि अगर आप मानदेय नहीं बढ़ायेंगे तो उनके खून के आंसू तो कोई पोंछ ही नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाय। होम्योपैथी चिकित्सकों को नियमित करने की भी हम मांग करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में जो अभी थोड़े दिन पहले प्रयोगशाला सहायक भर्ती हुई थी और उसकी अंतिम सूची भी जारी कर दी, उनकी नियुक्ति के आदेश करें। अभी आपने उनकी 1200 सीटों की सूची जारी की है जबकि कुल 1587 पद हैं। बचे हुए पदों की वेटिंग लिस्ट भी आप जारी करें। हमारी मांग है कि एमएनडीवाई में सुचारु रूप से संचालन हेतु फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती की जाय।

(श्री बलवान पूनियां)

108 और 104 की हालत यह है, सारे साथी बार-बार बोल रहे हैं, 108 एम्बुलेंस वालों की दादागीरी भी है। बीकानेर में मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो-चार लड़के 108 एम्बुलेंस में लगे हुए थे। वह यह कह रहे हैं कि हमें यह कह रहे हैं कि यहां लगना है तो लगो नहीं तो आपको दूसरी जगह भेजेंगे। एक-दो बीकानेर के साथी से मैंने सिफारिश कराई कि इन लड़कों को परेशान कर रहे हैं। लास्ट में उन लड़कों को घर आना पड़ा। गंगानगर में भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 108 और 104 एम्बुलेंस को भी ढंग से ठीक करें।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मेरे को तो तीन मिनट ही हुए हैं, सात मिनट ही बोलूंगा। सात मिनट के बाद मैं बैठ जाऊंगा, मैंने तो बात ही सात मिनट की लिखी है।

सभापति महोदय, जैसे कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हास्पिटल में ऑक्सीजन की कंटीन्यू जरूरत होती है। ऑक्सीजन प्लांटों के रख रखाव के लिए अभी तक आईटीआई किये हुए लड़कों को कहीं भर्ती नहीं किया। 450 ऑक्सीजन प्लांट तो लगे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लग गया। सबसे पहले बजट जारी हुआ और संगरिया और भादरा में लग गये, लेकिन उनके लिए एक भी पद जनरेट नहीं हुआ और एक भी आदमी उनकी सार-संभाल के लिए नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं, वह चीज हम सब लोगों ने फेस की है।

सभापति महोदय, मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि चिकित्सा विभाग के सफाई कर्मी से लेकर डाक्टर तक, एसएमएस से लेकर पीएचसी, सीएचसी तक बहुत मजबूती के साथ वह लोग आज भी मास्क लगाये हुए काम कर रहे हैं। आज हम सब लोगों ने मास्क छोड़ दिया, लेकिन इस सदन में मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि नर्सेज आज भी टीकाकरण के अभियान को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। इसलिए उनका नियमितीकरण करें। 2013 की नर्सिंग भर्ती की करीब डेढ़ हजार पेंडिंग बची हैं, मंत्री महोदय, उनकी भर्ती को कम्प्लीट करो, बाकी तो और दूसरे पदों पर एडजस्ट हो गईं।

2013 की मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की निकाली हुई भर्ती में वे छोरियां ओवरएज हो गयीं, बार-बार मांग कर रही हैं। मंत्री महोदय ने भी मांग की थी, मैं भी मांग करता हूं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की कुछ मांगें रखना चाहता हूं। जो भादरा का निनाड़ गांव जो कि बड़ा गांव है, उसमें

(श्री बलवान पूनियां)

पीएचसी खोली जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र छेरड़ा को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। अजीतपुरा बड़ा है, उसके चारों तरफ बड़ी-बड़ी सात पंचायतें हैं, उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। भरवाणा और डूंगराना बड़े गांव हैं, वहां पर भी पीएचसी खोली जाये। यह मेरा निवेदन है। मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से आयुर्वेद में और अच्छे से काम हो सकता है, आयुर्वेद के पद खाली हैं, उन पदों को भी भरा जाये और उनके वेतनमान को लेकर जो विसंगतियां हैं, उसे दूर किया जाये। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सम्बन्धित आडियोलाजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलोजी के डाक्टर की नियुक्ति भी की जाये।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सीएचसी में सफाई को लेकर एक दिक्कत है। हालांकि, आज के दिनों में एसएमएस में बहुत जोरदार सफाई है। मैं एसएमएस में एडमिट रहा हूं। सब ठीक होने के बाद जब डाक्टर ने कहा कि आप अब ठीक हो तो मैं पूरा राउण्ड करके आया। अच्छी सफाई है, लेकिन नीचे सीएचसी तक और तेजी से आगे बढ़े, ऐसा मेरा मंत्री जी निवेदन है।

मेरी लास्ट बात है, शुद्ध के लिए युद्ध। चिकित्सा विभाग अगर उस पर ढंग से काम नहीं करेगा तो हम सिर्फ दवाई से लोगों को ठीक नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी ही दवाएं गटकवा दें, नि:शुल्क दें, पर्ची नि:शुल्क कर दें, इलाज नि:शुल्क कर दें, लेकिन आज जो दूध में मिलावट चल रही है। मंत्री महोदय, मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय अपनी बात रखी थी। आज फिर कह रहा हूं कि मेरे हनुमानगढ़ जिले में डेयरी के एमडी जो कि पिछले पांच साल से बैठे हैं, वे मिलावटी दूध का धन्धा करते हैं, आप उसकी उच्च स्तरीय जांच कराइये। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हनुमानगढ़ के दूध की खपत हनुमानगढ़ में ही नहीं हो रही है, दूसरी जगह पर भी उसके प्रोडक्ट जाते हैं। मिलावट के दूध से कैंसर होने के खतरे हैं और हम कैंसर से नहीं मरना चाहते और अपनी जनता को मरते नहीं देखना चाहते। इसलिए आप जांच करायें और जांच के बाद सही एक्शन लें। जो कोविड सहायक लगे थे, उनका मानदेय बढ़ाने का काम करें, मैं उनके स्थायीकरण की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री लक्ष्मण जी मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं मांग

(श्री लक्ष्मण मीणा)

संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य तथा मांग संख्या 13-आबकारी पर संक्षिप्त में अपने विचार रखूंगा। मैं पहले मांग संख्या 13-आबकारी पर अपने कुछ विचार रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, माना कि आबकारी विभाग राज्य की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, जिससे सरकार चलती है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, वेतन-भत्ते दिये जाते हैं, साथ ही विकास के कार्य भी होते हैं। लेकिन इन दुकानों को खोलने के भी कुछ नियम, कानून और कायदे हैं कि किस-किस स्थान पर खुलेंगी, किस पर नहीं खुलेंगी। एक लाइसेंस की एक दुकान होती है, 25 दुकान खोल ली जाती हैं। धार्मिक स्थल हो, हास्पिटल हो, स्कूल कालेज हो और एससी, एसटी और श्रमिक वर्ग की कालोनियों के बीच में ये दुकानें खोली जाती हैं। आपका जो महकमा है, राज्य सरकार का जो आबकारी विभाग है, वह ठेकेदारों और दुकान के मालिकों के नौकर के रूप में कार्य करता है, वह उनको कुछ नहीं कहता है। जहां पर ये दुकानें खोली जाती हैं, वहां पर काफी समस्याएं होती हैं। महिलाएं उनका विरोध करती हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। कृपा करके इस तरह से जो लाइसेंस दिया जाये, वह एक दुकान के लिए दिया जाये और प्रतिबन्धित स्थानों पर नहीं दिया जाये। दूसरी बात, हथकढ़ शराब में भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं। इसमें गरीब लोग, राजस्थान में पहले भी कई लोग हथकढ़ शराब पीकर मरे हैं। ऐसा ही दूसरे प्रदेशों में भी है। इसलिए इस पर भी प्रभावी तरीके से नियन्त्रण रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की मांग पर आता हूं। पिछले तीन साल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबर्दस्त और ऐतिहासिक काम किया है। बहुत सारे मेडिकल कालेज खोले हैं। नर्सिंग कालेज खोले हैं, पीएचसी, सीएचसी और सब-सेन्टर्स जबर्दस्त तरीके से खोले हैं और गांव-गांव तक पहुंचे हैं। नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच, जो सबसे ऐतिहासिक काम किया है, वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि पहले पांच लाख की थी, अब उसे दस लाख रुपये किया गया है। 1 अप्रैल से जितनी भी आउटडोर और इंडोर की जांचें होंगी, सब नि:शुल्क होंगी और सब-सेन्टर तक होंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी सब्सेन्टर हैं, मेरे बस्सी में 53 सब-सेन्टर हैं, 28 में तो बिल्डिंग ही नहीं है, वे कहां पर बैठकर इलाज करेंगे तो कृपा करके

(श्री लक्ष्मण मीणा)

सब-सेन्टर के निर्माण के लिए पैसे दें। इसी तरह से हास्पिटल खोल दिये। या तो हास्पिटल की बिल्डिंग नहीं है या फिर बिल्डिंग है तो दूरदराज के इलाकों में डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के रहने की जगह नहीं है। वे थोड़े समय वहां रुकेंगे, बाद में वहां से निकल जायेंगे। अगर कोई इमरजेंसी होती है या इलाज के लिए लोग आते हैं तो वहां पर कोई डाक्टर नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें यह समस्या है कि उनके लिए वहां पर रहने के लिए जगह नहीं है। दूरदराज के इलाकों में उनको टायलेट तक की सुविधा नहीं है। किराये के मकान नहीं मिलते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

मैं बस्सी की बात करूं। माननीय सभापति महोदय, बस्सी की साढ़े तीन-पौने चार लाख की आबादी है। वहां पर मात्र 11 हास्पिटल हैं। कम से कम 10-15 हजार की आबादी पर एक हास्पिटल खोलें। जो बड़े-बड़े गांव हैं, जैसे पाटन, बठेरी, बूड़थल, कासीपुरा, देवगांव हैं, इनमें भी पीएचसी खोलने की बहुत आवश्यकता है, ताकि लोगों को सस्ती व नजदीक की स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

01 अप्रैल, 2022 से नि:शुल्क आउटडोर योजना शुरू हो जायेगी। काफी लोग आयेंगे क्योंकि यह कैशलेस है। जेब से एक पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए व्यवस्था की जाये, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। माननीय मंत्री जी ने एक आदेश तो किया कि जितने भी डेपुटेशन पर हैं या दूसरी जगह पर पोस्टिंग है, दूसरी जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन उन सारे लोगों ने अभी जोइन नहीं किया। मंत्री जी ने कहा भी था कि उनकी नौकरी चली जायेगी तो आप पांच-दस की नौकरी खतम कर दो तो वे जल्दी आ जायेंगे, वरना तो आपके आदेशों की कोई पालना नहीं कर रहे हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं हैं, उनकी जगह पर एमओ लगा रखे हैं। आजकल लोग इलाज स्पेशलिस्ट से कराना चाहते हैं। सरकार सुविधा भी दे रही है, इसलिए कनिष्ठ विशेषज्ञ लगाये जायें। दो हजार डाक्टर्स की पोस्ट खाली हैं तो हमारे बस्सी के हिस्से में भी पांच-सात डाक्टर आते होंगे, तो उनका भी जल्दी से जल्दी पदस्थापन किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने इसी बजट में 157 पीएचसी और 59 सीएचसी, सीएचसी से 15 उप जिला अस्पताल और 7 जिला अस्पताल बनाये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और उनका आभार

(श्री लक्ष्मण मीणा)

व्यक्त करता हूं, लेकिन बस्सी में भी जरूरत है। वहां पर उप जिला अस्पताल बनाया। वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है। वहां पर आरसीडीएफ है, उससे हमने 12 बीघा जमीन की मांग की है। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह उसमें से जमीन दिलायें, ताकि नेशनल हाईवे पर हास्पिटल बन सके।

इसके अलावा जो सफाई की बात है। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर 11 हास्पिटल हैं, एक भी सफाई कर्मचारी की पोस्टिंग नहीं है तो फिर सफाई की बात करना तो बेकार है। क्योंकि सफाई कर्मचारी ही नहीं है तो फिर कैसे होगी? वार्ड बाय्ज नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जबकि डाक्टर का काम है। वह देख लेगा, प्रिसक्रिप्शन लिख देखा, बाकी सारा काम नर्सिंग स्टाफ और वहां के वार्ड बाय्ज एवं सफाई कर्मचारी करते हैं तो इनके पद जल्दी से जल्दी भरने की कार्यवाही करें, ताकि लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती इन्दिरा जी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेड़ता रोड और जसनगर में जो पीएचसी है, उसके लिए मैं आपसे मांग करती हूं कि उनको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। दूसरी बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने पहले भी ट्रोमा सेन्टर की घोषणा की और मंत्री जी ने लैटर भी दे दिया तो उसके लिए भी मैं आपसे मांग करती हूं कि उसे जल्दी चालू करवायें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बडायली और लिलीया हैं, उनमें आप पीएचसी की घोषणा करें क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गरीब लोग हैं, उनके पास किराया तो अलग बात है, दवाई का पैसा भी नहीं होता है। मैं आपसे मांग करती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर की बहुत जरूरत है। मैं आपसे मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेड़ता रोड और जसनगर में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करें और ट्रोमा सेन्टर की आपने घोषणा की, उसे जल्दी चालू करें।

(समय: 16.00 बजे)

वैसे मेड़ता और रियांबड़ी में नर्सिंग कालेज की भी आप घोषणा कीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। ट्रोमा सेंटर की बात आई, ट्रोमा सेंटर की भी मैं आपसे मांग

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

करती हूं क्योंकि हाईवे भी है और 100-100 किलोमीटर दूरी पर कोई हास्पिटल नहीं है। ट्रोमा सेंटर हो जाए तो जनता को राहत मिले। मैं आपसे यही मांग करती हूं कि हमारी विधान सभा के लिए आप घोषणा करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: सभी सदस्यों का जो बोलने का समय है, वह मेक्सिमम 7 मिनट का रखा गया है क्योंकि बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। श्री जब्बर सिंह जी सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 व मांग संख्या-13 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा पर आज चर्चा हो रही है। मैं सर्वप्रथम पिछले दो वर्ष जो कोरोनाकाल के निकले, उसको हम सब माननीय सदस्यों ने देखा है। उस कोरोनाकाल में जैसे भीलवाड़ा मॉडल हुआ था, भीलवाड़ा मेरा जिला है, भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में प्रख्यात हुआ था। भीलवाड़ा मॉडल में जिन-जिन विभागों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और भी जितने विभाग हैं सभी, हमारे मीडियाकर्मी, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, सभी जन-प्रतिनिधिगण और सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, जिन्होंने उस कोरोनाकाल में प्रदेश की जनता की जो सेवा की है, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने घर परिवार को छोड़कर जिन्होंने उस समय एक कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, मैं उन सभी को मेरी ओर से बधाई देता हूं और मैं उनके सामने नत-मस्तक होता हूं और उनको सेल्यूट करता हूं।

सभापति महोदय, मैं मेरी विधान सभा की कुछ मांगें हैं, मैं डायरेक्ट उन्हीं पर आऊंगा। मंत्री महोदय, आपने मेरी विधान सभा में अंटाली पी एच सी को सी एच सी किया। मोडका निम्बाड़ा सब-सेंटर को पी एच सी घोषित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में मेरी विधान सभा में बदनौर सी एच सी है शायद पहली सी एच सी होगी जो बिना डाक्टर की सी एच सी कहलाती है। सी एच सी है और बहुत जोरदार बिल्डिंग है। भीलवाड़ा जिले में बदनौर की जो सी एच सी की बिल्डिंग है, बहुत ही आधुनिक बिल्डिंग है, लेकिन वहां डाक्टर नहीं है। सी एम एच ओ साहब से बात होती है, वह एक डाक्टर की व्यवस्था करते हैं। इधर-उधर

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

से लगाते हैं। उसी से काम चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि बदनौर में जो डाक्टर्स के पद खाली हैं, उनको भरा जावे।

दूसरी, बदनौर सी एच सी में ही मेरी मांग है कि वहां की जो 108 एम्बुलेंस है, वह बिलकुल खटारा हालत में है। आप शाम को जवाब दें तब उसमें आज ही डाक्टर्स की और बदनौर सी एच सी में एम्बुलेंस की घोषणा करें। प्लीज, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन यह रहेगा, अभी एक माननीय सदस्य बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे मोटास ग्राम पंचायत है, जहां एक पी एच सी है, जो पिछली सरकार ने घोषित की थी आज के चार साल पहले, वहां जगह नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत ने जगह भी उपलब्ध करा दी और उसका पट्टा भी बना दिया पी एच सी का, लेकिन वहां बिल्डिंग नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप भीलवाड़ा कलेक्टर महोदय को आदेशित करें कि डी.एम.एफ.टी. फंड से उस बिल्डिंग का पैसा रिलीज हो।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा और गुलाबपुरा एन एच 79 के बीच में एक कंवलियास बहुत बड़ा कस्बा है, जो गुलाबपुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने तीन-चार बार मंत्री महोदय जी को लिखकर भी दिया है और हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री रहे हैं, उन सभी को लिखकर दिया है। वहां अति-आवश्यक है, सी एच सी की मांग है, क्योंकि गुलाबपुरा और भीलवाड़ा के बीच सेंटर में गांव पड़ता है और हाईवे होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कंवलियास को भी सी एच सी घोषित करें।

मंत्री महोदय, मेरा अपसे निवेदन रहेगा कि ब्राह्मणों की सरेरी, जो आसीन्द से भीलवाड़ा के बीच में गांव पड़ता है। आसीन्द से वह 20 किलोमीटर की दूरी पर है और भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। एन एच 158 मेन हाईवे रोड पर बहुत बड़ा कस्बा है। वहां आसपास 10-15 ग्राम पंचायतें लगती हैं और सैकड़ों गांव वहां लगते हैं। वहां भी हाईवे होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैंने ब्राह्मणों की सरेरी के लिए भी सी एच सी की मांग की है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उसको भी सी एच सी में घोषित करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

रहेगा कि बरसनी ग्राम पंचायत, दस हजार की वहां जनसंख्या है। बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। मेरे हिसाब से मेरी विधान सभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बरसनी है और वहां 8-10 ग्राम पंचायतें आसपास लगती हैं। वहां भी सैकड़ों गांव लगते हैं। वहां एक सब-सेंटर है केवल। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बरसनी को आप पी एच सी आज ही घोषित करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साथ ही मेरी बदनौर पंचायत समिति में भादसी ग्राम पंचायत है, अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ गांव है और वहां पहाड़ों पर तीन-चार पंचायतें हैं, जहां बदनौर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वहां केवल एक सब-सेंटर है। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भादसी सब-सेंटर को भी आज ही पी एच सी घोषित करें।

अंत में मैं केवल एक बात मेरी रखना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा की झालरिया ग्राम पंचायत का एक मरेवड़ा गांव है। मंत्री महोदय, वह मेरे आसीन्द से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और करेड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां किसी भी तरीके की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि आप मरेवड़ा में भी एक सब-सेंटर खोलने की आज ही घोषणा करें। साथ ही मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरी एक मांग रहेगी कि 108 एम्बुलेंस के जितने भी कर्मचारी हैं, आप उनको स्थायी कीजिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, वंदे मातरम्।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गोपाल लाल जी मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई एवं मांग संख्या 13- आबकारी पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में जिस प्रकार से बजट दिया है, पूरे राजस्थान की जनता उससे खुश है। जिस प्रकार से दो वर्ष से कोरोना का जो कहर पूरे विश्व पर पड़ा और उसका प्रबन्धन आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया, उसका प्रबन्धन इस प्रकार से किया कि देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक मॉडल के रूप में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने नाम रोशन किया। भीलवाड़ा और रामगंज का मॉडल पूरे विश्व में एक तरह का मॉडल बनकर आया।

(श्री गोपाल लाल मीना)

मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सेवाएं प्राप्त हों, इस संकल्प के तहत मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना को और विराट रूप देते हुए इलाज के लिए होने वाले खर्च की राशि की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख से दस लाख रुपये किया, सम्पूर्ण राजकीय चिकित्सालयों में इनडोर व आउटडोर नि:शुल्क किया, जांचें एवं दवाएं पहले से ही फ्री कर रखी हैं जिसके कारण प्रदेश का हर गरीब से गरीब आदमी भी अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज आसानी से करवा सके।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से 5 लाख से 10 लाख और यह चिरंजीवी योजना उनकी सोची हुई थी कि जिस प्रकार से कोरोना में लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गयी थी, लोगों को किस प्रकार से सहायता दे सकें, यह चिरंजीवी योजना लागू की, बजट में 10 लाख की और इसके साथ ही दुर्घटना बीमा के रूप में 5 लाख रुपये की घोषणा की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज प्रदेश का हर व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए घबरा नहीं सकता क्योंकि उसको केवल हास्पिटल जाना पड़ता है और उसका इलाज फ्री हो जाता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं। चूंकि समय को देखते हुए मैं मेरे क्षेत्र की जो घोषणाएं की हैं पिछले बजट में, कुछ दिया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी द्वारा पिछले तीनों बजट में मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जिला अस्पताल दिया, ट्रोमा सेंटर दिया।

बहुत से उप स्वास्थ्य केन्द्र दिये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिये, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, मेरे व मेरे विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता की ओर से, हार्दिक आभार एवं धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा, आमजन के लिए आवश्यक है। मेरे क्षेत्र की कुछ मांग है, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, उसी तरह हर पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी होनी चाहिये, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल पायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर-दूर पंचायतें हैं, पंचायत

(श्री गोपाल लाल मीना)

मुख्यालय है, हर मुख्यालय पर डाक्टर बैठेगा, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रान्ति आयेगी। निश्चित रूप से लोगों को, इसका फायदा मिल पायेगा।

मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, मेरे क्षेत्र में रायसर पीएचसी है। रायसर में सीआई का थाना भी है। वहां नेशनल हाईवे है, इसलिए वहां पीएचसी की जगह सीएचसी होगी, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की, 8-10 पंचायतों और उस क्षेत्र के 70-80 हजार लोगों को उसका फायदा मिलेगा। नेशनल हाईवे से 30 किलोमीटर पर सीएचसी पड़ती है। कभी किसी के साथ हादसा होता है, तो उनको 30 किलोमीटर दूर जाकर, पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है। रायसर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन होना चाहिये। ताला में पीएचसी है, वहां भी करीबन 60-70 हजार लोगों का समूह है। वहां भी सीएचसी होती है तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को फायदा मिल पायेगा।

उप जिला अस्पताल में ब्लड बैंक हो। मेरा क्षेत्र करीबन 150 किलोमीटर लम्बाई-चौड़ाई में है। जयपुर आने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वहां ब्लड बैंक हो जाये।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): उप जिला अस्पताल में गायनिकी यूनिट होना जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ट्रोमा वार्ड खुला है, उसको जल्दी चालू करवायें। मेरे क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। कुछ जगह, ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, जो बड़े कस्बे हैं, जिनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र से पीएचसी करने की मांग करता हूं। निमला, भूज, डांगरवाड़ा, नेवर, फूटालाव, बिलौच, मातासुला, मानौता, धामस्या, बहलोड।

इसी तरह उप स्वास्थ्य केन्द्रों की, जहां अब तक उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुले, शाहीपुरा, देविता, रामपुराबास रामगढ़, मानौता, खरड, श्रीनगर, बट का बास, थापरबास, बासना, सरजोली, सामौर, बाज्यावाला, नाबावाल्या, मीणों का बास, हरिकिशन पुरा, श्री रामनगर, टीकमपुरा, ऐसी 5-6 जगहें और हैं, जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र होंगे तो निश्चित रूप से, उन लोगों को फायदा मिलेगा।

मैं आबकारी के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में निरीक्षक स्तर का कार्यालय खोला जाये, ताकि अवैध शराब, अवैध दुकानें हैं, उन पर रोक लगाई जा सके।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): निरीक्षक शाहपुरा बैठता है। यहां कभी आता है, कभी नहीं आता, उसका कोई पता नहीं होता। निरीक्षक स्तर का अगर कार्यालय खुलेगा, तो निश्चित रूप से वहां अवैध शराब पर काबू पाया जा सकेगा। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवा पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। हाल-ए चिकित्सा राजस्थान का बयान तो इसी से होता है, जब माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वास्थ्य समस्या होती है और एसएमएस में भर्ती होते हैं, वहां के शौचालय का हाल देखकर। जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है, वह व्हीलचेयर ही टूटी हुई होती है। अगले दिन ही सुपरिन्टेंडेंट को हटा दिया जाता है। जब राजस्थान के मुखिया का यह हाल है, तो राजस्थान के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का यह हाल है। बीकानेर में, रेगिस्तान में, लूणकरणसर में बैठे, हम क्या सोचें, जब सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में यह हाल है।

जब हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं, हमेशा यह बात होती है प्राइमरी, सैकण्डरी, टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में पीएसची, उप स्वास्थ्य केन्द्र सीएचसी। सैकण्डरी में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल। टर्शरी में मेडिकल कालेज, सुपर स्पेशलिस्टी सेंटर, यह देखने का प्रयास करते हैं कि उनमें सुधार हो।

अब हमारे पीएचसी व उप स्वास्थ्य केन्द्र का क्या हाल है, लूणकरणसर में ज्यादातर जगह से एएनएम हटा दी गयी हैं। ट्रांसफर के नाम पर, इस सरकार ने अपने को बचाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को दांव पर लगा दिया। पीएचसी पर डाक्टर्स बैठते ही नहीं हैं। लूणकरणसर का हाल यह है, सीएचसी लूणकरणसर में कोई स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं है। सारी की सारी पोस्टें खाली हैं। कोई तीन डाक्टर बैठते हैं, वह भी कभी बैठते हैं, कभी नहीं बैठते, रोज लड़ाइयां होती हैं। मंत्री जी दो मिनट बैठते, तो कुछ अच्छी बात होती, कुछ आप भी सुनते।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं सुन रहा हूं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): नहीं, आप नहीं सुन पाओगे। आप तो ताली बजाओगे। मंत्री जी को सुनाना चाह रहे थे पर वह मुख्य मंत्री का

(श्री सुमित गोदारा)

नाम लेते ही चल दिये। उन्हें लगा और भी बोलेंगे। कालूओज, मेरे वहां स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां मैं औचक निरीक्षण पर गया, तो वहां 6 चिकित्सकों की पोस्ट है लेकिन मात्र 2 ही चिकित्सक। मैंने सीएमएचओ को फोन किया कि साहब यह क्या है, उन्होंने कहा, साहब, मैं हटा देता हूं। अब हटाना क्या, यह भी एक बड़ा खेल है। माननीय सभापति जी, सीएमएचओ ज्यादातर जिलों में ज़िले का मालिक है, पर चिकित्सा सेवाओं में वे क्या करते हैं, वह इसी चीज के लिए, डाक्टर नहीं बैठा, उससे उनका कुछ न कुछ आपस में होता है। ऐसे ही नर्स नहीं बैठती। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत परेशान होते हैं।

ऐसे ही बीकानेर सीएमएचओ, उन पर कई बार आरोप लगे, अभी उन्हें बिठाया गया है। उन्होंने कभी कोई कार्यवाही नहीं की, जाते सब जगह हैं, पर कार्यवाही कहीं नहीं करते। पता नहीं क्या बात होती है, जाते हैं फिर कार्यवाही बन्द हो जाती है। यह भी जांच का विषय होना चाहिये। ज़िले के मालिक, जिनके ऊपर सारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वे क्या कर रहे हैं।

ऐसे ही मेरी सीएचसी नापासर है। वहां एक डेंटिस्ट है, वह ही सारे मरीज देख रही है, यह हाल है। सामान्य बीमारियों के लिए भी डेंटिस्ट इलाज कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट डाक्टर है ही नहीं। होते हैं, उनको यह फटाक से डेपुटेशन कर देते हैं। हम जा-जाकर थक जाते हैं, डेपुटेशन के नाम पर यह उन लोगों को, ये नियुक्ति करते नहीं हैं, लोग परेशान होते हैं।

कोविड काल में, ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा, बड़ी रूचि से, हमने एम्बुलेंस दी, पर हाल यह है कि वह खड़े-खड़े खराब हो रही है। पूछ रहे हैं तो कहते हैं हमारे पास धन नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने आरएमआरएस का कलेक्शन तो बन्द कर दिया, 5 रुपये,10 रुपये, पर संस्थाएं चलेंगी कैसे, यह तो बताओ? आपके पास फण्ड होता ही नहीं है। वे संस्थाएं कैसे चलेंगी? आप कहोगे, यहां से भेजेंगे, यहां से तो वैसे ही पैसे नहीं भेज रहे, कहां से उनका होगा? जो छोटे-मोटे काम अस्पताल में होते थे, वे भी रुक जाएंगे। लोक लुभावनी घोषणाएं करो, पर साथ में यह भी देखो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब न हो।

मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि एम्बुलेंस कैसे संचालित करें, इसकी कुछ व्यवस्था तो दें। मेरा तो मरुस्थल क्षेत्र है, वहां भामाशाह तो हैं ही नहीं, वहां तो किसान हैं। एम्बुलेंस खड़ी है, हम किसको कहें? दो-दो लाख रुपये कौन दे? यह समस्या है। अगर आप एम्बुलेंस अच्छी तरह से संचालित करने दोगे,

(श्री सुमित गोदारा)

तो ग्रामीण क्षेत्र का पेशेंट सीएचसी जाये, सीएचसी नहीं तो मेडिकल कालेज जाये, कितने लोगों को लाभ मिले, यही तो हमारा उद्देश्य है। पर वह उद्देश्य सिर्फ कागजों में ही रह गया। उस एम्बुलेंस का कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा। कितने लोगों को, मरीजों को, महिलाओं को मदद मिल सकती है। हमने सिर्फ घोषणा दे दी, एम्बुलेंसें खड़ी हैं, टायर खराब हो जाएंगे और अशोक गहलोत जी भाषण देते रह जाएंगे व सुभाष गर्ग जी मेज़ थपथपाते रह जाएंगे।

ऐसे ही मेडिकल कालेज बीकानेर है, उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है। प्रिंसिपल का चार्ज किसको दिया गया, माननीय मंत्री जी हैं, उनका बीपी नापते हैं, इसलिए उनको चार्ज दे दिया गया, कि मेरे बीपी नापने आ जाते हैं, तो ठीक है, इसको प्रिंसिपल का चार्ज दे दो। अब वह डाक्टर रूचि ही नहीं रखता। खुद घर में प्रेक्टिस करके, उसने हास्पिटल खोला हुआ है। ऐसे आदमी को आपने, कहते हैं न बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी। आप बताओ, ऐसा प्रिंसिपल क्या काम करेगा? जो खुद ही इस तरह काम करता है, वह प्रिंसिपल क्या काम करेगा? यही हाल आपके स्वास्थ्य का।

इमरजेंसी सेवाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। कार्डियोलॉजी, ट्रोमा पर बात करूं। कार्डियोलॉजी हाल-ए दिल, यहां कई विधायकों ने बयान किया। खेतड़ी के माननीय विधायक जी, डाक्टर साहब हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं। सभापति महोदय, हमारे बीकानेर में कार्डियोलॉजी की बहुत शानदार बिल्डिंग है। बहुत ही शानदार है। आप देखोगे कि क्या बिल्डिंग है। पर उसमें इलाज की व्यवस्था पी.एच.सी. से भी बदतर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से भी बदतर है और बदतर क्यों है? क्योंकि जो विभागाध्यक्ष है वह कभी आउटडोर में नहीं बैठता है और उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह जाकर अपनी हाजिरी भी नहीं लगाता, कोई दूसरा व्यक्ति ही जाकर हाजिरी लगाता है, यह भी बड़ी शर्म की बात है। कौन लगाता है यह भी जांच के विषय की बात है। हार्ट का मामला है। बैठते कहां हैं, कैथ लैब में। कैथ लैब में क्यों, साहब, बैठ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो सबसे इमरजेंसी है, गरीब आदमी ही जाता है।

माननीय सभापति महोदय, छह घंटे सिर्फ जांचें होती हैं पर हार्ट अटैक कोई पूछकर आता है? 18 घंटे ट्रोपोनिन जांचें बाहर से करवाते हैं, दलाल वहां पर घूमते रहते हैं और दलाल वहां लैब वालों से करवाते हैं और जो भर्ती मरीज हैं, उनसे भी अस्पताल के समय में जांच नहीं करवायेंगे, यह होशियारी से कि अस्पताल के समय के बाद, ताकि अस्पताल में यह जांचें नहीं हों, बाहर जाकर उसको करानी पड़े तो यह हाल है वहां पर।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। प्लीज, जनता के लिए दो मिनट दीजिए।

दूसरा, आप यह देखिये कि यह स्टेंट और एंजियोग्राफी के नाम पर भी घोटाला, क्यों नहीं यहां से राजस्थान सरकार सप्लाई करती जयपुर से? क्यों वहां पर यह लोकल डाक्टर्स को दी गयी है जिम्मेदारी कि वे मर्जी से खरीदें? ये रुचि ही नहीं लेते। यह जांच की जाये कि इतने-इतने अधिकारी बैठते हैं।

एक और देखिये आप कि इसमें ईको भी नहीं होती है और यह भ्रष्टाचार की सबसे दु:खद बात है कि 35-35 हजार के इंजेक्शन जिसके हार्ट अटैक होता है उससे बाहर से मंगाये जाते हैं। गरीब आदमी को यह कहते हैं कि मर जायेगा तो वह डर कर लेकर आता है। बाहर से नहीं, दलाल वहां पर ही इंजेक्शन लेकर आता है 35 हजार रुपये का, सरकारी नहीं देते हैं। यह हाल हमारे वहां की कार्डियोलॉजी का है।

माननीय सभापति महोदय, ट्रोमा का हाल देखिये कि वहां पर डाक्टर नहीं है। वहां पर एम.ओ. की पोस्टिंग नहीं है और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हमारे चार डाक्टर्स हैं बीकानेर में, पर आउटडोर लगता है सिर्फ तीन दिन और वे भी सारे घर में पेशेंट देखते हैं। सात दिन क्यों नहीं लगाते जब सुपर स्पेशलाइज्ड डाक्टर हैं, वहां तनख्वाह लेते हैं तो इतना सुपर स्पेशलिटी ब्लाक बना हुआ है पर पता नहीं वहां पर क्या सैटिंग इनकी आपस में है?

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक यह परम्परा चल पड़ी है कि डाक्टर द्वारा अपने आवास में, जो सरकारी आवास मिला हुआ है, उसके बाहर जाकर प्रैक्टिस करने के चैम्बर बनाकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह कहां की व्यवस्था है? हमने अपने पिताजी को भी देखा है, कभी ऐसे नहीं होता था। सरकारी डाक्टर बाहर जाकर चैम्बर में प्रैक्टिस करने लगे हैं, इस पर रोक लगायें और यह कोई जरूरी नहीं है कि शिकायतें ही आयें, विभाग के इतने-इतने अधिकारी यहां पर बैठते हैं, वे क्या काम करते हैं? वे क्यों नहीं करते?

माननीय सभापति महोदय, आपने समय कम दिया, वैसे बोल तो बहुत सकते हैं पर लास्ट में एक बात कहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि यदि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारनी हैं तो जो सरकारी नियम है कि जो

(श्री सुमित गोदारा)

डाक्टर पेशेंट देखता है, वह एक पर्ची लिखता है तो उस पर्ची का इन्द्राज ऑनलाइन होता है, यदि यह सी.एच.सी. से, पी.एच.सी. से, मेडिकल कालेज में प्रत्येक डाक्टर का, एच.ओ.डी., यूनिट हैड सबका हो तो सारे आउटडोर में बैठेंगे और मरीज/बीमार को सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी। आप यह पाबन्द करें कि उनका रोज (डेली) ऑनलाइन करें जिससे उनकी जानकारी लोगों को मिल सके कि हमारे कितने मरीज देख रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): हालत यह है कि सीनियर डाक्टर्स बैठते नहीं हैं, घर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, रेजिडेंट डाक्टर्स बैठते हैं, आप किसी भी मेडिकल कालेज, हास्पिटल में चले जायें, रेजिडेंट डाक्टर्स ही हास्पिटल चला रहे हैं, सीनियर डाक्टर कोई नहीं बैठ रहा है। मैं यह मांग करता हूं कि जो पिछले तीन साल में राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं का हाल बेहाल हुआ है, जब मुख्य मंत्री के साथ ही यह हुआ है तो, माननीय सभापति महोदय, आप ही हमारा ध्यान रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का समय दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और 13 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आभार और धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है जिसका सम्बन्ध साफ तौर से आम जनता के स्वास्थ्य और उनके भविष्य से है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि भोपालगढ़ क्षेत्र के अन्दर जो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. है उनमें पर्याप्त स्टाफ ही नहीं है। जब पिछले बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निरोगी राजस्थान की बात की और इस बार भी बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जो डायलिसिस है वह सी.एच.सी. स्तर पर शुरू करवाया जायेगा लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चार सी.एच.सी. हैं, उनकी क्या स्थिति है?

आसोप सी.एच.सी., जिसके अन्दर कनिष्ठ विशेषज्ञ की दो पोस्टें स्वीकृत हैं, एक भी कार्यरत नहीं है। यही स्थिति भोपालगढ़ की है कि वहां पर भी वरिष्ठ विशेषज्ञ की दो पोस्टें हैं और दोनों खाली हैं, एक भी डाक्टर नहीं

(श्री पुखराज)

है। यही स्थिति दूसरे डाक्टर्स जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी है। सात पोस्ट सेंक्शन हैं उनमें से दो हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ की दस पोस्टें हैं, उनमें से ये चार हैं। यही स्थिति नर्सिंग स्टाफ की है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सी.एच.सी. और पी.एच.सी. के अन्दर पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर्स ही नहीं हैं तो फिर यह डायलिसिस की बात और निरोगी राजस्थान की बात कैसे पूरी होगी? यह जो घोषणा की गयी है, यह घोषणा पूरी नहीं होनी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ सी.एच.सी., जो पिछले पांच साल से, पिछली जो सरकार थी, उसने क्रमोन्नत किया था कि भोपालगढ़ सी.एच.सी. 30 बैड की नहीं 100 बैड की होगी। अभी पिछले सत्र के अन्दर, प्रथम सत्र के अन्दर मैंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछा था तो उन्होंने लिखित में मेरे को यह जवाब दिया था कि भोपालगढ़ सी.एच.सी. है वह मौके पर 100 बैड की संचालित हो रही है लेकिन आज भी वह मौके पर 30 बैड की सी.एच.सी. ही संचालित हो रही है। वहां पर किसी तरह की 100 बैड के हिसाब से कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर मंत्रीजी विराजमान हैं, गर्ग साहब, आप अभी भोपालगढ़ पधारे थे, उस टाइम भी मैंने प्रोग्राम के अन्दर यह निवेदन किया था कि हमारी जो भोपालगढ़ सी.एच.सी. 100 बैड की घोषणा कर रखी है, उसके अनुरूप इस सी.एच.सी. के अन्दर डाक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, टैक्निशियन आदि की यहां ड्यूटी लगायें, उनकी पोस्टिंग करें।

मेरी तीसरी जो सी.एच.सी. है वह बावड़ी सी.एच.सी. आती है।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): बावड़ी सी.एच.सी. जो नेशनल हाईवे 62 के ऊपर है, उस हाईवे पर हमेशा अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और यह जोधपुर -नागौर सीमा पर है। यहां से 75 किलोमीटर तक जोधपुर की सीमा है अगर उस सीमा पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां से घायल या जो मृत्यु कारित हो जाती है, उन लोगों को लेकर जोधपुर जाना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बावड़ी सी.एच.सी. के अन्दर ट्रोमा सेंटर की घोषणा करें और वहां पर जो पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भी भरा जाये। बावड़ी सी.एच.सी. के अन्दर न तो ट्रोमा सेंटर है, न मोर्चरी है, न फिजिशियन है, न गायनोकोलोजी का कोई डाक्टर है और

(श्री पुखराज)

न ही पर्याप्त कोई फार्मासिस्ट या नर्सिंग स्टाफ ही है, तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ट्रोमा सेंटर की स्थापना की जाये।

साथ ही, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सबसे पुरानी जो पी.एच.सी. है सालवाकलां, यह काफी बड़ा गांव है, करीब 12 हजार मतदाता हैं और पी.एच.सी. सालवाकलां के अन्दर 9 सब सेंटर आते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: वे नोट कर रहे हैं।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सालवाकलां पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: सब कुछ ठीक चल रहा है, आप चिंता न करें। नोट कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आपकी बातों पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। आप बोलिए।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सारी बातें सुन रहा हूं और नोट भी कर रहा हूं।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): साथ ही हमारे साथीन सब सेंटर और बुडकिया सब सेंटर बहुत पुराने सब सेंटर हैं, काफी बड़े गांव हैं, टाउन हैं तो इनको भी क्रमोन्नत करके पी.एच.सी. घोषित करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 और 13 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

समय कम है इसलिए मैं शुरुआत माननीय मुख्य मंत्रीजी के धन्यवाद से करूंगा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, आम जनता के स्वास्थ्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन और क्रांतिकारी निर्णय इन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लिए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आप में एक बहुत ही

(श्री सुरेश टाक)

क्रांतिकारी योजना है, जिसको पांच लाख से दस लाख बढ़ा दिया और इसके अलावा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित कर दिया गया है कि इस योजना में कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उनका इलाज करवाया जाये। साथ ही, दुर्घटना होने पर पांच लाख रुपये का क्लेम भी इसमें निर्धारित किया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगा, जिनका ध्येय आम गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बिलकुल निश्चिंत रहने के लिए यह कदम उठाया गया है और दस लाख रुपये की राशि अपने आप में एक इतनी बड़ी राशि है कि एक गरीब आदमी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो सकता है।

समय का अभाव है, इसलिए मैं सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में ही कहूंगा। मुझे सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को कहना है कि तीन साल में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा नहीं मिली है। मेरे विधान सभा क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया। कोई सीएचसी, पीएचसी, सब सेन्टर, किसी भी तरह की कोई सुविधा मुझे नहीं दी गई। मैं इस मांग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ को एक भी सब सेन्टर, पीएचसी या सीएचसी कोई भी नहीं मिली है इसलिए क्रमवार नाम बताऊंगा, जिस प्रकार से मैं क्रम तय कर रहा हूं, मुझे तीन या चार सीएचसी, पीएचसी दी जाएं, जिससे मेरे लोगों को भी एहसास हो कि मैं सरकार का पार्ट एण्ड पार्शल हूं और सरकार के साथ खड़ा हूं।

पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल को जिला अस्पताल कर दिया था, लेकिन अभी तक भी उसको जिला अस्पताल का दर्जा नहीं मिला है। उस अस्पताल को अहसास नहीं हो रहा है कि मैं जिला अस्पताल बन गया हूं। मैं यह चाहता हूं कि मेरे उस अस्पताल को अहसास कराया जाए कि वह जिला अस्पताल बन गया। उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं। मानव संसाधन के साथ-साथ दूसरे संसाधनों की भी भारी कमी है। उस कमी को दूर किया जाए जिससे अस्पताल और वहां के लोगों को लगे। किशनगढ़ एक मार्बल नगरी है, औद्योगिक नगरी है, विश्व का सबसे बड़ा मार्बल का उद्योग है और दो-दो टेक्सटाइल पार्क हैं, लाखों लोग वहां रोज आते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या, साढ़े तीन-चार लाख की जनसंख्या का शहर है, लेकिन वहां के अस्पताल में सुविधाओं के अभाव

(श्री सुरेश टाक)

की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। अजमेर, जयपुर और दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि इस बजट में, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी पूरक बजट पेश करें तो किशनगढ़ पर विशेष कृपा दृष्टि रखें और जो तीन साल में मुझे नहीं मिल पाया है, वह किशनगढ़ को मिले।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि किशनगढ़ के वाई एन अस्पताल को एमसीएच की सुविधा मिले। वहां पर एक साल में 7 हजार से 8 हजार के करीब महिलाओं के आपरेशन होते हैं और 700-800 बच्चे एडमिट रहते हैं तो अलग से वहां पर एमसीएच की विंग बने, जिससे अस्पताल की ओपीडी की भीड़ कम हो और एमसीएच की वजह से वहां की महिलाओं को, 210 गांव हैं, 42 पंचायतें हैं, दो उपखण्ड हैं मेरे, दोनों उपखण्ड के ग्रामीणजन वाई एन अस्पताल में आते हैं लेकिन पूरी सुविधाओं के अभाव में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसी के साथ एन एच-8 पर बांदर सिंदरी एक गांव बसा हुआ है, जहां पर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है, देश के हजारों बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, बहुत से प्राचार्य/व्याख्याता सभी आते हैं, कई दुर्घटनाएं वहां हुई हैं, उस हाईवे पर इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनको इलाज समय पर नहीं मिलने की वजह से वह काल-कवलित हो गये, मैं चाहता हूं कि बांदर सिंदरी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए ताकि वहां पर दुर्घटना होने पर वहां लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके और किसी की जान को बचाया जा सके।

मेरे अरांई उपखण्ड का अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सीएचसी है वह। उपखण्ड स्तरीय कार्यालय है, लेकिन वहां का अस्पताल जर्जर हो रखा है। पीडब्ल्यूडी ने कन्डम की रिपोर्ट कर रखी है, बावजूद इसके वह भवन पूरी तरह से जीर्ण-जीर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस बजट में उसके लिए घोषणा की जाए कि उस भवन को नया बनाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया सुनिये। उनको बोलने में दिक्कत आ रही है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरे यज्ञनारायण चिकित्सालय में लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए मैंने श्रीमान् पेडणेकर साहब को भी संसाधनों की एक लिस्ट दी थी। बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे संसाधन मैंने विधायक कोष से भी दिये हैं। करीब दो करोड़ रुपये के एम्बुलेंस और बहुत सारे संसाधन मैंने वाई.एन. अस्पताल और आसपास की डिस्पेंसरियों को दिये

(श्री सुरेश टाक)

हैं, लेकिन मैं सरकार से चाहता हूं कि वहां कुछ मशीनें जो आवश्यक हैं वे उपलब्ध करवायी जाएं। जैसे सर्जरी विभाग में पूरा लेप्रोस्कोपी सर्जरी सिस्टम चाहिए। ब्लड बैंक में एक एफ्रेसिस मशीन, जिससे ब्लड सेपरेशन और प्लाजमा की जो समस्या है, वह समाप्त हो सके। ब्लड बैंक में कम्पोनेंट मशीन, ईएनटी विभाग में एण्डोस्कोपी कैमरा सिस्टम, अस्थि रोग विभाग में सी-आर्म मशीन, टीबी एण्ड चेस्ट विभाग में ब्रोंकोस्कॉपी मशीन, दन्त रोग विभाग में ओपीजी एक्स-रे मशीन, ये अति आवश्यक मशीनें हैं, जिनकी आवश्यकता मेरे वाई.एन. अस्पताल को, जिला अस्पताल को है। आज मैं इस मांग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा और विभाग के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बात पर ध्यान दें और मेरे वाई.एन. अस्पताल को ये जो मशीनें, जिनकी मैंने मांग की है, बहुत सारे संसाधन मैंने उपलब्ध कराये हैं, मैंने अपने निजी फण्ड से कराये हैं, एमएलए लैड से कराये हैं और मेरे बहुत सारे मित्र भामाशाह हैं, उनसे मैं बिल्डिंग भी रिनोवेट करवा रहा हूं, बहुत सारे काम अस्पताल में करवा रहा हूं जिससे अस्पताल को नया रूप मिले।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी, दो मिनट में कन्क्लूड करता हूं, सर।

श्री सभापति: एक मिनट में ही समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): हां जी। इसी के साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। हमारे वाई.एन. अस्पताल में डाक्टर्स की कमी है। जितनी भी सीएचसी, पीएचसी हैं, वहां पर डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर हर जगह डाक्टर मिले।

एक और निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान् गालरिया साहब बैठे हैं, मैं यह चाहता हूं कि पीजी करने वाले डाक्टर्स, जितने भी हैं, उनमें से कम से कम 10 से 15 डाक्टर्स को जिला अस्पतालों में लगाया जाए, ताकि दो-दो महीने के लिए अगर वे आयेंगे तो अस्पताल में डाक्टर्स की कमियां पूरी होंगी, उनका अनुभव बढ़ेगा और जो मानव संसाधन की कमी है, वह पूरी होगी। शायद ऐसा सिस्टम भी है कि हर दो-तीन महीने के लिए आप पीजी करने वाले डाक्टर्स को जिला अस्पताल में लगा सकते हैं तो उनको लगाया जाए ताकि उनका अनुभव बढ़े।

श्री सभापति: Thank you.

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट, सर। इसी के साथ मेरी कुछ पीएचसी, सीएचसी हैं। मैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि मेरे उप स्वास्थ्य केन्द्र डसूक, आकोड़िया, टिकावड़ा, खंडाच, छोटा लाम्बा, भरना, भोगादीत और डबरेला को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए और बांदर सिंदरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाए।

इसी के साथ भामोलाव, सिरोंज, कालानाड़ा, काकलवाड़ा और मनोहरपुरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। यह जरूरी है। पंचायत हैड क्वार्टर होने के बावजूद भी वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि मेरी मांगों पर विचार करें और मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र को, जो तीन साल से अभी तक उपेक्षित रहा है, उसको स्वास्थ्य सेवाओं के साथ लबरेज करें और मेरे लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का मौका दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 व 13 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायसिंहनगर व श्रीविजयनगर कस्बे में ट्रोमा सेन्टर खोलने की मांग मेरे द्वारा लगातार पिछले तीन वर्षों से की जा रही है मगर आज तक पूरी नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रायसिंहनगर, श्रीविजयनगर एवं समेजाकोठी सीएचसी में न तो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, न ही कोई चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध हैं। बहुत से चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। एक ओर तो सरकार चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा व जांच निःशुल्क किये जाने की घोषणा कर रही है, दूसरी ओर क्षेत्र में मरीजों की जांच हेतु विशेषज्ञ और चिकित्सकीय उपकरण ही नहीं हैं तो जांच करवायेंगे कहां? मजबूरन गरीब और असहाय लोगों को निजी चिकित्सालय एवं लैबों में पैसे देकर अपनी जांच करवानी पड़ती है, जो कि आमजन के हित में नहीं है।

सभापति महोदय, दिनांक 03 मार्च, 2022 से मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायसिंहनगर के सीएचसी श्रीविजयनगर के सामने चिकित्सकों सहित 6 मांगों को लेकर आमरण अनशन चल रहा है। आज आमरण अनशन को चलते नवां दिन जारी है। अनशनकारी का किटोन लेवल प्लस तीन आ चुका है। उसकी जान को खतरा है। मैं इस सन्दर्भ में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

मिला। उन्होंने अपने पीएस से बात भी की, लेकिन मुझे लगता है कि चिकित्सा मंत्रीजी की बात अधिकारी नहीं मान रहे।

दिनांक 03.03.2022 से भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया तथा 04.03.2022 को क्षेत्र में मांगों को पूरा करने के लिए श्रीविजयनगर कस्बे का सम्पूर्ण बाजार बन्द रहा। प्रशासन द्वारा एक दौर की वार्ता भी की गई, मगर विफल रही। जहां एक ओर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा मांगें पूरी करने के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं और पीड़ा का समाधान नहीं करवाकर दिनांक 08.03.2022 को भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को धरना स्थल से जबरन उठाकर श्रीगंगानगर रैफर कर दिया गया। आमरण अनशन आज भी, अभी जारी है। सभापति महोदय, मैं इस सन्दर्भ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी जायज मांगें हैं इनको पूरी करें और अनशनकारी का आमरण अनशन तुड़वाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, अचानक एक्सीडेंट हो जाने की स्थिति में दोनों सीएचसी श्रीविजयनगर एवं रायसिंहनगर में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, मरीजों को रैफर करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर से मेरा विधान सभा क्षेत्र 100 किलोमीटर व बीकानेर 180 किलोमीटर पड़ता है। कई बार तो इलाज के अभाव में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है और परिवार के पास रोने-धोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता।

कोरोनाकाल में भी राजस्थान सरकार आम जनता को इलाज मुहैया कराने व अन्य सुविधाएं देने में नाकाम रही। इस संकटकाल में भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर पीड़ित परिवारों की सेवा की। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता के बीच में नहीं गया, जिसका परिणाम 2023 के चुनावों में आपको देखने को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, श्रीविजयनगर सी.एच.सी. 30 साल पहले के पैटर्न पर बनी हुई है। शहर की घनी आबादी हो जाने के कारण यह शहर के बीचों-बीच स्थित है, जिसके कारण एम्बुलेंस एवं अन्य इमरजेंसी वाहन हास्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। हास्पिटल परिसर में वाहन खड़ा करने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि सी.एच.सी. श्रीविजयनगर को सिंचाई विभाग की कालोनी में शिफ्ट कर दिया जाये तो आमजन के लिए काफी

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सुविधाजनक होगा। यहां उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग की कालोनी वर्ष 1962 की बनी हुई है। इस कालोनी के राजकीय आवास एवं बन्द पड़े कार्यालय जर्जर अवस्था में हैं। सिंचाई विभाग के कई कार्यालय भी यहां से अन्यत्र शिफ्ट हो चुके हैं। इस कालोनी का काफी भू-भाग खाली पड़ा है। विभाग के पास पर्याप्त भूमि है। वर्ष 2015 से इस कालोनी में पंचायत समिति श्रीविजयनगर कार्यालय का निर्माण भी किया गया है, जो विधिवत रूप से आज वर्तमान में वहां संचालित है। यदि सी.एच.सी. श्रीविजयनगर को सिंचाई कालोनी में रिक्त पड़े भू-भाग पर निर्माण किया जाता है तो क्षेत्र के आमजन निवासियों को सुविधाजनक होगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। आपकी बातों से दिक्कत आती है बोलने में।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सी.एच.सी. समेजा वर्ष 2013 में क्रमोन्नत हुई थी। वर्तमान में वहां सी.एच.सी. संचालित है, उसका भवन काफी जर्जर अवस्था में है और समेजा सी.एच.सी. हेतु जगह भी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का संचालन करने में काफी समस्याएं आती हैं। इसके साथ ही जर्जर भवन होने के कारण किसी भी प्रकार का आकस्मिक हादसा होने का भय बना रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी.एच.सी. हेतु जमीन उपलब्ध करने के लिए वहीं के स्थानीय निवासी भामाशाह श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री सांवत सिंह शेखावत द्वारा मुझसे सम्पर्क कर कहा गया कि वह स्वयं की कृषि भूमि में से सी.एच.सी. हेतु जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी, वह भूमि दान कर देंगे। सी.एच.सी. हेतु जमीन दान देने के सम्बन्ध में भामाशाह श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर; उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पत्र के माध्यम से अवगत भी करवाया हुआ है। इनकी कृषि भूमि समेजा गांव के बिलकुल समीप सटी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): साहब, अभी तो चार मिनट ही हुए हैं।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर शहर के आस-पास गजसिंहपुर, करणपुर, विजयनगर, अनूपगढ़, घड़साना एवं रावला शहर लगते हैं। श्रीगंगानगर के बाद अगर घनी आबादी वाला कोई शहर है तो वह रायसिंहनगर है। यहां बी एस एफ की बड़ी यूनिट भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। श्रीमान जी, रायसिंहनगर के आस-पास के गांव के क्षेत्र के लोगों को सी टी स्कैन, एम आर आई के लिए गंगानगर जाना पड़ता है तथा राजकीय चिकित्सालय में सी टी स्कैन, एम आर आई मशीनों के अभाव में निजी लैब या निजी चिकित्सालय में जांच करानी पड़ती है, जिस पर कम से कम पांच हजार रुपये खर्चा आता है, जो कि हर आदमी वहन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में इलाज एवं आने-जाने में ही मरीज का बहुत खर्चा हो जाता है। हर आदमी इस खर्च को वहन नहीं कर पाता। इलाज के अभाव में कई मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि अगर रायसिंहनगर के राजकीय महाविद्यालय में ये मशीनें लगा दी जाएं और राजकीय लैब खोल दी जाए तो आस-पास के पूरे बोर्डर एरिया में इसका फायदा मिलेगा और मरीजों को जांचों के लिए श्रीगंगानगर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल रायसिंहनगर सी.एच.सी. में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, मगर उसको आपरेट करने वाला वहां कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, विजयनगर के गांव 15BLD वाले में उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए और 12MBLM डबजाल उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, वहां भवन भी जर्जर अवस्था में है। उसका नया भवन बनाकर उसे पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए। इसके साथ-साथ ग्राम 6BLM, 32GB, 36GB में भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इन गांवों में भवन नहीं हैं। कृपया इन गांवों में भवन का निर्माण करवाया जाए और तहसील 26GB हरिपुरा, 29GB शिवपुरी, 8BLM में नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। अनूपगढ़ तहसील के गांव सलेमपुरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावे एवं खोकरावाली उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जावे। श्रीविजयनगर के गांव 45GB उप-स्वास्थ्य केन्द्र को भी पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जावे। (व्यवधान)

श्री सभापति: थैंक यू। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): साहब, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: नहीं, अब टाइम हो गया आपका।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): बस, एक मिनट और।

रायसिंहनगर सी.एच.सी. के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जावे। उप-स्वास्थ्य केन्द्र बग़ीचा, श्यामगढ़, मुकलावा, सगलाना, कमरपुरा, गढ़वाली, सी.एच.सी. समेजा के उप-स्वास्थ्य केन्द्र मोखमवाला को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जावे। चूंकि यह काफी बड़ा गांव है, आस-पास के 20-25 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। सी.एच.सी. समेजा में डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरा जावे।

हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी का सपना है स्वच्छ भारत का, इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी सी.एच.सीज. और पी.एच.सीज. एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। सी.एच.सी., रायसिंहनगर में मेरे द्वारा विजिट करने पर देखा गया कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। शौचालय एवं बाथरूम चालू हालत में नहीं है। इसी प्रकार सी.एच.सी., विजयनगर में शौचालय एवं बाथरूम सही हालत में नहीं हैं। सीवरेज के कारण व हास्पिटल काफी नीचे होने के कारण अस्पताल का भवन जर्जर अवस्था में है। डाक्टर एवं स्टाफ क्वार्टर भी जर्जर अवस्था में हैं। जगह-जगह पानी लीकेज हो रहा है। सी.एच.सी. समेजा में भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 और 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हर गांव-गांव में शराब की दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं। इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। गांव के अन्दर शराब को कोई जानता नहीं था, उन गांवों में आज शराब पहुंच चुकी है। हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि गांव के अन्दर जो शराब की अवैध बिक्री हो रही है और जो एक जगह का ठेका है, वहां उन लोगों ने हर गांव में शराब की दुकानें खोल रखी हैं। एक जगह का ठेका है और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी खुद की सर्कल बना रखी है कि यह सर्कल मेरी हो गयी। एक गांव में एक जगह शराब का ठेका खोलने का अधिकार आप दे सकते हैं। उस ठेकेदार को इतने पावर किसने दे दिये कि वह पूरी पंचायत के हर गांव के अन्दर शराब की दुकानें खोल दें। हमारे आबकारी विभाग वाले उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मेरी तो सरकार से यही मांग है कि गांवों के अन्दर जो शराब की बिक्री हो रही है, जो आपने यह दुकानें खोली हैं, उन दुकानों को बन्द कराया जाये और बाजार के अन्दर भी इतनी ज्यादा तादाद में दुकानें खुली हुई हैं, चाहे वह हमारी सरकार में खुली हों, चाहे वह बीजेपी की सरकार में खुली हों, यह दुकानें कम की जावें और इससे आने वाले पीरियड में हमारी जो नई पीढ़ी है, वह इस नशे की ओर बढ़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि थोड़ा बहुत राजस्व कम आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इतने पैसे उनके इलाज में खर्च कर रहे हैं। उनके घर-परिवार में रोजाना के आये दिन के झगड़े हो रहे हैं और फिर, माननीय सभापति महोदय, शराब पी-पीकर वह रोजाना झगड़े कर रहे हैं, रोजाना मोबाइलों पर गाली बक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। यह सब शराब की देन है। जो नशाखोरी है, वह बहुत ज्यादा फैल रही है। माननीय सभापति महोदय, ये दुकानें कम कराई जावें और इसको बन्द ही कराया जावे तो ज्यादा ठीक है। मेरी समझ में तो इस शराब से किसी का भला नहीं होता है, इसको बन्द कराया जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं मांग कर रहा हूं मेरे बाड़ी में उप जिला चिकित्सालय, जो 'बी' श्रेणी का हास्पिटल है, इसको क्रमोन्नत किया जावे। माननीय सभापति महोदय, इस चिकित्सालय में मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसको 200 बैड के बजाय 300 बैड का कराया जावे। इसमें 200 बैड हमेशा फुल रहते हैं। मंत्रीजी चाहें तो इसकी रिपोर्ट मंगा सकते हैं। इनको अभी जवाब देना है, उसमें काफी समय है। माननीय सभापति महोदय, उप-जिला चिकित्सालय बाड़ी की जगह कम है, तो इसको देखते हुए एक नवीन भवन बनाया जावे और जगह अलाट करायी जावे। बढ़िया जगह पर 300 बैड के हास्पिटल के लिए 10-15 बीघा जमीन अलाट कराये सरकार तो उस पर अच्छी बिल्डिंग बन जाए। अभी वर्तमान वाला 2 बीघा में है, उसको दो मंजिल तो हम बना चुके। अब दो मंजिल के अलावा तीसरी मंजिल पर कहां लेकर जाएं। जो बीमार व्यक्ति है, वह तीन मंजिल कैसे चढ़ेगा? माननीय सभापति महोदय, भूमि अवाप्ति करके नये चिकित्सालय के लिए एक नया भवन बनाया जावे।

माननीय सभापति महोदय, बाड़ी चिकित्सालय में डाक्टर और स्टाफ की काफी कमी है। 200 बैड का हास्पिटल जरूर है, पर इतना पर्याप्त स्टाफ नहीं लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, हमारे सैंपऊ के अन्दर हमारा

(श्री गिर्राज सिंह)

ग्रामीण एरिया लगता है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश से भी मरीज आ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, सैंपऊ चिकित्सालय में जमीन पर मरीजों को लिटाते हैं और वहां की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जमीन पर जगह कम पड़ जाती है तो बाहर रोड पर लोग पड़े रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, 50 बैड की बजाय सैंपऊ में 100 बैड का क्रमोन्नत किया जाए।

सभापति महोदय, एक हमारे ग्राम पंचायत मुख्यालय परवा है। वह भी एक बीच का केन्द्र है। यहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मंत्री जी घोषणा करें। मंत्री जी, यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि बाड़ी चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर की तो आपको आज ही घोषणा करनी पड़ेगी। आप जब जवाब दें तो इसकी घोषणा करें। बहुत हालत खराब है।

सभापति महोदय, बोर्डर की दूरी हमारे यहां 100 किलोमीटर है। हमारे यहां इतने एक्सीडेंट होते हैं कि आप चाहें तो हास्पिटल से रिकार्ड मंगा सकते हैं। महीने में करीबन 60 के आसपास मौतें हो जाती हैं। हमारे यहां से जो नेशनल हाईवे निकला है, उसमें एक महीने में एक रोड पर कम से कम 55 से 60 मौतें होती हैं। कितने घायल होते हैं, उनका तो कोई रिकार्ड ही नहीं है। कितने ही घायल हो जाते हैं और कितने एक्सीडेंट में ऊपर चले जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। 100 किलोमीटर की दूरी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि आज ही ट्रोमा सेंटर की घोषणा करें।

सभापति महोदय, सैंपऊ और बाड़ी में बैड बढ़ाने की घोषणा करें। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप चाहें तो हमारे बाड़ी के हास्पिटल का रिकार्ड मंगा सकते हैं। आपके पास अभी जवाब देने में काफी टाइम है। वहां बिल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या है। वहां न तो डाक्टर्स के क्वार्टर बन रहे हैं रहने के लिए कोई जगह नहीं है, रात में डाक्टर्स रुक नहीं पाते हैं। उनका मकान पास हो तो कोई रुके। कोई 5 किलोमीटर दूरी पर रह रहा है, कोई 2 किलोमीटर दूरी पर रह रहा है। रात को वहां पर 01 डाक्टर रहता है। वह ढंग से नहीं देख पाता है।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे बाड़ी हास्पिटल की बिल्डिंग स्वीकृत करायी जाये। इसके लिए

(श्री गिर्राज सिंह)

जमीन अलाट की जाये। मंत्री जी आज मैं आपसे पुन: निवेदन कर रहा हूं कि ट्रोमा सेंटर के लिए आप इस सदन में घोषणा करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गिरधारीलाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री गिरधारीलाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 13 एवं 26 पर विचार

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 13 एवं 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप आपस में बातें नहीं करें। कितनी बार आपको कहना पड़ेगा? अपनी-अपनी सीट पर रहें आप लोग। This is bad.

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के दुलचासर में पीएचसी लम्बे समय से बनी हुई है। आसपास की जनता के द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है कि इसको सीएचसी किया जाये। आसपास के 20 गांव लगते हैं।

श्री सभापति: बोलिए आप।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, दुलचासर में पीएचसी होने के कारण पूरा इलाज नहीं हो पाता है। इस कारण मरीजों को बीकानेर

(श्री गिरधारीलाल)

जाना पड़ता है या डूंगरगढ़ जाना पड़ता है। मेरी यही मांग है कि इसको क्रमोन्नत करके सीएचसी की जाये।

सभापति महोदय, सरकार ने श्रीडूंगरगढ़ में प्राइमरी ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की है किन्तु श्रीडूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय, नेशनल हाईवे पर पूर्ण ट्रोमा सेंटर की आवश्यकता है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बीकानेर जिले में सर्वाधिक हादसे श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में बीकानेर, जयपुर नेशनल हाईवे नम्बर 11 पर होते हैं। ऐसे में श्रीडूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय पर पूर्ण ट्रोमा सेंटर की आवश्यकता है।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर सरकारी भूमि उपलब्ध है। क्षेत्र के भामाशाह पूर्ण ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ में पूर्ण ट्रोमा सेंटर खोलने की स्वीकृति दें।

इसके अलावा श्रीडूंगरगढ़ में वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहर के बीचों-बीच, भीड़-भाड़ वाले इलाके में हैं। सीएचसी का भवन छोटा होने के कारण मरीजों को भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी को नेशनल हाईवे 11 पर शिफ्ट किया जाता है तो ज्यादातर हादसों में कमी आयेगी। मेरी मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी को नेशनल हाईवे पर शिफ्ट करके एक ही परिसर में ट्रोमा सेंटर और सीएचसी संचालित की जाये। क्षेत्र के भामाशाह भवन निर्माण में अपना सहयोग देने को तैयार हैं। सरकार को इस पर रुचि लेकर सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में यह आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव सादासर, सोनियासर, अड़सर, बरजांगसर, बापेऊ में उप स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों से आसपास के गांवों के हजारों मरीज लाभ उठाते हैं किन्तु यहां डाक्टर का पद नहीं होने के कारण, पर्याप्त जांचों के अभाव में मरीजों को उचित इलाज नहीं मिलता, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित में श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सादासर, सोनियासर, अड़सर, बरजांगसर, बापेऊ में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाये।

सभापति महोदय, कोरोना महामारी में प्रदेश में घर-घर जाकर फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार न

(श्री गिरधारीलाल)

तो फ्रंट लाइन वर्कर मान रही है और न ही इनका बीमा करवा रही है। नर्स ग्रेड सैकण्ड की तरह काम करने के बावजूद इन्हें सिर्फ कोविड स्वास्थ्य सहायक माना जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि फ्रंट लाइन पर रहकर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए इनको 50 लाख का बीमा प्रदान किया जाये एवं नर्स ग्रेड सैकण्ड पर स्थायी किया जाये।

इसके अलावा सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाये। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में जीएनएम भर्ती के 15773 पदों में से 4514 पदों की कटौती कर दी गयी थी। इसके अलावा वर्ष 2013 में एएनएम भर्ती के 12268 पदों में से 6719 पदों की कटौती की गयी थी। इससे अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर हो गये।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि जीएनएम एवं एएनएम की भर्ती में से कटौती किये गये पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाये।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की सीएचसी, पीएचसी केन्द्रों में चिकित्सा कर्मियों के भिन्न-भिन्न पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें तुरन्त भरा जाये।

सभापति महोदय, पिछले समय में पीएचसी स्वीकृत हुई थी। वहां अभी भवन बने हुए नहीं हैं।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): एक मिनट।

सभापति महोदय, आबकारी के संबंध में मांग है। प्रदेश भर में शराब की दुकानें सही समय पर बन्द नहीं होने की शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। शराब माफिया पनपते जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की शह पर प्रशासन की आंखों के सामने शराब की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। वहां असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अगर इन शराब की दुकानों पर कार्यवाही के लिए कोई आवाज उठाता है तो शराब माफिया शिकायतकर्ताओं को धमकाते हैं और मारपीट करते हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में शराब की

(श्री गिरधारीलाल)

ज्यादातर दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, किन्तु आबकारी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। आबकारी पुलिस की मिलीभगत से शराब माफियाओं के हौंसले बुलन्द रहते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि शराब माफियाओं और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए शराब की दुकानों को निश्चित समय पर बन्द किया जाये। आबकारी विभाग को कड़े निर्देश दें और लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों पर निगरानी रखकर कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, पिछली दफा शराब की दुकानें देर तक खुली थीं, वहां पत्रकार पहुंचे थे, 2 दिन रास्ता बन्द रहा फिर भी सम्बन्धित शराब माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह मांग करता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में असामाजिक तत्व फैले हुए हैं। अवैध शराब की बिक्री करते हैं। एक दुकान से 50-50 दुकानें चलाते हैं फिर भी आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि शान्ति बनाने के लिए, समय पर, 8 बजते ही दुकानों को बन्द करने की विशेष व्यवस्था करायें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। दिव्या जी मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य की चर्चा में भाग ले रही हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में एनएफएचएस के जो आंकड़े स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हैं, वे हैल्थ डेटा के सन्दर्भ में सबसे आथेंटिक और रिलायबल डेटा माने जाते हैं। जब हम उन इंडिकेटर्स को देखते हैं तो केरल हैल्थ की दृष्टि से पूरे हिन्दुस्तान में टॉप करता है। एक मॉडल राज्य है। अगर हमें केरल के काम्पिटिशन में आना है तो हमें व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। हमारा जो हैल्थ केयर सिस्टम है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम इन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर सकें।

मैं चिरंजीवी योजना की बात करूंगी। यह एक बहुत अच्छी योजना है। उसका कवर 5 लाख से 10 लाख रुपये कर दिया, लेकिन आज उसकी जरूरत है। प्राइवेट हैल्थ केयर सिस्टम्स बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के ढांचे पर हावी है और पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम वीक है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

(समय: 17.00 बजे)

इसका नजारा हमने कोविड में बहुत अच्छी तरह देखा। जब कोरोना की लहर आयी, प्राइवेट हैल्थ केयर सिस्टम ने हमें डिच किया और रायली डिच कर दिया। अस्पताले बन्द हो गये, अगर उपचार के लिए वहां गये तो मनमर्जी की, गये तो बुरी तरीके से उन्होंने पेशेंट्स को लूटा, उस समय किसी ने सहारा दिया तो पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम ने दिया इसलिए हमें पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो ही हम केरल जैसी स्थिति में पहुंचेंगे।

We need to invest on private healthcare की जगह on public healthcare और जो हम योजनाएं ला रहे हैं वह ऐसी लायें जिनमें प्राइवेट हैल्थ केयर का दायरा नहीं पब्लिक हैल्थ केयर का दायरा ज्यादा एक्सटेंड हो। हैल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनका बेसिस है कि जितने ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तब उन इंश्योरेंस कम्पनीज को मुनाफा होगा। स्टेट का व्यू होना चाहिए कि हमारे लोग कम से कम बीमार पड़े और हम प्रिवेंटिव मैजर्स पहले से लेकर चलें। जो इंश्योरेंस स्कीम, जो चिरंजीवी योजना है, यह tertiary layer को कवर करती है, ये प्राइमरी सेक्टर को कवर नहीं करती है। जब आपका आपरेशन हो जाये या इसी तरीके की योजनाएं और प्रोग्राम्स पैकेजेज के अन्दर होते हैं लेकिन अगर आप सोचें तो आप अपने जीवन में कितनी बार हास्पिटलाइज हुए होंगे? कई लोग बिलकुल भी नहीं हुए होंगे, कई लोग एकाध बार हुए होंगे लेकिन ओपीडी में सबको जाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, हमें इस बारे में आगे और सोचना पड़ेगा कि हम आज तो दे सकते हैं ये योजना, जो कि एक बेहतरीन योजना है लेकिन हमें इसके आगे भी सोचना पड़ेगा, हम इसका कवरेज बढ़ायें लेकिन हम पब्लिक हैल्थ केयर को भी पैरेलल मजबूत करें, यह हमारा परमानेंट सोल्यूशन होगा।

माननीय सभापति महोदय, कोविड आज कोई ओवर नहीं हुआ है, and maybe this is not the last pandemic. हमें 50 साल के हिसाब से हमारे हैल्थ की स्ट्रेटिजी बनानी पड़ेगी। हमें हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है जो इतनी मशरूम हो रही है पब्लिक हैल्थ, प्राइवेट हैल्थ केयर और पब्लिक को वीक कर रही है। इस पर हमें लगाम लगाने की जरूरत है।

कोविड में हमने दूसरी चीज देखी कि आम व्यक्ति की आमदनी पर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

इसका असर पड़ा, उसकी आय पर असर पड़ा। उसका हैल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर उस इन्कम के कम होने से बदला। अब वो पहले जो खर्च कर सकता था, वैसा खर्च नहीं करेगा, उसकी पाकेट पर मार पड़ी है, वह सरकारी व्यवस्था पर ज्यादा निर्भर होगा, उसकी पर्चेजिंग पावर भी कम हो गयी और उसकी निर्भरता भी कम हो गयी तो हमें और भी जरूरत हो गयी कि हम हमारे पब्लिक सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करें।

माननीय सभापति महोदय, जो फंडामेंटल मोड आफ आपरेशन है चिरंजीवी योजना का, वो भी प्राइवेट हास्पिटल्स हैं, सारे प्राइवेट हास्पिटल्स पैनल्ड हैं, प्राइवेट हास्पिटल आम व्यक्ति को एक्सप्लाइट करते हैं। हम बहुत ज्यादा पावर्स प्राइवेट हास्पिटल्स को दे रहे हैं। हमने पहले भी देखा कि ये क्या करते हैं, जब मन हुआ इलाज बन्द कर देते हैं, इंश्योरेंस कम्पनीज का कभी पैसा नहीं आता तो ये इलाज बन्द कर देते हैं और वहां जाते ही उस व्यक्ति को कैसे एक्सप्लाइट करते हैं। लोगों पर ही नहीं, ये इंश्योरेंस कम्पनीज सरकार पर भी हावी हैं। मान लीजिये आपका 20 हजार का एक पैकेज है उदाहरण के तौर पर, आप इलाज करवा रहे हैं तो आपको वो चार चीजें और बता देंगे, चार आपको जांच और बता देंगे, दवाइयां और ऊपर बता देंगे, कोई और आपरेशन और बता देंगे फिर आउट आफ पाकेट एक्सपेंडिचर होगा जिसे ओपीई कहा जाता है। आउट आफ पाकेट एक्सपेंडिचर आपको गरीबी रेखा से नीचे लेकर जाता है। यह स्टडीज ने प्रूव किया है। ये इस तरह से एक्सप्लाइटेशन करते हैं। हम किस तरीके की पावर उनको दे रहे हैं? मैं मानती हूं कि आज इस तरीके की जरूरत है, आम व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम नहीं है, इतनी अच्छी योजना, चिरंजीवी योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी लेकर आये हैं और इसकी सीमा 10 लाख रुपये की है, लेकिन पैरेलल उसको मजबूत करके ग्रेजुअली हमें इस इंश्योरेंस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के वहां से विड्रा करने की जरूरत है ताकि हमें एक मजबूत, सक्षम, सुविधाजनक, गुणवत्ता भरा हैल्थ केयर जनता को दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात हमारे घोषणा पत्र में भी थी। मैं जब पिछली बार स्वास्थ्य की चर्चा में भाग ले रही थी तो मैंने एक बात यह कही थी कि जो भी आता है, सरकारी अस्पताल में लोग ही कितने आते हैं, विश्वास ही कितना है हमारा आज उस पर लेकिन जो भी हो सरकारी अस्पताल में आते हैं, आप उन सबका इलाज मुफ्त कीजिये। मैं माननीय

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ओपीडी और आईपीडी कैशलेस कर दी, फ्री कर दी, यह बहुत ही बड़ा कदम है। जैसे मैं कह रही थी tertiary layer और हास्पिटल्स में तो हम जाते हैं, लेकिन आप सबको कितनी बार हमें एक डाक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी, खांसी, जुकाम हो गयी, कोई दवाई हो गयी, तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम हमने उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, हम अकाउंटेबिलिटी एक्ट लेकर आ रहे हैं, but Accountability Act is not same as Right to Health Act. मुझे लगता है कि हमें राइट टू हैल्थ एक्ट भी लाना पड़ेगा। I don't know why is the government so reluctant. किस बात की घबराहट है, हमारे पास हैल्थ वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मुझे पता था कि उस दिन के बाद समय नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आलरेडी एक्जाम्पल सैट कर चुका है। आरटीआई, नरेगा, नि:शुल्क दवा, ओल्ड पेंशन स्कीम, कृषि बजट, जेंडर बजट, हम इतनी योजनाएं लेकर आये हैं, इतने ऐतिहासिक काम हम हैल्थ में कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना का पैकेज बढ़ा रहे हैं, ओपीडी, आईपीडी फ्री कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी लाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। हमें ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी फार्म करना चाहिए ताकि कोई शिकायत करे तो उसका निस्तारण 7 दिन में हो।

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर्स और नर्सेज की जो कमी है, उसमें मुझे लगता है कि इसके अन्दर भी आपको रेशनल डिस्ट्रिब्यूशन करने की जरूरत है। एक ही जगह पर 10 डाक्टर लगे हैं, 5 नर्सें लगी हैं और दूर के गांव में 1 नर्स ही बैठी है, तो मुझे लगता है कि यदि हम अच्छी गुणवत्ता भरी स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह देना चाहते हैं तो हमको रेशनल डिस्ट्रिब्यूशन करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी जो बेसिक सर्विसेज हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र आधे घण्टे की पैदल दूरी पर होना चाहिए, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा है। पीएचसी दस किलोमीटर पर, emergency healthcare, one hour of motorized distance. जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, जब हार्ट अटैक या एक्सीडेंट हो जाता है, स्पेशलाइज्ड केयर कम से कम सौ किलोमीटर पर होनी चाहिए, ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया आफ फैसिलिटी होना चाहिए।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मानननीय सभापति महोदय, रैफरल सिस्टम बहुत अनिवार्य है। आप देखेंगे कि एम्स से भी 60 प्रतिशत से ज्यादा फुटफाल हमारा ओपीडी एसएमएस में होता है, सबसे हाइएस्ट क्योंकि आसपास के लोग भी यहां पर आते हैं। एक हमारी वन पोइंट सर्विस होनी चाहिए कि गांव में आपको खांसी जुकाम हो गयी तो आप अपने सब-सेंटर या पीएचसी पर दिखायेंगे। आप tertiary layer or secondary layer पर जाने वाले पेशेंट हैं तो वो आपको रेफर करेंगे। यहां पर सारी भीड़ आ जाती है, हमने स्पेशलाइज्ड डाक्टर्स यहां बैठा रखे हैं और वो खांसी जुकाम के पेशेंट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना में भी पेशेंट एक प्राइवेट हास्पिटल में जाता है और उसको पता लगता है कि यह पैकेज उसके पास नहीं है, वो प्राइवेट हास्पिटल उसे नहीं बताता कि आपका नी रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, आप दूसरी जगह कहां जाकर करेंगे तो मुझे लगता है कि वन पोइंट सर्विस रखिये जो आपको यह बताये कि आप यहां रैफर हो रहे हैं, और यहां रेफर होने के कारण आप यहां पर जायेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, पासबुक भी रखनी चाहिए चिरंजीवी योजना में, अगर आपके दस लाख हैं तो उसमें से कितने खर्च हो गये, कितने रहे हैं, वो भी देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय आप तो बहुत ही अनुभवी और बहुत बढिया मंत्री हैं, आपसे सबको उम्मीदें हैं, पिछले कार्यकाल में कोआपरेटिव में आपने ऐतिहासिक फैसले लिए थे, जिनकी आज पूरे देश में चर्चा है, चाहे वो ब्याज मुक्त ऋण की बात हो जो आपके टाइम पर लागू हुई थी। एक इनोवेटिव एप फैसिलिटी लोकेटर आप लेकर आएं जो गूगल मैप पर जैसे पेट्रोल पम्प वगैरह सब बताता है, तो आपके उन इम्पैनल्ड को बतायें कि वो यहां पर है, इसमें ये-ये सेवाएं हैं ताकि मरीजों को भटकना नहीं पड़े।

श्री सभापति: थैंक्स।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट मिनट।

माननीय सभापति महोदय, फ्री मेडिसिन का दायरा बढ़ाइये, जांच का दायरा बढ़ाइये। डाक्टर और नर्सेज की, स्पेशली डाक्टर्स और फार्मा कम्पनीज का जो नेक्सस है, उसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेगें, उस पर हमें

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

फोकस करना पड़ेगा और जो प्रैक्टिस करते हैं डाक्टर्स, वो कंसल्टेशन फीस ही नहीं कमाते हैं, वो जो दवाइयां लिखते हैं उनसे कमाते हैं, तो आप यह करिये कि अगर वो डाक्टर आपकी मुफ्त दवा योजना उस पर्ची में लिखे, जेनरिक नाम लिखे, दूसरी दवाइयां न लिखे। इस पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंस पोइंट है, हमने, we were the first one, और बहुत ही प्रभावी एक्ट माननीय मुख्य मंत्री महोदय पिछली गवर्नमेंट में लाये थे, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 लेकर आये थे। जो हैल्थ इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट और स्टेंडर्डाइजेशन करता है। हम फर्स्ट स्टेट थे उसको एडोप्ट करने वाले लेकिन उसके अभी भी रूल्स नहीं बने, और वह लागू नहीं हुआ। ये प्राइवेट लॉबी इसको लागू नहीं करने देना चाहती। People should get exploited that is what they want. मुझे लगता है कि, माननीय मंत्री महोदय, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिये। गुणवत्ता के चैक लगेंगे, प्रभावी कदम होगा, अननेसेसरी चीजें नहीं होंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 और 26 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीधी-सीधी बात अपने विधान सभा क्षेत्र की करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 सीएचसी हैं, जिनमें से टिब्बी सीएचसी में 12 डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वहां कार्यरत सिर्फ 5 ही हैं। संगरिया में 13 में से सिर्फ 4 ही स्वीकृत हैं। ढब्बा में जो सीएचसी है, वह पिछले साल खुली थी, उसमें एक ही डाक्टर है। उसके अलावा हमारे हास्पिटल्स का नाम रेफर हास्पिटल रख दिया गया है। कोई भी छोटा-मोटा एक्सीडेंट होता है तो उसे सीधा हनुमानगढ़ रेफर करते हैं। मेरे जिले में जो हास्पिटल है, उसके ऊपर बहुत भार पड़ता है। संगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर से जो मरीज रेफर होकर आते हैं, उसके कारण भी काफी भार हास्पिटल पर पड़ता है। मैं 3 साल से लगातार मांग करता आ रहा हूं कि मेरे संगरिया और टिब्बी सीएचसी में डाक्टर लगाये जाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टोटल 8 पीएचसीज हैं, 5 टिब्बी तहसील में हैं और 3 संगरिया में हैं। पांच पीएचसीज में डाक्टर नहीं हैं, सिर्फ नर्स बैठती है वहां या कम्पाउंडर बैठता है। मेरी मांग है उन पीएचसीज में डाक्टर्स लगाये जाएं ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

(श्री गुरदीप सिंह)

हमारे जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हैं पहले के, उनकी बिल्डिंग्स बड़ी जर्जर हालत में हैं। तीस-तीस साल पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आधी गिर चुकी हैं, कहीं छत खराब हो रही है। कई जगह तो नर्सें लोगों के घरों या पंचायत घर में बैठती हैं। अत: मैं उन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में मांग करता हूं कि उनके भवनों की मरम्मत करायी जाये अथवा नये बनाये जाएं। मेरे दोनों जो हास्पिटल्स हैं, संगरिया और टिब्बी, वहां एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। वह भी हमें दी जाये।

मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेडिकेटेड नशा, चिट्टा, स्मैक काफी मात्रा में सप्लाई होता है। हर दिन पुलिस के केस बनते हैं। वहां हमारे कुछ बच्चे नशा छोड़ना भी चाहते हैं पर डाक्टर नहीं होने के कारण, मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे जिले में एक नशा मुक्ति केन्द्र खोला जाये ताकि जो बच्चे नशा छोड़ना चाहते हैं, जिनके घर वाले उनका नशा छुड़वाना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके। गरीब बच्चे हैं वे। जो प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्र हैं, वहां देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे जिले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक नशा मुक्ति केन्द्र खोला जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मैं कुछ नयी मांगें रखता हूं। मेरे पीएचसी के उप-स्वास्थ्य केन्द्र शाहपीनी, उप-स्वास्थ्य केन्द्र खराखेड़ा, उप-स्वास्थ्य केन्द्र सिलवाड़ा और उप-स्वास्थ्य केन्द्र पीकमड़िया को पीएचसी का दर्जा दिया जाये।

हर गांव में मेडिकल की पांच-पांच, छह-छह दुकानें खुल चुकी हैं। लाइसेंस उन्होंने ले रखा है, पर वह सिर्फ एक बहाना है, उन दुकानों पर मेडिकेटेड नशे की गोलियां, कैप्सूल बिकते हैं। हमारे गांव के बच्चे नशा कर-करके खराब हो रहे हैं। मेरी यह सरकार से मांग है कि जो वहां ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, चिकित्सा के अधिकारी हैं, उनसे लगातार जांच करायी जाये और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, उनकी दुकानों के लाइसेंस खारिज किये जाएं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

मैं मंत्री जी से दुबारा मांग करूंगा कि मेरे दोनों हास्पिटल्स में डाक्टर्स लगाये जाएं और जो नयी पीएचसी है, वहां भी डाक्टर्स लगाये जाएं ताकि उसका जो नाम रेफर हास्पिटल है, वह हट सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आपका जो समय है, वह सम्बन्धित पार्टी के सचेतक के द्वारा आसन को दिया जाता है। आसन के नो डाउट अपने डिस्क्रिशंस भी हैं, लेकिन उसी के अनुसार से आज यह तय किया गया है कि कोई भी सदस्य मैक्सिमम सात मिनट ही बोलेगा ताकि सभी लोगों को मौका मिल जाये।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (अनुपस्थित)। श्रीमती गायत्री देवी।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 तथा 13 पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवर राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी। इसी प्रकार चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसमें पांच लाख रुपये तक की राशि कवर की है। मैं यह मानती हूं कि इन योजनाओं से मुझे यह विश्वास हो रहा है कि मुख्य मंत्री जी की भावना राजस्थान को राइट टू हैल्थ तथा नीरोगी राजस्थान बनाने की है।

मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी अधिकारियों को नियुक्त कर "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान को गति प्रदान की है। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में ही कोरोना जैसी महामारी में भी चिकित्सा विभाग ने राजस्थानवासियों को काफी सहायता दी तथा उनकी हरसम्भव मदद की, जिसमें भीलवाड़ा जिला पूरे देश में मॉडल रहा। इसी कोरोना जैसी महामारी से दिवंगत विधायक कैलाश चन्द्र जी त्रिवेदी सहित कई माननीय सदस्य बीमार होकर प्रभुलीन हो गये। अब हमें मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को नीरोगी बनाने में हरसम्भव मदद के लिए तत्पर रहना होगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि गंगापुर जो कि नेशनल हाईवे पर स्थित है, वहां से भीलवाड़ा 50 तथा उदयपुर 80 किलोमीटर पड़ता है। गंगापुर बीच में है। गंगापुर से करेड़ा-आसीन्द का राजमार्ग भी उस रोड पर है। अत: गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल घोषित करें, जिससे दुर्घटना में घायलों को तत्काल उपचार मिल सके।

दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर उप-खण्ड स्तर का अस्पताल है, जिसमें बैड्स की संख्या 100 की जाये और आईसीयू वार्ड प्रारम्भ कराया जाये। बरडोद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है। यहां की जनसंख्या लगभग आठ-नौ हजार है और आस-पास के नौ गांवों में कोई अस्पताल नहीं होने से मरीजों को जिला

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

मुख्यालय जाना पड़ता है। इस उप-स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर का भवन निर्मित करने के लिए भामाशाह तैयार हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि बरडोद उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें।

इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कारोई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा कराएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोकुन्दा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरिया में भवन नहीं होने से डाक्टर्स सहित मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रायपुर ब्लाक के मासिंगपुरा, मोकुन्दा एवं सहाड़ा के काली मंगरी, डेलाणा, पाबूनगर, महेन्द्रगढ़ में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाएं। रायपुर के नाथडियावास सांगवा, सहाड़ा के माझावास एवं ढोसर उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा सहाड़ा के पोटला में होम्योपैथिक अस्पताल घोषित कराएं।

वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टाफ के काफी पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण मरीजों को दिक्कत हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि शीघ्र से शीघ्र उन्हें भरवाकर स्वास्थ्य केन्द्रों का सुचारु रूप से संचालन करवाकर नीरोगी राजस्थान की ओर ले जाएं। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे रायपुर स्वास्थ्य केन्द्र में गायनिक डाक्टर को लगाया जाये ताकि महिलाओं को सुचारु रूप से सुविधा मिल सके। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष बावरी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26- चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं सफाई तथा मांग संख्या 13 - आबकारी पर विचार व्यक्त करने का समय दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राज्य में कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार खुद के संसाधन, केन्द्रीय संसाधन एवं एनजीओ के मार्फत उक्त सेवाओं में पिछले दो वर्षों से कार्य करने के उपरान्त भी पिछड़ रही है।

समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नीति आयोग की 19 राज्यों की ताजा सूची में हम सोलहवें स्थान पर हैं। देश में कोरोना वैश्विक महामारी की स्थिति बड़ी भयानक थी। ऑक्सीजन की कमी भी रही है। मैंने मेरे क्षेत्र में सीएचसी अनूपगढ़ और रावला में ऑक्सीजन प्लांट के लिए विधायक कोष से

(श्रीमती संतोष)

बजट दिया था। सीएचसी रावला में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गयी, लेकिन आज तक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि सीएचसी, रावला की बिल्डिंग के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए चार वर्ष हो गये हैं लेकिन आज तक सीएचसी, रावला की बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया है और रावला सीएचसी के पास पट्टा नहीं होने का कारण बताकर कार्य को रोक रखा है। मैं मांग करती हूं कि सीएचसी, रावला को सरकार पट्टा जारी करवाये ताकि तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकृत बजट से नयी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा सके।

मेरे क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 365RD जिला मुख्यालय से 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किसी भी मरीज को जब रेफर किया जाता है तो बीच में ही वे दम तोड़ देते हैं और कई ऐसे मामले हो चुके हैं। मैं मांग करती हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 365RD, रामसिंहपुर, नारावाली को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये व सब-सेंटर 22 RJD, 2KM डबर को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये।

मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर अनूपगढ़ के लिए मैंने काफी प्रयास किये लेकिन अभी तक नहीं खुला है। अनूपगढ़ में ट्रोमा सेंटर की मांग के जवाब में मुझे उत्तर दिया गया कि 100 किलोमीटर के दायरे में यह नहीं आता है। मैं सरकार से पूर्व में भी मांग कर चुकी हूं और आज पुन: मैं मांग करती हूं कि अगर अनूपगढ़ 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं आता है तो मेरे क्षेत्र का जो घड़साना है वह 100 किलोमीटर के दायरे में आता है, वहां ट्रोमा सेंटर खोला जाये। मेरे क्षेत्र से भारतमाला रोड गुजरती है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरे क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आदर्श सीएचसी बनाने के बाद इन अस्पतालों में जांच सुविधाएं एवं डाक्टर की नियुक्ति हो जायेगी पर जब तक नहीं होगी तब तक ये आदर्श सीएचसी केवल बिल्डिंग के आधार पर ही रहेगी। मैं मांग करती हूं कि आदर्श सीएचसी में एमआरई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी मशीन और सबसे महत्वपूर्ण स्टाफ होगा तभी आदर्श सीएचसी का कोई मतलब होगा। मैंने आदर्श सीएचसी अनूपगढ़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है और मांग

(श्रीमती संतोष)

करती हूं कि अतिशीघ्र क्रमोन्नत किया जाये और घड़साना में ट्रोमा सेंटर खोला जाये।

कोरोना वैश्विक महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए कोविड सहायक सरकार द्वारा संविदा पर लगाये गये थे लेकिन इनको अभी हटाया जा रहा है। आपातकालीन स्थिति में इन्होंने अपनी जान की भी परवाह किये बिना नि:स्वार्थ सेवा भाव से कार्य किया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि इनको स्थायी किया जाये ताकि इनका भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के समय सरकार ने घोषणाएं की थीं कि मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देंगे। राशन डीलर की मौत होने पर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन मेरे बीकानेर सम्भाग में राशन होल्डर के काफी मामले लम्बित हैं, जिनमें मेरे क्षेत्र के राजकुमार धूड़िया पुत्र श्री शंकर लाल वार्ड नं. 18, अनूपगढ़ डिपो, राजस्थान आटोमोबाइल डिपो की मौत 24 अगस्त, 2020 को; बालकृष्ण शर्मा, रावलामंडी की मौत 28 अप्रैल को और रघुवीर सिंह पुत्र मनफूल राम, पंचायत 2KWM, तहसील खाजूवाला की मौत 14 अप्रैल को हुई थी। इनकी फाइलें जिला कलेक्टर कार्यालय में आब्जेक्शन लगाकर रखी हुई हैं और ऐसे लगता है कि समाधान नहीं होने वाला है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि अतिशीघ्र पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिले में दुर्गम और दूरस्थ स्थानों पर डिलीवरी पाइंट नहीं होने से प्रसूताओं की हर वर्ष बच्चे को जन्म देने या प्रसव के दौरान उनकी मौत हो रही है। प्रसूताओं की डिलीवरी के लिए सीएचसी, पीएचसी में स्त्री रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, प्रदेश में एनआरएचएम, एनजीओ के द्वारा तथा संविदा पर कार्य करने वाले जीएनएम, एएनएम, कम्प्यूटर आपरेटर की पीड़ा की ओर भी सरकार ध्यान दे। लम्बे समय से अपनी सेवाएं दे रहे ऐसे कार्मिकों को अतिशीघ्र बोनस अंक देकर स्थायी किया जाये और इनका मानदेय भी बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): इतने कम वेतन में आज के समय में काम करना बहुत मुश्किल है। होम्योपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक जो

(श्रीमती संतोष)

संविदा पर लगा रखे हैं, उनकी भर्ती निकालकर उनको स्थायी किया जाये। फिजियोथेरेपिस्ट, जो डिग्री लेकर लम्बे समय से बेरोजगार बैठे हैं, उनको भी रोजगार देकर लाभ दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय से फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं की गयी है और हालात ये हैं कि जिन्होंने डी-फार्मेसी या बी-फार्मा की डिग्री ले रखी है वे रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी काउंसिल के चक्कर लगा रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल का ऑनलाइन पोर्टल एक वर्ष से बन्द है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि ऑनलाइन पोर्टल खोला जाये ताकि जो फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं, उनको लाभ मिल सके, उनको रोजगार मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरे क्षेत्र अनूपगढ़ व घड़साना में ब्लड बैंक खोला जाये क्योंकि मेरा क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मरीज रेफर किये जाते हैं और ब्लड की कमी के कारण कई महिलाएं डिलीवरी के समय दम तोड़ देती हैं।

माननीय सभापति महोदय, हास्पिटल में सफाई व्यवस्था सही नहीं है, जगह-जगह पानी लीक होता है। मेरे अनूपगढ़ शहर का जो हास्पिटल है उसका भवन बहुत ही जर्जर अवस्था में है। अभी पिछले कुछ दिन पहले उसकी बिल्डिंग का मलबा गिर गया था और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है....

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि हास्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये।

सभापति महोदय, एक छोटी सी बात मैं और रखना चाहूंगी कि एनजीओ के माध्यम से संविदाकर्मी, जो कम्प्यूटर आपरेटर लगे हुए हैं, उसमें मात्र डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने के बाद उस महिलाकर्मी को वहां से हटा दिया जाता है और वह जब वहां वापस पहुंचती है तो उसको यह कहा जाता है कि किसी सिफारिश के कारण अन्य को रख लिया गया है तो डिलीवरी के लिए अगर छुट्टी लेते हैं तो माननीय सभापति महोदय, इस ओर भी सरकार ध्यान दे, उन कार्मिकों को भी राहत दे। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 26 और मांग संख्या 13 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

सबसे पहले मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी

(श्री गणेश घोघरा)

को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। दुर्घटना योजना को 5 लाख किया। नि:शुल्क दवाइयां, कई जगह पीएचसी, कई जगह सीएचसी दीं और कोरोना काल में इतना बेहतरीन प्रबन्ध राजस्थान की सरकार ने किया, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने किया, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। टीएसपी क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र है। डूंगरपुर में एक ही बड़ा सामान्य चिकित्सालय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में कई डाक्टर अच्छे भी हैं, कोई स्टाफ अच्छा भी है, कोरोना में अच्छा काम भी किया है, लेकिन कई डाक्टर्स हास्पिटल में खाली हाजिरी लगाने आते हैं। उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है और सरकारी दवा का वहां उपयोग करते हैं और पर्ची हास्पिटल में कोई उनके मिलने आता है उनके माध्यम से प्राइवेट क्लीनिक पर बुलाते हैं तथा गरीबों को लूटा जा रहा है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इसकी आप जांच करवायें और जो दोषी डाक्टर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। इसके अलावा कोरोना में जिसने अच्छा काम किया है, भले ही वह डाक्टर हो, नर्स हो, वार्ड ब्वाय हो तो उनको सम्मानित भी किया जाये।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बार हास्पिटल में गया तो देखा कि बाहर जो मेडिकल वाले होते हैं उनके पास डाक्टर्स की सेटिंग होती है और वे ऐसी दवाई लिखते हैं कि वह दवाई वहां नहीं मिलती और उसको पर्ची लेकर बाहर मेडिकल की दुकान पर जाना पड़ता है। कई बार वहां 7-7 दिन तक मशीनें खराब हो जाती हैं। सीटी स्कैन की मशीन खराब, एक्स-रे मशीन खराब, दूसरी जांचों की खराब और ऐसे करके सरकार की योजनाओं को इन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा फेल किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप इसकी सही जांच करें और वास्तव में जो गरीब है उसको फायदा मिले। इस चिरंजीवी योजना से हमारे आदिवासी, ट्राइबल बैल्ट में काफी फायदा हुआ है लेकिन इस तरीके से जो अधिकारी बैठे हुए हैं वे इस योजना को, इस लाभ को गरीब तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आपके समय में स्टाफ रहता ही नहीं था। मरीज दूर से जाता है कि डाक्टर देखेंगे, स्टाफ मिलेगा पर रात को हास्पिटल में कोई स्टाफ भी नहीं मिलता है, डाक्टर भी नहीं मिलते हैं और मरीज पूरी रात परेशान हो

(श्री गणेश घोघरा)

जाता है। कई बार रात को भी घर बुलाते हैं क्योंकि उनको फीस चाहिए, दो-दो हजार, तीन-तीन हजार रुपये फीस चाहिए तब तो उसका हाथ पकड़ेंगे। ऐसी स्थिति है, माननीय सभापति जी। तो ऐसे जो अधिकारी, कर्मचारी, डाक्टर्स, जो भी हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

कई बार छोटी-मोटी बीमारी होती है उसके बाद भी कहते हैं कि आपको रेफर करते हैं, उदयपुर जाओ, अहमदाबाद जाओ, हिम्मतनगर जाओ। वह गरीब आदमी कहां जायेगा? जो एमएलए लैड से दो-दो एम्बुलेंस दी थीं, वे मरीजों के लिए नहीं लगाकर दवाई सप्लाई करने के लिए लगाते हैं। हमने जो एमएलए लैड से एम्बुलेंस दीं, बिछीवाड़ा डूंगरपुर में उसका उपयोग कर रहे हैं और बिल बना रहे हैं, फर्जी बिल बनाकर पैसा उठा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय जी, हमारे टीएसपी में कई झोलाछाप डाक्टर क्लीनिक खोलकर बैठे हुए हैं। वहां सीएमएचओ उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वे डिग्री कहां से लाये? गांवों में गरीबों को लूट रहे हैं, कैसी-कैसी दवाइयां चढ़ा रहे हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो गयीं, कई लोगों की मृत्यु भी हो गयी और वे झोला पकड़कर भाग जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो झोलाछाप डाक्टर हैं उनके क्लीनिक बन्द कराये जाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करिये, प्लीज।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, 7 मिनट नहीं हुए हैं। मुझे 7 मिनट दिये हैं।

श्री सभापति: 5 मिनट कुछ सैकण्ड हो गयी है।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, 5 मिनट नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: घड़ी हाउस की ही काम करेगी।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पाल देवल सीएचसी का भवन निर्माण नहीं हुआ और मझोला में पीएचसी का भवन निर्माण भी नहीं हुआ है। मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पाल देवल में

(श्री गणेश घोघरा)

सीएचसी और मझोला में पीएचसी का भवन निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाय।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, बिछीवाड़ा सीएचसी हाईवे पर है, आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि वहां ट्रोमा सेन्टर खोला जाय और मोर्चरी में 40-45 किलोमीटर सामान्य अस्पताल से आना पड़ता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पीएम कराने के लिए वहां मोर्चरी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसकी मरम्मत करायी जाय। पीएम बिछीवाड़ा अस्पताल में ही हो, मैं मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं।

इसके साथ ही संविदा पर प्लेसमेन्ट एजेंसी से जो कार्मिक लगे हुए हैं तो प्लेसमेन्ट एजेंसी का ठेकेदार उनके साथ-साथ मनमानी करता है, दो-दो, तीन-तीन महीनों का वेतन नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आरएमआरएस में समायोजित करने की कृपा करें, प्लेसमेन्ट एजेंसी से अधिकृत नहीं करें, ताकि कार्मिकों के अधिकारों का हनन नहीं हो।

इसी के साथ, माननीय मंत्री जी, मांग करूंगा, जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण एएनएम नर्सिंग भर्ती, 2018 के 1041 अभ्यर्थियों के आदेश न्यायालय से जारी हो गये हैं, तो मैं मांग करता हूं कि न्यायालय से आदेश जारी हो गये हैं तो उनको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाय। इसी के साथ जीएनएम, एएनएम भर्ती, 2013 के अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी नियुक्ति देने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, होम्योपैथिक चिकित्सकों के 656 नवीन पद सृजित कर संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित किये जाने की पुरजोर मांग करता हूं।

सभापति महोदय जी, मैं आबकारी के बारे में केवल 2 मिनट कहूंगा, क्योंकि टीएसपी एरिये से आते हैं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, हमको बोलने दिया जाय, हम आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। हमको यहां पर ही नहीं बोलने दिया जायेगा तो हमारे अधिकारों का हनन तो यहीं हो रहा है।

श्री सभापति: बोलिए आप।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हमको बोलने दें, पहली बार तो यहां पर बोलना सीखे हैं। हमें बोलने दें, सीखने दें, हम पहली बार आये हैं, हमको सीखने दें।

माननीय सभापति महोदय जी, आपसे कहना चाहता हूं कि आबकारी अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्होंने असत्य मुक़दमों में हमारे कई आदिवासियों को फंसा रखा है। भले एक-दो बोतल मिलती है, उनके दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह बोतलों के मुक़दमे लगाये हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाय। आदिवासी की संस्कृति, परम्परा, कल्चर, हमारा वार है, त्योहार है, हमारा ढूंढ उत्सव है, उसमें हमारे देशी दारू चलती है। यह संस्कृति, परम्परा, हमारे पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों को भी हम धार चढ़ाते हैं, उनको मानते हैं, पूजते हैं। हमारे आदिवासी टीएसपी एरिये में 12 बोतल देशी जो महुआ होता है, उसका रस, ज्यूस होता है, उसकी 12 बोतल रखने की हमें छूट दी जाय। भले आबकारी वाले अधिकारी आयें, चाहे पुलिस वाले आयें, हमारे आदिवासियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया जाय। यह मैं सरकार से मांग करता हूं, यह मंत्री जी से मांग करता हूं और हमारे सीएम. साहब से भी मांग करता हूं।

हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल रखी हैं, उनको बन्द किया जाय। हमको गरीब बनाने के लिए अंग्रेजी शराब की दुकानें गली-गली में खोल रखी हैं और अंग्रेजी शराब की दुकानें बाहर से आकर उनके नाम अलाटमेन्ट हो रही हैं। अगर अंग्रेजी शराब की दुकानें वहां पर लगानी हैं और वहां पर खोलनी हैं तो वहां के एसटी को भी आरक्षित दुकानें मिलनी चाहिये। अगर वास्तव में अंग्रेजी शराब की दुकानें वहां पर लगानी हैं, अगर सरकार की आय होती है तो सबके सब बाहर से आकर हमारी जनता को लूटते हैं। एक-एक हजार, दो-दो हजार की दारू हम कहां से, आदिवासी समाज कहां से खरीद सकता है? हमारी जो देशी सस्ती है, उसको बन्द करना चाहते हो और अंग्रेजी की दो-दो हजार की बोतल हमको पिलाना चाहते हो। हम आदिवासी तो पहले से गरीब हैं, और गरीब करना चाहते हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि महुआ दारू की 12 बोतल रखने की हमको छूट दी जाय। हमारे शादी हो, मौत-मरण हो, एक-दूसरे को हम देते हैं। जैसे मेरे भाई के बच्चे की शादी है तो मुझे पांच बोतल देनी पड़ती है। अगर मेरे अंकल के लड़के की शादी है तो आमने-सामने हम एक-दूसरे को आदान-प्रदान करते हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा रिवाज है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे असत्य मुक़दमे जो पुलिस ने, आबकारी ने, उनको वापस

(श्री गणेश घोघरा)

लिया जाय। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत। श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि सदन में मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया। आजादी के इतने सालों बाद आज भी जनता को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। मैं सरकार की चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के मगरा क्षेत्र से करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, सुनिये-सुनिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): महोदय जी, इस क्षेत्र में 50 किलोमीटर दूर तक चिकित्सा सुविधा के नाम पर सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। यहां सड़कें तक उपलब्ध नहीं हैं। यहां लोग गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लेकर नदी-नाले पार करके पहुंचते हैं 10-20 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केन्द्रों पर, वहां डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है।

महोदय जी, खोडिया, गुडा बीजा, गुडा कलां, हरियामाली, गुडा रामसिंह आदि ग्राम पंचायतों के लोग, जो दूर-दराज मगरा क्षेत्र में रहते हैं, इनको 60-70 किलोमीटर दूर सोजत शहर चिकित्सालय में आना पड़ता है यहां तक आते-आते कितनी माताएं काल का ग्रास बन जाती हैं। महोदय जी, छोटे-छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूं कि आपने मगरा क्षेत्र के लोगों के लिए सड़क और पानी तक की सुविधा नहीं की। इस मगरा क्षेत्र की गुडा कलां ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक उप-चिकित्सालय यदि खोला जाय तो 50 हजार से अधिक की जनता, जो कि पहाड़ों में निवास करती है, उनको छोटी-छोटी चिकित्सा जांचों, दवाइयों एवं गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

महोदय जी, दूसरी ओर रायपुर चिकित्सालय जहां पर 26 से अधिक ग्राम पंचायतों के लोग चिकित्सा सुविधा लेने वहां आते हैं। महोदय जी, रायपुर चिकित्सालय के डाक्टरों ने एक परिपाटी बना रखी है कि जांच करने के लिए बाहर जाओ, अन्यथा पाली या ब्यावर के लिए रेफर कर देते हैं। यहां पर चिकित्सा जांच की मशीनें खराब पड़ी हैं। गरीब लोग जैसे-तैसे धक्के खाकर अस्पताल पहुंचते हैं वहां पर उनको जांच कराने के लिए अन्यत्र निजी

(श्रीमती शोभा चौहान)

अस्पतालों में जाना पड़ता है जिससे गरीब लोगों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है, जबकि रायपुर चिकित्सालय शहरी क्षेत्र में गिना जाता है।

महोदय जी, मैंने सम्बन्धित डाक्टर व ब्लाक चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कई बार माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा, लेकिन इस बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि लोग रोज दुर्घटना में घायल हो रहे हैं, मृत्यु शय्या को प्राप्त होते हैं। सोजत राजकीय चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर हेतु पड़ी करोड़ों रुपये की मशीनें धूल फांक रही हैं। अभी तक ट्रोमा सेन्टर, सोजत का अता-पता नहीं है, जो कि बजट घोषणा है।

सोजत अस्पताल का ढर्रा भी मैंने विधायक कोष से कोरोनाकाल में 1 करोड़ 25 लाख रुपये देकर सुधारने का प्रयास किया है, सड़कें डींगें हांक रही हैं। सरकार ने लोगों की चिकित्सा हेतु इतनी राशि की है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय निजी अस्पतालों के लिए आपने चान्दी कर दी है। अभी भी सरकार में इंसानियत है तो सोजत अस्पताल में रिक्त पदों को भरा जाय। उप जिला अस्पताल में गायनी डाक्टर नहीं है, इसको भी प्राथमिकता से भरा जाय। शर्म की बात तो यह है कि इतने बड़े अस्पताल का यह हाल है, पाली जिले का दूसरा बड़ा अस्पताल है।

महोदय जी, विगत दिनों की घटना आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि एक घटना में घायल व्यक्ति को सोजत चिकित्सालय में लेकर आते हैं। उक्त व्यक्ति को खून की आवश्यकता है। यहां पर ब्लड बैंक में मना कर देते हैं कि ब्लड के बदले ब्लड देना पड़ेगा वरना ब्लड नहीं मिलेगा। चूंकि घायल व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति नहीं था, उस तड़पते व्यक्ति को जोधपुर रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गयी। बताइये इसका जिम्मेदार कौन है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवलीकलां एवं ऐसे कई दूरदराज के गांवों में चिकित्सालय भवन ऐसे बने हुए हैं जहां क्वार्टर नाकारा हैं और नाकारा घोषित होने के बावजूद वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे ही सीएचसी पर डाक्टर्स रहते नहीं हैं इसलिए गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन जर्जर भवनों की मरम्मत हेतु जिला स्तर पर सरकार को अनेकों बार अवगत कराया है लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। सोजत के पश्चिम क्षेत्र में राजोला, चौपड़ा,

(श्रीमती शोभा चौहान)

चाड़वास, रूपावास, सरदारसमन्द, सुरायता, शिवपुरा, घाघूड़ा, झूपेला, धाकड़ी, धीनावास, खारियानीम, मेव एवं बेबड़ावास क्षेत्र की पचास किलोमीटर के दायरे में एक भी सीएचसी नहीं है जबकि विगत तीन वर्षों से मैं लगातार मांग उठाती रही हूं। यहां तक कि बिलावास, बेराखंडी बगड़ी के भामाशाहों के सहयोग से हमने भवन बनाये हैं ताकि वहां पर सीएचसी खोली जाये, लेकिन इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पश्चिमी क्षेत्र की यदि सुध लेनी हो तो आप पाली जिले से सम्बन्धित अधिकारी से चर्चा कर लीजिये। चिकित्सा सुविधा के नाम पर सरदर्द की टैबलेट तक नहीं है।

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): यहां पर जिला चिकित्सालय में प्रतीक्षालय भी नहीं है। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात भर छत के नीचे ही गुजारनी पड़ती है। जरा सोचिये उन पर क्या गुजरती होगी, जिस परिवार का व्यक्ति अस्पताल में इलाज करवा रहा है उसके परिजनों को बैठने की सुविधा तक नहीं है। पता नहीं किन राजनीतिक कारणों की वजह से सोजत में ट्रोमा सेन्टर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ट्रोमा सेन्टर के निर्माण से आम जनता को लाभ मिलेगा, इसे दलगत राजनीति की भेंट मत चढ़ाओ। यदि सोजत में समय पर ट्रोमा सेन्टर नहीं खोला गया तो मुझे मेरे क्षेत्र की जनता के साथ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र आन्दोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां (अनुपस्थित)। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे चिकित्सकों, नर्सिंगकर्मियों, आशा सहयोगिनियों और समस्त कोरोना वारियर्स का अभिवादन करती हूं जिन्होंने इस विपत्ति काल में संयम, धैर्य और हिम्मत से अपना फर्ज निभाया और जी जान से लगातार मरीजों का उपचार जारी रखा। कई घंटों तक इन्होंने पीपीई किट भी पहना। सभापति महोदय, कोविड वार्ड में पीपीपी किट पहनकर इलाज करना आग की लपटों में काम करने के बराबर था। कई दिनों तक ये कोरोना वारियर्स अपने घर भी नहीं गये थे। इन सभी कोरोना वारियर्स को मैं सलाम करती हूं। साथ ही जहां लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घरों में सुरक्षित थे वहीं कोरोना के फ्रंटलाइन वारियर्स हर दिन अपनी जान हथेली पर रख

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

कर कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। कुछ ने तो इसमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए थे, उन सबको मैं नमन करती हूं। साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भामाशाहों को भी हृदय के अंत:करण से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, उन्होंने जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी तो इस युद्ध में आगे आकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा अन्य चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराकर मरीजों की सांसों में जान फूंक दी थी।

सभापति महोदय, पूरा विश्व दो वर्ष से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है जिसमें सबसे बड़ा लक्ष्य मानव की जान बचाने का है, जिसे हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रभावी तौर से निभाया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जान बचाने के उद्देश्य से किए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना तो स्वयं प्रधान मंत्री जी ने भी की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां बिना किसी भेदभाव के माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा गरीब तबके के हर व्यक्ति तक सहायता पहुंचायी गयी है। हर घर तक राशन भी पहुंचाया गया है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत के लिए दो पंक्ति में अभिवादन ज्ञापित करना चाहती हूं, 'समाज की आवाज को मसीहा बनकर उठाते हैं, विजय पथ के दृढ़ निश्चय सफर तय कर जाते हैं। करोड़ों के हृदय में यों ही बस जाते हैं, इसीलिए अशोक गहलोत जन नायक कहलाते हैं, जन नायक कहलाते हैं।'

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में अनेक उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही नेशनल हाईवे 76 पर एक्सीडेंटल केस बहुत ज्यादा थे। घायलों को चित्तौड़ या उदयपुर ले जाने तक जान की हानि होने की आशंका बनी रहती थी जिस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रसंज्ञान लिया और मेनार में ट्रोमा सेन्टर खोला, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूं। उन्होंने बजट भाषण के जवाब में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भम्भोरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर बजट में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर परिवार वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ ही उदयपुर में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अतिरिक्त सीएमएचओ कार्यालय खोलने की घोषणा की है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूं।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में चिकित्सा एवं

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं सभी तक सुचारु रूप से पहुंच सके, उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि जगत, लबानिया, करणपुर और आकोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही मालकीटूस के टाक में, सीआर के मांडकला में, कुंडई के गोटिपा में तथा रणछोड़पुरा और पिण्डोलिया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने बहुत आवश्यक हैं। विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में चिकित्सकों और नर्सिंगकर्मियों के भी काफी पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें भरा जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

राजकीय सामान्य चिकित्सालय भीण्डर तथा राजकीय मोडर्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड व भम्भोरा चिकित्सालय में मैं मांग करती हूं कि महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाये। बहुत आवश्यक है क्योंकि सभापति महोदय, गांव में महिलाओं को सीएचसी और पीएचसी में पुरुष चिकित्सकों से इलाज कराने में बहुत झिझक रहती है, जिसके कारण उनका समय पर उपचार नहीं हो पाता है और एक छोटी-सी बीमारी उनके लिए कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। इसके लिए आपके माध्यम से विनती करती हूं कि प्रत्येक सीएचसी पर महिला चिकित्सक का एक पद अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराया जाये, जिससे महिलाएं बेझिझक अपना उपचार करा सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि एनआरएचएम से जुड़े हुए सभी वर्गों को नियमित किया जाये क्योंकि उन्होंने भी कोरोना के काल में बहुत अच्छे वारियर्स के रूप में कार्य किया था। साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि कुछ चिकित्सक अपने हैडक्वार्टर पर क्वार्टर होते हुए भी वहां उपस्थित नहीं रहते हैं और प्राइवेट कमाई में बिजी रहते हैं, उन्हें पाबन्द किया जाये कि वो अपने हैडक्वार्टर पर ही रहें क्योंकि इसी दौरान हमारे भीण्डर में भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का निधन हो गया था क्योंकि रात को उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल सका था, तो इन्हें पाबन्द किया जाये।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री वासुदेव जी देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 व 13 पर चर्चा हो रही है। हालांकि डिमाण्ड्स पर चर्चा की सार्थकता घट गयी है। छोटी से छोटी घोषणाएं भी सीएम स्तर पर होने लगी हैं। ऐसे समय अपने क्षेत्र के लिए मांग करना केवल औपचारिकता रह गयी है। आज भले ही हम राइट टू हैल्थ की चर्चा करें और घोषणाएं करते रहें पर सारी व्यवस्थाएं आज चरमरायी हुई हैं। हालांकि स्टाफ, डाक्टर्स, नर्सेज आदि ने कोरोनो के दौरान अद्भुत व सराहनीय काम किया है, पर स्टाफ के पास वह संवेदना न होने की कमी के कारण सबके हाथ बांध दिये हैं। आज राजस्थान हैल्थ इंडेक्स में देश भर में 16वें नम्बर पर है। सरकारी खर्च में राष्ट्रीय औसत से पच्चीस प्रतिशत कम व्यय होता है। प्रति व्यक्ति राज्य में 3 हजार 406 रुपये खर्च हो रहे हैं, उसमें सरकार का केवल 1,369 रुपये है जबकि केरल में 9 हजार रुपये, हिमाचल प्रदेश में 6,500 रुपये खर्च होता है। ऐसी स्थिति में जबकि विश्व के सौ देशों में से ज्यादा शिशु मृत्यु दर आज अपने राजस्थान में है, यानी 1 हजार में 35 शिशुओं की मृत्यु हो रही है और फिर हम हैल्थ इंडेक्स की बात करते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे?

अब मैं सीधा अजमेर पर आ रहा हूं कि आज अजमेर में सुपर स्पेशियलिटी पूरी तरह से विकसित नहीं है। कई वर्षों से हमारे यहां कार्डियक सर्जरी सीटीवीएस थियेटर, जिसमें करोड़ों की मशीनें लगी हुई हैं सब धूल फांक रही हैं, उसका कारण सर्जन की वेकेंसी के कारण बाईपास सर्जरी तथा वाल्व रिप्लेसमेंट बंद है। यानी ऐसी स्थिति बनी है और नेफ्रोलोजी में नेफ्रो फिजीशियन नहीं है इसलिए डायलिसिस की भी कोई सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं है। गेस्ट्रोलोजी भी विकसित नहीं है, वहां स्टाफ नहीं है। कैजुअल्टी में एक्स-रे मशीन चालू नहीं है तो वहां के मरीजों को दूर ले जाना पड़ता है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, छोटी-छोटी चीजें जिसमें पैसा खर्च नहीं होता, वहां पर एक्स-रे मशीन को तो ठीक कराओ, वह भी खराब पड़ी है। नि:शुल्क दवा योजना काउंटर पर आज दवाएं पूरी उपलब्ध नहीं हैं। आप जांचों की संख्या बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ अच्छा है, जनता को लाभ मिलना चाहिये, लेकिन जेएलएन में महंगी जांचें उपलब्ध ही नहीं हैं। एमआरआई में वहां एक सिद्धार्थ नामक संस्था से अनुबंध कर रखा है। सरकार खुद एक एमआरआई मशीन खरीदकर जेएलएन में लगा दे तो लोगों को नि:शुल्क एमआरआई जांच की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। टीबी संक्रमित रोग है, आज शहर में टीबी यूनिट बनी है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

उसको यदि शहर से बाहर ले जायेंगे तो अजमेर को बहुत बड़ा लाभ होगा और उसी में आप सुपर स्पेशलिटी भी प्रारम्भ कर सकते हैं। आज हास्पिटल की स्थिति यह है कि चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं है जिसके कारण से कई बार पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को अपनी ट्रोली, व्हील चेयर खुद घसीट कर ले जाना पड़ता है। ऐसी दयनीय स्थिति कई बार बुजुर्ग लोगों के साथ दिखाई देती है।

मेरे क्षेत्र की मैं मांग करूं तो अजसर और हाथीकेड़ा मेरे दो गांव हैं, जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, इनको पीएचसी में कन्वर्ट करें। एक कुन्दन नगर में उप स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करें तो वहां की जनता को लाभ होगा, आज वह उससे वंचित है। हमारे समय हमने एक सीएचसी पंचशील में पांच करोड़ की लागत से बनवा दी। आज बिल्डिंग बनी हुई है, एक-दो डाक्टर फोरमल बैठे हैं, यदि उसमें आप डाक्टर भेज देंगे तो उस पूरे एरिया को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। चूंकि स्टाफ नहीं है, इसके कारण से वहां हालत बुरी है।

आज कोई भी बड़ा शहर ले लो, किसी भी चिकित्सालय के साथ संबद्ध चिकित्सालय, जयपुर में 12 संबद्ध चिकित्सालय हैं, जोधपुर में 10 हैं, बाकी किसी में 6-6 हैं। अजमेर ही एक मात्र केन्द्र है जिसके साथ संबद्ध चिकित्सालय केवल तीन हैं। अत: मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे अजमेर उत्तर में सैटेलाइट हास्पिटल खोलकर उसको संबद्ध चिकित्सालय के रूप में बनाइए, क्योंकि जितने आप संबद्ध चिकित्सालय बनायेंगे उतना ही जेएलएन पर भार कम पड़ेगा। आज जेएलएन पूरे संभाग का हास्पिटल है और उसकी यह हालत है कि उसमें जितने पेंशेंट के बैड हैं, उससे ज्यादा पेंशेंट तो आपको जमीन पर मिलेंगे, इस प्रकार की स्थिति है।

सभापति महोदय, आज कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आज अजमेर में कैंसर हास्पिटल की सख्त आवश्यकता है। यदि आप यह तय करेंगे तो मैं समझता हूं पूरे संभाग के लोगों का बहुत बड़ा भला होगा। साथ में मैं आपसे एक मांग करूंगा कि इस समय स्वास्थ्य मार्गदर्शक को आप एनजीओ के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, उसको एनजीओ से हटाकर आरएमएसआर से पेमेंट कराएं और वेतन 15,000 करें। इन लोगों ने बहुत सेवाएं दी हैं और आज भी दे रहे हैं।

इसके साथ, अजमेर में आयुर्वेद निदेशालय है। आयुर्वेद निदेशालय में पिछले 80 दिनों से धरना चल रहा है। संविदाकर्मी, आयुर्वेद चिकित्सक आज

(श्री वासुदेव देवनानी)

धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी सुनवाई नहीं है उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। वहां दूसरे छोर पर नर्सिंग बेरोजगार भी कर रहे हैं। यह धरने के केन्द्र बनते जा रहे हैं। उनसे बातचीत करके उनका हल निकालो और उनकी कोई डिमांड ऐसी भी नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। उनकी केवल तीन डिमांड हैं, जो आपके एक हजार चिकित्सक के पद खाली पड़े हैं, उनकी तो आप सीधी भर्ती की घोषणा करें। साथ में एक हजार हैल्थ वैलनेस सेंटर पर दो-दो आयुर्वेद चिकित्सक लगाएं।

श्री सभापति: कृपया कनक्लूड करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो मिनट में खतम कर रहा हूं। मुझे ध्यान है इसलिए मैं आज संक्षिप्त में मांगें ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: जी हां, टाइम तो निर्धारित है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज नर्सिंग शिक्षा का बेहाल है। एसएफएस में पद सृजित नहीं हैं। उनसे 40 हजार रुपये फीस ली जा रही है और वहां बाहर से कांट्रेक्ट वाले आकर केवल पढ़ा रहे हैं, तो वह शिक्षा कैसी होगी, उस पर एक बार ध्यान दे सकते हैं।

मैं आपसे एक डिमांड करूंगा कि आपके पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने कहा था जनता क्लीनिक खोलेंगे। मुझे तो पूरे अजमेर में एक भी जनता क्लीनिक दिखाई नहीं देती। आपने केवल वाहवाही लूट ली, हमने मेजें थपथपा लीं लेकिन आज एक भी जनता क्लीनिक हमारे यहां प्रारम्भ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में अजमेर के लिए घोषणा की थी कि पब्लिक हैल्थ कालेज खोलेंगे, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे, ट्रोमा सेंटर खोलेंगे, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय खोलेंगे। एक भी नहीं खुला। मल्टीपरपज इंडोर हॉल बनायेंगे। हास्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनायेंगे, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा, उस राय को अगर आप मानेंगे कि जो डाक्टर मेडिकल ग्रुप-2 में से ग्रुप-1 में गत 5-6 वर्षों से यूटीबी पर टीचिंग का काम कर रहे हैं, बिना फाइनेंशियल यदि आप उनको लेक्चरर बना दोगे, रेगुलर कर दोगे तो निश्चित रूप से टीचिंग फैकल्टी की सारी कमी दूर हो जायेगी, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

आज आपके एसएमएस के क्या हाल हैं? एसएमएस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितने बैड हैं, उससे दुगुने जमीन पर हैं। आपने जो कार्डियक विंग टावर की घोषणा की थी, उसका आज कहीं पता नहीं है। आपने कोटेज तोड़

(श्री वासुदेव देवनानी)

दिये, कहा था कि वहां 21 मंजिल की बिल्डिंग बनायेंगे। आज वह फिजिबल नहीं है, उसको नहीं बना पा रहे हैं। साथ में एक मांग करूंगा कि योग विश्वविद्यालय अजमेर में खोलेंगे तो आपके ऐलोपैथी पर कम भार पड़ेगा। योग से लोग स्वस्थ होना शुरू हो जायेंगे। इसलिए योग विश्वविद्यालय अजमेर में खोला जाय। सभापति महोदय, आपकी आज्ञानुसार मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में तीन, सवा तीन साल के इस कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री जी ने इस कोरोना काल में जो शानदार प्रबंधन किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही उन कार्मिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाएं आईं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा पहले 5 लाख था, उसको 10 लाख किया। अभी इस बजट में एक्सीडेंटल बीमा का भी प्रावधान किया। नीरोगी राजस्थान का जो अभियान चलाया, उड़ान योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नये नवाचार माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने प्रदेश की जनता के लिए किये, निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं।

चिरंजीवी योजना के द्वारा प्रदेश में लगभग 8 लाख 65 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया और करीब 1100 करोड़ रुपये का सरकार ने इसमें योगदान दिया है। यह कोई छोटा काम नहीं है। योजनाओं के बारे में कमी खामी जरूर हो सकती है, लेकिन आम जनता को इसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हिन्दुस्तान में शायद कोई ऐसी योजना नहीं होगी जिसमें 10 लाख रुपये कवर करते हैं। इसमें जो कई बीमारियां रह गई थीं, उनको भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में जोड़ने का काम किया है, चाहे वह

(श्री आलोक बेनीवाल)

कैंसर हो या ट्रांसप्लांट हो। यह कोई छोटी योजना नहीं है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर बार बड़ा दिल रखते हुए ही इस प्रदेश की 7 करोड़ जनसंख्या को लाभान्वित करने का काम किया है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी बताना चाहता हूं कि बीच में जब पांच साल कांग्रेस की सरकार रही, उस समय मेरे यहां तीन पीएचसी खुली थीं। जो 10 साल का समय निकला उसमें एक सीएचसी और एक पीएचसी बनी। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बजट में उन्होंने हमारी दो पीएचसी को क्रमोन्नत करके सीएचसी बनाया। पिछले बजट में उन्होंने शाहपुरा को उप जिला चिकित्सालय बनाया। मनोहरपुर के 30 बैड के हास्पिटल को लगातार दो साल क्रमोन्नत करके 70 बैड का हास्पिटल किया। स्वास्थ्य के संबंध में तीन साल का एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं।

(समय: 18.00 बजे)

मेरे यहां पर कोई-कोई जगह रह गयी है, जहां पर सब-सेन्टर नहीं है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री को बता दूंगा, वे भी खुल जायेंगे। मुख्य मंत्री जी ने और मंत्री जी ने मेरे यहां पर काफी सारी पंचायतों पर सब-सेन्टर खोले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है। विगत सालों में मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो स्वास्थ्य का पाया था, वह बहुत ही कमजोर था। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जब से शाहपुरा में जिला चिकित्सालय बना है, उसकी 1000-1100 की ओपीडी थी और आज 1700-1800 की ओपीडी आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में आईपीडी और ओपीडी को भी फ्री कर दिया। ये जो स्वास्थ्य के सम्बन्ध में फैसले लिए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन हमारे क्षेत्र को भी देखने को मिलेगा और वहां की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। मेरा क्षेत्र शाहपुरा जो कि नेशनल हाईवे पर है, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि मेरे यहां पर एक ब्लड बैंक जरूर खोलें, क्योंकि आसपास का एरिया बहुत बड़ा है, हाईवे का एरिया है। अगर आप वहां पर ब्लड बैंक खोलने की कृपा करेंगे तो आपका बहुत आभार रहेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं। मेरे यहां पर जो खेजरोली सीएचसी है, उसको अपग्रेड करेंगे कि उस क्षेत्र की 10 पंचायतों को लाभ मिलेगा। साथ ही, मेरे यहां पर कुछ पीएचसी नहीं खुली हैं। पिछले बजट में एक पीएचसी खुली थी। मैं मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से भी मांग करूंगा कि हमको कुछ

(श्री आलोक बेनीवाल)

पीएचसी और दें, जिससे जो वंचित पंचायतें हैं, जिनमें हम पीएचसी खोलना चाहते हैं, उसमें पीएचसी खोल सकें।

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो फैसले लिए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुदर्शन सिंह रावत।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 26 और मांग संख्या 13 पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने कोविड का शानदार और अच्छी तरह से प्रबन्धन किया और पहली वैव में 'कोई भूखा नहीं सोये' के नारे के साथ पूरे राजस्थान को लीड किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तब हम सभी एमएलएज को एमएलए लैड से सभी जगह पर फूड ग्रेन्स की सामग्री सप्लाई करने के लिए प्रेरित किया, उसके बाद सैकण्ड वैव में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कैप्टन के तौर पर अच्छी तरह से इसको लीड किया। आक्सीजन सिलेण्डर और सभी दवाइयों की टाइमली सप्लाई करके राजस्थान की जनता की सेवा की। हमारे सभी एमएलए लैड से वेंटीलेटर, आक्सीजन सिलेण्डर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स सप्लाई हुए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बोलना चाहूंगा। 2018-19 में जहां 12 हजार 800 करोड़ रुपये का हमारा बजट था, उसे बढ़ाकर अभी इस साल के बजटरी एस्टीमेट में 20 हजार करोड़ रुपये तक लेकर आये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। केन्द्र सरकार ने भी इसमें निश्चित तौर पर हैल्थ में अच्छी प्रोग्रेस की है, परन्तु जिस तरीके से जीडीपी के 3 परसेंट के करीब हमारे हैल्थ एक्सपेंसेज होने चाहिये थे, जो कि हमारी नेशनल हैल्थ पालिसी का हिस्सा है, उसकी जगह आज की तारीख में 0.35 परसेंट जीडीपी का पार्ट बना हुआ है। हमारे बजट में हैल्थ का जीडीपी का जो हिस्सा है वह बहुत कम है, उसे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि प्राइमरी हैल्थकेयर और इनिशियल हैल्थकेयर को हमको सुधारना बहुत जरूरी है।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मई, 2021 में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की थी, उसकी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपये किया है, जिससे आयुष्मान भारत नेशनल स्कीम है, उससे भी ज्यादा इसका कवरेज हो गया है। इसमें मैक्सिमम डिजीज कवर हो गयी और तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख परिवार इसमें लिस्ट हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि हर बजट के जैसे इस बजट में भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा एक्सपेंडिचर करने का मन बनाया है। 1 हजार सब-सेन्टर्स प्रस्तावित किये हैं। 50 सब-सेन्टर्स को पीएचसी में और 32 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है। 11 सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और 6 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाये हैं।

सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि World Health Organization का अस्ताना डिक्लेरेशन हुआ था। डा जितेन्द्र सिंह जी इस बारे में जानते होंगे। इसमें 2018 में सारी कंट्रीज ने मिलकर एक कमिटमेंट किया था - "commitment to the fundamental right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without distinction. It identifies disparity in access to health between rich and poor to access health care." मतलब गरीब और अमीर के बीच में हैल्थकेयर के डिफरेंस को कम करने का डिक्लेरेशन है। यह कैसे होगा? जब तक हम लोग हमारे इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अच्छा नहीं कर पायेंगे तो सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इसको हम अचीव नहीं कर पायेंगे। इसलिए हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पीएचसी, सब-सेन्टर और सीएचसीज को हम स्ट्रेन्थन करें। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विपक्षी साथी अभी कई चीजों को गिना रहे थे, पर पिछले पांच साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी तरह का काम नहीं हुआ। इन तीन साल में, आप एक बार इस बजट को साइड में रख दें, तो कांग्रेस की सरकार में 202 नये सब-सेन्टर्स बने हैं। 194 पीएचसीज हुई हैं, सीएचसीज 136 हुई हैं और एक्स्ट्रा बैड भी 5 हजार हुए हैं। ये सारे माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में हुए हैं। इसी के साथ हम लोग हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पायेंगे और इसके लिए हम सब लोगों को आगे काम करने की जरूरत है।

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

मैं माननीय मंत्री महोदय को कुछ सजेशन देना चाहूंगा। हम सब लोगों ने एम्बुलेंसेज खरीद-खरीद कर दी हैं। सब जगह पर एम्बुलेंसेज के आपरेशन को लेकर बहुत इश्यू आता है तो मैं चाहूंगा कि सारा सदन इसमें सहमति व्यक्त करे। हम लोगों का जो एमएलए लैड है, वह हम आरएमआरएस को देकर इन एम्बुलेंस के आपरेशन को अच्छी तरह कर पायें तो लोगों के लिए एक रियल हैल्प होगी। वे एम्बुलेंस खरीदी भी हैं और हम लोगों के काम भी नहीं आ रही हैं। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जिस तरह से सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स हैं, उसी तर्ज पर पीएचसीज बनें। इसी से असली मदद हो पायेगी।

डाक्टर्स के लिए कहना चाहूंगा कि एसआरशिप को लेकर डाक्टर्स चले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि हम लोग इस तरह का नियम लगायें कि एक अस्पताल से एक ही डाक्टर एसआरशिप के लिए जाये। होता यह है कि एक अस्पताल से पांच-पांच डाक्टर्स एसआरशिप के लिए जाते हैं तो पूरा अस्पताल खाली हो जाता है, पोस्ट भी भर जाती है और हम दूसरे को लगा भी नहीं पाते हैं। इसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं काम हो। जब वे एसआरशिप कर आयें, अगर मेडिकल कालेज में पोस्टेड नहीं होते हैं तो कम से कम उन अस्पतालों में उनकी सेवाओं का लाभ मिले। मंत्री महोदय, रूरल एरियाज में बहुत कम डाक्टर आना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव चाहे फाइनेंशियल हो या चाहे प्रमोशनल मिले, जिससे कि रूरल एरियाज में हमको डाक्टर्स की सेवाओं का लाभ मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के लिए मैं चाहूंगा कि यह बहुत 125 या 150 किलोमीटर लम्बा एरिया है। एमसीएच विंग कहीं नहीं है, हमें राजसमन्द पर डिपेंड होना पड़ता है तो यहां पर एक पचास बैड की मदर चाइल्ड यूनिट खोली जाये। यह अस्पताल जो कि 100 बैडेड है, उसको सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के तौर पर चलाया जाये।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम): हमारे सात पंचायत क्षेत्र और हैं, जिनमें सात गांव हैं। वे ब्यावर के नजदीक हैं, परन्तु हमारे हैडक्वार्टर से दूर हैं। उन शेखावास और आसपास के इलाके के लिए एक डायरेक्ट सीएचसी दी जाये। आपके दौसा जिले में 2020-21 के बजट में एक सीएचसी दी गयी थी, जो कि बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य के यहां पर दी गयी थी तो उसी तर्ज पर दी जाये। मेरे लिए यह बहुत जरूरी है, फौजियों का इलाका है। कृपया

(श्री सुदर्शन सिंह रावत)

इसको देने का कष्ट करें। देवगढ़ का जो मॉडल सीएचसी है, उसमें 25 एक्स्ट्रा बैड देने का कष्ट करें। राजसमन्द में नर्सिंग कालेज को जल्द से जल्द खुलवायें ताकि हम लोगों को नर्सिंग कालेज का लाभ मिल सके। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सफाई और मांग संख्या 13 - आबकारी पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में पिछली बार की तरह ही राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने नीरोगी राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए बजट पेश किया था। कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे इस बार जो पांच राज्यों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने कल्पना की थी, यूपी में जीतेंगे, पंजाब में जीतेंगे, उत्तराखण्ड में जीतेंगे, लेकिन आपकी यह कल्पना अधूरी रही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपका पिछले तीन सालों का यह बजट है। मैं सिर्फ यह बात कहना चाहूंगा, वर्तमान के चुनाव परिणामों को देखते हुए कि पूरे भारत में एक व्यक्ति है, जिसको न तो जीत की चिन्ता है, न हार का दु:ख है। वह कौन है? आपके आदरणीय नेता जी +++ न जीत की चिन्ता, न हार का दु:ख। आज इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गयी है कि जितने चरण में यूपी के चुनाव हुए उतनी सीटें कांग्रेस नहीं जीत पायी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जो हाउस का मैम्बर नहीं है, उनका यहां पर रेफरेंस नहीं दें, उसको डिलीट करायें। यह क्या है?

श्री सभापति: ये जो बोले, उसको डिलीट करें। डिलीट कर दीजिये। आप विषय पर बोलिए।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं बोल रहा हूं साहब। आज पंजाब ने अपना जेलेंस्की चुन लिया और उत्तर प्रदेश ने व्लादिमिर पुतिन को चुन लिया। ये वर्तमान की बात इसलिए कर रहा हूं अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ उसमें व्लादिमिर पुतिन ने देश का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते दुश्मन देश की सीमा में घुसकर दुश्मन ने जो आंख उठाई थी, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया।

श्री सभापति: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं स्वास्थ्य सेवाओं पर आ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने चिकित्सा सेवाओं को लेकर मेरे जैतारण के अन्दर बर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया। इससे पहले भी आपने जैतारण राजकीय सी एच सी में 50 बैड के हास्पिटल को 100 बैड पर क्रमोन्नत किया लेकिन दो साल गुजर जाने के बाद में आज भी उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण और जब क्रमोन्नति होती है तो कम से कम 16 चिकित्सक और स्टाफ और लगने थे लेकिन एक की भी नियुक्ति नहीं हुई। ये महज घोषणाएं करके क्षेत्र के अन्दर वाह-वाही लूटने का प्रयास जो हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। मेरा निवेदन रहेगा कि जो सी एच सी आपने क्रमोन्नत की है, उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करावें। 50 बैड से 100 बैड पर जो जैतारण सी एच सी को आपने क्रमोन्नत किया, उसकी भी वित्तीय स्वीकृति जारी करावें।

माननीय सभापति महोदय, जिस कोविड महामारी के अन्दर पूरा देश ही नहीं राजस्थान प्रदेश के लोगों ने भी वह दंश झेला, पीड़ा झेली। मैं धन्यवाद दूंगा जैतारण के उन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों को, मेडिकल स्टाफ को, जिन्होंने पूरे पाली जिले में मोदी जी के दिये हुए वैक्सीनेशन को प्रथम स्थान दिलाया। जैतारण वैक्सीनेशन के मामले में पूरे पाली जिले में प्रथम रहा। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं धन्यवाद दूंगा डाक्टर सुधीर भंडारी जी को, जो आज राजस्थान में चिकित्सा का बहुत बड़ा नाम है और मुझे फख्र इस बात का है कि वह मेरी जैतारण विधान सभा क्षेत्र से आते हैं। हमारे मार्गदर्शक के रूप में आज राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सी एच ए का, आपने कोविड के दरमियान सी एच ए को आपने लिया था। मैं मांग करूंगा कि उनको वेतनमान दिया जाये। उनकी वेतन बढ़ोतरी की जाए और उनकी नियमितीकरण की मांग भी मैं सरकार से करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक सीएच.सी. को आदर्श सी एच सी के रूप में विकसित करने का हम सब विधायकों को कहा था। मैंने भी मेरी जैतारण सी एच सी को आदर्श सी.एच.सी. के रूप में विकसित किया। एक करोड़ रुपये से ज्यादा के उपकरण मैंने दिये। आपने इस बजट में प्रत्येक सी एच सी पर डायलिसिस सुविधा शुरू करने की स्कीम की।

(श्री अविनाश)

मैंने पावन धाम ट्रस्ट जैतारण के माध्यम से एक हीमोडायलिसिस मशीन वहां दे दी लेकिन लगभग दस महीने गुजर जाने के बाद में आज दिन तक वह मशीन शुरू नहीं हुई। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पाली सी एम एच ओ को आर्डर करें, सख्त आदेश करें, जैतारण बी सी एम ओ को सख्त आदेश करें, सी.एच.सी. इंचार्ज को आदेश करें, वहां हीमोडायलिसिस मशीन चलाने के लिए डाक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग भी हो गयी लेकिन आज दिन तक शुरू नहीं हुआ। ब्लड बैंक के लिए वहां पर फ्रिज पड़ा है। मैंने मेरे एम एल ए कोटे से दिया है, लेकिन आज दिन तक वह शुरू नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री महोदय, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसके बारे में भी वहां पाबन्द करें।

माननीय सभापित महोदय, मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में तीन सी.एच.सी. हैं, जैतारण, निमाज और रास। ये बहुत बड़ेबड़े इलाके हैं और अलग -अलग स्थानों पर भौगोलिक दृष्टि से भी दूर-दूर है। आपने आदर्श सी एच सी के लिए पैसे तो हमसे मांग लिए लेकिन वहां पूरा स्टाफ नहीं है। मैं दोनों सी एच सी की बात करना चाहूंगा। जिस सी एच सी निमाज की पापुलेशन, उस कस्बे की जो सबसे बड़ा कस्बा है मेरी जैतारण विधान सभा का, 30 से 35 हजार की आबादी है। वहां पिछले कई वर्षों से भामाशाहों के सहयोग से सी सी यू का निर्माण किया गया, भामाशाहों के सहयोग से। वहां आपरेशन थियेटर बना हुआ है कई वर्षों से। ब्लड बैंक भी वहां बना हुआ है लेकिन स्टाफ नहीं होने के कारण वह नाकारा साबित हो रहे हैं। आज दिन तक आपरेशन थियेटर काम में नहीं आया, आज दिन तक सी सी यू काम में नहीं आया। मेरा आपसे निवेदन रहेगा इतना बड़ा कस्बा है जैतारण सी.एच.सी., निमाज सी एच सी के अन्दर, महिला गायकोनोलोजिस्ट नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। सारे के सारे एम ओ भरे हैं। आज अगर निमाज की स्थिति बताऊं मैं आपको, वहां 7 पोस्ट हैं। 7 में से 7 एम ओ लगे हुए हैं। वहां की 500 के करीब ओ पी डी पर-डे की है। लेकिन महिला चिकित्सक नहीं है, वहां पर सर्जन नहीं है, वहां पर एनेस्थीसिया नहीं है, वहां पर गायनोकोलोजिस्ट नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये जो तीन-चार प्रमुख विशेषज्ञ हैं, इनकी नियुक्ति आप अगर निमाज सी.एच.सी. पर करेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा।

निमाज के अन्दर ही ब्लड बैंक स्थापित था लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उसको धीरे-धीरे पाली शिफ्ट कर दिया गया जिला मुख्यालय पर।

(श्री अविनाश)

वहां जो फ्रिज था, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया। सी एच सी रास में पांच पद स्वीकृत हैं। पांचों विशेषज्ञ अंगेस्ट लगे हुए हैं एम ओ रेंक के, उनमें से दो का पी जी में सिलेक्शन हो गया है। अब वहां दो पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी और जो जैतारण से 35 किलोमीटर दूर इलाका पड़ता है अगर वहां चिकित्सक नहीं होंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): बस दो मिनट में मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर वहां चिकित्सक नहीं रहेंगे, उस क्षेत्र के लोगों को बहुत नुकसान होगा। इससे पहले भी डिलीवरी के मामले में महिला चिकित्सक नहीं थी, गायनिक नहीं थे, उनको ब्यावर ले जाया गया, अजमेर ले जाया गया, तब तक डैथ हो गयी। ये बहुत बड़ा पेचीदगी वाला मामला है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा। 108 एम्बुलेंस एम एल ए लैड से हम देना चाह रहे हैं लेकिन उसको आपरेट करने वाला ड्राइवर नहीं है। सी.एच.सी. वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। 108 की स्थिति क्या है? आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। खटारा साबित पड़ी है। खटारा है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, जो कॉल करते हैं तो एक घंटे पहले वह एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को भी ठीक किया जाए।

पिछले दो साल से कम्युनिटी हैल्थ सेंटर को रिपेयर के लिए लगभग 2-2 लाख, उप स्वास्थ्य केन्द्र जो मेरे हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए 2-2 लाख रुपये आए। दो साल गुजर जाने के बाद टेंडर हो गया, वर्क आर्डर हो गया लेकिन आज दिन तक वह काम शुरू नहीं हुआ। उसको भी पूरा करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा। मेरा जैतारण जो दो-दो नेशनल हाईवे के बीच में स्थित है, सी एच सी ट्रोमा सेंटर जिसकी सिफारिश भी गयी है, स्वीकृति भी हो गयी है। लेकिन मात्र 3 लाख रुपये देकर एक रूम के अन्दर संचालित हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आप उस ट्रोमा सेंटर को भी बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इसके साथ ही जो हास्पिटल्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स की स्थिति बहुत खराब है, इतने गन्दे हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी जाएगा तो उसको देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए साफ-सफाई के मामले में भी, आजकल क्या है टेंडर हो जाते हैं एक साल के। टेंडर के माध्यम से सफाईकर्मी होते हैं। वह साफ-सफाई का इतने ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाते हैं। वार्ड ब्वाय की जो स्थिति है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है।

(श्री अविनाश)

इसके अलावा एन.आर.एच.एम. योजना के अन्दर माननीय मंत्री महोदय, कार्मिकों को दस साल हो गये। उनका वेतनमान बहुत काम है और उसी कार्य के लिए स्थायी कार्मिकों का वेतन बहुत अधिक है। मेरा निवेदन रहेगा कि एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन योजना आप लागू करें। इसके साथ ही एन.आर.एच.एम. मैनेजमेंट संविदाकर्मी के अन्तर्गत पांच पदों को नियमित किया जाए। इसमें बी पी एम, लेखाकार, ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर, पी एच सी हैल्थ सुपरवाइजर और कम्प्यूटर आपरेटर। ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, 2018 के कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में इनको नियमित करने का वादा आप लोगों ने किया था लेकिन आज तीन साल के बाद में आप इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अविनाश (जैतारण): मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो पी पी पी मोड पर हैं। ये कोटकेनाडा, बूमरी और कुडकी, वहां लाखों रुपये प्रतिमाह उनको दिया जाता है। उसका जो एम.ओ.यू. सरकार के साथ में हुआ है, वह इसी मार्च के अन्दर पूरा हो रहा है। एम.ओ.यू. खतम होने के बाद में अब जब अप्रैल से नया स्टार्ट होगा तो मेरा निवेदन है कि उसको पी पी पी मोड से हटाकर स्वास्थ्य विभाग अपने अधीन काम में ले ताकि क्षेत्र के लोगों की जो शिकायतें हैं, उससे निजात मिल जाए।

श्री सभापति: थैंक यू, समाप्त कीजिए।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर डाक्टर्स जो वैकेंट हैं, उनको लगायें। एएनएम, जीएनएम के पद जो खाली है, उनको भरे जावें।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री अविनाश (जैतारण): लाम्बी, आनंदपुर कालू, बड़ी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको आप सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें।

श्री सभापति: ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री अविनाश (जैतारण): इसके अलावा सेंदड़ा, कलारिया जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर जो आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक ऐसा विषय है स्वास्थ्य का, जिस पर बड़े-बड़े माननीय विद्वान विधायकों की बातों को सुना। सबसे बड़ी बात है जब आदमी बीमार पड़ता है और अस्पताल जाता है तो आज के दस-पन्द्रह साल पहले जो स्थिति उनकी थी कि अपना गहना भी साथ लेकर जाते थे। इसलिए जाते थे कि अगर दवाई के पैसे नहीं होंगे, अगर किसी के हार्ट की बीमारी होगी, इंजेक्शन 5 हजार का आता है और कोई बड़ी बीमारी हो गयी, राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार भी लोगों को सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज करने का दिया और अभी चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो सरकार लोगों का इलाज करवा रही है, उससे आम आदमी को यह डर नहीं है कि मेरे पिताजी के हार्ट अटैक आ गया और मैं अस्पताल में जाऊंगा तो इनकी एंजियोग्राफी या हार्ट का आपरेशन होगा, उसकी प्राब्लम नहीं है। इसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, वैक्सीन फ्री दे दी, दिमाग में आता है कि यह फ्री देने वाले दानवीर कहां से आये। हमारी नेता इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अगर यह प्रयोगशाला खोलकर नहीं जाते, विज्ञान में समझते थे, यह खोलकर नहीं जाते, तो यह इंजेक्शन नहीं बनता। वहीं से यह वैक्सीन निकली है। इनको पूछो, यह नौजवान है, इनके तो नहीं। सभापति महोदय, कटारिया जी के चांदी की छाप की तरह चेचक का टीका लगा हुआ होगा।

श्री सभापति: आप विषय पर बोलिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): वह फ्री लगाया गया है। (व्यवधान) थोड़ा रूक जाओ। आप ही बोलना जानते हो क्या, सुन लो। जो-जो भी सरकारें आती हैं, वह कुछ न कुछ करती हैं। स्वास्थ्य के बारे में जितना कांग्रेस के राज में हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है यह लोग बड़े घरों से आये हो, मैं बिलकुल आम आदमियों में से निकलकर आया हूं। जब गरीब आदमी को, एक एनाल्जिन की गोली फ्री मिलती थी, जब भी खुश होता था और इंदिरा गांधी का धन्यवाद करता था। आज तो सारी की सारी दवाइयां, गरीब अस्पताल में जाना चाहिये, अस्पताल जाने के बाद, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाती है, इसके लिए मैं कांग्रेस की सरकार को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

(श्री राकेश पारीक)

सभापति महोदय, यहां सात मिनट बोलने का टाइम दिया। अगर हम इलाक़े की स्थिति के बारे में बयान नहीं करेंगे, तो वहां से भी खबर आने वाली है। मेरे मगरे का इलाका है। मगरे के इलाक़े में 23 आदमी शहीद हुए हैं। वहां रावल्याबाडा में एक सीएचसी, देशभक्त लोग रहते हैं। एक सीएचसी हमारे जालिया थर्ड है, जालिया सैकण्ड के अंदर की जाये। एक नागोला में, एक देवलीकलां में, जामोला में सीएचसी खोली जाये। बहुत लम्बा चौड़ा इलाका है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से, मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हमारे यहां पांच सीएचसी इस बजट में खोली जायें। मेरा आग्रह है। बड़ा इलाका है। ऐसा थोड़े ही है जयपुर में निकल गये, इधर-उधर की गलियो में ... (व्यवधान) यह क्यों बोल रहे हैं।

श्री सभापति: बोलिये, आप बोलिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): यह क्यों बोलने देंगे। यह बोलने नहीं देंगे, अपन लोग गांव के हैं। शहर के ज्यादा समझते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जो भी बात कहता है, उनको डिस्टर्ब नहीं करें। बोलें अपनी बात।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): ग्राम पंचायतों में प्राइमरी हैल्थ सेंटर नहीं है। डिस्पेंसरी नहीं है। मैं सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक-एक पीएचसी खोली जाये।

मेरे इलाके में, मैंने कागज भी बनाकर भेजे हैं, अल्पसंख्यक नर्सिंग कालेज खुलवाने के लिए, यहां आये हुए हैं। मैं मांग करूंगा कि मेरे मसूदा में अल्पसंख्यक नर्सिंग कालेज खोला जाये। मेरे भिनाई में (व्यवधान) ज्यादा होशियार दिखो भाईसाहब। मेरे इलाके में भिनाई सीएचसी है, उसको 30 बैड से बढ़ाकर 50 बैड किया जाये।

मैं सदन से, मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि विजयनगर अस्पताल को उप जिला अस्पताल में घोषित किया जाये। एक प्राइमरी पीएचसी विजयनगर के राजनगर में, क्योंकि रेलवे लाइन आती है, मरीजों को बहुत परेशानी होती है, राजनगर में पीएचसी खोली जाये। सदन ने मेरी बात सुनी, सभापति महोदय, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित कुमर ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, आपने

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं सबसे पहले मुफ्त वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने के लिए भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी साहब एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी मंडाविया का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी का, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, वैक्सीनेशन में लगे समस्त चिकित्सा कर्मियों का भी हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

आज चिकित्सा सुविधा की बात करें, तो शहरों में तो चिकित्सा की व्यवस्था फिर भी ठीक है। सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है। उनको ठीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अगर ग्रामीण इलाक़ों की बात करें तो ग्रामीण इलाक़ों में चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था बहुत दयनीय है। अस्पताल बहुत कम है। जहां है, वहां पर स्टाफ की कमी, लगभग सभी वक्ताओं ने बताई है। जहां पर दो की पोस्टिंग है, वहां एक कार्यरत है। जहां चार की पोस्टिंग है, वहां दो कार्यरत है। जहां एक पोस्टिंग सिर्फ एएनएम है, वह अधिकतर पद खाली पड़े हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र ले लो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले लो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले लो, लगभग सभी में पद खाली हैं, इनको तुरन्त भरा जाये।

(समय: 18.26 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मेरा एक निवेदन है, बीमारी समय देखकर नहीं आती है। ड्यूटी आवर्स के बाद भी आ सकती है तो रात्रिकालीन में भी, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक मेल नर्स स्तर का व्यक्ति हर समय उपलब्ध हो, ऐसा मेरा निवेदन है। पहला सुख नीरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आधार बनता है। स्वास्थ्य का मतलब, न केवल बीमारियों का अभाव है, वरन सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्थिति का स्वस्थ होना है। हमें इन सभी पहलुओं पर काम करना चाहिये, ताकि एक स्वस्थ समाज व देश का निर्माण हो सके।

कोरोना महामारी ने हमें सही चिकित्सा व्यवस्था की परिभाषा प्रस्तुत

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

की है। जान है तो जहान है, जैसी कहावतों की याद दिला दी। हमें चिकित्सा व्यवस्था को निरन्तर सुधारने का प्रयास करना चाहिये, ताकि हर व्यक्ति तक सही चिकित्सा, सही समय पर, उपलब्ध हो सके।

आज एक तिहाई से कम व्यक्ति ही सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि निजी अस्पतालों की तुलना में उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सरकार को स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिये। आज भी गरीब परिवारों का बहुत बड़ा तबका इनसे वंचित रह जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने 2019 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 95 पर नागरिकों को अपने निवास स्थान के पास तत्काल एवं नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनता क्लीनिक खोलने की बात कही। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो अभी तक एक भी जनता क्लीनिक नहीं खुला है। आपने 2021-22 के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-16 पर सीएचओ, कम्युनिटी हैल्थ आफिसर की भर्ती करने की बात कही थी। अभी तक वह भर्ती नहीं हुई है। इन्हें शीघ्र भरने की कृपा करायें।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना के अन्तर्गत 2011 से कार्यरत संविदाकर्मी जो अभी भी 8 हजार रुपये मासिक मानदेय पर कम्प्यूटर आपरेटर का काम कर रहे हैं। कम्प्यूटर आपरेटर को नियमित पद, क्लीनिक अभिलेख सहायक पद पर समायोजित कर नियमित किया जाये। ये कर्मचारी अभी जयपुर में पिछले 15 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर हैं। तीन दिन से तो वहां अनशन भी चल रहा है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है इनकी तरफ ध्यान दिया जाये, इनकी मांगों को मानकर इनको परमानेंट किया जाये।

मेरे यहां खण्ड मुख्य चिकित्सा कार्यालय बड़ी सादड़ी और डूंगला, दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में ही संचालित है अभी, इनके लिए नया भवन बनाया जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी पर संचालित एम्बुलेंस 12 वर्ष पुरानी हो गयी है। वह लगभग 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। आज की तारीख में वह मरीजों को उदयपुर या चित्तौड़ के अस्पताल में पहुंचाने की स्थिति में नहीं है इसलिए नई एम्बुलेंस दिलाई जाये।

उप स्वास्थ्य केन्द्र कचूमरा, किरतपुरा, पारलिया, जयसिंहपुरा, गुंदलपुर, जियाखेडी, यह भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र है, इन पर भवन की व्यवस्था की जाये।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी तौर पर कोई संस्था बी.एससी. नर्सिंग एवं विभिन्न पैरामेडिकल कोर्स शुरू करना चाहे तो उनको एन.ओ.सी. देनी चाहिए ताकि उनके साथ खुलने वाले हास्पिटल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

आपने अभी वाले बजट घोषणा पत्र में 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की बात कही है, यह बहुत कम है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, वह तुरन्त रख देता हूं। माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी सादड़ी को, एफ.आर.यू.बी. सिजेरियन को 100 बैडेड सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगला, बोहेड़ा, निकुम, बाराबरदा थड़ा को 30 बैड के स्थान पर 50 बैड में क्रमोन्नत किया जाये और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड़ जो सिक्स लेन पर स्थित है, आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, उसकी काफी जनसंख्या है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। देवगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़ जो कि टी.एस.पी. क्षेत्र में है, काफी सारा एरिया उस क्षेत्र में लगता है उसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धमोतर, बान्सी को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र पाल, जो एक सीता माता अभयारण्य में स्थित है, वहां पर कहीं पर जाओ तो पन्द्रह किलोमीटर से पहले सड़क नहीं है तो वहां पर यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये। पाल, रंठाजना, जोलर, मधुरा तालाब, खोरिया, देलवास, मुजबा टीला, खोड़ी, खरदेवला, नकोर, टांडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंगलवाड़ गांव नालवा, अरनिया, गोड़ाखेड़ा, देवली, उठेल, पिनोदड़ा, गुढ़ा, बागपुरा, पिराना, निमोदड़ा, इंदिरा कालोनी, बड़ी सादड़ी, पायरी, चैनपुरिया, माण्डकलां, खूंटगढ़, मंगरी, सामली पठार, बिहारा, खेड़ा नारसिंहमाता, बाबड़ीखेड़ा, काजलीखेड़ा, ढीकनिया, बम्बोरी, बरखेडा, केसरपुरा में नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, कन्क्लूड करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़, जय प्रतापगढ़।

श्री सभापति: माननीय श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, सरकारों का जब गठन होता है तो विधायकों के रूप में इस सदन में हम सब लोग उपस्थित होते हैं और इस सदन की गरिमा बनाये रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, बोलने की एक लिमिटेशन होती है। हम छोटे-छोटे बच्चे थे जब सदन के बारे में सुनते थे, कोई भी विषय जब उठता है तो उस विषय को गम्भीरता से लिया जाता है और यह अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिये हैं और भारत के संविधान की रचना डाक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने की है। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी सरकार चलाने का काम करती है।

राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोकजी गहलोत ने नीरोगी राजस्थान की कल्पना की और इस बात की चिन्ता की कि कोई गरीब व्यक्ति जब बीमार पड़े तो उसके इलाज के लिए किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़े। वह जब अस्पताल पहुंचे तो डाक्टर खुशी-खुशी उसका इलाज करें और उसको दवाई भी दें, यह कल्पना नीरोगी राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदय ने की। चाहे हम मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की बात करें या चाहे मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना की बात करें या चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें, पिछली बार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को आगे बढ़ाते हुए पिछले बजट में पांच लाख रुपये की नि:शुल्क एक परिवार की इलाज करने की व्यवस्था की और इस व्यवस्था को इतना बढ़ाया कि लोगों को जन-जन तक साढ़े सात करोड़, आठ करोड़ लोगों को यह अच्छी लगी और उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसकी दस लाख रुपये की घोषणा जो इस बजट में की है, मैं सभी राजस्थान के प्रदेशवासियों की ओर से उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं।

साथ ही साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं और सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र पर ही मैं आ जाऊं, मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा से मैं आता हूं। जब जनता ने चुनकर राजस्थान की विधान सभा 2013 में मुझको भेजा, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 बैड हुआ करते थे और मात्र 54 हजार

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

ओ.पी.डी. ही हुआ करती थी। यह चिकित्सा सेवाओं में बदलाव का परिणाम ही है कि आज वहां की ओ.पी.डी. सवा तीन लाख लोगों से ज्यादा साल भर की है। आपने इस बात को समझा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय अशोक गहलोतजी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय परसादी लालजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोगों के आशीर्वाद से वहां 110 बैड आपने बना दिये और उस अस्पताल को उप जिला अस्पताल दे दिया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डावर में 30 बैड का अस्पताल है, उसे 50 बैड की करने की कृपा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच-छह कस्बे बड़े हैं जिनमें हिंगोटा, हुलड़ा, बालाहेड़ी, पाखर, सालिमपुर और नाहिड़ा, यह छह गांव ऐसे हैं जो बड़े गांव हैं, जहां पर दूर-दूर तक अस्पताल नहीं है और वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र अभी संचालित है। मैं मुख्य मंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि इन छह गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें। नाहिड़ा तो एक ऐसा गांव है जहां गुर्जर समाज का बहुत बड़ा एक आस्था का केन्द्र बाहु महाराज का मंदिर है। वहां पर लाखों लोग मेले में आते हैं, बहुत बार पहलवान आते हैं दूर-दूर से। कई बार स्वास्थ्य की चिन्ता होती है, कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है तो ऐसी स्थिति में मैं यही मांग करूंगा कि नाहिड़ा के बाहु महाराज के मंदिर के आसपास एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलें।

मैं डाक्टर्स के लिए यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जब कोविड आया तो सवाई मानसिंह हास्पिटल के जितने भी चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ए.एन.एम., जितना भी जो स्टाफ है और साथ ही आर.यू.एच.एस. में दूरदराज से रैफर होकर जो मरीज आते थे, इन लोगों ने इधर यहां डाक्टर सुधीर भण्डारीजी के नेतृत्व में और उधर वहां डाक्टर अजीत सिंहजी के नेतृत्व में और पूरे राजस्थान में हर चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में जो कोविड का एक शानदार सफल कार्यक्रम इन्होंने रखा ताकि लोगों को परेशानी पैदा नहीं हो, लोगों की जान बचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

साथ ही साथ, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास, मैं परसादी लालजी के लिए यह कहना चाहता हूं कि ये बहुत धीर गम्भीर व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं इनके लिए यह कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास सहनशक्ति के साथ-साथ शक्ति हो तो उस व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं है इसलिए वे भी आभार के पात्र हैं।

साथ ही साथ, अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में यह दिया गया था कि जितने भी चिकित्सा में संविदाकर्मी लगे हुए हैं, आज लगभग तीन-साढ़े तीन साल बीत गये हैं, वह इस बात की आशा लगाये बैठे हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि इनको परमानेंट किया जायेगा। चाहे पंचायती राज की बात हो या चाहे चिकित्सा की बात हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे बहुत गरीब लोग हैं जो सात-सात, आठ-आठ हजार रुपये की नौकरी करते हैं, उनका पेट पालन भी नहीं होता है तो उनको जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जायेगा तो मैं यह समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई हो नहीं सकता।

साथ ही साथ, अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

"आंसू न होते तो यह आंखें इतनी खूबसूरत न होतीं,
अगर मिल जाता सब कुछ एक ही बजट में तो अगले बजट की इंतजार न होती।"

फिर भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, शानदार है। मेरे यहां पर कन्या महाविद्यालय खोली गयी है, एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोला गया है, उनकी जमीन के लिए अधिकारियों ने जाकर मीटिंग्स करना शुरू कर दिया है। आगे बातें बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं सम्माननीय प्रिंसिपल सैक्रेटरी, फाइनेंस साहब से भी मिला और उनको भी मैंने यह आग्रह किया तो उनका भी यही कहना था कि हम दो महीने के अन्दर-अन्दर जितनी भी चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया शुरू करके इस बजट को 31 मार्च, 2023 तक पूर्णतया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।

इनके पूरे वित्त विभाग की टीम, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं और इनके काम की प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय सर्व समाज।

श्री सभापति: माननीय श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने मांग संख्या 13-आबकारी और मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के ऊपर बोलना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में जो आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शराब की दुकानों से जो अवैध वसूली करते हैं उसको मंत्रीजी, रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि यह इसमें पूरे लिप्त रहते हैं।

दूसरा, आबकारी के जो ठेके होते हैं तो वह या तो बस्तियों में होते हैं, जनजाति बस्तियों में होते हैं, अनुसूचित जाति की बस्तियों में होते हैं, मंदिरों के पास, विद्यालयों के पास, चिकित्सालयों के पास, राजकीय कार्यालय के आस-पास और भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर रखा जाये, यह मेरा निवेदन है।

प्रदेश में शराब की दुकानों की लोकेशन स्वीकृति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने वाले आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। राज्य की आबकारी नीति में कृषि भूमि पर व आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकान नहीं खोलने का नियम शामिल करें।

सभापति महोदय, मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगा। राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम कैशलेस स्कीम के अन्तर्गत जो प्रारम्भ की गई है, इस योजना के अन्तर्गत जो मुख्य बड़े अस्पताल हैं, वह केवल आईपीडी की सेवाएं तो उपलब्ध करवा रहे हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को ओपीडी और आईपीडी दोनों तरह की सेवाएं दिये जाने हेतु माननीय चिकित्सा मंत्रीजी निर्देश दें।

ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे डिस्पेंसरी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, उनमें जितने भी डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से 80-90 परसेंट जन प्रतिनिधि आते हैं, वहां पर डाक्टर ठहरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। वे जिला मुख्यालय पर चले जाते हैं या अन्य जगह पर प्रतिनियुक्ति करवा लेते हैं। उसको रोका जाना चाहिए।

अभी हाल ही माननीय चिकित्सा मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया कि जहां से चिकित्सक का वेतन ले रहा है, वहीं उसकी नियुक्ति की जाए, इस आदेश का पूर्णतया पालन कराया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से खुले हुए हैं उनके भवन नहीं हैं। उनके भवनों की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(श्री अमृतलाल मीणा)

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पंचायत समिति जयसमंद और सेमारी में विभाग का ब्लाक कार्यालय खोला जाए। सराड़ा में चिकित्सा विभाग ब्लाक कार्यालय का निर्माण करवाया जाए। अभी सराड़ा में ब्लाक चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का भवन नहीं है।

सराड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां उपखण्ड कार्यालय भी है और बड़ा मुख्यालय है, वहां 50 बैड की स्वीकृति की जाए तथा कस्बे से बाहर उसको स्थापित किया जाए।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के इड़ाणा, खरका, गुडेल, खैराड़, डालटोड़ा, पीलादर, केवड़, नठारा, बलुआ एवं अदवास उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदला जाए और जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जावद, देवपुरा उतरदा, बड़गांव, चावंड, बड़ावली, बरोड़ा, पलोदड़ा, सगतड़ा, इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सलूम्बर की जिला अस्पताल पिछले साल बजट में घोषणा की है लेकिन उसकी न तो वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, न जमीन का मामला है। उस अस्पताल में सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और कार्डियोलॉजी की व्यवस्था कराने की व्यवस्था करें। साथ ही, जिला हास्पिटल होने के नाते 200 बैड करने की बहुत जरूरत है। जनजाति क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सलूम्बर के सभी चिकित्सालयों में समुचित सफाई की व्यवस्था, सफाईकर्मियों के पद रिक्त होने की वजह से हो नहीं पा रही है, उसको कराने की व्यवस्था करायें।

राजकीय हास्पिटल, सलूम्बर व सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों का पदस्थापन कराने के सम्बन्ध में मेरा विशेष चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है। मंत्रीजी बहुत संजीदा हैं, बहुत साइलेंट रहते हैं। करने की चेष्टा है, इच्छा है।

जिला हास्पिटल, सलूम्बर में ब्लड बैंक खोलना बहुत जरूरी है और जो एक्स-रे और सोनोग्राफी की मशीन खराब पड़ी है, उसको ठीक करवाया जाए।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात है कि होम्योपैथिक विभाग से भेजे गये 656 पद सृजित करने के प्रस्ताव को बजट में मंजूर कराने के लिए जन घोषणा पत्र के अनुरूप 571 संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित

(श्री अमृतलाल मीणा)

कर अपना वादा पूरा करें। यही मेरा निवेदन है। सरकार इस वायदे को पूरा करे। धन्यवाद। जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मेरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिस तरह से आज राजस्थान में आवाज गूंज रही है, गांधीवादी नेता के आज पूरे राजस्थान की जनता, सभी कर्मचारी, अधिकारी उनके गुण गा रहे हैं। ऐसा नेता राजस्थान को कभी नहीं मिलेगा। मैं उनको मेरी जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में सीएचसी है, उस सीएचसी में 100 बैड थे, उन्होंने उसमें 50 बैड बढ़ाकर 150 किये। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन है, वह राजा-महाराजाओं के समय का बना हुआ है। वह जर्जर अवस्था में है। हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब ने स्वर्गीय खड़ियाजी की पुण्य तिथि के अवसर पर भवन बनवाने की घोषणा की थी। आज उस भवन के लिए बजट देने की घोषणा करें। वह भवन बहुत पुराना है इसलिए मैं आज कहना चाहूंगी कि इस भवन की मुझे सख्त आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 सीएचसी हैं। कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और डूंगरा छोटा में हैं। डूंगरा छोटा में भी बहुत पुराना भवन है, उस भवन का भी नवीनीकरण किया जाए। मेरे क्षेत्र में कसारबड़ी है, पिछले बजट में माननीय गहलोत साहब ने कसारबड़ी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। जनता आस लगाकर बैठी हुई है। बिलकुल मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर लगता हुआ एरिया है। आये दिन घटनाएं घटती रहती हैं और हमारे लोगों को बांसवाड़ा, गुजरात बहुत दूर पड़ता है तो दौड़कर गाड़ी लेने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं तो देरी होने के कारण कई बार मरीज को जान गंवानी पड़ती है। इसलिए, मैं इसकी मांग करती हूं कि जो पी.एच.सी. हैं, उसको सी.एच.सी. में क्रमोन्नत की जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ीसरवा है, बड़ीसरवा बिलकुल एम.पी. की बोर्डर पर

(श्रीमती रमीला खड़िया)

है। वहां की जनसंख्या आज की तारीख में पांच हजार के लगभग है। उसमें इन लोगों को बहुत दूर पड़ रहा है। आज वहां पर मैं पी.एच.सी. खोलने की मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जीवाखूंटा है, जीवाखूंटा में भी काफी घनी आबादी है। उस आबादी को देखते हुए वहां पर भी मैं पी.एच.सी. खोलने की मांग करती हूं। जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुशलगढ़ में जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें 32 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से आज 22 पद रिक्त हैं, भरे हुए 10 पद हैं। मैं मेरी ओर से और मेरी जनता की ओर से मांग करती हूं कि जल्द से जल्द उन पदों को भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी घटना घट जाती हैं। मैं आबकारी के बारे में कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जन-प्रतिनिधि का पति शादी में से आ रहा था, तो दो पुलिसकर्मियों ने रात को रोककर मारपीट की और पुलिस थाने ले गये और वहां पर भी ले-जाकर मारपीट करके वहां से भाग गये। ऐसे अधिकारी दारू पीकर इस तरह से रात की ड्यूटी निभाएंगे तो जनता का क्या भला होगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इसकी जांच की जाए और ऐसे पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सबक मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुशलगढ़ में दो पी.पी.पी. मोड पर, एक तो टिमेड़ा और दूसरा रामगढ़ में आज तक जो पी.पी.पी. मोड पर दिये गये हैं, इनमें न तो डाक्टर वहां पर बैठता है, न नर्स है और जिन्होंने काम किया था, उनकी तनख्वाह आज तक नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि ऐसे छोटे-छोटे बच्चे लगाकर काम करते हैं, पर उनका पेमेंट नहीं होता है तो उनकी घर-गृहस्थी कैसे चलेगी? मैं मेरी तरफ से और मेरी जनता की तरफ से आपसे मांग करती हूं कि जिन्होंने भी काम किया, उनको भुगतान करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोशनी करके एक महिला है। वह काफी समय से काम करती है और पी.पी.पी. मोड पर वह महिला काम करते-करते आज बहुत परेशान हो गयी। उसको सरकारी विभाग में लगाया जाए, बहुत अच्छी वर्कर है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देती हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री हरेन्द्र निनामा (अनुपस्थित)।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 8.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री हमीर सिंह भायल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 एवं 13 पर विचार

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 13-आबकारी और मांग संख्या 26-चिकित्सा, स्वच्छता एवं सफाई पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-13 के विषय में कहूंगा। विभाग अगर ठेका देता है तो यह लोकेशन से लगाकर, कई ग्राम पंचायतों से लगाकर, नगरपालिका, नगर निगम में कई जगह झगड़े की हालत बनती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव है कि उसकी लोकेशन के लिए यह तय करें कि जो स्थानीय संस्था है, चाहे वह नगरपालिका हो, पंचायत हो, उनका अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर अगर करें तो उसमें थोड़ी सहूलियत मिलेगी। इसी को लेकर अभी मेरे सिणधरी में अन्याली में आज से 10 दिन पहले अवैध ब्रांच पर इतना झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस ने कम से कम 20 लोगों को अन्दर डाल दिया। उसमें भंवरलाल प्रजापत, निम्बाराम जी का छोरा, रामाराम जी का छोरा, इनको चार दिन अन्दर रहना पड़ा। अपन अगर यह लोकेशन सही करके देंगे। माननीय सभापति महोदय, पुलिस वालों ने ऐसे-ऐसे नाम लिख दिये कि आज वह हैदराबाद या मुम्बई में बैठे हैं, ऐसे बीसों आदमियों के नाम लिख दिए, इस वजह से बड़ी प्रोब्लम है। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर मैं निवेदन करना

(श्री हमीर सिंह भायल)

चाहूंगा कि 2020-21 से लगाकर पूरे भारत में और राजस्थान में कोरोना का प्रकोप बहुत रहा। इसका प्रकोप न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में रहा। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी को, कि उन्होंने इस तरह के कुशल प्रबन्ध करके, ऑक्सीजन, हवाई जहाजों से बाहर से लाकर भी, राजस्थान में भी, मैं चिकित्सा विभाग और सारे अधिकारियों को और सब लोगों ने मिलकर कोरोना का सामना किया। इस वजह से अपन को काफी राहत महसूस हुई।

मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, कि चिकित्सा की सुविधा अगर प्रदेश में अच्छी होगी तो हर व्यक्ति को इसका सहारा मिलेगा। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजस्थान में एम्स खोलने का कार्य किया तो आज ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सब लोगों को सुविधा मिल रही है। 2014 से पहले प्रदेश में सिर्फ 7 मेडिकल कालेज थे। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधान मंत्रीजी को, कि राजस्थान के अन्दर अब हर जिला हैडक्वार्टर पर कालेज खोलने के लिए फण्ड देकर आज की तारीख में कितनी कालेज बन गयीं बाड़मेर से लेकर सब जगहों पर।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंहजी के समय में भी इच्छा तो थी, पर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्र में दीनदयाल ज्योति योजना से लाइट देने की इच्छा भी थी, पर पूर्ति मोदीजी ने की। भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा, कि उन्होंने ऐसा कार्य करके जनता के लिए एक सुविधाजनक जो कार्य किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कोविड प्रबन्ध को लेकर सारे अधिकारियों ने और जन-प्रतिनिधियों ने मिलकर, भामाशाहों ने मिलकर राजस्थान में गांव-ढाणी तक, जो बाहर बैठा था, बाहर से जो पैदल लोग आये, उनके लिए भी, भामाशाहों, जन-प्रतिनिधि और ग्रामीणजनों ने भी, सबने मिलकर उनकी मदद की, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना काल के दो साल में हर व्यक्ति की सेवा करने में, जिसके पास भी जो गुंजाइश थी, मदद की। मैं भामाशाहों के लिए निवेदन करूंगा कि मेरे समदड़ी में पीपाजी के मन्दिर में उन्होंने डेढ़ साल तक अपना लंगर चलाया। कोई भी कोरोना पीड़ित और उनकी सेवा करने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने कोई तरह की कमी नहीं रखी।

(श्री हमीर सिंह भायल)

माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में ऐसा भी हुआ कि कई जन-प्रतिनिधियों ने अलग जमीन पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को हटाने के लिए बंकर लगाकर वहां कोरोना का कैम्प लगा दिया और दूसरी जगह से स्टाफ के लोगों को ले-जाकर वहां एक भी पेशेंट भी भर्ती नहीं हुआ। आदरणीय मेवाराम जी मेरे सामने देख रहे हैं और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मंत्रीजी, आप जांच करवा लेना, एक भी पेशेंट नहीं था। वहां पर केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए बंकर लगाकर कोरोना का कैम्प खोला गया। वह नजारा भी देखने को मिला।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दो सी.एच.सी. मिलीं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं मुख्य मंत्रीजी को। पी.एच.सी., सी.एच.सी. खोली, उसका धन्यवाद दे रहा हूं। वहां जमीन रोकने के लिए कार्य किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर इंडीकेट करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कोविड काल में भी जमीन पर कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी बिराजे हैं, पूरे बाड़मेर में वहां पर इतने पद रिक्त पड़े हैं और सिवाना में भी हर विभाग में अधिकारी नहीं है, पर चिकित्सा के बारे में मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पी.एच.सी., सी.एच.सी. में जितने पद होने चाहिए, वह सारे खाली पड़े हैं। आप जल्दी से जल्दी जो भवन जर्जर पड़े हैं, उनको भी ठीक करवाएं और स्टॉफ की भी पूर्ति करें। आज की तारीख में सिवाना के अन्दर सी.एच.सी. होते हुए एक भी डाक्टर नहीं है। समदड़ी में छह डाक्टरों की जगह है उसकी जगह एक डाक्टर है। पादरू में दो डाक्टरों की जगह एक है, सिणधरी में चार पद खाली पड़े हैं। जगह-जगह पद खाली पड़े हैं, उनको भरने की कोशिश करें। अस्पताल में महिला चिकित्सकों की वास्तव में कमी है, मैं मानता हूं, पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम रहती है। अगर जिले में नम्बर आए तो सिवाना विधान सभा क्षेत्र में भी देने के लिए मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि वहां भी पद भरें।

(समय: 19.00 बजे)

बजट घोषणा के आधार पर पंचायत मुख्यालयों पर सब सेंटर्स खोले जायें। इसमें भी मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप सिवाना को राजस्थान में मानते हुए व्यवस्था करें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

सभापति महोदय, मैं स्टाफ की कमी की पूर्ति करने के लिए निवेदन करूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें। नई पीएचसी, जिसमें आप आबादी के आधार पर मान रहे हो, उसमें स्वास्थ्य केन्द्र कम हैं। धनवा, जेठंतरी, चारणों की ढाणी, थापन ग्राम पंचायत मुख्यालय में नये पीएचसी केन्द्र खोले जाने का निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि समदड़ी का जो अस्पताल है, बहुत बड़ा और पुराना अस्पताल है। बजट की स्वीकृति हो गयी है तो जल्दी ही टेंडर कराकर उसकी मरम्मत करा दें तो बहुत बढ़िया होगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग के सभी डाक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को कोरोना के और वैक्सीनेशन के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए अपनी तथा अपनी जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से यह लोग बधाई के पात्र हैं।

मैं राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस बजट में और इससे पूर्व के बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए, जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बेहतरीन काम किया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

सरकार ने जो काम किये हैं उसके लिए मेरे से पूर्व सदस्यों ने सदन में सारी बातें रख दी हैं इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं।

सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करके नीमकाथाना की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। एक मदर एंड चाइल्ड हास्पिटल 100 करोड़ की लागत का स्वीकृत किया है। इसी तरह से अन्य सुविधाएं सीएचसी वगैरह खोली हैं।

(श्री सुरेश मोदी)

मेरे यहां अब 3 और सीएचसी सिरोही, हशामपुर और मावण्डा खुर्द की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि यह सीएचसी शीघ्र खोली जायें। एक शहरी सीएचसी की योजना नयी आई है। उसके तहत मैं इंडस्ट्रियल एरिया नीमकाथाना में शहरी सीएचसी खोलने की मंत्री जी से मांग करता हूं।

मेरे यहां दरीबा, कोटड़ा, नाथा की नांगल, पुराना बास, बिहार, बासड़ी खुर्द व घासीपुरा में नवीन पीएचसी खोली जायें। इस बात की मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने 1 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है। मेरे यहां डूंगरवास, मीणा की नांगल, नानगवास, बलेश्वर और मानपुरा ऐसे गांव हैं, जिनमें नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग करता हूं।

नीमकाथाना माइनिंग जोन है। बहुत सारे क्रेशर यहां लगे हुए हैं। बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। चारों तरफ हाईवे से जुड़ा हुआ है। आये दिन वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे यहां के अस्पताल में साल में 5 हजार से ज्यादा प्रसव होते हैं। ब्लड की बहुत बड़ी आवश्यकता हर समय बनी रहती है। मेरे यहां एक नये ब्लड बैंक की स्थापना की जाये। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं।

मेरे यहां जिला अस्पताल क्रमोन्नत हुआ। लेकिन जो पूर्व से उप जिला अस्पताल में रेडियोग्राफर के 7 स्वीकृत पद थे, जिला अस्पताल बनने के बाद उनको कम करके 5 कर दिया। यानी सुविधा बढ़ाने के बजाय कम कर दी गयी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जो पहले से 7 पद थे, वह तो कम से कम रखे ही जायें। उनसे एक-आध पद बढ़ाये जाने की मैं मांग करता हूं।

जिला अस्पताल स्वीकृत हो गया, घोषित हो गया लेकिन उसमें सुविधाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। उसमें एक्सरे और सोनोग्राफी की जो मशीनें आनी हैं, वह जल्द से जल्द आयें। यह मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं।

मैं मंत्री जी का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में डाक्टर्स जो गंभीर मरीज होते हैं उनको बाहर रेफर कर देते हैं। जयपुर या सीकर रेफर कर देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि कोई दिशा-निर्देश राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिये जायें कि किन मरीजों को बाहर रेफर करना होता है। यह लोग पल्ला झाड़ लेते

(श्री सुरेश मोदी)

हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। मेहनत करने से बचना चाहते हैं इसलिए यह उनको रैफर कर देते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई दिशा-निर्देश दिये जायें कि किन केसेज में मरीज को बाहर रैफर करना होगा।

इसी प्रकार से सरकारी अस्पताल के जो डाक्टर्स हैं, वह अस्पताल के बजाय घर पर या किसी प्राइवेट अस्पताल में मरीज को देखना ज्यादा पसन्द करते हैं। इस सम्बन्ध में भी कोई इस तरह के दिशा-निर्देश या व्यवस्था की जाये जिससे कि वह लोग अस्पताल में भी मरीजों को देखने में उतना ही ध्यान लगायें, जितना वह प्राइवेट अस्पताल, घर पर देखने में लगाते हैं। वह जो घर पर फीस लेते हैं उस पर कोई अंकुश नहीं है। मनमानी फीस बढ़ा देते हैं। अभी मेरे यहां घर पर देखने की फीस डबल कर दी गयी है। इस पर भी अंकुश लगे, इस तरह की कोई व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक समस्या और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से डाक्टर पीजी करने चले जाते हैं। वह 2 साल में पीजी करके वापस आते हैं, तब तक वह अस्पताल बगैर डाक्टर के ही चलता है। जबकि सरकारी कागजों में उस अस्पताल में डाक्टर की पोस्टिंग है। तनख्वाह वहां से उसकी उठती है। यदि ऐसा कोई डाक्टर पीजी करने जाये तो उसको या तो एपीओ किया जाये अथवा उसकी तनख्वाह और कहीं से उठे। ग्रामीण क्षेत्र में जिस अस्पताल में वह काम कर रहा था, उसमें दूसरे डाक्टर की पोस्टिंग की जाये जिससे कि वहां जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो पद खाली हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाये। दूसरे विभागों में खाली हैं, उनमें जैसे-तैसे काम चल सकता है लेकिन स्वास्थ्य के मामले में समझौता नहीं होना चाहिए। इसमें जितने पद खाली हैं, उन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जाये। चाहे आपको नयी नियुक्तियां करनी पड़ें, चाहे आपको जो पुराने हैं, उनको वापस ड्यूटी पर लेना पड़े, चाहे संविदा पर लेना पड़े, कोई भी व्यवस्था करें लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पद जल्दी से जल्दी भरे जायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के डाक्टर्स, जीएनएम, एएनएम और जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह किये बिना क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए मदद की। उसके लिए उनका खूब धन्यवाद और खूब बधाई।

मैं लम्बी चर्चा नहीं करूंगा। मैं सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 2 सीएचसी हैं। वहां पर एक आदर्श सीएचसी बनाने के लिए मुझसे एक लैटर मांगा था। मैंने आदर्श सीएचसी के लिए आहोर का लिखकर दिया। आदर्श सीएचसी में बाकी सब संसाधन तो व्यवस्थित हैं, लेकिन मेरे यहां जो भी स्पेशलिस्ट डाक्टर होते हैं जैसे सर्जन, गायनिक, बच्चों के डाक्टर और आई स्पेशलिस्ट इन सभी के पद रिक्त हैं। वह आदर्श सीएचसी कैसे बनेगी? जब वहां पर पद ही रिक्त हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आदर्श सीएचसी उसी को मानें जिसमें सारे पद 100 परसेंट भरे हुए हों, तभी वहां इलाज होगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आहोर सीएचसी में जो भी डाक्टर्स के पद रिक्त हैं, तुरन्त प्रभाव से उनको भरा जाये। उसके बाद, इसी अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाया जाये। वह बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरा उपखण्ड स्तर का है। इसको अगर उप जिला अस्पताल बनायेंगे तो वहां के जो रहवासी हैं उनको इलाज मिलेगा। घोषणाएं तो हम बहुत कर लेते हैं लेकिन इसकी क्रियान्विति तभी होगी जब वहां पर इलाज मिलेगा। इलाज तभी मिलेगा जब वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। वहां पर जो 50 बैड का हास्पिटल है उसको भी 100 बैड का किया जाये जिससे आहोर की सीएचसी लोगों के इलाज के काम आ जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे आहोर में ट्रोमा सेंटर भी घोषित हुआ था लेकिन अभी तक वहां पर ट्रोमा सेंटर का कोई वजूद नहीं लग रहा है तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि उस ट्रोमा सेंटर की व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखें।

(श्री छगनसिंह)

माननीय सभापति महोदय, सियाणा में जो सीएचसी है, वहां 6 डाक्टरों की पोस्ट है, 6 के 6 ही खाली हैं। हमारे दो सीएचसी हैं दोनों में डाक्टरों की पूरी की पूरी कमी है। माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करूंगा कि दोनों जो भी पद खाली हैं, डाक्टर्स के वो सारे भरे जायें, जिससे वहां की जनता को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से आपने जो 01 लाख की आबादी का हवाला दिया है कि वहां पर सीएचसी कर सकते हैं तो हमारे यहां ऐसे क्षेत्र भाद्राजून, बागरा, गुढ़ा बालोतन और चांदरई है, इन चारों जगहों के लिए आप अपने अधिकारियों से प्रपोजल मंगवाकर वहां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नति की व्यवस्था करें। भाद्राजून, बागरा और चांदरई और गुढ़ा बालोतन, वास्तव में सीएचसी बनाने के लायक हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन चारों पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांवों में आज भी हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए तरसते हैं, हमारे कई क्षेत्रों में आज भी पीएचसी की सुविधा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बारबार मांग कर रहा हूं और इसके प्रपोजल भी आये हुए हैं तो ग्राम पंचायत ऊण, शंखवाली, मेड़ा ऊपरला, नोरवा, अगवरी, उम्मेदपुर, रोडला और रामा, इनमें पीएचसी स्वीकृत करवायें क्योंकि वहां पर वास्तव में बहुत ही, बहुत ही जरूरत है, वहां के लोग हमेशा बहुत दूर से क्योंकि ढाणियों में बसे हुए हैं और दूरी भी खूब है तो यहां पर अगर पीएचसी हो जाये तो वास्तव में हमारे क्षेत्र में लोगों का भला होगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट सत्र में अबकी बार बजट घोषणा में एक हजार सब सेंटर की घोषणा की है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं और ज्यादा लम्बी मांग भी नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुमेरगढ़, खेड़ा, पाण्डगरा, तरवाड़ा, साण्डन, नारवणा, छांगाड़ी, पलासिया, गुढ़ा रामा, बीजली और रसियावास खुर्द, इनमें अगर सब सेंटर खुल जायें तो वहां पर आधों में तो सब सेंटर की बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन वहां पर पोस्ट अभी तक नहीं भरी गयी है तो इन गांवों में अगर सब सेंटर की घोषणा कर दी जाये तो बहुत मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, पीपीपी मोड की सब चर्चा कर रहे हैं और

(श्री छगनसिंह)

लास्ट में मुझे जवाब भी मिला था पिछली बार कि जो भी पीपीपी मोड पर हैं उनका नया एमओयू नहीं करेंगे, नया एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो मेरी भंवरानी और घाणा पीएचसी इनको जल्दी से अपने पीपीपी मोड से हटाकर गवर्नमेंट में लाया जाये जिससे वहां के लोगों का समुचित इलाज हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जो सब सेंटर की बिल्डिंग्स हैं, काणदर, कान्बा और थावला में बार-बार चर्चा करता रहता हूं, लेकिन तीनों की बिल्डिंग एकदम खण्डहर हैं और दूसरी जगह पर बैठकर एएनएम इलाज करती है तो इन तीनों सब सेंटर की बिल्डिंग के लिए नया बजट स्वीकृत करायें। पावटा पीएचसी जो घोषित की हुई है, पिछले बजट में जिसकी घोषणा की गयी थी उसको अभी तक बनाया नहीं गया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी भी वित्तीय स्वीकृति जारी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सै विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, अपने क्षेत्र में राजस्थान के अन्दर जो पहले पेंशनर और कर्मचारी होते थे उनका इलाज राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी होता था, मध्य प्रदेश में भी होता था मतलब पूरे भारत में कहीं भी करवा सकते थे लेकिन अब जो कैशलेस व्यवस्था में सरकारी चिकित्सालयों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न निजी चिकित्सालयों को भी आरजीएचएस योजना में जोड़ा गया है। राजस्थान के बाहर के चिकित्सालय इस आरजीएचएस योजना में शामिल नहीं किये गये हैं। इस योजना से पहले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, गम्भीर और अति गम्भीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए राजस्थान के बाहर चिकित्सा कराने पर पुनर्भरण राशि उनको देय होती थी, लेकिन अब जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र जालौर, सिरोही और पाली के लोग हमारे पास गुजरात नजदीक पड़ता है, अहमदाबाद, मेहसाणा, पालनपुर, डीसा, वहां जाते हैं क्योंकि उनको इन जगहों की तुलना में जयपुर, बीकानेर जाना ज्यादा कठिन होता है। यही स्थिति सभी सीमावर्ती जिलों के पेंशनरों और राज्य कर्मचारियों की है, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के व्यक्ति पंजाब के किसी निकटवर्ती अस्पताल, झालावाड़ के लोग मध्य प्रदेश जाते हैं, वहां जाना उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, भाषा संवाद की सरलता, भौगोलिक निकटता की दृष्टि से सब प्रकार से सुविधाजनक रहता है। मेरा निवेदन है कि आरजीएचएस योजना

(श्री छगनसिंह)

में गम्भीर और अति गम्भीर स्थिति होने पर, राज्य से बाहर चिकित्सा कराने पर पहले की भांति पुनर्भरण सुविधा बहाल करें, इसकी मैं मांग करता हूं। पहले जो पुनर्भरण देते थे वह सुविधा पुन: शुरू करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 13 और मांग संख्या 26 पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हम किन शब्दों में हमारे जन नायक मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करें, शब्दों में उनके कार्यों का हम व्याख्यान नहीं कर सकते। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने, आम जन, गरीब व्यक्ति के दु:ख दर्द को समझते हुए अपने हर कार्यकाल में चाहे हम मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की बात करें, चाहे हम चिरंजीवी बीमा योजना की बात करें, इस बढ़ते महंगाई के दौर में उन्होंने चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे मध्यम परिवार हो जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज किसी के परिवार में कोई भी बीमारी आती है तो परिवार आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होता है। इस बढ़ती महंगाई में छोटी-सी बीमारी के लिए भी हजारों-लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन मुख्य मंत्रीजी के फैसले की वजह से उनकी कार्यकुशलता की वजह से आज हमारे राजस्थान का आम नागरिक अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है कि उसके समस्त तरह की बीमारियों का इलाज राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क होता है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जो 10 लाख रुपये का जो इलाज फ्री हो रहा है और उसमें बोनमेरो, हार्ट, किडनी जैसी गम्भीर बीमारियां भी सम्मिलित की गयी हैं, इसके लिए भी हम मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि आज समय का अभाव है, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी बताया और हमारे वर्तमान चिकित्सा मंत्री

(श्री अमित चाचाण)

परसादीलाल जी भी सरकार की योजनाओं के बारे में उल्लेख करेंगे इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है माननीय सभापति महोदय, इसमें जो डिलिवरी सिजेरियन द्वारा की जाती है उस पैकेज को इसमें शामिल नहीं किया गया है, हालांकि राजकीय चिकित्सालयों में तो यह शामिल है लेकिन निजी चिकित्सालय में जाने पर कोई डिलिवरी सिजेरियन द्वारा की जाती है तो उसमें आज बीस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का खर्चा आता है जो गरीब परिवार को, मध्यम परिवार को वहन करना पड़ता है। आपके माध्यम से मेरी यह मांग है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में सिजेरियन डिलिवरी का भी निजी चिकित्सालयों के पैकेज में शामिल करना चाहिए। इसके तहत आज बड़े हास्पिटलों में हम देखते हैं कि अमूमन हार्ट की बीमारी रोजाना होती रहती है लेकिन बड़े हास्पिटल हार्ट के जो स्टेंट डलते हैं उनके उस पैकेज को मानते नहीं हैं, मना कर देते हैं तो सख्ती के साथ उनको पाबन्द किया जाये कि हार्ट का कोई भी पेशेंट आये तो उसको भी इस पैकेज में शामिल करते हुए उसको राहत दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ हमारे संविदाकर्मी एनआरएचएम के जो काफी दिनों से धरने पर भी हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सभी माननीय विधायकों ने भी कहा उनका भी समर्थन करते हुए चाहे उसमें लेखाकार हो, चाहे ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर हो, चाहे पीएचसी हैल्थ सुपरवाइजर हो, चाहे कम्प्यूटर आपरेटर हो या चिकित्सा विभाग में अन्य कोई संविदाकर्मी हो, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सरकार को उनको नियमित करने का काम करना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, इसकी भी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रयोगशाला सहायकों की अंतिम चयन सूची जारी करने की मैं भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस पर भी विचार किया जाये। इसके साथ में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदयजी का, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्माजी का, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाषजी गर्ग का, वर्तमान हमारे चिकित्सा मंत्री परसादीलालजी का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र जो चार दशकों से राजकीय चिकित्सालय के क्रमोन्नति की बाट जोह रहा था, उसको 50 से 100 बैड में करने का काम किया। ट्रोमा सेंटर की आपने हमें सौगात दी। इस पर उप जिला चिकित्सालय के तहत जो

(श्री अमित चाचाण)

क्रमोन्नत किया और मेघाणा में सीएचसी दी, ललाणा को पीएचसी में क्रमोन्नत किया उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का चिकित्सा मंत्रीजी का तहेदिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे नोहर का राजकीय चिकित्सालय जो पूर्व की सरकार के समय में एक रैफरल हास्पिटल माना जाता था और जहां 4-5 डाक्टर काम करते थे और हमारे पूर्व के जन प्रतिनिधियों की उदासीनता से उस हास्पिटल में कोई मरीज जाता नहीं था, आज वही राजकीय चिकित्सालय जब कोरोना जैसी महामारी आयी तो वहां रोजाना 60 से 65 मरीजों का इलाज किया जा रहा था।

वैसे हाई स्कोर के जो बीस से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल के स्कोर थे, उनका इलाज और अगर मेरे पड़ोस के हरियाणा में वे मरीज जाते थे तो पांच लाख रुपये प्रति मरीज का लगता था, मैं मानता हूं कि लाखोंकरोड़ों रुपये नोहर विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों के बचे हैं। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं मेरे क्षेत्र के दानदाताओं का, भामाशाहों का और एक हमारे यहां समिति बनी है मिशन सौ स्वास्थ्य समिति का, जिनके अथक प्रयासों से आज हमारा राजकीय चिकित्सालय रोजाना नयी ऊंचाइयों को छू रहा है।

मैंने मेरे प्रयास से डीएमएफटी फंड से एक अत्याधुनिक सात बैड का आईसीयू निर्मित किया है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, छोटे कस्बे में सीएचसी लेवल पर राजस्थान में कहीं भी ऐसा आईसीयू वार्ड नहीं मिलेगा। मैंने पचास लाख रुपये से सौ सिलेंडर डेली क्षमता के हिसाब से विधायक कोटे से ऑक्सीजन प्लांट लगाया, पच्चीस लाख की लागत से एम्बुलेंस दी, दो डायलिसिस मशीनें लगवायीं, ऑर्थो का अलग से ओटी बनाया।

आज मुझे गर्व है कि मेरे राजकीय चिकित्सालय में, पूरे हनुमानगढ़ जिले की सीएचसी को मिला दिया जाये तो उससे ज्यादा नोहर के सीएचसी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में कार्य किया जा रहा है और अस्सी लाख रुपये से ज्यादा का कार्य मेरे नोहर के चिकित्सकों ने किया है। इसके लिए मैं उनका और तमाम स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि वे ईमानदारी और सच्चाई के साथ कार्य कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में चाहे वह कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, दानदाताओं, भामाशाहों के द्वारा बनायी गयी है, लेकिन आज मुझे इस चीज का अफसोस है कि नोहर में 1998 में सेठ

(श्री अमित चाचाण)

फकीरचंद लालचंद कंदोई चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक चिकित्सालय का भवन बनाकर गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया था। तत्कालीन राज्यपाल द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। उस समय यह मातृ शिशु रोग की इकाई के रूप में शुरू हुआ, लेकिन हमें उसके लिए बड़ी शर्म आ रही है कि आज वह राजकीय चिकित्सालय मात्र टीकाकरण का बनकर रह गया है और उसे शहरी पीएचसी के रूप में संचालित किया जा रहा है। अगर दानदाता करोड़ों रुपये लगाएं और इस तरह की व्यवस्था देखें तो शायद उन्हें भी दर्द होगा। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि दानदाताओं के मान-सम्मान को रखते हुए, उनके मान-सम्मान को बढ़ाने के लिए उस शहरी पीएचसी को या तो शहरी सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये या उसमें पुन: मातृ एवं शिशु रोग इकाई का संचालन किया जाये, जिससे कि दानदाताओं के हौसले बुलन्द हों और अन्य भी उससे प्रेरित हों।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे नोहर का राजकीय चिकित्सालय, जो लगभग साठ वर्ष पूर्व दानदाताओं के द्वारा, सेठ कृष्ण लाल जी थिराणा के द्वारा बनाया गया था, वह आज छोटा पड़ रहा है। उसके पूरे भवन के निर्माण की आवश्यकता है। उसकी पूरी बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये। इसके साथ ही मैं दानदाता साहेवाला परिवार, रानियावाला परिवार और चाचाण परिवार का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा भी करोड़ों रुपये इसमें लगाये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पल्लू क्षेत्र, जहां मां ब्रह्माणी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें हमने सीएचसी भवन का तो उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसके चारों तरफ की चारदीवारी आज भी बकाया है। 48 लाख रुपये का उसका एस्टीमेट बनकर आया है। मेरे द्वारा अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन वह काम आज तक अधूरा है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं, उसका भी निर्माण करवाया जाये। इसके तहत नोहर के राजकीय चिकित्सालय में नेत्र रोग के डाक्टर हैं, ईएनटी के डाक्टर हैं, लेकिन उनके पास कोई सामग्री ही नहीं है। इसके लिए भी मैंने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है।

हालांकि मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं राजकीय चिकित्सालय में अधिकांश पैसा दानदाताओं, भामाशाहों, विधायक कोटे और डीएमएफटी फंड से लगाऊं, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता होती है कि सरकार के द्वारा भी

(श्री अमित चाचाण)

उसमें कुछ किया जाये तो मेरी आपसे मांग है कि उसमे यदि यह व्यवस्था की जाती है तो लोगों को फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा कस्बा जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर है। वहां कई प्राइवेट हास्पिटल भी हैं, सिजेरियन आपरेशन भी होते हैं तो मेरी आपके द्वारा मांग है कि उसमें यदि ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है तो हमें बहुत फायदा होगा और हरियाणा से हमें ब्लड नहीं लाना पड़ेगा। रोगियों को इससे सुविधा मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से आबकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं गांवों में दलित बस्तियों में दुकानें खोल दी जाती हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम दलित परिवारों की ज्यादा संख्या है, वहां ये दुकानें न खोली जाएं। इसके साथ ही, हरियाणा निर्मित शराब बोर्डर से होते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, उस पर अंकुश लगाया जाए और आज आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास एक-दो बोतलें होती हैं, उन पर तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो शराब माफिया पनप रहे हैं, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती। आठ बजे बाद भी शराब की बिक्री की जाती है। आपके द्वारा मैं मांग करता हूं कि अधिकारियों को पाबन्द किया जाये कि एक अभियान चलाकर, जो भी जहरीली शराब, चाहे हरियाणा निर्मित हो, बाहर से सप्लाई की जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जाये। रात को आठ बजे बाद जो शराब बिक्री की जा रही है, उस पर अंकुश लगाया जाये। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। इसके साथ ही, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नोहर के खुइयां मोटेर में सब्सेंटर को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये और इसके साथ ही, धानसिया व मन्दरपुरा को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। एक बार पुन: आपका आभार। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई एवं आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज जब पूरे विश्व में कोविड-19 की वजह से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी और यूं लगने लगा कि विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और

(श्रीमती अनिता भदेल)

इस विज्ञान के भरोसे ही इंसान को बचाया जा सकता है, तब कोविड-19 आया और देखने को मिला कि कितनी कोशिशें करने के बावजूद भी हम हमारे बहुत सारे ऐसे साथियों को नहीं बचा पाये, जिन्हें अपनी पूरी उम्र जीनी थी। आज वे इस दुनियां में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब हम विचार करते हैं कि इंसान ने कितनी तरक्की की है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न हमारे सामने लगता है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, जिसके बारे में भी आज तक भी यह कहा जाता है कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी वह नहीं देती है, उसके बावजूद भी चूंकि उसका प्रचलन इतना विस्तार ले चुका है कि हम पीछे नहीं हट सकते, ऐसी स्थिति में हम सिर्फ उसमें सुधार करके उस चिकित्सा पद्धति को लोगों के स्वास्थ्य के लिए बना सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, चूंकि बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं मिला है इसलिए अपने विधान सभा क्षेत्र और अपने जेएलएन मेडिकल कालेज के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जेएलएन मेडिकल कालेज अजमेर सम्भाग का सबसे बड़ा मेडिकल कालेज है और उस मेडिकल कालेज से सम्बद्ध दो चिकित्सालय हैं- एक जनाना हास्पिटल और एक सैटेलाइट हास्पिटल। जब कोविड-19 आया, उस समय पूरे जेएलएन हास्पिटल को डेडिकेटेडली कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बाकी की बीमारियों के मरीज कहां जाएं उपचार कराने के लिए तो उनके पास एकमात्र रास्ता था अजमेर का सैटेलाइट हास्पिटल। अब अजमेर सैटेलाइट हास्पिटल चूंकि पूरे सम्भाग का भार नहीं सह सकता था, इसीलिए उसमें अतिरिक्त डाक्टर्स को लगाया गया स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप डाक्टर रहे हैं, इसलिए स्टाफिंग पैटर्न में एक सौ बैडेड हास्पिटल में कम से कम 23 डॉक्टर्स का होना आवश्यक है, लेकिन अजमेर सैटेलाइट हास्पिटल में 23 की जगह मात्र 9 पद स्वीकृत हैं। अब यह जो सौ बैडेड चिकित्सालय है, वह 160 बैडेड होने जा रहा है। आपके आदेशों से 60 बैड और 20 अतिरिक्त बैड बढ़ाये जाने के आर्डर निकाले जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में जब यह 160 बैडेड हास्पिटल हो जायेगा तो 9 डाक्टर्स के पदों से हम कितनी सेवाएं दे पायेंगे, यह बहुत बड़ी समस्या उस हास्पिटल के लिए खड़ी होने वाली है, क्योंकि आपने फिलहाल ही

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक आर्डर निकाला है कि जो डाक्टर्स कहीं और से वेतन उठा रहे हैं, उन सबको रिलीव होकर अपने-अपने मूल पदस्थापन पर जाना है, पर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार हम उस सैटेलाइट हास्पिटल के पद क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अजमेर सैटेलाइट हास्पिटल, जो जिला चिकित्सालय है और मेडिकल कालेज का पार्ट है, उससे सम्बद्ध है, उसमें स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार चूंकि वह 160 बैडेड होने जा रहा है, आपको कम से कम 36 पद सृजित करने चाहिये और उन पर पोस्टिंग करनी चाहिये। हमेशा से ही, मैं लगभग 15-20 सालों से देख रही हूं, जब-जब डाक्टर्स को अपने मूल पदस्थापन पर भेजने की बारी आती है, तब-तब सैटेलाइट हास्पिटल में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अब इस हास्पिटल को चलाएं कैसे तो क्या इसे ताला लगा देना चाहिये?

माननीय सभापति महोदय, प्रतिदिन उस हास्पिटल का आउटडोर लगभग दो हजार है और ऐसी स्थिति में हम उस आउटडोर को बन्द कर दें तो यह ठीक बात नहीं होगी। एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। समस्या तो आप खतम करेंगे, क्योंकि समस्या तो आपके अधिकारियों ने पैदा की थी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, जब कोविड-19 आया तो सरकारों, जन प्रतिनिधियों और आम जन, सबने इसके उपायों पर ध्यान देने की कोशिश करी कि किस तरह से इससे बचा जा सके। माननीय मंत्री महोदय, अवेयरनेस के नाते से या ऑक्सीजन की कमी न रहे, इसलिए आम लोग भी सामने आये और उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अपनी तरफ से उपलब्ध कराए और हमें भी क्योंकि हम जन-प्रतिनिधि हैं और लोगों की जान बचाना हमारा पहला दायित्व था इसलिए अपने विधायक कोष से जितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद सकते हैं, उतने खरीदने के लिए हमने हाथों-हाथ स्वीकृतियां जारी कीं। जितना जिला कलेक्टर महोदय ने हमें कहा कि आपको 50 लाख देने हैं तो 50 लाख दिये, उन्होंने कहा एक करोड़ देने हैं तो एक करोड़ दिये, उन्होंने कहा 25 लाख देने हैं तो 25 लाख दिये। माननीय सभापति महोदय, मैंने विधायक कोष से 25 लाख रुपये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए दिये और उसमें यह लिखा कि दस लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसमें खरीदा जाये पर, माननीय मंत्री

(श्रीमती अनिता भदेल)

महोदय, कितना मजाक हुआ है, मतलब उस दरमियान जो खरीद हुई वह कितनी घटिया किस्म की हुई है। जो हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको मैंने लगातार, मेरे फोन का रिकार्ड आप देख सकते हैं कि मैंने उनको यह फोन किया है कि आप दस लीटर के खरीदेंगे और आप आईएसआई मार्का वाले खरीदेंगे। माननीय सभापति महोदय, उसके बावजूद मेरे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गये और वे 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, चूंकि आज मैं लायी नहीं, मैं चाहती थी कि उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विधान सभा के पटल पर रखूं, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज भी मैंने रखा हुआ है, वह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मात्र खिलौना था माननीय सभापति महोदय। वह कामर्शिलय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं था। मैंने जब उसको चैक किया तो उसमें बहुत सारी कमियां निकालकर जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी कि आप इस-इस बिन्दु पर जांच कराइये और जब उसकी जांच हुई, जो मेडिकल कालेज की टीम ने जांच की तो उस जांच रिपोर्ट में यह आया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस मानदण्ड के नहीं हैं जो हास्पिटल में काम लेने चाहिए। इसलिए वह रिपोर्ट उन्होंने बनायी, लेकिन मेरे बार-बार आग्रह पर वह रिपोर्ट मुझे आज तक नहीं दी। उसको मेडिकल कालेज के डिस्पेच रजिस्टर में डिस्पेच कर रखा है, हास्पिटल के डिस्पेच रजिस्टर में वह रिपोर्ट है लेकिन मुझे आज तक नहीं मिली। फिर प्रभारी मंत्री जी जब अजमेर गये तो मैंने प्रभारी मंत्री जी को निवेदन किया। प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि उसकी जांच करायेंगे, लेकिन आज तक उसकी जांच कहां हुई, पता नहीं। माननीय सभापति महोदय, जांच होने के बाद में मेडिकल कालेज की रिपोर्ट सीएमएचओ कार्यालय आयी तो सीएमएचओ ने जो 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे उनको रातों-रात रिप्लेस कर दिया। जब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घटिया क्वालिटी के थे तो आपने रिप्लेस क्यों किये और रिपोर्ट यदि आयी है तो रिपोर्ट आपने मुझे क्यों नहीं दी? फिर उसके बाद में मेडिकल कालेज को सिर्फ जांच करने का राइट था कि आप जांच करके बतायेंगे कि ये उस मापदण्ड के अनुसार सही हैं या गलत हैं। मेडिकल कालेज में भी डाक्टर हैं और सीएमएचओ कार्यालय में भी डाक्टर हैं तो एक डाक्टर दूसरे डाक्टर की बुराई नहीं कर सकता, एक डाक्टर दूसरे डाक्टर के लिए नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता इसलिए वे सारे के सारे, 26 के 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रातों-रात बदल दिये गये। अब जब पूछा जाता है तो रिपोर्ट नहीं आती कि रिपोर्ट गलत है, अब यह बताया जाता है कि हमने तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बदल दिये। सभापति महोदय, यह तो मैंने आवाज उठायी थी इसलिए मेरे विधायक कोष के 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बदल गये पर उसी टेंडर में बाकी के एमएलए के भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे और वे 100 के 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज रद्दी में, कबाड़ में पड़े हुए हैं तो 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिस सप्लायर से आपने खरीदे, कहां-किसने कमीशन खाया, कितना कमीशन खाया?

मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि इसी प्रकार से खरीद में यह घोटाला होता रहेगा तो फिर कोई एमएलए विश्वास नहीं करेगा, कोई जनता विश्वास नहीं करेगी कि एमएलए ईमानदारी से अपना काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम में नहीं आया और वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बदलकर नये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख दिये गये। वे भी चूंकि 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेटेलाइट हास्पिटल के लिए थे और 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे चन्द्रवरदाई सीएचसी के लिए थे। सेटेलाइट हास्पिटल में तो 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच गये, परन्तु सीएचसी चन्द्रवरदाई में आज तक वे 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं पहुंचे माननीय मंत्री महोदय। तो किसने पैसा खाया? उस अधिकारी को आपको सस्पेंड करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है ताकि आइंदा कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं करे। मतलब हम तो लोगों को बचा रहे हैं, हम तो दर-दर की ठोकरें खाकर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और उस समय आपके अधिकारी इस तरह से कमीशन खाकर लोगों को मारने का काम कर रहे थे। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जांच करायें। जांच हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें और जो दोषी अधिकारी है उसको दण्ड देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरे यहां जेएलएन मेडिकल कालेज है, अब घोषणाएं तो हर वर्ष होती हैं कि हम जेएलएन हास्पिटल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक बनायेंगे, हम ट्रोमा सेंटर बनायेंगे, हम नेफ्रोलॉजी का डाक्टर अपाइंट करेंगे। मुझसे पूर्व अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको निवेदन किया है। हमारे यहां अजमेर मेडिकल कालेज में जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें सीटीवीएस विभाग है, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि बाईपास सर्जरी आज अजमेर जेएलएन मेडिकल कालेज में नहीं हो रही है। अजमेर सम्भाग के जितने पेशेंट हैं उन सब पेशेंट को, चाहे वह नागौर

(श्रीमती अनिता भदेल)

का हो, चाहे टोंक का हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, या तो उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है या उनको जयपुर आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां हार्ट की, अब तो सब जगह, एक-एक जिला मुख्यालय पर यह सुविधा हो गयी है तो वह तो सम्भाग मुख्यालय है और जेएलएन सबसे पुराना मेडिकल कालेज है। यदि उस मेडिकल कालेज में यह सुविधा नहीं रहेगी तो लोग जायेंगे कहां? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट को शुरू करना चाहिए और वहां पर एक विशेषज्ञ डाक्टर को अपाइंट किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने चिरंजीवी योजना में जांचें तो बढ़ायी हैं। जांचें आप बढ़ा लीजिये, लेकिन आप उन जांचों में देखिये कि जो कैंसर की जांच है, कैंसर का आपरेशन करने से पहले एक जांच होती है, वह जांच इस चिरंजीवी योजना में नहीं है। योजना में नहीं होने के कारण से वह 6-6 हजार की जांच जो आम, गरीब बीमार व्यक्ति है उसको बाहर से करानी होती है तो 6 हजार की जांच पहले वह बाहर से कराकर आये और उसके बाद में फिर आपरेशन कराने के लिए जेएलएन हास्पिटल आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वह जांच भी फ्री करायें ताकि कैंसर के रोगियों को, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी मैं बात कर रही हूं, उस ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जे.पी. नगर में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र है और चन्द्रवरदाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और ये एनआरएचएम के तहत खुले हैं। यहां पर जो पोस्ट है वह कांट्रेक्ट बेसिस की पोस्ट है तो थोड़े दिन मन करता है तो डाक्टर रहते हैं और फिर बाद में वहां से हट जाते हैं जिससे जितने दिन डाक्टर रहता है उससे डबल टाइम में डाक्टर की पोस्टिंग वहां नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वहां डाक्टर नहीं होने की वजह से वह इतनी सुन्दर, शानदार बिल्डिंग किसी काम की नहीं है तो मेरा निवेदन है कि कांट्रेक्ट की पोस्टों को खतम करके वहां नियमित पद सृजित किये जाने चाहिए ताकि डाक्टर हमेशा अवेलेबल रह सकें।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं अजमेर से आती हूं और अजमेर में आयुर्वेद विभाग का निदेशालय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आयुष नर्सेज का जो ग्रेड-पे है उसमें मेडिकल के नर्सेज के ग्रेड-पे से बहुत ज्यादा अन्तर है, 3600 का है और 4200 का है। वे पिछले 80 दिन से इस बात का धरना लगाये बैठे हैं कि हमारा ग्रेड-पे समान किया जाये और जो उनका ग्रामीण कैडर है उस ग्रामीण कैडर को खतम किया जाये तथा उनकी

(श्रीमती अनिता भदेल)

नियमित भर्ती की जाये। माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन मैं करते हुए अपनी बात को पूरा करती हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, मांग संख्या 13 व 26 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, कोरोना काल में समय पर इलाज, समय पर खाना, नि:शुल्क इलाज के लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब का अपनी ओर से व मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाये। सीएचसी, बयाना में प्रतिदिन 1000-1200 की ओपीडी, आईपीडी में मरीजों की संख्या है और बयाना सीएचसी भरतपुर जिले की सबसे नम्बर वन सीएचसी है जिसमें गायनी, ट्रोमा, फिजिशियन, डेंटल, सोनोग्राफी, एक्स-रे और सिजेरियन डिलीवरी सहित सारी व्यवस्थाएं हैं और इसको बस क्रमोन्नत ही करना है। महोदय जी से मांग है कि बयाना सीएचसी को क्रमोन्नत कर जिला चिकित्सालय किया जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के उपखण्ड रूपवास में काफी समय से संचालित 30 बैड की सीएचसी को बढ़ाकर 50 बैड में क्रमोन्नत किया जाये। सभापति महोदय, सीएचसी रूपवास में 30 बैड होने के कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पताल या जिला चिकित्सालय में जाना पड़ता है। सीएचसी, रूपवास में सुविधाओं की कमी है जिससे न सोनोग्राफी मशीन, न डिजिटल एक्स-रे मशीन है। डाक्टर और स्टाफ की कमी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहूंगा कि सीएचसी रूपवास में बैडों की कमी को देखते हुए बैड बढ़ाये जाएं। सीएचसी, रूपवास पर मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। वहां सोनोग्राफी मशीन, डिजीटल एक्स-रे मशीन, डाक्टर, स्टाफ आदि को बढ़ाया जाय, जिससे आम जन को होने वाली असुविधाओं से राहत मिल सके।

सभापति महोदय, रूपवास मेगा हाईवे भरतपुर से धौलपुर के बीच में पड़ता है जहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और सबसे नजदीक सीएचसी

(श्री अमर सिंह)

रूपवास लगती है। रूपवास या आसपास कोई ट्रोमा सेन्टर नहीं है। ज्यादा गंभीर मरीज को जिला अस्पताल या जयपुर रैफर किया जाता है जिसकी दूरी बहुत ज्यादा है, जब तक मरीज की हालत खराब हो जाती है और मरीज अपनी जान खो बैठता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रूपवास में ट्रोमा सेन्टर खोला जाए जिससे कि हमारे हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट के केसों का उपचार किया जा सके और किसी की जान बच सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में सीएचसी रूदावल और सीएचसी बंशी पहाड़पुर में स्टाफ की कमी को दूर किया जाय। यदि स्टाफ पूरा ही नहीं होगा तो मरीज का इलाज कैसे होगा।

(समय: 19.41 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसलिए सभापति महोदय, स्टाफ पूर्ण किया जाय। सीएचसी, रूदावल, बंशी पहाड़पुर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाय जिससे महिलाओं को होने वाली असुविधाओं से राहत मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में नयी ग्राम पंचायतें बनी हैं, जैसे कि सज्जनवास, महलपुर कांछी, कंजोली, मेडता, इनमें उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्री साहब से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में और रूपवास में तीन दिशाओं में पीएचसी, सीएचसी सब कुछ हो गये, लेकिन एक दिशा खाली है, वहां ज्यादातर एससी, एसटी के लोग रहते हैं। उनकी मांग है कि ग्राम पंचायत मिलकपुर में, वे काफी समय से आ रहे हैं, मेरे पास काफी चक्कर लगा रहे हैं, दो-तीन गांव तो कल ही आये थे कि क्या हम इस विधान सभा क्षेत्र में, क्या हम राजस्थान में, क्या हम इस जिले में रहने वाले नहीं हैं, क्या हम सुख सुविधा नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मंत्री साहब से निवेदन करता हूं कि पीएचसी यदि मिलकपुर में खुल जाती है तो तकरीबन 15 गांवों को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में, मेरी निजी ग्राम पंचायत बंशी पहाड़पुर में हथकढ़ शराब निकाली जा रही है, तकरीबन 100 भट्टियां चलती हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमर सिंह (बयाना): 2021 में एक दिन में ही सात मौतें हुई थीं। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री साहब को कि उन्होंने जैसे ही सुना, उनके परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया। फिलहाल आबकारी विभाग के जो सीआई साहब लगे हुए हैं, उनकी मिलीभगत से कम से कम 100 भट्टियां खुले आसमान के नीचे चल रही हैं, चौतरफा हथकढ़ शराब की बिक्री हो रही है।

मेरा आदरणीय मंत्री साहब से कहना है कि उनको तुरन्त वहां से हटाया जाय, किसी अन्य को लगाया जाय। आपने बोलने का मौका दिया, जय जवान, नमस्कार साहब।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो बजट की घोषणा है, उसकी क्या स्थिति है? 2019-20 की बजट घोषणा में 200 नये सब-सेन्टर खोलने की घोषणा की गयी। अभी आपने जो आंकड़े दिये, उनको देखा। आप दिसम्बर 2021 तक मात्र 45 सब-सेन्टर खोल पाये हो, 155 सब-सेन्टर कब खुलेंगे? अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में एक हजार नये सब-सेन्टर खोलने की घोषणा कर दी। मुझे तो लगता है कि यह घोषणा भी, आप तीन साल में 155 सब-सेन्टर खोल नहीं रहे हो तो यह घोषणा भी हवा-हवाई ही लगेगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देश आजाद होने के बाद कई गम्भीर बीमारियां आयीं। जैसे पोलियो की बीमारी आयी और पोलियो की वैक्सीन बनते-बनते 40 साल लग गये। हेपेटाइटिस-बी का टीका बनते-बनते 24 साल लग गये। देश के प्रधान मंत्री जी, वैज्ञानिकों और डाक्टरों को धन्यवाद देना चाहिये कि आठ महीने के अन्दर कोरोना जैसी नयी महामारी की वैक्सीन आ गयी। अब तक 100 करोड़ लोगों को नि:शुल्क वैक्सीन भी लगी। हमारे पड़ोस के देशवासियों को भी वैक्सीन लगी।

देश के प्रधान मंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। हमारे यहां बेहतरीन उपकरण नहीं बनते थे, दवाइयां नहीं बनती थीं, अन्य सामान के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। आत्मनिर्भर भारत में, आज हमारे देश में एन-95 मास्क बन रहे हैं, पीपीई किट बन रहे हैं, वेन्टीलेटर बन रहे हैं, जो पहले हम आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

देश के प्रधान मंत्री जी ने 1 अप्रैल, 2018 से बहुत बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत की। इसमें 10 करोड़ लोगों व 50 लाख परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमे का प्रावधान किया गया। राजस्थान की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं चाहे हमारा जालोर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, डूंगरपुर हो या बांसवाड़ा हो, यहां के लोग आपके जयपुर या जोधपुर नहीं जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा पड़ता है। वे लोग गुजरात के अन्दर इलाज कराने जाते हैं, परन्तु वहां पर आपकी चिरंजीवी योजना या आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का कोई फायदा नहीं मिलता है। उस कार्ड को वहां फेंक देते हैं। इसलिए, मेरी मांग है कि आप या तो जो केन्द्र की योजना है, उसको लागू करें या फिर आपकी जो चिरंजीवी योजना है, आप इसको लागू करें।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बिलकुल गुजरात से सटा हुआ है। सांचौर है, रेवदर है, और कई विधान सभा क्षेत्र गुजरात सीमा से सटे हुए हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, 108 एम्बुलेंस में मरीज को गुजरात लेकर जाना पड़ता है तो बोर्डर पर रोक देते हैं। मेरी मांग है कि 108 एम्बुलेंस को भी गुजरात में जाने की आप इजाजत दें।

मेरे यहां रानीवाड़ा उपखण्ड कार्यालय है। वहां पर रानीवाड़ा का हास्पिटल है। वहां ट्रोमा सेन्टर खोला जाय। रानीवाड़ा में सीएचसी को मॉडल सीएचसी विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया है और विधायक कोष से एक-एक करोड़ रुपये काटे भी गये हैं, परन्तु अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आप यहां ट्रोमा सेन्टर खोलने की घोषणा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुडा पांचला है, वह 2017 की अतिवृष्टि में पूरी तरह बह गया है, कोई नामो-निशान नहीं है, तीन साल से मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी तक कोई स्वीकृति नहीं हुई है। वहां का जो स्टाफ है वह प्राइवेट मकान के अन्दर इलाज करता है।

इसी तरह से सब-सेन्टर गोलाणा, दांतावाड़ा, डाडोकी, भाटीप, कोट की ढाणी कोडी में सब-सेन्टर बिलकुल जर्जर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है तो इसकी मरम्मत या नये बनाने का आप आदेश करें। पीएचसी, करवाड़ा और राज़ी का वास का हास्पिटल बन चुका है, परन्तु उसके चारदीवारी नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हमारे यहां वाडाभोजा, मैत्रीवाड़ा, सेवाडियां, वाडापादर, मनोहर जी का वास और मण्डारडी में भवन नहीं है। इन भवनों की स्वीकृति भी दिलायी जाय। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी व मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में जो कम्प्यूटर आपरेटर लगे हुए हैं। उनको मात्र 8 हजार 500 रुपये दिये जाते हैं। मेरी मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाय। इसी तरह से, जो नर्सिंग ट्यूटर पद पर कर्मचारी लगे हैं, उनको राजपत्रित का दर्जा दिया जाय। इससे सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, कोविड के समय कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती आप लोगों ने कर दी, परन्तु उनको आज दिन तक तनख्वाह नहीं मिली है। तो मेरी मांग है कि उनको जल्दी से जल्दी आप लोग तनख्वाह देने की व्यवस्था करें ताकि उनके परिवार का लालन-पालन हो सके और जो हमारे पद खाली हैं चाहे डाक्टर हो, मेल नर्स हो, कम्पाउण्डर हो, इन पदों को आप भरें ताकि जनता को रिलीफ मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर 9.00 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

श्री हाकम अली खां।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 एवं 13 पर विचार

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय, निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से प्रत्येक प्रदेशवासी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने में राजस्थान यूनिवर्सल हैल्थ उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इस योजना से लगभग 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। इन योजनाओं से प्रदेश का हर गरीब, मध्यम व आम आदमी लाभान्वित हो रहा है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की सोच है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा। इस योजना के लागू होने से पहले एक गरीब आदमी बीमार होने पर विचार करता था कि यदि मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाऊं तो इलाज हो जायेगा परन्तु प्राइवेट अस्पताल में जाने के खर्चे से डरता था। खर्चे के बारे में सोच कर वह अपना इरादा बदल देता था परन्तु हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जनता का सपना साकार किया और चिरंजीवी योजना लाये। इस योजना में एक आम आदमी अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ इस योजना में कमियां हैं उनके बारे में। मैं अमूमन क्षेत्र के मरीजों से मिलने के लिए अस्पतालों में जाता रहता हूं और वहां डाक्टरों और मरीजों से मिलता हूं तो इस योजना में जो खामी है वह यह है कि मरीज जब अस्पताल में जाता है और भर्ती होता है तो डाक्टर उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं कि चिरंजीवी योजना में इस पेशेंट का इलाज करना है तो बीमा कम्पनी वाले एक्स्ट्रा जांच लिख देते हैं कि यह जांच और करवाओ जबकि डाक्टर नहीं चाहता कि यह जांच होनी चाहिये, इस जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो बीमा कम्पनी वाले फिर भेज देते हैं कि नहीं, यह जांच कराओ तो डाक्टर कहते हैं कि इलाज हम कर रहे हैं या बीमा कम्पनी वाले कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाये और बीमा कम्पनियों को पाबन्द किया जाये कि आप लोग जो डाक्टर बताते हैं उस हिसाब से इलाज करो।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं एसएमएस की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि एसएमएस राजस्थान का ही नहीं राजस्थान, हरियाणा, एमपी, यूपी क्षेत्र का बहुत बड़ा हास्पिटल बन चुका है

(श्री हाकम अली खां)

और उसमें बहुत सारे मरीजों का भार भी है, लेकिन इसमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के बोर्डर के लोग भी यहां इलाज कराने के लिए आते हैं तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ख्याति प्राप्त हैं कि राजस्थान में जो योजना मुख्य मंत्री जी ने नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क दवा की लागू की है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आते हैं और जो अन्य स्टेट्स से लोग आते हैं उनसे कुछ पैसे वसूले जाते हैं तो डाक्टर्स का कहना है कि मुख्य मंत्री जी को कह करके और मंत्री जी को कह करके जो अन्य स्टेट्स से आते हैं उनका भी फ्री इलाज कराया जाये जिससे उन मरीजों को भी लाभ मिले।

सभापति महोदय, दूसरा यह है कि राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब बच्चे आते हैं, कई बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं तो उनको भी जो वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लोग चक्कर कटवाते हैं तो उनको थोड़ा सरल किया जाये।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधीन कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जो काफी पुराना शहर है तथा उपखण्ड मुख्यालय है। यहां पर 30 बैड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काफी समय से संचालित है और यहां भवन भी पहले से भामाशाहों द्वारा बनाया गया है, वह भवन काफी बड़ा है। उसमें अगर पचास बैड का हास्पिटल कर दिया जाये तीस बैड की जगह तो सारे संसाधन देने के लिए भामाशाह तैयार हैं, भवन तैयार है सरकार को सिर्फ उसको क्रमोन्नत करना है।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में ग्राम बीबीपुर में एक पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का मैंने निवेदन किया था तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रिप्लाई में बताया गलती से कि वह पीएचसी को सब सेन्टर में, तो मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उसको सीएचसी में किया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुर में दो हाईवे गुजरते हैं इस पर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो यहां ट्रोमा सेन्टर तो हैं पर चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक आर्थो के डाक्टर का पद और एनेस्थीसिया का, एक सर्जन और नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत किये जायें और वहां डाक्टर लगाये जायें।

तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खोटिया ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर

(श्री हाकम अली खां)

है, एक भिंचरी ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है। इन गांवों के आसपास में कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है इसलिए यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये तो गांव के लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश निकाला था जिस आदेश के तहत सभी सीएचसीज पर और उप जिला अस्पतालों पर ड्राइवर और एलएचयू के पद समाप्त कर दिए गये तो महोदय, ड्राइवर का पद समाप्त करने से वहां जो एंबुलेंस है वह खड़ी रह गयी। मेरे यहां फतेहपुर में धानुका उप जिला अस्पताल है उसमें स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला के द्वारा एक एंबुलेंस दी गयी थी और वह एंबुलेंस रोगियों के लिए काफी सार्थक काम आ रही थी, लेकिन वह ड्राइवर की पोस्ट खतम करने से वह ड्राइवर रिलीव हो गया और वह एंबुलेंस खड़ी हो गयी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस पोस्ट को वापस क्रिएट किया जाये। एक जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं उनमें पद नहीं हैं, उनमें पद स्वीकृत किये जायें। वो बहुत अच्छे चल रहे थे, लोगों को उनका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा था तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनमें पद स्वीकृत किये जायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एएनएम भर्ती 2018 में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को जो जामिया अलीगढ़ से पास थे, उनका चयन होने के बाद भी उनको नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था जो सरासर इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकरण को न्यायालय में चुनौती दी गयी। माननीय न्यायालय ने निर्णय इनके पक्ष में किया तो अब उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आयुष विभाग की महत्वपूर्ण यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 2013 में यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए अलग निदेशालय की स्थापना हमारी सरकार के कार्यकाल में हुई। इस पद्धति के जनक हिन्दुस्तान के मशहूर हकीम अजमल खान साहब थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं। प्राचीन काल से ही इस पद्धति से असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा था तथा यह एक लोकप्रिय पद्धति है।

(श्री हाकम अली खां)

पिछले दिनों कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में यूनानी चिकित्सकों ने सराहनीय काम किया। जयपुर के रामगंज क्षेत्र तथा जोधपुर शहर को कोरोना मुक्त करने में यूनानी चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान था जिसमें जोशांदा वितरण, विशिष्ट यूनानी दवाओं का काढ़ा तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली यूनानी दवाओं का वितरण किया गया था जिससे संक्रमितों की संख्या में कमी आयी थी। वर्ष 2013 में हमारी सरकार के कार्यकाल में यूनानी चिकित्सकों के 358 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, परन्तु गत भाजपा सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्ती के 180 पद कम कर दिये थे जिससे बहुत से यूनानी चिकित्सक वंचित रह गये थे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यूनानी निदेशालय द्वारा प्रेषित यूनानी चिकित्सकों के नवीन 580 पद सृजित किये जाने के लिए प्रस्ताव चार माह पूर्व भेजा गया था। इस प्रस्ताव के नवीन पदों के सृजन को प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति देकर यूनानी चिकित्सकों की भर्ती शुरू की जाये जिससे आमजन तक यूनानी चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके तथा सरकार का निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर चर्चा चल रही है, इस पर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और थोड़ा मेरे पर रहम रखना।

सभापति महोदय, मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सुविधा देने की चर्चा तो इस हाउस में बहुत होती है पर हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वही हालत है जो आज से बीस वर्ष पहले थी। गांवों के अन्दर सभापति महोदय, आरएमपी डाक्टर थे प्राथमिक उपचार करने के लिए, उन पर भी सरकार ने सख्ताई करके और उनके झोले-झण्डे भी उठा दिये। अब गांवों के अन्दर चाहे पीएचसी है, चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र है सारे के सारे पद रिक्त पड़े हैं और अगर डाक्टर, एएनएम लगे हुए भी हैं तो भी सात दिन के अन्दर दो दिन गांव में आकर हाजिरी लगाने का काम करते हैं।

(समय: 20.00 बजे)

मंत्री महोदय, एक प्रथा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार चाहे आपकी हो या हमारी हो, डाक्टर की प्रथम बार

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पोस्टिंग करने में जो आपने पांच वर्ष का समय तय किया है, मैं इसके लिए आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आप सर्वप्रथम डाक्टर को बड़े हास्पिटल में लगाओ ताकि उसको कुछ सीखने के लिए मिले। डिग्री करने से कुछ नहीं होता, जब तक प्रेक्टिकली ज्ञान नहीं हो। मेरे कहने का भावार्थ है इस प्रथा को बंद करो। चाहे डाक्टर हो या एएनएम, पहले उसको प्रेक्टिकली ज्ञान दो। गांव में चरागाह मत बनाओ, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर और एएनएम के नहीं रहने का कारण सुविधा का अभाव है। सुविधा नहीं होने के कारण, क्वार्टर नहीं होने के कारण उनको फैसेलिटी नहीं मिलती, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक एएनएम है जिसका नाम कृष्णा है, लाडना गांव में पोस्टिंग है। 2007 में माल्लेर गांव में उसकी प्रथम पोस्टिंग हुई थी। वह इतनी ट्रेंड नर्स है कि 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से डिलीवरी के केस आते हैं। मंत्री महोदय, आप पता कर लेना, वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां इस तरह से डिलीवरी वाले मरीज भर्ती हैं जैसे कोई शहरी क्षेत्र का हास्पिटल हो। मेरे कहने का भावार्थ है कि आप इस बात की मानिटरिंग करो तो अवश्य कुछ सुधार होगा। करोड़ों रुपये लगाकर सरकार डाक्टर बनाती है और डाक्टर किसी शहर में अच्छा काम जमने के बाद, ज्यादा टाइम हो जाये और सरकार स्थानांतरण करे तो वह वहीं प्राइवेट हास्पिटल बनाकर अपना धंधा शुरू कर देता है। इस पर भी रोकथाम लगाओ। कोई न कोई ऐसा कानून बनाओ कि वह कम से कम 15-20 वर्ष तक प्राइवेट धंधा नहीं कर सके। नहीं तो आप कितने ही डाक्टर बनाते जाओ, गांवों में तो सुविधा मिलनी नहीं है, वह चरागाह वैसे का वैसा रहना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा मैंने मेरे कोटे से तीन एंबुलेंस और अन्य उपकरण खरीदने के लिए करोड़ रुपये दिये थे। मेरे पास उत्तर आया, सीएमएचओ ने लिखित में कहा कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है, डीजल नहीं है। मैंने टेलीफोन करके कहा कि बहुत से भामाशाह हैं, बहुत से दानी लोग बैठे हैं, आप कम से कम एंबुलेंस तो खरीद लो। एंबुलेंस के लिए स्पष्ट जवाब दे दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी मेरी वह राशि पेंडिंग पड़ी है। तीन एंबुलेंस के लिए आप स्वीकृति दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा। मेरे

(श्री रामप्रताप कासनियां)

क्षेत्र में जैतसर और राजियासर में पीएचसी है। बिल्डिंग के लिए जो राशि मुख्य मंत्री जी ने निर्धारित की है, वह तो मैं खर्च कर दूंगा पर आप उसको सीएचसी में क्रमोन्नत करने का काम करें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, विधायकों को या दूसरे जन प्रतिनिधि को स्वास्थ्य केन्द्रों में, पीएचसी हो, चाहे उपकेन्द्र हो, उसमें एब्सेंट लगाने की आप पावर दें तो काफी हद तक डाक्टर और एएनएम प्रजेंट रहेंगे।

सरकार बार-बार एक प्रचार कर रही है नि:शुल्क दवा योजना। मैंने मेरी आंखों से देखा है नि:शुल्क दवा में सेंट परसेंट तो बहुत दूर की बात है 20-25 परसेंट भी ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं मिलती। ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, जहां आप और हम तप रहे हैं, राज कर रहे हैं, अपनी डिस्पेंसरी में भी दवा नहीं मिल रही है। इसके प्रमाण के तौर पर मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं। कोई बहुत बड़ी दवाई नहीं है। इसके अलावा मुझे प्रेक्टिकली अनुभव है, मैंने इस हाउस में पूर्व में भी कहा था, यह जो सरकारी दवा है मुझे पता नहीं क्या बीमारी है, आप कम्पेरीजन करके देख लो, मैं शुगर का मरीज हूं। पहले मैं शुगर की 2 एमजी की गोली बाहर के मेडिकल स्टोर से लेता था उससे शुगर कंट्रोल रही और यहां वाली अब और ली है, वही हालत फिर हो गई, आज दूसरी लिखा कर लाया हूं। यह हकीकत है। मैं कोई आलोचना के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र को वास्तव में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी है तो वर्तमान में जितनी पीएचसी, स्वास्थ्य उप केन्द्र बना रखे हैं, इनमें जो पद रिक्त हैं, उनको भर दो और एक जन प्रतिनिधियों को यह पावर जरूर दो कि कोई एएनएम, डाक्टर एब्सेंट हो तो उसकी एब्सेंट लगाने का अधिकार हो तो काफी सुधार हो सकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बस, ऐसे ही मैं भटक जाता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): रहा सवाल नि:शुल्क जांच करने का, यह बिलकुल एक कहावत बनकर रह गई। सरकारी हास्पिटल में ज्यादातर जांच करने वाली मशीनें चाहे ठीक हों, डाक्टरों का एक ही उत्तर है कि मशीन खराब है तो क्या करें, कहते हैं कि अमुक जगह उस डाक्टर के पास जाओ, उस हास्पिटल में जाओ। यह भी एक कमीशनखोरी का चक्कर है। मेरे सूरतगढ़

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीन 8-9 वर्ष से धूल फांक रही है, उसको चलाया ही नहीं, आज तक बटन ही ऑन नहीं किया। सभापति महोदय, सूरतगढ़ जैसे बड़े शहर में डिलीवरी की सुविधा नहीं होना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ यह कह देना कि रेफर कर देते हैं। गंगानगर चले जाओ, प्राइवेट हास्पिटल में चले जाओ, यह प्रथा भी बन्द करो। मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं कि उस एएनएम में इतनी शक्ति है कि 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से डिलीवरी केस वहां आते हैं और आज उस एएनएम की वाहवाही हो रही है। इस तरह का काम करने वाली एएनएम को बढ़ावा दें। उनको कोई न कोई प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दें, चाहे पांच रुपये ही दो, उसको इनाम दो ताकि उसको भी हौसला हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, इसके अलावा क्या बोलें..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): धन्यवाद साहब, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह की संवेदनशीलता उन्होंने इस बजट में चिकित्सा के क्षेत्र में दिखायी और विशेष तौर से कोरोनाकाल में उन्होंने पूरे प्रदेश में संवेदनशीलता दिखायी। उसके बाद भी इस विभाग में सुधार लाने और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का जो काम किया है, उसके लिए पूरा प्रदेश और हम लोग, उनके बहुत-बहुत आभारी हैं। उस समय विशेष तौर से उन्होंने जो आक्सीजन प्लांट जगह-जगह लगवाये, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो उसमें भी पांच आक्सीजन प्लांट सरकार और भामाशाहों के सहयोग से लगे। उन्होंने इसी दौरान बड़ी संख्या में डाक्टरों और एएनएम की भर्ती भी की, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद है।

साथ ही, कोविड हैल्थ केयर, सीएचए की भर्ती की गयी है। मेरे क्षेत्र में भी 62 सीएचए भर्ती हुए थे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन 62 में से 56 का उस समय डेपुटेशन किया गया और दूसरी जगह पर लगा दिये गये, पर मंत्री जी को जब

(श्री मनोज कुमार)

यह विभाग दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे डेपुटेशन कैंसिल किये और उन 56 के भी कैंसिल हुए। एएनएम, जो डेपुटेशन पर थे, उनके भी खतम हुए और डाक्टर्स के भी खतम हुए। साथ ही, बताना चाहूंगा कि शायद या तो आपकी जानकारी में नहीं है या आपकी जानकारी के बिना ही दुबारा वह खेल शुरू हो गया है। दुबारा डेपुटेशन का खेल चालू हो गया है, इस पर आप ध्यान दें क्योंकि इस बार यदि फिर डेपुटेशन हुए तो जिस सब-सेन्टर, जिस पीएचसी में यदि एक भी स्टाफ नहीं होगा तो जनता आपके बंगले पर आकर धरना दे देगी।

सभापति महोदय, आप सोच सकते हैं कि 62 में से 56 डेपुटेशन पर हों तो क्या हालत हुई होगी? अधिकारियों ने सोचा भी नहीं कि मुख्य मंत्री जी की क्या मंशा है? चिकित्सा मंत्री जी की क्या मंशा है? किस मंशा से उन्होंने ये लगाये? इन्होंने डेपुटेशन निरस्त किये, वापस वह खेल शुरू होने जा रहा है। इसी दरमियान माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में सुजानगढ़ के अस्पताल में आईसीयू भी स्वीकृत किया। उसके वेंटिलेटर भी आ गये हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका जो कमरा बनना है या चालू करने के जो संसाधन हैं, वे अभी उपलब्ध कराने बाकी हैं, जिससे कि आईसीयू प्रोपर चल सके, जो स्वीकृत हुआ है। इसके लिए एनआरएचएम और हास्पिटल के द्वारा बनाया हुआ है, जो कि विभाग में भेजा हुआ है। पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सुजानगढ़ के अस्पताल को बढ़ाया था और विभाग ने वहां पर 21 डाक्टरों के पद और बढ़ाये, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। बहुत-से डाक्टर्स लग भी गये हैं, पर जितने डाक्टर्स हैं, उस हिसाब से एनेस्थीसिया के पद स्वीकृत नहीं हैं क्योंकि आपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का डाक्टर होना बहुत जरूरी है। विशेष तौर से जब सर्जन अलग हो, एमसीएच विंग अलग हो, तो दोनों जगह अलग-अलग डाक्टर चाहिये। उसके लिए मैंने निवेदन किया था कि इनमें से भले ही एमओ के दो-चार पद कम कर दो, उसकी जगह एनेस्थीसिया के पद और स्वीकृत करें, ताकि यहां पर एनेस्थीसिया के डाक्टर लग सकें।

पिछली बार जब मैं बजट भाषण पर पहली बार बोल रहा था, उस समय भी कहा था कि सुजानगढ़ का अस्पताल है, वह बहुत पुराना है। भामाशाहों के सहयोग से उस समय बना था। उसके बाद आबादी बहुत बढ़ गयी। वह शहर के एकदम बीच में है, एकदम कंजस्टेड एरिया है। अस्पताल में

(श्री मनोज कुमार)

पार्किंग की बिलकुल भी व्यवस्था नहीं है। उसमें जगह नहीं है कि एक एम्बुलेंस भी खड़ी हो सके। दूसरी बात यह है कि रास्ता अब ऐसा हो गया है कि वहां पर एम्बुलेंस को जाने में भी दिक्कत होती है तो उसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाये, ताकि एम्बुलेंस को दिक्कत न हो और रोगियों को भी सहायता मिले। क्योंकि शहर के एकदम बीच में आ गया है। आज के समय हम देखते है कि बिना पार्किंग और जहां पर एम्बुलेंस के लिए भी जगह नहीं हो तो वहां पर रोगियों और उनके अटेंडेंट के वाहनों की क्या हालत होती होगी?

एक सडू बड़ी की सीएचसी का मसला बहुत लम्बे समय से चल रहा है उसको पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करने का मैं आपसे आग्रह करूंगा। इसके अलावा जो बड़े कस्बे हैं, जो दस-दस हजार से ज्यादा की आबादी के हैं। दस-दस हजार से ज्यादा की आबादी के जो गांव हो गये हैं, उन गांवों और कस्बों में अभी सब-सेन्टर चल रहे हैं। जोगलसर, मलसीसर, लोटसर, जिनकी आबादी दस हजार से ज्यादा है। उन सब-सेन्टर्स को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में भी बहुतसी पीएचसी स्वीकृत की हैं, उनका और का भी इरादा है। पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। अभी एक हजार सब-सेन्टर बढ़ाये हैं, उसके लिए भी मैं उनको बहुतबहुत धन्यवाद देता हूं कि वे एक हजार सब-सेन्टर आने वाले समय में राजस्थान में खुलने जा रहे हैं।

दूसरी मांग आबकारी की है। मैंने पहले इस सदन में अपने भाषण में शराब बन्दी का मुद्दा उठाया था कि क्यों न प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी शराब बन्दी लागू कर दें, ताकि बहुतसी जनता, बहुतसी महिलाएं, बहुतसे घर, जो कि इससे उजड़ रहे हैं, वह न हों।

दूसरी बात जो इस विभाग में देखने को मिल रही है। मुख्य मंत्री जी की मंशा है और उन्होंने घोषणा भी की है कि एक भी दुकान न बढ़ जाये। फिर भी ब्रांचों के नाम से दुकानें खुल रही हैं, जिन पर रोकटोक नहीं हो रही है। कहते हैं कि टार्गेट है। मिनिमम गारन्टी है कि आपको इतनी मिनिमम उठानी पड़ेगी। आपको यह मिनिमम वाला पूरे विभाग में बन्द कर देना चाहिये कि कम से कम इस विभाग में तो यह नहीं होना चाहिये कि इतने रेवन्यू के लिए इतना टार्गेट है। उस चक्कर में, आज आप शहर में निकल जाओ तो बड़े-बड़े बैनर लग रहे हैं कि भारी छूट। ये कोई छूट देने वाली चीज है? जहां स्वीकृत नहीं है, वहां पर वे बेचते हैं। बेमतलब से बढ़ाया जा रहा है। ठेकेदार की मजबूरी में, वे कैसे इसकी सप्लाई बढ़ायें, कैसे खपत बढ़ायें? जो मुख्य

(श्री मनोज कुमार)
मंत्री जी की मंशा नहीं है, फिर भी विभाग के अधिकारी टार्गेट देकर इसकी खपत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसकी मैं पुरजोर निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि इस व्यवस्था को बन्द किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): जो बीदासर, पिछली बार इसके अस्पताल को 30 से 50 बैड का किया गया था, पर उसके बाद वहां पर कायदे से जो सुविधाएं बढ़नी चाहिये थीं, वे अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। शहरी पीएचसी में तो अपन जानते हैं कि शहरी पीएचसी में डाक्टर्स की दिक्कत आती है। जिस हिसाब से बैड बढ़े हैं, उस हिसाब से पद और स्टाफ भी बढ़ना जरूरी है, सुविधाएं भी बढ़ना जरूरी है, यह मैं आपसे मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मोहन राम चौधरी।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2021-22 में मेडिकल कालेज की स्वीकृति दी तथा दिनांक 8 मार्च, 2022 को शिलान्यास किया और 395 करोड़ में से 200 करोड़ केन्द्र सरकार तथा 195 करोड़ राजस्थान सरकार ने दिये, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा धन्यवाद मैं इस बात का दूंगा कि सभी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कालेज की 2022-23 के बजट में घोषणा की है, उसके लिए भी धन्यवाद। इसमें नर्सिंग की जो ट्रेनिंग होनी है, उसकी संख्या नहीं बढ़ायी है। वर्तमान में नागौर में एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर की 25 सीटें स्वीकृत हैं, यह कम से कम 100 सीटें की जायें, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों से प्रशिक्षण लेकर आते हैं, उसमें राज्य और जनता दोनों का नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कालेज का 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसकी मानिटरिंग हेतु एक समिति ऐसी बनायी जाये, जिसमें जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाये। इसलिए कह रहा हूं कि जेएलएन अस्पताल में एमसीएच विंग है, जो कि जेएलएन में बनी है। उसका निर्माण 7 वर्ष पूर्व ही हुआ है, लेकिन इतना घटिया हुआ है कि

(श्री मोहन राम चौधरी)

छत गिर रही है। बच्चा और जच्चा कोई सुरक्षित नहीं है। किसी भी समय छत ऊपर से गिर सकती है। दीवारों का प्लस्तर गिर रहा है। उनकी काफी शिकायतें भी हुई। उसमें जांचें भी हुई परन्तु उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। नागौर से इस भवन की मरम्मत हेतु डेढ़ करोड़ का तकमीना बनाकर एन एच एम, जयपुर को भेजा गया लेकिन विभाग ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि हम नये भवनों का निर्माण करते हैं, मरम्मत का काम नहीं करते हैं। इसमें सात वर्ष पूर्व ही 6 करोड़ लगकर हुआ है, इतने हल्के स्तर का हुआ, इसमें मुकदमे भी दर्ज हुए परंतु जांचों में तो वही हुआ, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है 'बहुआं हाथ चोर मरावै, चोर बहूरा भाई' अर्थात् जांच करने वाले और जो वहां हैं, कुल मिलाकर इसी प्रकार का रिजल्ट सामने आया।

मानिटरिंग का मैं इसीलिए जिक्र कर रहा था कि नागौर में एक समित शर्मा, कलेक्टर आये। उन्होंने आते ही दो-तीन दिन लोगों का तीन-चार जगह जिले में ऐसा बनाया, वह समय पर कार्यालय में जाते थे, स्कूलों में जाते थे और अनुपस्थित हैं, उनका लेकर कलेक्टर को भेज देते थे तो वे उनको एपीओ कर देते। इस हिसाब से एक-दो महीनों के अन्दर ही इस प्रकार का वातावरण बना। सभापति महोदय, प्रत्येक व्यक्ति समय पर कार्यालय जाना सीख गया। इस प्रकार के कुछ अच्छे लोग हैं जो अस्पताल टाइम पर चले गये, कौन है, कौन नहीं? कैसा क्या हो रहा है? तो इस भवन का भी इस प्रकार का कीजिए। यह नहीं कि उस भवन की स्थिति भी मातृ और शिशु अस्पताल की हुई, वैसी नहीं हो जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला चिकित्सालय जो शहर से 4 किलोमीटर दूर, शहर के दूसरी ओर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। 200 बैड्स हैं, एम सी एच में 100 बैड हैं, कुल मिलाकर 300 बैड हैं। इसमें वरिष्ठ विशेषज्ञों के 6 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 5 पद खाली हैं। इसी प्रकार कनिष्ठ विशेषज्ञों के 22 पद स्वीकृत हैं, 8 पद खाली हैं। वरिष्ठ लैब टैक्निशियन के 7 पद हैं जिनमें 3 खाली हैं। रेडियोग्राफर 2 पद स्वीकृत हैं, दोनों ही खाली हैं। भौतिक चिकित्सक 2 पद, दोनों ही खाली हैं। दंत चिकित्सक का एक पद है, वह भी खाली है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय सभापति महोदय, गर्भवती महिलाओं के कभी तकलीफ होती है तो जाते ही उनको कहते हैं कि सोनोग्राफी

(श्री मोहन राम चौधरी)

कराओ और जाते ही एक महीने का समय दे देते हैं। मान्यवर, अगर उनकी दस दिन में ही डिलीवरी होनी है तो क्या? अर्थात् उनको बाहर जाकर इस हिसाब से पिटना पड़ता है और कई इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा सोनोग्राफी होती है, उनकी रिपोर्ट देखकर डाक्टर कहते हैं कि मुझे इसका विश्वास नहीं है। इस प्रकार की जो ये धांधली चल रही है, इस ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सी.एच.सी. हैं। पी.एच.सी. भी पीपासर, रोहिणी, धूंद वालों की ढाणी, हिन्दाना, बागरोद है और शहर में एक यू.पी.एच.सी. भी है। जनता क्लीनिक के नाम पर जो घोषणा हुई थी, सरकार ने दो की थीं, जिसमें एक नागौर में चल रही है संजय कालोनी में। दूसरी जो थी उसका अता-पता नहीं है। ये जो जनता क्लीनिक शहर में है, वहां एक डाक्टर और एक नर्स बैठते हैं। रात्रि को कोई नहीं है। जो जिले का मुख्य चिकित्सालय था, रामदेव पिती मुख्य चिकित्सालय, भामाशाहों द्वारा जनता को लाभ मिलने की दृष्टि से बनाया, उन्होंने अपनी खरी कमाई से खर्च करके बनाया था। आज जनता क्लीनिक के नाम से इतना बड़ा भवन है, विशाल भवन में जहां सी.एच.सी. चालू हो जाए, मंत्री महोदय, तब तो वह काम आ सकता है अन्यथा खाली पड़ा भवन जर्जर अवस्था में होने जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री रामलाल मीणा।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय सभापति महोदय, धूंद वालों की ढाणी पीएचसी काफी पुरानी है। वहां आसपास कई गांवों के लोग आते हैं। वहां की ओ.पी.डी. 100 से 150 हैं, वहां महीने में 60 से 70 डिलीवरी भी होती हैं। यदि उसको भी सी.एच.सी. का दर्जा दे दिया जाए तो जिला अस्पताल का भी काफी लोड कम हो जाएगा। एक मिनट में, मैं समझता हूं कि जे.एल.एन. अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बीच में आ रहा है और इस दृष्टि से वहां दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसलिए वहां न्यूरो सर्जन एवं न्यूरो फिजिशियन के पद नहीं हैं, वे स्वीकृत किए जाएं जिससे लोगों का ठीक से उपचार हो सके। नागौर औषधि नियंत्रण कार्यालय जो है, शहर के व्यापारियों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री रामलाल मीणा।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): इसीलिए लोगों ने धरने भी दिये हैं। अख़बार में भी आया है। सभापति महोदय, जो संविदाकर्मी हैं, उनको भी स्थायी किया जाये।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): वर्ष 2018 की जो भर्ती है, उसमें पद बढ़ाकर उनको करिए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने चिकित्सा एवं आबकारी मांग पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 'पहला सुख निरोगी काया' कहा गया है कि जीवन का पहला सुख ही निरोगी काया है। आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी में जूझ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो व्यवस्थाएं राजस्थान की जनता को दी हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि जहां रात के 12 बजे यह अनाउंस हो जाता है कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू किया जाता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह नहीं देखा जाता है कि जनता किस परिस्थिति में होगी? कौन कहां होगा? माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषम परिस्थिति में एक नारा देते हैं कोई भूखा नहीं सोयेगा। एक-एक घर पर व्यवस्था की और कोरोनाकाल के अन्दर मजदूर किस प्रकार से त्राहिमाम पुकारते हुए पैदल आ रहे थे, विभिन्न राज्यों से आ रहे थे, लेकिन राजस्थान की सीमा में आते ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने समस्त एस.डी.एम. को यह निर्देश जारी किये कि सारे एस.डी.एम. अपने-अपने क्षेत्र में बसों की व्यवस्था करेंगे और मजदूरों को अपने-अपने घर तक पहुंचाएंगे। इसके बाद में खाने की व्यवस्था भी सब तरफ से हुई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज की व्यवस्था की। प्रतापगढ़ के अन्दर भी मेडिकल कालेज के निर्देश दिये गये। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को मनोनीत किया गया। हमने तीन दिन के अन्दर मेडिकल कालेज के लिए 65 बीघा जमीन आबंटित करवा दी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां से मेडिकल कालेज परमिशन के लिए केन्द्र सरकार को भेजा। बड़े दु:ख की बात है कि एक साल बीतने के बाद भी प्रतापगढ़ का मेडिकल कालेज अधर झूल में है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़, सिरोही जैसे दो-तीन जिले जो वंचित रह गये हैं, उनमें भी मेडिकल कालेज खोलकर राजस्थान के अन्दर एक नया कीर्तिमान स्थापित कीजिए। आज प्रतापगढ़ के अन्दर 150

(श्री रामलाल मीणा)

बैड से डायरेक्ट 300 बैड का हास्पिटल माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। प्रतापगढ़ जिला एक आदिवासी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की सीमा से आता है। वहां चिकित्सा की पूर्व में कोई सुविधा नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी जब सुहागपुरा पधारे थे, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि साहब हमारे प्रतापगढ़ जिले में कोई चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूरे जिले के अन्दर जिला चिकित्सालय में सिर्फ 150 बैड है, तुरंत उन्होंने 150 बैड से 300 बैड किया। मैं सारे अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि अभी एक लैटर आपने जारी किया है 300 बैड को लेकर। उस लैटर को करेक्शन करवाकर उसको सही कराएं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि प्रतापगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जिले में भी चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। पहले जब जिला चिकित्सालय के अन्दर कोई जाता था तो हाथ देखकर डाक्टर उदयपुर रैफर कर देते थे। प्रतापगढ़ में एक भी डिलीवरी नहीं होती थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, माननीय अशोक जी गहलोत साहब पद पर आये, मैंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करना प्रारम्भ किया। आज कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, रेफर कर दिये जाते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, अगर महीने में एक दिन-दो दिन सारे विधायक, जिला चिकित्सालय या आपके आस-पास के जो भी चिकित्सालय हैं, उनका अगर भ्रमण कर लें, निरीक्षण कर लें, तो निश्चित जिला चिकित्सालय की स्थिति सुधर सकती है।

मैं महीने में दो दिन, जिला चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड में, प्रभारी डाक्टर को लेकर घूमता हूं। एक-एक समस्या सुनता हूं। आज 99.99 परसेंट डिलीवरी प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के अन्दर हो रही हैं, जो पहले नहीं हो रही थीं। आज रीढ़ की हड्डी का आपरेशन भी प्रतापगढ़ जैसे ज़िले में होने लग गया।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने हमारे यहां 3-3 डाक्टर एनेस्थीसिया के लगाये। 5-5 डाक्टर डिलीवरी के लिए लगाये। हमारे प्रतापगढ़ ज़िले के अन्दर हड्डी रोग विशेषज्ञ सिर्फ एक ही है, दो-तीन हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे यहां कर दें, ताकि इस समस्या का समाधान भी हो जाये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे दलोत व सुहागपुरा में तीव्र गति से

(श्री रामलाल मीणा)

विकास हुआ है। वहां तहसील भी बन गयी। पंचायत समिति भी बन गयी, लेकिन पीएचसी को सीएचसी में अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है। दोनों जगह सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये।

गोपाल मीना जी भी कह रहे थे, कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हर पंचायत मुख्यालय पर पीएचसी होनी चाहिये। राजस्थान के अन्दर हो या नहीं हो, आदिवासी क्षेत्र, बिखरी आबादी है, दूर-दूर तक अलग-अलग घर हैं, वहां टीएसपी क्षेत्र में, हर पंचायत मुख्यालय पर, पीएचसी की व्यवस्था हो, ताकि वहां रहने वाले आदिवासियों को सुविधा मिल सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोविडकाल में कोविड सहायक लगाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): उन्होंने पूरी व्यवस्था की। पूरी तैयारी के साथ मेहनत की। मैं मेरे प्रतापगढ़ के सारे चिकित्सा अधिकारियों को, कोविड सहायकों को, जीएनएम, एएनएम को, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर, टीकाकरण में, पहली व दूसरी डोज में, प्रतापगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। ऐसे कोविड सहायकों के ऊपर भी, माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का ध्यान जाये। उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाये या उनको कोई इनाम दिया जाये, ताकि उनकी पूरी व्यवस्था हो सके।

आज जीएनएम भर्ती 2013, एएनएम भर्ती 2013 के अभ्यर्थी भी इन्तजार कर रहे हैं, उनको भी नियुक्ति दी जाये, ताकि कोरोना जैसे महामारी के अन्दर भी हमें इनका सहयोग मिल सके।

एएनएम ट्रेनिंग सेंटर काफी समय से खुला हुआ है, साहब। हमारे यहां एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के अन्दर, एक भी पद सृजित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जवाब के अन्दर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के अन्दर पद सृजित करने की घोषणा करें।

दूसरा, आबकारी के बारे में। आज गणेश घोघरा जी भी कह रहे थे, अन्य सदस्य भी कह रहे थे। आदिवासी क्षेत्र है, वहां दारू कोई नहीं खरीदता है। खुद के मउडी का पेड़ होता है, उसी से बनाकर, खुद के लिए काम में लेते हैं। शादी-ब्याह में काम में ली जाती है। ठेकेदारों से मिलकर, ये अधिकारी उन गरीब आदिवासियों के ऊपर, एक बोतल की जगह पांच बोतल, दस बोतल का केस लगाया जाता है, पेशियां कराई जाती हैं। उनको यह छूट दी जाये। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं ग़रीबों को दारू के नाम पर परेशान नहीं किया जाये।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में, जिस प्रकार राजस्थान मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल की चर्चाएं सब जगह हुई हैं, देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब के काम को लेकर प्रशंसा की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 26-चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य, मांग संख्या 13-आबकारी पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देश के 175 करोड़ नागरिकों के नि:शुल्क वैक्सीन लगाकर, हज़ारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। कोरोना काल में, देश में सफल प्रबंधन करने, कई देशों को मानवता के नाते कोरोना काल में वैक्सीन उपलब्ध कराने, राजस्थान के हर ज़िले में मेडिकल कालेज खोलने हेतु, 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने, कोरोना काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने, वैक्सीन, 95 मास्क, पीपीई किट सहित अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम, मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से सराहनीय है।

राजस्थान में कोरोना काल का, दो वर्ष का कठिन समय निकला है, लेकिन कोरोना से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। कोरोना से सबक लेकर राजस्थान सरकार को चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने थे, लेकिन सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए। आज भी चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं है। कई जगह नर्सिंग स्टाफ नहीं है। एएनएम के ज्यादातर पद रिक्त हैं। गांवों में सब सेंटर नहीं है और जहां है वहां भवन नहीं है। स्थाई चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किये। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करुंगा कि हर गांव में स्थायी चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए आप कोई न कोई व्यवस्था करे।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की बात करूं। सुमेरपुर में कानपुरा, भाचुन्दा, रोजड़ा, दौलपुरा, मोरड़ू, बापूनगर, बाणियावास, डिगाई, बानियावास, सोनाई मांजी में उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, लेकिन कई वर्षों से वहां भवन नहीं हैं। बिना भवन के उप स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। एएनएम किराये के मकान में

(श्री जोराराम कुमावत)

ठहरती है या एएनएम का ठहराव ही नहीं होता। इन केन्द्रों पर भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता है।

जाखोड़ा, खिमाडा, धन्नापुरा, ऐसे कई उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो भवन क्षतिग्रस्त हैं। भवन एएनएम व मरीज के बैठने लायक भी नहीं है। इस कारण मरीज सरकारी उप स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज कराने की बजाय प्राइवेट हास्पिटल में जाकर, इलाज करा रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन क्षतिग्रस्त भवनों का भी नवीनीकरण करवाने का श्रम करवाएं।

इसी तरह, बांगरी, पोयना, अणगोर, वेनपुरा, केरला, वडरेवास, कोणदरा, साकदडा, गुरडई, पादरली, तुर्कान, सेदरिया, गलथनी सहित कई गांवों में चिकित्सा सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। पड़ोसी गांव की एएनएम को चार्ज दे रखा है। वह एएनएम गांवों में आती ही नहीं है। ग्रामवासी मजबूरी में प्राइवेट क्लिनिक में जाकर इलाज कराते हैं। इन गांवों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र व एएनएम की पोस्टिंग करवाने की आवश्यकता है।

पाली पंचायत समिति के रूपावास गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र है। एएनएम की पोस्टिंग है, लेकिन वहां बिना क्रमोन्नत किये ही, चिकित्सा विभाग ने पीएचसी भवन बना दिया। अब वह भवन खण्डहर बन रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं रूपावास, सिंदरू, दुजाना उप स्वास्थ्य केन्द्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करवाने का श्रम करावें।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में, खेरवा, लांबिया, मणिहारी, दुदावास, गिरवर, सापुनी, जाखोडा, भाचुन्दा, लापोद, बडली, पावा, कोशिल, बसंत, गोगरा, नवाखेड़ा, खोड, पराखिया, छाछोडी, खरोकडा में एएनएम के पद लंबे समय से रिक्त हैं। एएनएम के पद रिक्त होने से, इन गांवों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ताले लगे हुए हैं, जिससे आमजन प्राइवेट हास्पिटल में जाकर इलाज करा रहे हैं।

सुमेरपुर सीएचसी में एक भी एएनएम का पद स्वीकृत नहीं है। कई सीएचसी व पीएचसी में डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी से ग्रामीण क्षेत्र व तखतगढ नगरपालिका क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था लंबे समय से चरमराई हुई है। इन रिक्त पदों को भरने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सुमेरपुर नगर की आबादी 50 हजार है। सुमेरपुर पाली, जालौर, सिरोही ज़िले का सबसे बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है। ज्यादातर मरीज यहां पर इलाज कराने आते हैं। सरकारी सुविधा के नाम पर एक मात्र

(श्री जोराराम कुमावत)

सीएचसी है जिससे प्राइवेट हास्पिटलों का हब सुमेरपुर बनता जा रहा है। अत: सुमेरपुर सीएचसी को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता है। इसी तरह गुंदोज को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत, प्रबंधकीय कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है व इन्हें परमानेंट करवाने की आवश्यकता हे।

सभापति महोदय जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पाली से सिरोही की दूरी 110 किलोमीटर है। दोनों ज़िलों के हैडक्वार्टर के बीच सुमेरपुर या साडेराव में ट्रोमा सेंटर नहीं है जिससे कई बार दुर्घटना होने पर, मरीजों को पाली या सिरोही ले जाना पड़ता है। साडेराव सेंट्रल पाइंट है। साडेराव में नेशनल हाईवे पर नवीन ट्रोमा सेंटर मय डाक्टर व स्टाफ के स्वीकृत कराने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर में आबकारी थाना स्वीकृत है। पहले किराये के मकान में चल रहा था अब हाउसिंग बोर्ड में एक विद्यालय भवन में यह चल रहा है। आबकारी थाने के लिए भूमि आबंटन करवाकर भवन निर्माण का बजट स्वीकृत करायें जिससे थाना नये भवन में शिफ्ट हो सके व बच्चों की पढ़ाई में विद्यालय भवन उपयोग में लिया जा सके।

कोरोना काल में आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। सिन्दरू व बांकली में आयुर्वेद औषधालय खोलने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना में पहले साधारण डिलीवरी व सिजेरियन डिलीवरी नि:शुल्क होती थी लेकिन चिरंजीवी योजना आने के बाद में डिलीवरी साधारण और सिजेरियन दोनों को ही इसमें से हटा दिया है जिससे महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और कई गरीब परिवारों की महिलाएं वहां हास्पिटल्स में भटकती रहती हैं।

सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो चिरंजीवी योजना है, उसमें महिलाओं की जो डिलीवरी है, वह वापस शामिल करायें जिससे महिलाओं को उसका लाभ मिले। आयुष्मान भारत योजना में पूरे भारत में पांच लाख रुपये तक का इलाज ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, अनुबंधित प्राइवेट हास्पिटल्स में नि:शुल्क होता है लेकिन चिरंजीवी योजना में इसे राजस्थान तक ही सीमित रखा है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसे वापस आयुष्मान भारत योजना की तरह पूरे भारत में लागू किया जाये जिससे लोगों को लाभ मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 13 - आबकारी और मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बजट में पूरे राजस्थान के लिए जो घोषणा हुई है उनमें चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उसके अन्तर्गत प्रति परिवार सालाना पांच लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये की घोषणा हो, चाहे वर्ष 2013 में पूर्व में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना प्रारम्भ की गयी थी, उसी के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर एवं इनडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतया नि:शुल्क करने की घोषणा की गयी हो। चाहे माननीय मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, वर्तमान बजट में दुर्घटना हो जाने पर परिवार को सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी हो, जिसमें बीमित परिवार को पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का कवर भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया गया, आपके द्वारा यह घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, गत बजट वर्ष में सात जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय की घोषणा की गयी, अब आगामी वर्ष में शेष अठारह जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। प्रदेश में खुलने वाले पन्द्रह मेडिकल कालेजों हेतु 1,224 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 3,674 बैड क्षमता के पन्द्रह नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य करने की घोषणा की है जिसमें अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुन्झुनूं, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, गंगानगर, टोंक आदि की घोषणा हुई।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करने एवं सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की गयी हो या चाहे आगामी वर्ष में जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में 250 करोड़ रुपये की लागत से नये मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किये जाने की घोषणा की गयी हो। राज्य में आमजन को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा गया हो। चाहे 1,000 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने एवं नवगठित ग्राम पंचायतों में इन्हें प्राथमिकता से खोले जाने की घोषणाएं की गयी हों।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग भी करना चाहूंगा कि मेरी तहसील उच्चैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपखण्ड अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाये। इसी तरह से ग्राम पंचायत वरिघा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्दनपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। पहरसर जो नेशनल हाईवे जयपुर के लिए आ रहा है भरतपुर से, उस पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वहां पर ट्रोमा सेंटर खोलने की, स्थापना करने की भी मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई को, जो तहसील है, उसको 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की भी मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चन्दनपुरा पी.एच.सी. व उच्चैन में ट्रोमा सेंटर की जो पिछले दिनों घोषणा हुई थी, उसका कार्य शुरू करवाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई की सी.एच.सी., नदबई, उच्चैन व खानुआ सहित समस्त पी.एच.सी. पर रिक्त पदों पर डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ को लगाया जाये।

महिला चिकित्सकों की भारी कमी है, उसको भी पूरा किया जाये और इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में जो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. है, वहां पर एक्स-रे, सोनोग्राफी, उच्चैन सी.एच.सी. में डेंटल चेयर एवं अन्य जांच मशीनें, जहां पर नहीं हैं उनकी व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

सी.एच.सी., नदबई की बिल्डिंग काफी जर्जर है, उसके लिए भी फण्ड दिया जाये, कई पी.एच.सीज की भी यही स्थिति है। खानुआ सी.एच.सी., जो

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

बहुत ही महत्वपूर्ण सी.एच.सी. है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि खानुआ सी.एच.सी. पर कोई एम्बुलेंस नहीं है, यह नेशनल हाईवे पर पड़ती है, जो भरतपुर से धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश जाता है तो वहां पर एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाये।

पिछले दिनों मेरे साथ-साथ ही अन्य विधायक साथियों ने भी विधायक कोटे से एम्बुलेंस सरकार को दी थी हर सी.एच.सी. पर, लेकिन उनमें ड्राइवरों की कुछ कमियां हैं उसके लिए भी मैं यह मांग करना चाहूंगा कि ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए माननीय मंत्रीजी यहां सदन में मौजूद हैं, उस पर भी विचार किया जाये और जो डाक्टर्स, कर्मचारी, कम्पाउंडर, एल.डी.सी., यू.डी.सी. का ट्रांसफर, जो काम नहीं करते, उनका हम लोग कर देते हैं तो वे कोर्ट से अक्सर स्टे लेकर आ जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कि उन सबको तुरन्त ए.पी.ओ. के बाद में एक कमेटी ऐसी बनायी जाये कि जिनको हैडक्वार्टर पर, मुख्यालय पर तुरन्त नियुक्ति दे दी जाये।

इसी तरह से कुछ अन्य मांगें और भी हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का मैं ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा कि पहली बार इस बजट में नदबई विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ कमियां रही हैं और मुझे यह पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से जब-जब मैं जिस भी चीज के लिए चाहे वह डाक्टर्स हो, अन्य स्टाफ हो, उनके लिए जब भी मैं निवेदन करता हूं तो हमेशा आप प्राथमिकता के आधार पर नदबई, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमेशा जो भी मैं मांगता हूं वह देते हैं तो यह मांग मैं विशेष रूप से करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना बहुत ही आवश्यक है। उसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र, बारहमाफी जो मेरा स्वयं का पुश्तैनी गांव है, उप स्वास्थ्य केन्द्र, आघापुर; उप स्वास्थ्य केन्द्र, सैदपुरा; उप स्वास्थ्य केन्द्र, तलछेरा; उप स्वास्थ्य केन्द्र, न्यौठा; इसी तरह से विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिचूना; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पींगोरा के लिए भी मैं माननीय मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा और मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का इस बात के

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतना सुन्दर बजट और वह भी विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस तरह से पूरे प्रदेश के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): इस तरह पूरे प्रदेश के अन्दर जो बजट दिया है उससे निश्चित तौर पर एक-एक व्यक्ति को इस बजट का लाभ मिलेगा और जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह पूरे देश के साथ, पूरे विश्व में जो भयानक कोरोना की महामारी आयी और माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने, जो दूसरी लहर आयी थी तो आपने देखा होगा कि उसमें जो बड़ी घोषणाएं कीं और मैं आज सदन में यह कहना चाहता हूं, जिस तरह से दूसरी लहर में हम सबने कहीं न कहीं, किसी न किसी ने चाहे वह परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, हम सबने किसी न किसी को खोया है, लेकिन उस सबका निचोड़ निकालकर इस प्रदेश के जन नायक मुख्य मंत्री आदरणीय श्री अशोकजी गहलोत साहब और हमारे बहुत ही लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्री मीणाजी ने सारी चीजों को विस्तार से समझने के बाद में पूरे प्रदेश के अन्दर हर सी.एच.सी. के ऊपर जिस तरह से ऑक्सीजन के प्लांट दिये और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपने देखा कि पिछले दिनों अधिकांश मरीजों की डैथ हुई, उस सबको देखते हुए मेरी खुद की सीएच.सी., चाहे वह नदबई की सी.एच.सी. हो, उस पर 81 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट दिया, चाहे वह उच्चैन की सी.एच.सी. हो, उस पर भी 51 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट दिया हो, उसके लिए मैं बार-बार माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

आपने मुझे मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद पर इसके साथ-साथ मैं दो मिनट में, केवल मेरी दो-तीन चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण रह गयीं, उन पर भी बोलना चाहूंगा।

आबकारी विषय पर मैं बोलना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई का जो हैड क्वार्टर है, कस्बा है, उसके अन्दर मोहल्ला है, उसमें एससी समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। आये दिन वहां नकली शराब पीने के कारण मौतें हो जाती हैं, सैकड़ों महिलाएं

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

विधवाएं हो गई हैं। नदबई में अवैध शराब की भट्टियां कई जगह चलती हैं। नेशनल हाईवे पर शराब का ठेका खोलने का प्रावधान भी नहीं है। कुछ दूरी उसमें निर्धारित की गई है लेकिन नेशनल हाईवे पर आगरा-भरतपुर-जयपुर के ऊपर लुधावई टोल टैक्स, बिलकुल एनएच पर शराब का एक ठेका पिछले दिनों खोला गया। मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उस ठेके को वहां से हटवाया जाए और जिस तरह से अवैध शराब का कारोबार नदबई में चल रहा है, जिसकी जानकारी मैं माननीय मंत्रीजी के संज्ञान में सारी चीजों को विस्तार से डालूंगा। जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत। माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, मेरे ऊपर ही राइडर क्यों लगा रहे हो। सात मिनट का टाइम है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, मांग संख्या 26 और 13 के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। पिछले दो साल से देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने विभिन्न रूपों में मानवता को काफी नुकसान पहुंचाया है लेकिन हमें बहुत ही गर्व है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में हमारे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सहित हैल्थ वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल कर भी लोगों को बचाने का जो काम किया है, कोरोना साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरा धन्यवाद हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि कोरोना में करोड़ों लोगों को फ्री में वैक्सीन भेजकर सब लोगों को बचाने का जो काम किया है, वास्तव में पूरे देश में उन्होंने किया है, राजस्थान में भी सबको दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां के सरकारी तंत्र ने भी, पक्ष और विपक्ष सबने मिलकर, कोरोना के अन्दर स्थानीय सरकार ने भी जो सहयोग किया है, उन सबको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

हमारे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी हमेशा बहुत ज्यादा खलती रही है। चिकित्सकों की कमी की वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। चिकित्सालयों में पूरा स्टाफ लगाया जाये।

सभापति महोदय, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में

(श्री शंकर सिंह रावत)

राजपत्रित व अराजपत्रित कार्मिकों के 384 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 282 कार्मिक कार्यरत हैं और 102 पद रिक्त हैं। रोजाना अजमेर सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को रैफर किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, इसके ऊपर जरूर आप ध्यान देवें। अमृतकौर चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 5 लाख मरीजों की ओपीडी आती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह डाक्टर्स का आदेश है। आपके विभाग को भी भेजा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, इतना बड़ा अस्पताल और 9 हजार सामान्य और डिलीवरी के केस वहां पर आते हैं। 25 हजार के करीब सीजेरियन डिलीवरी होती है।

महोदय, अमृतकौर चिकित्सालय में 300 बैड ही स्वीकृत हैं और लोगों को मजबूरन अजमेर रैफर करना पड़ता है। इसलिए वहां पर 500 बैड स्वीकृत किए जाएं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। अमृतकौर चिकित्सालय की बिल्डिंग अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है और उसके साथ ही ब्यावर एक डाक बंगला भी बना था। वह डाक बंगला अपने आप धराशायी हो गया है। अगर कहीं अस्पताल की बिल्डिंग धराशायी हो गयी तो समस्या हो जायेगी। उस बिल्डिंग को कन्डम करने के लिए मेडिकल आफिसर ब्यावर, जिला कलेक्टर, अजमेर ने, सभी ने पत्र लिखे हैं और वह जर्जर अवस्था में है। एक्सईएन जो चिकित्सा विभाग का है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को कन्डम की रिपोर्ट लगाकर उसको धराशायी करने के लिए बोला है और साथ ही जितने भी आपके विभाग के अधिकारी हैं, उन सबने, उसको कन्डम बताया है। इस प्रकार की रिपोर्ट जाने के बाद भी हम अपने कान में तेल डाल लेते हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप बहुत सजग हैं, आप बहुत ही ईमानदार हैं, आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप इसके ऊपर ध्यान देते हुए बजट स्वीकृत करें। अगर विधायक कोष से इसके लिए आवश्यकता हो तो आप लेकर बिल्डिंग नई बनाने के लिए बजट आप दें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

ब्यावर में हृदय रोग, यूरोलॉजी के काफी संख्या में मरीज आते हैं। कार्डियोलॉजी यूनिट, यूरोलॉजी यूनिट नहीं हैं। इनको भी आप स्वीकृत करते हुए यहां पर डाक्टर लगाने की कृपा करें। सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की मशीन, दोनों ही संख्या में कम हैं। एक-एक ही होने की वजह से वहां मरीजों की लाइन लगती है।

ब्यावर में राष्ट्रीय मार्ग चारों तरफ से मिले हुए हैं। चाहे आबूरोड की तरफ से आने वाला हो, उदयपुर की तरफ से आने वाला हो, राष्ट्रीय राजमार्ग

(श्री शंकर सिंह रावत)

होने की वजह से अमृतकौर चिकित्सालय बड़ा अस्पताल होने की वजह से चार जिलों के मरीज एट ए टाइम वहां पर आपको मिलेंगे। अजमेर, पाली, राजसमन्द, भीलवाड़ा, इन चारों जिलों के मरीज हमेशा मिल जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अस्पताल में एक मेडिकल कालेज खोला जाए तो लोगों को बचाने का काम किया जा सकेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप टेबल कर दीजिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, 2018 में बराखन में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भवन के लिए बजट स्वीकृत किया जाए।

श्री सभापति: जो भी कुछ बचा हुआ है, टेबल कर दीजिए। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, मुझे तो चार मिनट ही नहीं हुए। सभापति महोदय, सिर्फ मांग कर देता हूं।

श्री सभापति: टेबल कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): कोटड़ा, किशनपुरा, बड़ाखेड़ा और राजियावास को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए और देलवाड़ा मुख्यालय, ब्यावर खास और बंजारी में पीएचसी स्वीकृत करने का कष्ट करें। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर 9.30 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 एवं 13 पर विचार

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 13 और 26 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आबकारी और मेडिकल हम दोनों की बात करें तो हम मान सकते हैं कि दोनों ही अगर ज्यादा मात्रा में मिल जाएं तो व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी घातक है लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अगर शराब की बात करें तो शायद एक भी गांव, शहर का वार्ड ऐसा नहीं होगा जहां पर अवैध शराब की ब्रांच नहीं चल पा रही होगी। हम लगातार देखते हैं कि महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, सब कुछ करती हैं। चाणदा खुर्द, मेरे ही गांव में लगातार दो साल से महिलाएं और गांव के वासी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? शांत रहें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि 24 घंटे, किसी भी गांव में चले जाएं, कोटा और बूंदी जिले को छोड़कर, मैं बात करूं पूरे राजस्थान की तो हर ब्रांच पर शराब मिलती है।

श्री सभापति: शांति रखने वाली बात दोनों तरफ ही लागू होती है, इधर भी और उधर भी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): इस बात को सब जानते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि क्या कार्यवाही होती है। कार्यवाही के नाम पर किस तरह से लीपापोती होती है। मैं कहना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आज देश में 135 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और उसके साथ 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भी लग रहा है। यह बहुत खुशी की बात है।

मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सभी डाक्टर्स को, जिन्होंने वास्तव में, कोरोनाकाल में हमने गत वर्ष देखा कि आम जनता के लिए भगवान बनकर आये, उन्होंने किस तरीके से देखरेख की और सभी का इलाज किया। मैं कहूंगी कि कोटा-बूंदी क्या, पूरे राजस्थान के डाक्टर्स को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हम उनको याद करते रहते हैं।

साथ ही मैं इस बात के लिए धन्यवाद देनी चाहूंगी कि जिस राजस्थान में 2013 की हम बात करेंगे तो तीन मेडिकल कालेज हुआ करते थे,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आज आठ मेडिकल कालेज हमारे राजस्थान में बनेंगे और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जिला हैड क्वार्टर पर मेडिकल कालेज खुलने की जो बात चल रही है, वह निश्चित तौर पर एक राजस्थान और देश के लिए बहुत बड़ी विज्ञान की दृष्टि से हमारी प्रगति है। निश्चित तौर पर छात्रों को विदेश में पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। यह मैं कहना चाहूंगी। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि बूंदी में मेडिकल कालेज की घोषणा शुरू हुई थी। अभी तक बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो पाया। ट्रोमा हास्पिटल नैनवां घोषित हो चुका है लेकिन अभी सालभर से हम देख रहे हैं कि जमीन का क्या विवाद है, किस तरह से है, जिस गांव में, जिस जगह के लिए घोषणा हुई है, उसी जगह बने तो निश्चित तौर पर जनता को लाभ मिलेगा।

(समय: 21.00 बजे)

बूंदी में ब्लड बैंक का विस्तार किया जाए, क्योंकि ब्लड की बहुत प्रोब्लम आती है। जब भी वहां कोई मरीज जाता है तो ब्लड नहीं मिल पाता। 75 बैड के हास्पिटल की रामगंजमण्डी में घोषणा की थी, 2008 से 2013 में जब मैं चुनाव लड़ी थी, निश्चित तौर पर वह भी चालू होना चाहिए, वह अभी तक चालू नहीं हो पाया। नि:शुल्क दवा योजना में लगे हमारे कम्प्यूटर आपरेटर जो विद द मशीनमैन हैं, उनको परमानेंट किया जाए। उन्हें साढ़े आठ हजार रुपये पेमेंट देकर इतना काम उनसे हम लोग करवा रहे हैं। वह अनशन पर भी बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके साथ न्याय होगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करती हूं कि हमारे यहां पर पी.एच.सी. की घोषणा की जाए। जो जैसतर है, जैतपुर है, घाट का बरेना, गंडोली, पीपल्या, जरकोता, ज्याणदां खुर्द, लबान और माधोराजपुरा, सभी में बड़ी पंचायतें हैं, यहां पर पी.एच.सी. की घोषणा होगी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा। केशोरायपाटन का जो आयुर्वेदिक हास्पिटल है, वह एक कमरे में चल रहा है। हमारी पी.एच.सी. की पुरानी बिल्डिंग, जो खाली पड़ी है, उसमें उसे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कोरोना काल में आयुर्वेदिक का कितना लाभ लोगों ने लिया है। लाखेरी ट्रोमा हास्पिटल है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। सोनोग्राफी मशीन मैंने दो साल पहले एम.एल.ए. फण्ड से दी थी, उसका अता-पता नहीं है। करबर सी.एच.सी. आज से चार साल पहले सी.एच.सी. घोषित हुई थी पी.एच.सी. से,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लेकिन मात्र बोर्ड लगा हुआ है, बिल्डिंग कहां है, क्या है, इसका कुछ भी अता-पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि सोनोग्राफी मशीन हमारे कापरेन, इन्द्रगढ़, करबर और लाखेरी सी.एच.सी. पर दी जाए और साथ ही जो हमारी सी.एच.सी., मेरी पांच सी.एच.सी. और नौ पी.एच.सी. पर गायनिक डाक्टर भी लगे, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं। बहुत गरीब मजदूर वहां पर रहते हैं। एम.एल.ए. फण्ड से कोरोनाकाल में बूंदी और कोटा में जो सामग्री की खरीद की गयी थी चिकित्सा विभाग द्वारा, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी बू आती है, क्योंकि जनता हमसे पूछती है कि आपने इतना पैसा दिया है, उसका क्या हुआ? साथ ही जो 14 एम्बुलेंस मेरी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. पर मैंने दी हैं....

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): न तो डीजल उनके पास चलाने के लिए है, और न ड्राइवर है। 108 एम्बुलेंस, जो हमारी प्राइवेट चलती है, उसकी भी जांच करवायी, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में मैंने खुद ने प्राण त्यागते हुए लोगों को देखा है। इसके साथ ही साथ मैं मांग करूंगी कि पिछली बार मैंने रामगंजमण्डी में एम्बुलेंस दी थी, वह चार साल से कम्पनी में अभी तक पड़ी हुई है। उसको भी जिस हास्पिटल को दी है, वहां पर पहुंचायी जाये। चल चिकित्सा इकाई करबर सी.एच.सी पर लागू की जाए। चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख रुपये दिये, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। जिस समय पेशेंट हास्पिटल में एडमिट हो, उसी समय से उसकी सारी जांचें इसमें सम्मिलित की जाएं, क्योंकि दो-तीन दिन अगर उसको हास्पिटल में रखा जाए तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। कोविड सेंटर जो बने हैं, उनकी दूरी हम लोग देख रहे हैं 50-50 किलोमीटर दूर लगे हैं, उन्हें भी पंचायत हैडक्वार्टर पर ही लगाया जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे डाक्टर्स हैं, उन्हें अलग से भत्ता दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय दें। मैं कोई आलतू-फालतू कुछ भी नहीं बोल रही हूं। मेरा यह भी निवेदन है कि नवीन चिकित्सालय कोटा में जो कोविड-19 में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

काफी सिलेण्डर चोरी हुए हैं, यह बड़ा गंभीर इश्यू है। हम इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं और भगवान करे आगे यह नहीं आये, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि कितने सिलेण्डर चोरी हुए, अभी वर्तमान में कितने सिलेण्डर हैं? साथ ही साथ नवीन चिकित्सालय कोटा का जो हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है, उसे जे.के. लोन में स्थानान्तरित करने के बाद जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको तो रखा जाता है जे.के. लोन में, और नवीन चिकित्सालय में मेडिकल कालेज में हमारी जो माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वह रहती हैं। निश्चित तौर पर चार-पांच किलोमीटर की दूरी है, इसमें भी हमें कुछ करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एम.एल.ए. फण्ड से दी गयी एम्बुलेंस, मैं कहूंगी कि नवीन मेडिकल कालेज में किस-किस दर पर उनकी क्या-क्या दूरी तय हुई है, यह किस दर पर चल रही है? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक मिनट माननीय सभापति महोदय, उसकी भी हमें जांच करनी चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल के गेट के पास जो बैरियर और गार्ड क्वार्टर का निर्माण किया गया है, वह बनने के बाद क्षतिग्रस्त होने वाला है। उसको हम चालू भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी हमें कुछ विचार करना चाहिए।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में, आर.जी.एच.एस. में सरकारी कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह हम देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे बड़े अस्पताल हैं, जैसे मैत्री है, जयपुर शहर का इटरनल हास्पिटल है, इनको इससे बाहर रखा गया है। निश्चित तौर पर इन्हें भी उनमें शामिल करेंगे तो कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आर.जी.एच.एस. में सरकारी कर्मचारियों में जो भेदभाव किया है, उसे मिटाने का काम करें, 2004 से पहले लगे कर्मचारियों...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आधा मिनट।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं टेबल कर दूं, साहब मेरा? टेबल कर दूं?

श्री सभापति: हां, टेबल कर दीजिए। टेबल पहले ही कर देते। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर मांग संख्या 13-आबकारी और मांग संख्या 26-चिकित्सा पर बहस हो रही है। जिस माहौल में बहस हो रही है, मैं लम्बा समय इसलिए नहीं लूंगा कि आज का जो राजनीतिक वातावरण बना है, कुछ लोग उल्लास और उत्सव में शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग अपने गम को कम करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बात करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन की बड़ी सुदृढ़ परम्पराएं रही हैं, नियम रहे हैं। सदन का सत्र जब चलता हो तो कोई भी नीतिगत घोषणा सदन चलते हुए सदन के बाहर नहीं की जा सकती। इसमें अध्यक्षीय फैसले हैं, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा और मैं सिर्फ फैसला आपके सामने टेबल कर दूंगा। 10 दिसम्बर, 1959 का फैसला है। सतीश चन्द्र जी अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में मामला उठाया, फिर 30 दिसम्बर, 1979 में मानिक चन्द जी सुराना ने उठाया, फिर 22 सितम्बर, 1977 को परसराम जी मदेरणा ने उठाया। यह मैंने इसलिए मामला बताया, मंत्री महोदय, कि आपने आबकारी एवं मद्य संयम नीति, 2022-23 एवं 2023-24 में अपने पत्र क्रमांक वित्त/आब/2020, 7 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मैंने जब से आहूत हुआ है इस सदन में जो भी आपके नोटिफिकेशन टेबल हुए हैं, उन सबको पढ़ने के बाद मैं यहां आया हूं। उसमें आपने बड़े ही नीतिगत फैसले कर लिए। आपने शराब की गारण्टी धरोहर राशि का फैसला कर लिया। आपने उसके अन्दर प्राप्त अधिकतम बिड की राशि का फैसला कर लिया। मैं समझता हूं यह सदन की परम्पराओं का, सदन का अपमान है, अध्यक्षीय निर्णयों का अपमान है। माननीय सभापति महोदय, मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि आप इसमें क्या निर्णय करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब सरकार बनी ही थी तब आपने मद्य संयम नीति लागू करने की बात पर आपने पूर्ववर्ती सरकार पर यह कहकर आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार में शराब की दुकानें बहुत खोली गयीं। मंत्री महोदय, अब आप बताएं अभी आपने कम्पोजिट दुकान के नाम पर जो राजस्थान में एक हजार शराब की दुकानें थीं, आपने बढ़ाकर 7,666, यानी 6,666 दुकानें खोल डालीं। मैं समझता हूं इससे बुरी कोई बात और नहीं हो सकती। यह शराब के विक्रय को बढ़ावा देना है। मैं यह मानता हूं आबकारी एक्साइज रेवेन्यू एक्ट बहुत बड़ा कम्पोनेंट है। आपने इस वर्ष 15 हजार करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का रखा है। पिछली बार आपका 13,250 करोड़ का था, पर मैं समझता हूं कि आप अगर इस प्रकार एक साथ इस राजस्थान के अन्दर शराब की दुकानें बढ़ाएंगे तो फिर किस मुंह से मद्य-संयम नीति की बात कर रहे हैं? इतने असीमित आपको नहीं होना चाहिए। आपने दूसरा बड़ा काम किया, पहले, माननीय सभापति महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं, कुछ ही परिवारों का काम था, जितना भी शराब का व्यवसाय था, उनके कब्जे में था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को, एक नई योजना लेकर आये, एकल दुकान लाटरी सिस्टम से आबंटित करने की। आपने अचानक बदल दी। आपने बदलकर ई-टेण्डरिंग ऑक्शन नीति लागू की। मैं समझता हूं यह आप जो 2021-22 से यह नई नीति लेकर आये, आपका जो आबकारी राजस्व था, जो आपका रेवेन्यू था, 13,250 करोड़ में, मेरे पास 01 जनवरी तक के ही आंकड़े हैं, 8,748 करोड़ आपको मिला है और उससे पहले जब आप एकल दुकान में, जिसमें हजारों बेरोजगार अपनी किस्मत को आजमाते थे, जिसकी दुकान खुलती थी वह उस व्यवसाय से जुड़ता था। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 30 हजार रुपये उस समय एक आवेदन पत्र का शुल्क था और उसके अनुसार सिर्फ आवेदन पत्र के शुल्क पर 2019-20 में 4 लाख 25 हजार, राजस्थान सरकार को पैसा मिला 01 हजार 50 करोड़ रुपये, सिर्फ आवेदन शुल्क पर। मैं केवल एप्लीकेशन शुल्क की बात कर रहा हूं। 2020-21 में 3 लाख 50 हजार लोगों ने एप्लाई किया और 800 करोड़ का मिला। आप नई नीति लेकर आ रहे हैं, आपको क्या मिला? लाटरी सिस्टम से दुकान थी, लाखों लोग एप्लाई करते थे, दुकान के लिए कोशिश करते थे। आपके 12 हजार आवेदन आये, आपको मात्र 75 करोड़ का राजस्व मिला। मैं समझता हूं पिछले दरवाजे से आप किसकी मदद करना चाहते हैं? क्यों मदद करना चाहते हैं? माननीय परसादी लाल जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपको चार बार ई-बिड को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं निवेदन करूं, मैं इस बात को लम्बी नहीं करूंगा लेकिन यह आबकारी नीति, आबकारी बन्दोबस्त, जो आप इन 2 वर्षों में लेकर आये हैं 2021-22 और 2022-23 का, किसका फायदा करने के लिए लेकर के आये हैं?

सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने सब शराब व्यवसायियों को कह दिया कि आरएमएल दारू, मैं समझता हूं रसद मंत्री जी आप मुझे करेक्ट करेंगे, राजस्थान मेड लिकर, यह लिकर कौन बनाता है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2 इंडस्ट्री, एक तो है आरएन प्रोडेक्ट और एक है एनवी डिस्टिलरी। आपने इस नीति के अन्दर लिखकर दे दिया कि 30 परसेंट आपको आरएमएल मदिरा बेचनी पड़ेगी। कौन हैं इसके मालिक? मैं समझता हूं यह आरएन प्रोडेक्ट और एनवी डिस्टिलरी, यह रुचिर पारीक जी का, हम अगर उनकी रुचि के अनुसार नीतियां बनायेंगे तो बन्द करो यह मंत्री महोदय, यह जोधपुर, यह जोधपुर खेलना। बन्द करो आप।

मैं निवेदन करूं कि आपकी आबकारी नीति बिन्दु संख्या 3.10.4, आपके अधिकारियों को कह देना गलत हो तो मुझे आप बता दें। आपने आरएमएल शराब बनाने वाली निजी डिस्टिलरी की बॉटलिंग में जो पहले 6 रुपये थी, उसको 5 रुपये कर दिया। क्यों जी, किसने मांग की आपसे? आपने कितना फायदा कर दिया, क्योंकि इस सारे खेल में सिर्फ 2 इंडस्ट्री हैं। मेरा आरोप है कि आपने 35 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया।

दूसरी, आपकी नीति 3.10.2, यह आप ही की नीति मैंने पढ़ी है। आरएमएल और देशी शराब, देशी शराब में 10 रुपये पेटी बढ़ा दी। प्रतिपक्ष के नेता, आरएमएल में बनाने वाला एक ही है इसलिए 30 रुपये बढ़ा दी, 100 करोड़ का फायदा। क्यों? आपको राजस्व एकत्र करना है कि राजस्थान की जनता को, आप एक तरफ आरएमएल की दारू पिलाने के लिए मजबूर कर रहे हो और दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से उनकी मदद कर रहे हो।

यह आपकी आबकारी नीति का बिन्दु संख्या 10, यह गंगानगर शुगर मिल्स को आप जानते हैं, मंत्री महोदय, गंगानगर जिले के अन्दर जितना गन्ना किसान उत्पादित करता है, उसका गन्ना भी खरीदती है। यह 1956 से लगातार लाभ में है। इसके पास देशी शराब खरीदने का सिंगल होलसेल का एकाधिकार था। अब आप किसको दे रहे हो? आरएसबीसीएल, क्योंकि आरएमएल खरीद रही है। यह सुखबीर जी का सुख अपने कहां है। आपका कहां लेन-देन इन सुखों से?

मैं निवेदन करूं, आपने एक नयी बात और कर दी कि आरएमएल दारू बनाओगे ईएन स्प्रिट से। मैं जो बात कह रहा हूं, आप उत्तर दे देना। जबसे यह सरकार आयी है, यह ईएन स्प्रिट राजस्थान में एनवी डिस्टिलरी के अलावा किसी ने सप्लाई किया हो तो मुझे बताओ। मतलब, आप पूरी नीतियां बदल रहे हो। इसको कहते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने अब कर क्या रखा है? आरएमएल के अन्दर जो स्ट्रेंथ है 25 यूपी की, वही स्ट्रेंथ अंग्रेजी शराब की है। आरएमएल की एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि सैंया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, जिसको फायदा पहुंचाना है तो पूरा ही पहुंचाएं। उसमें 200 रुपये प्रति एलपीएल और अंग्रेजी की 260, यानी 412 करोड़ का फटका। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास वह आंकड़े हैं कि कितनी शराब बेची गयी।

अब आप एमनेस्टी योजना लेकर आये हैं। बजट में किया है न, बजट पैरा 170 में, आपने कहा कि 31 मार्च, 2014 तक समस्त बकाया प्रकरणों में मूलधन में छूट देंगे। उसके बाद आपने कह दिया कि 31 मार्च, 2021 में तो प्रकरणों में, ब्याज में शत प्रतिशत की छूट देंगे। क्यों? जिस ठेकेदार ने ठेका लिया, उसने अपनी जमीन मोर्गेज की। सोल्वेंसी है उसकी। बैंक गारंटी है। आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए, आपकी निगाह कहां है? मैं अगर कहूं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, नवरत्नों में चमकता हुआ रत्न, मैने इनका फीका पड़ता हुआ चेहरा उस समय देखा। आप पुलिस हैड क्वार्टर पर गये। लिस्ट लेकर गये। यह 24 थाने हैं। इन थानों में थानेदार पुलिस हैड क्वार्टर लगाता है और यह स्मगलिंग करते हैं। मैं सही कह रहा हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने यह पहली बार देखा है। तस्कर की शराब पकड़ो। चलो पकड़ो। उसमें आधी वापस तस्करों को बेच दो। यह खेल नहीं खेला अभी भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि इसको देखना चाहिए।

जालौर में एक धानोली गांव है। 7 वर्ष से उन्होंने शराबबन्दी कर रखी है, पर 156 करोड़ का ठेका गया क्योंकि बिलकुल बोर्डर पर है। यह आपके खुद के सिरोही में आपके निर्वाचन क्षेत्र का गांव मैं भूल रहा हूं 3 हजार की आबादी और 54 करोड़ का ठेका।

सभापति महोदय, मैं अब मेरी बात दूसरी तरफ ले जाऊंगा, पर आखिर में कहूंगा कि एक नवजीवन योजना इसलिए बनायी गयी थी कि अवैध शराब दुखान्तिका हुई, उसमें आपके एक्सपर्ट कमेंट के लिए कुछ नहीं कहूंगा। आपके स्ट्रैट-फारवर्ड बातें करने का मैं आशिक हूं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जहरीली शराब पीते ही क्यों हैं? अंग्रेजी शराब पीओ। अपने आप ठीक हो जायेगा। कितनी बड़ी समस्या का एक झटके में समाधान। मैं समझता हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बहुत ठीक किया लेकिन कम से कम नवजीवन योजना, इस योजना में एक परसेंट, टोटल एक्साइज राजस्व का आपको खर्च करना है, उसको तो कम से कम खर्च कर दो तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा।

सभापति महोदय, इन बातों के साथ मैं मंत्री महोदय, उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, जो बातें मुझ से पहले बहुत लोगों ने कह दीं।

श्री सभापति: 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस बार निश्चित तौर पर हम जब बात करते हैं 9 करोड़ 52 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया तो मैं समझता हूं कि इस बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि वैक्सीन आयी कहां से? आपको प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए।

मैं उस बात को कहकर भी सनसनी नहीं फैलाना चाहता कि 1,500 वेंटिलेटर, प्रधान मंत्री केयर के वेंटिलेटर खराब सिर्फ राजस्थान में देखे गये। पूरे हिन्दुस्तान में वेंटिलेटर गये और वह मंत्री महोदय के समधी के हास्पिटल में कैसे ठीक हो गये जी? किराये पर दिया था अपन ने। यह सारे अनुत्तरित सवाल हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे खेल में, कोरोना के अन्दर बहुत से लोगों ने सेवाएं दीं। धरती के भगवान के 2 रूप हमने देखे। धरती के भगवान के चेहरे से उठता हुआ नकाब हमने देखा। प्राइवेट हास्पिटल्स की लूट हमने देखी लेकिन यह नर्सिंग स्टाफ डटा रहा। मेरे यहां के एक चेयरमैन बीमार हो गये। काल-कवलित भी हो गये। मैं पूरी ड्रेस पहनकर कहता रहा। डाक्टर को पुकारता रहा। मैं साढ़े 8 साल इस राज्य का मेडिकल मिनिस्टर रहा हूं। मेरे कहने से नहीं आया, 3 नर्सिंग कर्मी खड़े थे।

मंत्री महोदय, यह राजस्थान के एएनएम, एलएचवी जिनकी ग्रेड पे 2800 से 3600 रुपये है, अपना पदनाम बदलना चाहते हैं। सिर्फ सीनियर हैल्थ नर्सिंग आफिसर, इस बन्दे ने कर दिया, ग्राम सेवकों को ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। वह ग्राम विकास अधिकारी जब नेम प्लेट लगाता है, छोटे से अक्षरों में आरआर लिखता है। मैं चाहता हूं कि पीआर लिखा जाये, इसलिए आप इस काम को भी करें।

सभापति महोदय, मैं इस बात को लम्बी नहीं कहूंगा। मुझे कहने को तो बहुत था, परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि यह जो अभी रिपोर्ट आयी है इंटरनल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट एक्सचेंज, अब मुझे 3 मिनट दे दें, यूएनओ की ताजा रिपोर्ट, उसमें लिखा है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से लेकर अब तक 125 वर्षों में वैश्विक तापमान 1.25 परसेंट बढ़ गया। ऑक्सीजन की कमी पूरे वातावरण में हो गयी। माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर पिघल गये।

इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि साइनो बैक्टीरिया बढ़ेंगे। यह जहरीले हैं। भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में अल्फा टॉक्सीन फैलेगा। यह कैंसर फैलाता है। आज जलवायु पोल्यूशन, मैं एक निवेदन करके बात समाप्त करूंगा, यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आज राजस्थान के अन्दर जो एनएफएस फिफ्थ का सर्वे आया है, टोटल मौतों में 61.6 परसेंट लोग इससे मरते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हृदय रोग से जुड़ी हुई बीमारियां मैं समझता हूं कि अगर इसको रोकने की कोशिश नहीं की, ठीक है आपने कैंसर में तम्बाकू वाली बात की, लेकिन मैं क्यों उठाऊं?

अलग-अलग बात है। मेरे गांव में भी बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इतना तम्बाकू पीया। मैं एक बार स्वास्थ्य मंत्री था और माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत के साथ एक कार्यक्रम में था। वहां बात चली कि गुटखे से कई बीमारियां होती हैं। उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं गुटखा कई क्विंटल खा गया। मैं आपकी उस बात पर आपकी बुद्धिमता की नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इन 16 जिलों में, जिसमें मेरा जिला भी है, हम इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पीते हैं। कितनी बार यहां इस सदन के अन्दर जालंधर, फगवाड़ा के बाद मेन कैनाल के अन्दर सीवरेज और ड्रेनेज का पानी डाला जाता है। वह पानी हम पीते हैं। मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी। उसमें कहा गया कि इस पानी में मर्करी है, निकिल है, क्रोमियम है। इनसे कैंसर फैलता है। एक सर्वदलीय दल में हम साथ चलेंगे। आप इसको रुकवायें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इसी प्रकार आपके चौमूं में आपके जयपुर के पास, जोधपुर के पास गन्दे पानी से, धड़ल्ले से सब्जियां पैदा की जाती हैं। इनमें हैवी मैटल्स हैं। यह हैवी मैटल्स इन सब्जी खाने वालों को हृदय रोग की तरफ ले जाते हैं। कैंसर की तरफ ले जाते हैं। मैं सिर्फ आपको सुझाव दूंगा।

इसके साथ हम कम से कम समय में ज्यादा अनाज पैदा करना चाहते हैं, कैमिकल फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अभी 600 करोड़ का राजस्थान आर्गेनिज्म मिशन चालू

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है। सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अगर फैलती है तो उसका जनक यह पेस्टिसाइड, इनसेक्टिसाइड है जो धरती में जल्दी से जल्दी अनाज पैदा हो उसके कारण फैलती है। आपको इस मिशन के साथ जुड़कर लोगों को प्रेरित करना चाहिये।

आप पीएसएम विंग को मजबूत करो। आप बीमारी से पहले बचाव की बात करो, अर्ली डिटेक्शन की आप व्यवस्था करायें, आप प्रिवेंटिव ओपीडी चालू करो। आज योग की बात यूं ही नहीं आयी, योग को स्कूल के साथ और स्वास्थ्य के साथ जोड़ो।

माननीय सभापति महोदय, अन्त मैं यह कहूंगा कि आपको जो बजट मिलता है, यह मैं एनएचएम का ही लेकर आया हूं। एनएचएम में आपको पैसा मिला 2020-21 में 5,013 लाख और आपने खर्च किया 3,318 लाख यानी 66 परसेंट, और यह इमर्जेंसी रिलीफ रेस्पोंस प्लान में आपको पैसा मिला 629 करोड़ और आपने खर्च किया 313 करोड़ रुपये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसी प्रकार से 2021-22 में आपको पैसा मिला 4,358 लाख और आपने पैसा खर्च किया 21.73 लाख यानी 10 परसेंट भी नहीं, इसको ठीक करो आप।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहने को तो बहुत है आपने राइट टू हैल्थ वाली बात का बहुत झुनझुना बजाया। इन लुटेरों को, इन डाक्टरों को, आप क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के नीचे तो ले आओ। हमसे जमीनें ले लीं और जनता को लूटने का काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज न जाने क्यों मुझे आपसे कुछ डर और खौफ लगता है। मेरी बातें कहना बड़ी चाहता हूं पर यह जो बजट के अन्दर आपने कहा था 2021-22 में कि एक हजार अरबन पीएचसी, सब-सेंटर्स को वेलनेस सेंटर करेंगे, इसके पीछे कौन रोकता है, करते क्यों नहीं हो? आपको करना चाहिए, पैसा भारत सरकार का है, आपका है।

माननीय सभापति महोदय, मोबाइल कैंसर यूनिट की घोषणा हुई, उसका मैं स्वागत करता हूं, पर आपको ध्यान है एक बार राज्य में एक वक्त था।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बैठ जाऊं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट में। माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान है कि 2021-22 के अन्दर, 22 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल एम्बुलेंस दी थी आपने। एक चल रही हो तो बताओ, सिंगल। अब आप यह और कर दोगे कि मानव संसाधन लगाओ। यह जो मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कहा कि उपकरण डिब्बे में बन्द पड़े हैं, जब तक मानव संसाधन न हो, आप चाहे उपकरण मत खरीदो, खरीदो तो उसको एनुअल रिपेयर कोन्ट्रेक्ट के साथ खरीदो।

सभापति महोदय, बाजरे का महत्व तब समझ में आया जब इंटरनेशनल डे आफ मिलेट्स मनाना चालू हुआ। यहां पर भी आपने 100 करोड़ का राजस्थान मिलेट्स प्रमोशन मिशन चालू किया। बाजरा खाने से डाइबिटीज दूर होती है। मेरे यहां माना जाता है, बाजरा खाओ तो हृदय रोग दूर। आप भी इसको प्रमोट करो, आप भी इसको रिकमंड करो कि बाजरे को एमएसपी पर खरीदें ताकि बाजरा ज्यादा से ज्यादा पैदा हो।

माननीय सभापति महोदय, इतनी सी बात कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, वैसे बहुत-सी बातें कहने को थीं, पर आज मैं कुछ आपकी उदासी देखता हूं। मैं आपको पसन्द करता हूं और विशेष रूप से उड़े हुए चेहरे यह होता रहता है राजनीति में, इस घटना को आप इतने मन से मत लगाओ और फिर हम उधर आयेंगे तो जो बातें रह गयीं, जो बातें रह गयीं, जो आपके खौफ से मैं कर नहीं पाया, माननीय सभापति महोदय, मैं लिखकर दे दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जो पहला बुनियादी सवाल खड़ा किया, यह जो सदन को बाईपास करके इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का जो कुकृत्य किया है वो निन्दनीय है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई व मांग संख्या 13-आबकारी की मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं माननीय उप नेता प्रतिपक्ष से एक सवाल पूछ लूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं ऐसे सवाल का जवाब देने का आदी नहीं हूं माननीय मंत्री महोदय, फिर मैं सवाल करूंगा। मैं जानता हूं कि आप क्या पूछोगे। छोड़ो न। ढंकी ही रहने दो न बातों को।

श्री सभापति: श्री सुभाष गर्ग।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 13 एवं 26 पर विचार

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 के सन्दर्भ में मुझे अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

अभी मेरे से पहले उप नेता प्रतिपक्ष बड़े खुश हो रहे हैं और हमारे माननीय मंत्रीजी पर व्यंग्य कर रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। शायद आज उप नेता प्रतिपक्ष बहुत खुश हैं और ऐसा लगता है कि भविष्य की सम्भावनाएं उनको नजर आ रही है राजस्थान में। आज बड़े खुश हैं सर, और आप समझ सकते हैं कि क्यों खुश हैं।

श्री सभापति: इनको आप थोड़ा च्यवनप्राश भिजवाओ ताकि हैल्थ बनी रहेगी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, अभी बजट की बात कर रहे थे। केन्द्र सरकार के सन्दर्भ में बजट की बात मैं करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जो निरोगी राजस्थान का संकल्प माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने लिया और उसी के तहत मेडिकल हैल्थ, आयुष, सारी पद्धतियों को बढ़ावा देने का काम किया। दूसरी तरफ मैं भारत सरकार का उदाहरण देना चाहता हूं, 2021-22 का कुल बजट 82,920 करोड़ रुपये था और 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, मुझे पढ़ने में भी शर्म आती है, माननीय सभापति महोदय, 83,000 करोड़

(डा. सुभाष गर्ग)

रुपये, 80 करोड़ रुपये की वृद्धि, पूरे देश के सन्दर्भ में, एक तरफ तो खोलना चाहते हैं हर जिले में मेडिकल कालेज, तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी साथियों से कि जो मेडिकल और हैल्थ की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क की बात कर रहे थे, 80 करोड़ रुपये बढ़ाकर मेडिकल हैल्थ को कितना एंश्योर कर पायेंगे, यह जवाब दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल आयुष के सन्दर्भ में बात करना चाहूंगा। मुझे 8 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें बहुत सारी बातें आयीं और जिन माननीय सदस्यों ने आयुष के बारे में बात उठायी, कई बार लगता है कि विपक्ष के साथी करीब-करीब 75 हैं, केवल 9-10 लोगों ने आयुष की बात उठायी और बात करते हैं चिकित्सा पद्धति, इंडियन मेडिसिन को डवलप करने की। राजकुमारजी, कैलाशजी मीणा, बलवान पूनियाजी, गायत्री देवीजी, श्रीमती संतोष देवीजी, वासुदेव देवनानीजी, अनिता भदेलजी, हाकम अलीजी ने, इन लोगों ने आयुष को लेकर चिन्ता जाहिर की।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कुछ समस्याओं के ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिलाया, कोन्ट्रेक्ट डाक्टर्स की बातें कहीं और सारी बातें कहीं लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर आप देखें तो आयुष का जो डवलपमेंट हुआ, शुरू से लेकर आज तक तो करीब-करीब 9 संस्थान खोले गये। आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जो इनकी सरकार के दौरान खुला। इंडियन मेडिसिन बोर्ड कांग्रेस सरकार के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड कांग्रेस सरकार के अधीन, प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड कांग्रेस शासन के दौरान, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड कांग्रेस सरकार के द्वारा, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी आपके द्वारा, निदेशालय आयुर्वेद विभाग कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान, निदेशालय होम्योपैथिक विभाग कांग्रेस शासन के दौरान और निदेशालय यूनानी विभाग कांग्रेस के द्वारा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट के बारे में भी बात करना चाहूंगा। संस्थानों की बात कर रहा हूं उससे पहले 2017-18 में आयुर्वेद के केवल 2 संस्थान थे और 2021-22 में हमने 8 किये। 2017-18 तक होम्योपैथी का एक भी कालेज नहीं था, जो दो अब हम खोल रहे हैं। यूनानी का शुरू से चला आ रहा है जो किसी ने नहीं खोला, जो अभी भी है। योगा और नैचुरोपैथी जिसकी बात कर रहे थे देवनानीजी, योग विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि योग और नैचुरोपैथी के जीरो

(डा. सुभाष गर्ग)

थे, जो आज आठ कालेज खोल दिये गये हैं और जिनमें एडमिशन शुरू भी हो गये हैं। कुछ लोगों ने बात उठायी थी वेलनेस सेंटर की, कहा कि खोल तो दिये गये लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 2020-21 के बजट में एक हजार वेलनेस सेंटर खोलने की बात हुई थी जिसमें से 500 हमने 2020-21 में खोल दिये, जिसमें से 480 के करीब शुरू हो गये हैं और 2021-22 में 500, मैं बता दूंगा मेरे पास आंकड़े हैं सारे। इसमें जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की गाइडलाइन थी, जो हमारे औषधालय हैं उनको ही डवलप किया जायेगा और हमने वह प्रोसेस कर लिया है और जिस पर करीब-करीब एक पर 13 लाख रुपये का खर्चा आ रहा है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है, 400 और कुछ पर तो काम हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा बजट की, आयुष जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नैचुरोपैथी और सिद्धा, जिसको लेकर इंटीग्रेटेड हैल्थ पालिसी को लेकर राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने 2021 में आयुष पालिसी की घोषणा की। इस पालिसी में पूरा रोडमैप दिया गया है जिसमें हमारे जिला चिकित्सालय होंगे, ब्लाक लेवल के चिकित्सालय होंगे, पंचायत हैडक्वार्टर पर एक औषधालय खोला जायेगा। उस पालिसी के तहत अब काम शुरू हो रहा है और उसमें न केवल आयुर्वेद होगा बल्कि ब्लाक लेवल हास्पिटल तक जो चिकित्सालय खुलेंगे उनमे एक यूनानी का भी होगा, एक होम्योपैथी का भी होगा और एक नैचुरोपैथी का होगा। मैं बताना चाहूंगा के 400 के करीब हमारे जो वेलनेस सेंटर शुरू हो गये हैं इन पर इंस्ट्रक्टर, एक लेडी और एक जेंट्स भी नियुक्त कर दिये गये हैं। कुछ पर नहीं हुए हैं लेकिन काफी हद तक कर दिये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बजट के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद का 2017-18 में बजट था भाजपा सरकार के दौरान वह केवल 594 करोड़ रुपये था। जो आज बजट 2021-22 में हमने दिया, 1,088 करोड़ का दिया। इस तरह से होम्योपैथी का 2017-18 में 33 करोड़ 49 लाख का था, जो हमने बढ़ाकर 2021-22 में 47 करोड़ 96 लाख का किया। इस तरह से यूनानी का 26 करोड़ 82 लाख था, उसे बढ़ाकर 35 करोड़ 23 लाख दिया। इसके बाद भी, समय कम है, मुझे 6-7 मिनट के लिए कहा गया है, मैं बताना चाहूंगा 2022-23 की बजट घोषणा, हमारा लक्ष्य है कि हर जिला हैडक्वॉर्टर पर इंटीग्रेटेड कालेज खुलें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सुन लीजिये मदन दिलावर जी। सुन लें आप।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, आप आसन को सम्बोधित करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): एक नया कान्सेप्ट लेकर आये कि जो इंटीग्रेटेड कालेज खुले हैं आयुष के, जिसमें होम्योपैथी होगा, आयुर्वेद होगा, योगा-नैचुरोपैथी भी होगा और उसी के तहत हमने सारे सम्भागीय मुख्यालयों पर ये कालेज खोलने की घोषणा की, जिसकी एसओपी भारत सरकार से आनी बाकी है। जमीनें आबंटित हो गयी हैं। इसके अलावा मेडी-टूरिज्म थीम के आधार पर बीस जगह, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, 11 जगह जमीन का आबंटन हो चुका है। उसकी एसओपी तैयार हो रही है और विज्ञापन जारी कर दिया जायेगा, जिसके साथ हम प्रस्ताव मांग रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर मेडी-टूरिज्म के तहत किया जायेगा।

इसी तरह से यूनानी की बात कर रहे थे हाकम अली साहब। हमने एक लक्ष्य लिया है कि 352 जो ब्लाक लेवल के चिकित्सालय होंगे, वहां यूनानी भी खोली जायेगी और होम्योपैथी भी खोली जायेगी। उसके प्रस्ताव हमने वित्त विभाग को भेज दिये हैं और जल्दी ही वे स्वीकृत हो जायेंगे। इसी तरह से यूनानी कालेज, टोंक बहुत पुराना कालेज है, पहली बार दस करोड़ रुपये की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की। यूनानी चिकित्सकों की भर्ती का मामला है, वह भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

एक बात जो वासुदेव देवनानी जी ने कही, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हड़ताल कर रहे हैं निदेशालय के स्तर पर। उस पर सरकार बहुत संवेदनशील है। जो टैम्परेरी काम कर रहे थे या जो कान्ट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसके लिए कमेटी विचाराधीन है, वह काम कर रही है, लेकिन जहां तक जो वहां धरना दे रखा है, वह मेडिकल एंड हैल्थ डिपार्टमेंट में जिन्हें नियुक्त किया गया था, आयुष विभाग के अधीन नियुक्त नहीं किया गया था तो वे एनएचएम के तहत नियुक्त किये गये थे, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद चाहते हैं, इनकी समस्या का समाधान हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे सदन को, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो और चाहे योग-नैचुरोपैथी हो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, 33 हर जिला स्तर पर एक योग एंड नैचुरोपैथी का टीचर होगा, जिसकी आरपीएससी से लिस्ट आ गयी है।

(डा. सुभाष गर्ग)

एक और बात करी थी कि 704 नर्सिंग कर्मियों का विचाराधीन है, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार संवेदनशील है, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। कुछ शिकायतें आयी थीं कि मेघालय, मणिपुर से लोग करके आ गये हैं ढाई साल का कोर्स, उसकी जांच विचाराधीन है। तीन कमेटीज बैठाकर लगातार, एक के ऊपर एक, और फाइनल उसकी रिपोर्ट हमने लॉ डिपार्टमेंट को भेजी है। जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, उन 704 की भर्ती भी कर दी जायेगी। 500 कुछ की भर्ती पहले की जा चुकी है।

मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल निर्देशन, कुशल नेतृत्व में जो निरोगी राजस्थान का संकल्प है, उसी को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड हैल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल हैल्थ पर तो मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन आयुष को जो इम्पोर्टेंस दी है, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी, योगा, ये आने वाले समय में, हमने जो बीस साल का रोडमैप बनाया है, इसे आप चाहें तो देख सकते हैं, यह उपलब्ध है, वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, इसमें पूरी पालिसी दी गयी है और इसी के तहत हमारा काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, आज चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही जोश में थे। हमारा बहुत पुराना साथ है 1990 से। बीच में ब्रेक हो गया, अब कंटीन्यू है। इतना अहम भी नहीं करना चाहिये। पहले भी यूपी में योगी जी मुख्य मंत्री बने थे, फिर हमने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सरकार बनायी थी। इतना अहम न करें। यह जनता है, किसी की सगी नहीं है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से 164 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन सबके जवाब तैयार कर लिए गये हैं। सबको जवाब कल तक भिजवा दिये जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने कई अच्छे सुझाव दिये। यह भी कहा गया कि अवैध शराब की दुकानें चलती हैं, तस्करी होती है, थानों की कार्रवाई नहीं होती है, सब चीजें माननीय सदस्यों ने कहीं। हमने सब नोट किया है। निश्चित रूप से आपके जो सुझाव आये हैं कि नियमानुसार दुकानें चलें, हमारी सरकार बनने के बाद हमने यह तय किया कि सुबह दस बजे से रात के आठ बजे तक ही

(श्री परसादी लाल)

दुकानें खुलेंगी और आठ बजे बाद बन्द हो जायेंगी। उसका पूर्णत: हमने तीन साल तक पालना से उसको फोलो किया। मुख्य मंत्री जी ने शुरू में आते ही यह कह दिया कि रात भर जो दुकानें चलती थीं पहले, उससे शान्ति भंग होती थी और लोगों को निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता था। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं माननीय सदस्यों को मेरी ओर से आश्वस्त करता हूं कि आपके यहां आठ बजे बाद दुकान चले तो आप उसका मुझे पत्र लिखें। सम्बन्धित जो भी इंस्पेक्टर होगा, अगर आपकी बात सही मिलेगी तो सस्पेंड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहां। खुले रूप से है सब। अगर किसी की एक दुकान है, उसने सब-शाप लगा रखी हैं, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप माननीय सदस्य हैं, आपको छूट है, शिकायत करें, भेजें, निश्चित रूप से कार्रवाई न हो, तब कहियेगा। आपने सुझाव दिये हैं, निश्चित रूप से यह होना चाहिये। एक दुकान है तो एक दुकान ही होनी चाहिये, अलग-अलग दुकानें कहीं लगा देते हैं, उससे अशान्ति होती है। एक दुकान होती है, उससे चार-पांच सब-शाप लगा लें, उस चीज की निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। जो भी अभी कहा गया कि आबकारी में पहले नीलामी होती थी, पहले क्या होता था नीलामी में, बीस लोग, पचास लोग एक दुकान के लिए फार्म भरते थे, वह सब-लेट कर देता था दुकान। उसे दुकान चलानी थोड़ी न थी। किसी महिला वगैरह के नाम लेकर, दुकान के दस लाख-बीस लाख लेकर जो शराब के माफिया थे, उन्हें वह सब-लेट कर देता था। अब जिसे दुकान चलानी है, वही दुकान लेगा, उस गारंटी पर लेगा कि दुकान वही चलायेगा। इससे बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिला है।

जब वह प्रणाली थी पहले, हमने भी देखा है आपकी सरकार के समय, शायद हमारी सरकार के समय भी पिछली बार थी, निश्चित रूप से उस प्रणाली में दस लाख-बीस लाख, इसीलिए फार्म लगाते थे लोग, मेरे निकल जायेगी तो बीस लाख-दस लाख मिल जायेंगे। मुझे पूरी तरह पता है, गांव में यह धन्धा होता था। अब जिसे दुकान चलानी है, वही लेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने कहा, आबकारी नीति, जो भी सरकार आती है, आबकारी नीति बनाती है, कैबिनेट अप्रूवल होता है, ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कि आबकारी मिनिस्टर ने कह दिया और बन गया।

(श्री परसादी लाल)

माननीय मुख्य मंत्री जी तक जाता है, जो भी कुछ आपने कहा कि छूट वगैरह दे दी तो निश्चित रूप से कोविड में तीन महीने तक तो दुकानें बिलकुल बन्द रही थीं, उस कारण ठेकेदारों को जो नुकसान हुआ, उसकी छूट देना कोई ज्यादा वो नहीं है। तीन महीने बिलकुल दुकानें बन्द रही थीं, यह तो आपको भी पता है, लॉकडाउन रहा था। निश्चित रूप से जो भी आपके सुझाव आये, फिर भी हमने जो राजस्व अर्जित किया, आपसे कम शराब बेची, राजस्व ज्यादा लिया। टैक्सेशन के बाद दूसरी नम्बर की इनकम होती है, इसी से होती है। आपकी सरकार के समय भी होती थी। आपने भी चलाया। हमारी सरकार के समय में भी होती थी।

आपके समय 2014-15 में जो राजस्व था 5,557.77 करोड़ और शराब बेची थी 48.30 करोड़। हमने उससे ज्यादा इनकम करके अब 46.68 करोड़ बल्क लीटर, बीच में 57 करोड़ भी हो गया था आपके टाइम 2017-18 में, 58 भी हो गया था, 60 भी हो गया था और हमने 46.68 करोड़ बल्क लीटर बेचकर इनकम पहले से ज्यादा की। दुकानों की संख्या भी, कंट्रोल भी, समय भी जो हुआ, उसके कारण यह फर्क पड़ा है। निश्चित रूप से गुरुशरण छाबड़ा जी की याद में हमने अभियान चलाया कि शराब पीना ठीक नहीं है, शराब से बचना चाहिये, इस अभियान को हमने चलाया है। पिछली बार भी हमने पांच करोड़ इसमें रखे थे प्रचार-प्रसार के लिए। फिर इस बार मुख्य मंत्री जी ने दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया। निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं, शराब नहीं पीयें लोग, गरीब आदमी नहीं पीये, फिर भी अगर लोगों को शराब नहीं मिलेगी तो फिर आप जानते हैं कि अवैध पीते हैं, दूसरी पीते हैं।

सभापति महोदय, गुजरात में शराबबन्दी है, पर वहां भी शराब पीते हैं लोग, वहां भी शराब जाती ही है, इसलिए निश्चित रूप से आपने भी बन्द नहीं किया, हमने भी नहीं किया। सभापति महोदय, हालांकि, मैं तो इस पक्ष का हूं, इस मत का हूं कि पूर्णतया शराबबन्दी कर देनी चाहिये, पर सरकार की एक जॉइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है, सरकार का फैसला है, चाहे आपके समय हो, चाहे हमारे समय हो, निश्चित रूप से नशे से दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जो लोग पकड़े जाते हैं, उनके विकास के लिए पहले दस करोड़ का प्रावधान था, इस साल उसे बढ़ाकर हमने 50 करोड़ कर दिया तो निश्चित रूप से उन लोगों को जो शराब के आदी हैं, बच्चे हैं जो इससे पीड़ित होते हैं, उनको निश्चित रूप से राहत देने के लिए मुख्य मंत्री जी ने इस बार

(श्री परसादी लाल)

10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ का प्रावधान किया है। समय की पाबन्दी के लिए आपको कर दिया है और जिस भी माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो, अवैध दुकान की हो या समय की हो, वह लिखे तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे या मुझे लिखें व्यक्तिगत तौर पर। हम भी चाहते हैं कि जो समय निर्धारित कर दिया उसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए। उनका समय यही है और इसी शर्त पर उनको ठेके दिये हैं तो जो भी अभियोग दर्ज हुए हैं, मामले जो दर्ज हुए, आपके समय की भी हमारे पास लिस्ट है, हमारे समय की भी है। अवैध मामलों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से बहुत सारी गिरफ्तारियां आपके समय भी हुईं, हमारे समय भी हुईं इसलिए जो अभी आपने गंगागनर की बात कही, आबकारी नीति आपके समय भी चलती थी, हमारे समय भी चलती है, नयी कोई बात नहीं है। आबकारी नीति को बदलना या और कोई बात हो पर किसानों का जो आपने कहा, हमने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों का मूल्य पहले से बढ़ाया है और किसानों को राहत दी है। वे किसान मुख्य मंत्री जी से मिलने आये थे तब उसका पैसा बढ़ाया है। 16.13 परसेंट की वृद्धि की है जो 16 परसेंट की एक साथ गन्ने के भाव में बढ़ाना निश्चित रूप से ठीक है।

आपने जो भी मामले उठाये हैं उन पर निश्चित रूप से हम देखेंगे कि क्या हैं। शान्ति रहनी चाहिए, समय पर दुकान खुले। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों की शिकायतें हैं उनको हमने नोट किया है। चाहे आदिवासी इलाके का हो, कहीं का भी हो, गरीब आदमी हो, जब नजदीक दुकान होती है तो निश्चित रूप से उससे गरीब के घर में अशान्ति पैदा होती है, उस बात का भी हम ध्यान रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग की जो मांग संख्या 26 है उसमें सभी माननीय सदस्यों ने, सबसे ज्यादा 56 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। अपने इलाके की समस्या भी बतायी, जो डाक्टरों की कमी है वह भी बतायी, भवनों की कमी है वह भी बतायी, सरकार के जो अच्छे काम हैं, मुख्य मंत्री जी ने जो अच्छा बजट दिया, उसकी भी सराहना की। निश्चित रूप से आपके विचार चाहे पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों, अच्छा काम किया है तो आपने भी उसकी सराहना की तो बहुत बड़ा काम तीन साल में राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

(श्री परसादी लाल)

पहले गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए, जब कोई डिलीवरी कराने आता था, जयपुर इलाज कराने की सोचता था तो अपने जेवर बेचता था या वह जमीन गिरवी रखता था। जयपुर आने तक का किराया उसके पास नहीं होता था, जोधपुर जाने का किराया नहीं होता था, बीकानेर जाने का किराया नहीं होता था और गरीब इलाज कराने में सक्षम नहीं था। मुख्य मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में नि:शुल्क दवा योजना शुरू की और उसके बाद में नि:शुल्क जांच योजना शुरू की। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा काम था। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई कि ये दवाइयां फर्जी हैं, आपने उस समय आलोचना भी की पर फिर जब आपकी सरकार आ गयी तो आपने भी उसको चालू रखा। अगर फर्जी थी तो आपने चालू क्यों रखा? यह जनहित का काम था, चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, लोगों को फ्री में इलाज मिले, फ्री में दवाई मिले, फ्री में जांच हो। अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा काम कर दिया कि 5 लाख का चिरंजीवी योजना में बीमा दिया तो आदमी स्वत: ही आता है। अब उसको बढ़ाकर जो ट्रांसप्लांट वगैरह, किडनी, घुटने के आपरेशन इसमें कवर नहीं हो रहे थे तो उनको भी इसमें शामिल किया है। बड़े से बड़ा, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये इसको किया और यह बहुत बड़ा काम है, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा काम है जो निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी ने किया है। हम भी नहीं सोच रहे थे, हमारे मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों को भी पता नहीं कि मुख्य मंत्री जी एकदम 5 से 10 लाख रुपये कर देंगे। यह बहुत बड़ा काम है और प्रदेश की जनता इसको आज भी मानती है कि मुख्य मंत्री ने निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा काम कर दिया। इतना बड़ा काम कर दिया कि लोगों को चिन्ता ही नहीं है। साथ में यह और कर दिया कि पहले लोगों को जानकारी नहीं होती थी और वे चिरंजीवी का कार्ड नहीं बना पाते थे। अब कह दिया कि अगर कोई हास्पिटल में आ गया, उसका कार्ड भी नहीं है तो कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका इलाज करायेगा और कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका कार्ड भी बनवायेगा टाइम पर। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी राहत लोगों को, गरीब से गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी इसमें अपना इलाज कराने अगर हास्पिटल में आ गया तो उसको भी डाक्टर वापस नहीं भेजें। यह बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लोगों को, आप सबको, हमको सराहना करनी चाहिए कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम यह किया है।

(श्री परसादी लाल)

यह बहुत बड़ा काम उन्होंने निरोगी राजस्थान का भी शुरू किया। सरकार की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने 17 दिसम्बर, 2019 से निरोगी राजस्थान का शुभारम्भ किया। कितने सारे कैम्प लगाये, कितने लोगों को जोड़ा, हर पंचायत में कैम्प लगाकर जो भी लोग थे उनको जोड़ा। 8,680 स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर 30 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गयी और उनका नि:शुल्क इलाज किया गया। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा काम किया है। जब एक कैंसर वैन आयी थी, सुधीर भण्डारी जी वहां लेकर आये थे, मित्तल जी आये थे वहां सी.एम. आवास पर, कैंसर वैन को स्टार्ट करने की बात थी। मित्तल जी उद्योगपति हैं। हमने कहा था कि मुख्य मंत्री जी, हर जिले में कैंसर वाहन होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, बीमारी का पता ही नहीं चलता और जब लास्ट स्टेज में पता चलता है तब उसका इलाज सम्भव नहीं है। अब देखिये मुख्य मंत्री जी ने हमारी बात को, मैंने स्वयं ने ही कहा था, जब तो मुझे यह मंत्री बनाया ही था, कि हर जिले में होनी चाहिए तो उन्होंने कह दिया कि हर जिले में कैंसर वाहन होगा। बहुत बड़ी बात है, हर जिले में रोज जांच करेंगे। कोई भी आदमी उसमें जांच करायेगा, गांव-गांव में वह गाड़ी जायेगी तो निश्चित रूप से लोगों को पता चलेगा कि मुझे क्या बीमारी है, मुझे बीमारी है भी या नहीं है, तो यह बहुत बड़ा काम मुख्य मंत्री जी ने किया है। निरोगी राजस्थान में भी जिस तरह का काम किया, नि:शुल्क दवाइयां वगैरह कीं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम था।

स्वास्थ्य का अधिकार के सम्बन्ध में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया। निश्चित रूप से मानिये, राइट टू हैल्थ मिलेगा और मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत लाकर रहेंगे, बहुत जल्दी ही इसकी तैयारी कर दी और निश्चित रूप से सरकार ने इसकी ओर जो कदम बढ़ाया है उसको हम पूरा करेंगे। इस प्रकार बहुत बड़ा काम हैल्थ में हुआ है।

हमारी चिरंजीवी योजना का तो मैंने आपको बता ही दिया कि निश्चित रूप से बहुत बड़े पैकेज की बढ़ोतरी हुई है। बड़ेबड़े आपरेशन थे, उनका भी निश्चित रूप से फ्री में इलाज होगा, घुटने का, ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं।

कोविड 19 जब आया, पहली लहर जब आयी तो अफरा-तफरी पूरे देश में मच गयी थी, पूरे देश में हाहाकार मच गया था और पहली बार हमारे यहां

(श्री परसादी लाल)

लॉकडाउन हुआ। कोई इटली के दो आये थे, उनको कोविड हुआ। हमारे पास जांच के कोई संसाधन नहीं थे। हमने पुणे में या दिल्ली में जांच भेजी। जब हमारे यहां पेशेंट बढ़े तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा क्योंकि रिपोर्ट पुणे से 5-7 दिन में आती थी, दिल्ली से भी इतने ही टाइम में आती थी, सभापति महोदय, आज हमारे हर जिले में इस जांच की सुविधा उपलब्ध करायी है। यह आरटी पीसीआर यहां होता है, सैम्पल वायरोलॉजी के भेजे जाते हैं। निश्चित रूप से आरटी पीसीआर फ्री किया है हमने सबका। एक लाख 45 हजार जांच पर-डे करने का हमने प्रावधान कर दिया। जहां पर एक जांच नहीं थी, वहां पर एक लाख 45 हजार जांच पर-डे होती है और सेम-डे 24 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है, तभी तो हमको पता चलता है कि आज इतने पेशेंट हैं, कल इतने पेशेंट थे।

निश्चित रूप से जो दूसरी हमारी लहर आयी तो दूसरी लहर में हमारे सामने सबसे बड़ा संकट आया, भारत सरकार के सामने भी आया कि ऑक्सीजन के बिना आदमी जिन्दा ही नहीं रह सकता। ऑक्सीजन नहीं होगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी की डैथ हो जाती है और बहुत जगह घटनाएं हुई पर हमारे सौभाग्य से हमारे प्रदेश में नहीं हुईं। एमपी. में 40 लोग मरे थे, दूसरी लहर में गुजरात में मरे थे पर हमारे यहां एक भी डैथ ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई। 40 हजार कंसंट्रेटर हमने जो भी भाव मिले उसमें खरीदे और देखा नहीं कि चाहे कितना ही महंगा हो, हमने 40 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे। अभी अनिता जी कह रही थीं कि गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, उसकी तो हम जांच करा देंगे, पर अनिता जी, उस समय कोई चीज देखने लायक नहीं थी और जो भी भाव मिले वह चीजें खरीदें। यू.पी. के लोग भी हमारे यहां इलाज कराने आये, उनका भी फ्री में इलाज किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी मारामारी हुई, नेता, प्रतिपक्ष महोदय हमें खुद फोन करते थे कि इनको इंजेक्शन चाहिए, ये मेरी कांस्टीट्यूएंसी का है, सब फोन करते थे जन-प्रतिनिधि चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे मिनिस्टर हो, पर उस समय ऐसी मारामारी थी कि इंजेक्शन मिलना ही जीवनदान था। मुख्य मंत्री जी ने कितनी संवेदनशीलता दिखायी। अपना स्पेशल प्लेन भेजकर भी गुजरात से, अहमदाबाद से, मुम्बई से उन्होंने इंजेक्शन मंगवाये। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, वह संकट का समय था। आपसे सबसे संवाद किया, सबसे बराबर सम्पर्क में रहे, उन्होंने 21 घन्टे तक वीसी की, इस बीमारी से कैसे फ्री हों। बहुत बड़ा इंजेक्शन, जो 40 हजार की कीमत का था। कालीचरण जी को

(श्री परसादी लाल)

तो पता है, इनको तो लगा है, 40 हजार का इंजेक्शन गरीब से गरीब आदमी को फ्री लगाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन का पैसा किसी से भी नहीं लिया, इतना सारा पैसा खर्च किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकट के समय में जो काम किया, दोनों पति-पत्नी के लगे हैं, एक के नहीं दोनों के लगवाये हैं। इसलिए, संकट का समय था, जीवन बचाना सरकार का काम था। मुख्य मंत्री जी ने कह दिया चाहे मेरे सारे विकास के काम बन्द करने पड़ें पर मैं किसी के जीवन को खतरे में नहीं डालूंगा। कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, उसके लिए सरकार तैयार है, सारी विकास योजनाएं बन्द कर देंगे।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आपको तो पता है, जब वैक्सीनेशन का मामला आया, भारत सरकार ने कह दिया हम वैक्सीन फ्री नहीं देंगे। सारे देश के मुख्य मंत्रियों ने कहा, हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि आप वैक्सीन फ्री कीजिये, पूरे देश का काम है। मुख्य मंत्री जी ने सब विधायकों के 100 करोड़ रुपये रोके कि मैं वैक्सीनेशन के लिए तीन हजार करोड़ का इंतजाम करूंगा। वह किया, आपने, हमने सबने सहमति दी कि हमारा विधायक कोष रोक लें, पक्ष विपक्ष सबने कहा, सबने मिलकर कहा। प्रधान मंत्री जी ने बाद में हमारे मुख्य मंत्री जी की सलाह से पूरे देश में वैक्सीनेशन को फ्री किया। उसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, हमारा तीन हजार करोड़ बचा। उसके लिए प्रधान मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे सी.एम. साहब के कहने पर और किसी सी.एम. की हिम्मत नहीं हुई, पूरे देश में किसी मुख्य मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि प्रधान मंत्री जी को कह दें कि आप फ्री दीजिये, पर अशोक जी गहलोत मोदी जी से सीनियर थे मुख्य मंत्री में। निश्चित रूप से, इसके लिए भारत सरकार को प्रदेश की जनता और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू हुआ। हमने दिसम्बर तक 98 प्रतिशत फर्स्ट डोज लगा दी। हमने 84 प्रतिशत सैकण्ड डोज लगा दी। आज उसी कारण हमारे प्रदेश के लोग सुरक्षित रहे। ओमिक्रॉन-ओमिक्रॉन का बहुत-बहुत हल्ला मचा और उस हल्ले से भी लोग घबरा गये, पर जो हमारा दिसम्बर में वैक्सीनेशन हुआ और जनवरी में रिकार्ड डेढ-डेढ़ करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इतना बड़ा काम हुआ, उसके कारण ही हमारे यहां बहुत कम लोग हास्पिटलाइज्ड हुए बहुत कम लोगों की डैथ हुई सब लोग ठीक हो गये, अस्पताल आने की जरूरत ही नहीं।

(श्री परसादी लाल)

निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा काम हमारे चिकित्साकर्मियों ने, हमारे डाक्टर्स ने, हमारे कलेक्टर्स ने, कई जिलों में फर्स्ट और सैकण्ड डोज 100 प्रतिशत हो गयी, 20 जिलों में तो 100 परसेंट हो गया। हमारे सारे चिकित्साकर्मी थे, स्वास्थ्यकर्मी थे, जो भी हमारे कलेक्टर्स थे, पटवारी थे, सीएचओ थे, सीएचए थे। सबने मिलकर इस काम को बहुत बखूबी किया, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है।

दूसरी बात, जो मैं आपको कहना चाह रहा था। अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बच्चों का वैक्सीनेशन कम हुआ है। यह बात सही है, वैक्सीनेशन 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का शुरू किया। भारत सरकार ने दिया और हमने उसको 100 प्रतिशत किया। बच्चे उपलब्ध नहीं थे, स्कूलें बन्द थीं, अब उनका वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं। आपको हमको सबको बच्चों की चिन्ता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने तो यह भी कहा कि आप 12 से 18 करें, 9 से 18 करें, सब बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। जब दूसरे देशों में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों का हो गया। भारत सरकार को आप और हम सब कहेंगे, इस बीमारी का कुछ पता नहीं कब आ जाय, पर तीसरी लहर का हमने जो मुकाबला किया, वह वैक्सीनेशन से किया। हमारे यहां कैजुअल्टी कम हुई हमारे यहां हास्पिटलाइज्ड कम हुए। निश्चित रूप से हमको न ज्यादा लॉकडाउन लगाना पड़ा, न ज्यादा कर्फ्यू लगाना पड़ा। निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय हमने सब-सेन्टर, पीएचसी, सीएचसी खूब खोले। बीजेपी सरकार में 5 साल में केवल 7 सब-सेन्टर खुले थे। हमारे टाइम में 220 खुले हैं और इस साल एक हजार और खोलेंगे। आपने पीएचसी 5 साल में 46 खोली थीं, हमने 194 खोल दी हैं और 100 पीएचसी, सीएचसी का और प्रस्ताव है। आपके समय में केवल सीएचसी 22, हमने 136 खोली हैं। आपने शय्याओं में वृद्धि 785 की थी, हमने 5 हजार बढ़ाये हैं। निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली।

हमने एसएमएस, आरयूएचएस, जिन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, नेता महोदय, आप सबको जानकारी है कि हमने आरयूएचएस में दूसरी लहर

(श्री परसादी लाल)

में 500 बैड को बढ़ाकर 1300 बैड किया। कितना अच्छा काम किया हमारे डाक्टर्स ने, हमने मिलकर, तो लोगों को राहत मिली। ऑक्सीजन के लिए जो हाहाकार मचा, भारत सरकार ने हमको ऑक्सीजन कहां से अलाट किया? ओडिशा से किया। गुजरात को कहां से किया? दिल्ली से किया। ऑक्सीजन के लिए नेता प्रतिपक्ष से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात की, लेकिन हमारे यहां कमी नहीं आने दी, इतना हाहाकार था, ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं। इस तरह का दृश्य कभी देखा नहीं, पहली बार प्रदेश में इस तरह का दृश्य था। उसका भी आपने हमने सबने सहयोग करके अच्छे से मुकाबला किया। लोगों को फ्री इलाज दिया, किसी भी पेशेंट का एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ।

हमारे जो कोविड वारियर्स थे, उनकी भी इसमें डैथ हुई। उनको भी 50 लाख का अच्छा पैकेज दिया। जो भी डैथ हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि जो भी डाक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, एएनएम हैं, जीएनएम हैं, क्योंकि वे तो दिन भर उनकी सेवा करने में, 50 लाख का पैकेज हमने डेढ़ सौ लोगों को दिया। निश्चित रूप से उनके बच्चों के लिए मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया।

भर्तियों की स्थिति देख लें। हमने 2020 में 737 डाक्टर भर्ती किये। उसके बाद 2,000 डाक्टर और भर्ती किये। सहायक रेडियोग्राफर के जो 1,058 पद थे, उनमें से 692 की भर्ती की। लैब टेक्नीशियन 877 पदों पर भर्ती की। प्रयोगशाला सहायक भर्ती किये। ईसीजी टेक्नीशियन हमने भर्ती किये, पर वे कम मिले। ईसीजी टेक्नीशियन हमारे यहां नहीं है। हम और भी भर्ती करना चाहते हैं। अभी कोई कह रहे थे कि जोधपुर में नहीं है, लालसोट में नहीं है, वहां नहीं है। वास्तव में, ईसीजी टेक्नीशियन की कमी हैं, मिलेंगे तो हम इसमें और भर्ती करेंगे। हम चाहते हैं कि ईसीजी टेक्नीशियन हर हास्पिटल में हो। यह सुविधा हम निश्चित रूप से करेंगे।

महिला स्वास्थ्यकर्ता नर्स ग्रेड-द्वितीय के हमने 6,700 पद निकाले हैं, 6,712 भर्ती किये हैं। कोविड में भर्ती जरूरी थी, हमने जो भी लोग आये, सबको भर्ती किया। हमने 7,800 सीएचओ भर्ती किये हैं। कोविड के समय गांवों में किस तरह वैक्सीनेशन हो, किस तरह से लोगों को जानकारी हो। हमने 25,000 सीएचए भर्ती किये हैं। निश्चित रूप से कोविड का मुकाबला करने में आप सबके सहयोग से, माननीय सदस्यों ने जो सहयोग दिया, उसका भी बहुत बड़ा रोल है।

(श्री परसादी लाल)

नि:शुल्क जांच योजना में, मुख्य मंत्री जी ने बजट में ऐलान किया है कि मेडिकल कालेज, चिकित्सालयों में 90, जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 56, सीएचसी में 37, पीएचसी पर 15 प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं। इसको बढ़ाने का भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं।

कैंसर की बात आपने बतायी। कैंसर के लिए जो भी प्रावधान हैं, अभी जांच के लिए पैसा लगता है, पर अब 10 लाख का पैकेज हो गया है तो अब किसी भी जांच का और कैंसर की जांच का भी पैसा नहीं लगेगा। अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि 5 हजार, 6 हजार लगते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कैंसर की जांच का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सब जिलों में कैंसर वैन हो जायेगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है।

मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें भी राष्ट्रीय औसत जहां 88.6 है, हमारा 94.9 है। उससे भी हम बैटर हैं। हमने बच्चों के लिए चिरंजीवी एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की। अभी कह रहे थे, 108 एम्बुलेंस खराब है। आपकी सरकार के समय में जो गाड़ियां चलीं, जो गाड़ियां खराब हैं, हम उनकी जांच कराकर सबको बदल देंगे। निश्चित रूप से जो माननीय सदस्यों ने एम्बुलेंस दी है।

(समय: 22.00 बजे)

उस पर हम विचार कर रहे हैं कि ड्राइवर की, डीजल की कैसे व्यवस्था हो, वो सुचारु रूप से कैसे चले। हमने भी दी आपने भी दी होगी कोविड में, निश्चित रूप से उसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे जो गाड़ियां खराब हो गयीं उनको हटाकर 108 से या दूसरी एजेंसी से बात करके, सरकार 108 को पैसा दे रही है, हमारी गाड़ियां खुद की हैं उनको देने में हमको क्या तकलीफ है उनको भी यथासम्भव निश्चित रूप से माननीय सदस्यों ने जो एंबुलेंस दी है वह भी बराबर चलती रहे। जननी सुरक्षा भारत सरकार ने भी हमको दी है उन्होंने भी जननी सुरक्षा एक्सप्रेस हमको दी इसमें बच्चों के बारे में बहुत हल्ला मचा था कोटा में और यहां। अब बहुत अच्छा अस्पताल बना दिया। मैं यहां गया था जेके लोन में एक दिन तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि क्या कायाकल्प हो गया जेके लोन हो, क्या कायाकल्प हो गया आपके एसएमएस का। बहुत अच्छा काम इस कोविड में किया है। आप देखेंगे कि वहां पर जिस तरह के हमारे आईसीयू बैड वेंटिलेटर वगैरह जिस तरह के बनाये हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस कोविड के समय ऐसा काम हो जायेगा तो निश्चित रूप से अच्छा काम यहां पर हुआ है।

(श्री परसादी लाल)

सभापति महादेय, कल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य उप नेता महोदय ने सवाल उठाया था कि खाद्य सुरक्षा में मिलावट, निश्चित रूप से आप भरोसा रखिये मुख्य मंत्री जी पर, हमारे मुख्य मंत्री जी जो कहेंगे, वह करेंगे, सौ प्रतिशत होगा। यह मानकर चलिए आप। इसमें जो भी है अभियान 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च तक संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 5 मार्च तक 4,594 नमूने लिए गये हैं उनमें से 1,175 नमूने अमानक पाये गये। आपने पिछले 2 साल का पूछा था, निश्चित ही अमानक पाये गये हैं। इन पर विधिवत जो कार्यवाही है, वह कार्यवाही करेंगे। हमारी प्रयोगशालाएं, वगैरह सब जिलों में, आपके समय तो थी ही नहीं प्रयोगशालाएं, आपने तो कभी अभियान चलाया ही नहीं। आप खुद हैल्थ मिनिस्टर थे। कालीचरण जी खुद हैल्थ मिनिस्टर थे पर हमारी ओर से लोगों को शुद्ध खाना मिले, शुद्ध मसाले मिलें। सही कह रहे थे आप कि यह पानी जो आ रहा है, रोज एक कैंसर ट्रेन, ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया बीकानेर आती है रोज पंजाब से। यह पानी हमको भी प्रभावित कर रहा है। सही बात है पानी से, खाने से, पीने से, सब्जियों से, मसाले से, जो हमको अशुद्ध मिल रहे हैं न, उसी से कैंसर हो रहा है। ज्यादातर उसी से हो रहा है। बीकानेर आती है ट्रेन, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर हो गया। पंजाब से आती है सीधी सारे पेशेंट बीकानेर आते हैं यहां इलाज कराते हैं। पानी के मामले में निश्चित रूप से जो यह गंग नगर का पानी आ रहा है यह अशुद्ध पानी है। सब्जियां होती हैं। आप सही कह रहे हैं चौमूं में गन्दे पानी से होती हैं। सही बात है हम अशुद्ध खाना खा रहे हैं, मसालों का कोई पता नहीं है तो निश्चित रूप से यह अभियान चलने के बाद एक तरह से लोगों को शुद्ध मसाले मिले, शुद्ध खाना मिले और 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद हमने स्वीकृत किये थे। आप तो 50 छोड़कर गये थे। क्या होता है 50 से? अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद और स्वीकृत कर दिये। उनकी बहुत जल्दी भर्ती करके निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि कम से कम हर ब्लाक में हर विधान सभा क्षेत्र में हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा। हर उपखण्ड पर हमारा होगा तो निश्चित रूप से एक चैक एंड बेलेंस रहेगा, भय रहेगा मिलावटखोरों के कि निश्चित रूप से यहां अधिकारी कार्यवाही कर सकते हैं, छापा डाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है। आज तेल देख लो, मसाले देख लो, सारे मिलावटी आते हैं,

(श्री परसादी लाल)

हम सब जानते हैं तो यह बहुत बड़ा काम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का हर समय चलेगा। यह 1 जनवरी से शुरू हो गया, हर समय चलेगा, कभी भी नमूने ले सकते हैं। हमने पचास डाक्टर्स को जब तक हमारी पोस्टें नहीं भरें तब तक स्पेशल जिम्मेदारी दी है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है।

सभापति महोदय, एक बेटी बचाओ कार्यक्रम में पीसीपीएनडीटी की कोई बैठक ही नहीं हुई। इसकी बैठक हमने ली है। हमने कह दिया कि जांच ही नहीं हुई, कभी जाते ही नहीं सोनोग्राफी सेन्टर्स पर, सब मिले हुए रहते हैं। पता नहीं, हमने कहा है कि साल में एक बार हर सोनोग्राफी सेन्टर की जांच होगी। अगर नहीं करेगा तो वह अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनकी ड्यूटी है। अब इसके बाद 482 सोनोग्राफी सेन्टर्स का पंजीकरण निरस्त किया। अगर ये सोनोग्राफी सेन्टर्स अवैध काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी तो हमने प्रकरण भी दर्ज किए हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करेंगे।

सभापति महोदय, औषधि नियंत्रण संगठन भी एक बहुत बड़ा झमेला है जो दुकानदार हैं वो सब परेशान हैं। हमने कह दिया, दुकानदारों को भी कह दिया कि आज से कोई पैसा मांगे, सही काम करो, सही दवा रखो, अगर कोई इंस्पेक्टर आकर पैसा मांगे तो आप सीधा फोन मेरे को करो, हमारे सेक्रेट्री को करो। यह अभी एपिसोड हुआ जो उसने कहा कि पैसा ऊपर तक जाता है, कहां तक जाता है यह तो राठौड़ साहब को पता। मैं तो अभी आया हूं दो-तीन महीने से। कालीचरण जी सराफ को पता कहां तक जाता है, मैं तो अभी दो महीने से ही आया हूं। हमने उसके ऊपर का जो अधिकारी था उसको तुरन्त एपीओ कर दिया और ये दुकानों का जो बेलेंस कर रखा है किसी को हजार, किसी को पांच सौ, किसी को पचास, हमने हमारे विभाग को कह दिया कि सबको बराबर करो। ट्रांसफर किसी के दस साल से नहीं हो रहे हैं, बारह साल से नहीं हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बहस करा लो एक दिन। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल तैयार हैं। स्वागत है आपका। अध्यक्ष जी जब इजाजत देंगे तभी हम तैयार हैं बहस करने को।

श्री सभापति: अभी तो आप मांग पास कराओ। बहस की बात बाद में करेंगे।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसलिए हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी किसी भी बहस से डरने वाले नहीं हैं और चाहे जब कराओ आप। एक जनता क्लीनिक की बात आयी, जनता क्लीनिक कहीं खुल नहीं रही है। मालवीय नगर के पास वाल्मीकि कालोनी में प्रदेश के पहली जनता क्लीनिक का शुभारम्भ किया। आपके ही क्षेत्र में किया है। चल रहा है वह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बगरू में है यह। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मालवीय नगर में है। नाम मालवीय नगर का आ रहा है श्रीमान्, इसलिए मैंने देखा कि उनके ही इलाके में चल रहा है। इस समय जयपुर शहर में 12, जालौर में एक, कुल 13 जनता क्लीनिक संचालित हैं और निश्चित रूप से इसमें जो प्रावधान था भारत सरकार का सहयोग भी इसमें था, तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई हम रास्ता निकालेंगे। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना, कोई भी एक्सीडेंट हो जाये उसको कोई सम्भालता ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने अब कह दिया है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको लेकर आयेगा तो पांच हजार रुपये का इनाम देंगे, प्रशस्ति पत्र और देंगे जिससे, बहुत सारे लोगों ने यह काम किया है उनकी सूची हमारे पास है, कितनों को दिया है।

चिकित्सा संस्थानों में भवन निर्माण के लिए भी 1,408 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। इस दौरान 585 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 275 पीएचसी, 70 सीएचसी, 2 एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर, झुंझुनू में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र को 50 से 100 शय्याओं की वृद्धि का कार्य, झालरापाटन, झालावाड़ में सेटेलाइट अस्पताल, करौली जिला चिकित्सालय आईपीडी टावर के ब्लाक बनेंगे, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा काम है।

एक जो चिकित्सा शिक्षा में आपने कहा, यह सही बात है यूपीए गवर्नमेंट के समय मेडिकल कालेज खोलने की सहभागिता योजना स्टेट और सेन्टर की योजना शुरू हुई थी। आप हैल्थ मिनिस्टर थे। आपके चूरू में भी खुला था। हम तो भारत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि यूपीए सरकार की योजना को भी आपने चालू रखा और उससे सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को हुआ। देश में सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा मेडिकल कालेज राजस्थान को मिले। हमने समय पर उनकी जमीन का, जो भी उनकी शर्तें थी उनको पूरा करके आज हमारे 30 मेडिकल कालेज यहां पर हो जायेंगे। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य, जालौर, राजसमन्द और प्रतापगढ़ तीन जिलों

(श्री परसादी लाल)

के लिए मुख्य मंत्री जी ने परसों भी माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को वीसी के द्वारा कहा है कि आप हमारे पड़ोस के हो, जालौर में और राजस्थान में फर्क नहीं है, इन तीनों जिलों को आप और कर दो तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें खर्चा उठाने को तैयार है। भारत सरकार का साठ प्रतिशत है हमारा चालीस प्रतिशत है पर सारी जिम्मेदारियां चलाने की, बनाने की और सब सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है तो निश्चित रूप से यह पालिसी 2014 में यूपीए के समय थी, आपको तो पता है उस समय से ही चली आ रही है, इसको जो इन्होंने चालू रखा उसके लिए भारत सरकार को मुख्य मंत्री जी ने धन्यवाद दिया है। आप और हम सब ही दे रहे हैं कि हमारे तीस मेडिकल कालेज हो जायेंगे और मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हर जिले में नर्सिंग कालेज बिना भेदभाव के जिनमें भर्ती शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोग जो बाहर नर्सिंग करने जाते हैं कोई एमपी जाता था, कोई यूपी जाता था कोई साउथ में जाता था अब राजस्थान के लोगों को ही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब निश्चित तौर पर मांग पारित करा दो आप।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसी साल शुरू कर देंगे, हमारी कोशिश है नेता महोदय, कि नर्सिंग कालेज हमारे हर जिले में चालू हो तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को कम किराये में, अभी हुआ न हमारे यूक्रेन में गये, दूसरी जगह गये, कितनी आफत आई, कोई थर्ड ईयर में था, कोई फोर्थ ईयर में थे, कोई कौनसे ईयर में था, सारी पढ़ाई अधूरी रह गयी। प्रधान मंत्री जी ने हमारे मुख्य मंत्री जी से कहा हमको इनकी व्यवस्था करनी चाहिये और होनी चाहिये। किसी का तीन साल का खर्चा लगे, क्यों जाते हैं वहां, क्योंकि हमारे यहां प्राइवेट कालेजों में मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई महंगी है। सरकारी कालेज में नहीं हो पाता है तो वह बाहर जाकर अपनी एमबीबीएस करते हैं। मैंने एक दिन पढ़ा था, भारत सरकार ने भी यह तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कालेज में भी जो 50 परसेंट सीटें हैं, उनकी रेट को भी हम करेंगे। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए है।

राजकीय मेडिकल कालेजों में पिछले तीन वर्षों में 1,080 एमबीबीएस सीटों की बढ़ोतरी हुई है जो वर्ष 2018 की तुलना में 58 परसेंट अधिक है। इसी प्रकार पिछले तीन वर्षों में 519 पीजी सीटों की वृद्धि हुई है जो 2018 की तुलना में 50 परसेंट अधिक है। निश्चित रूप से मेडिकल कालेज खोलेंगे।

(श्री परसादी लाल)

हमारे बच्चे, हमारे इलाके के लोग यहीं पर अच्छी शिक्षा लेंगे। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर मेडिकल कालेजों में इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर सुपर स्पेशियलिटी को प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। (व्यवधान) हो गया क्या बस? मैं भी तो सुबह से बैठा हूं, नहीं बैठा क्या?

श्रीगंगानगर, चित्तौड़, धौलपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा, अलवर, नागौर, यह 8 मेडिकल कालेज हम शुरू करेंगे। हमने भारत सरकार को लिखा है कि इन मेडिकल कालेजों को शुरू किया जाय।

अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एसएमएस में बहुत कमी हो गई। आपको जानकर खुशी होगी 500 बैड के आईपीडी टावर की स्थापना होगी। आईपीडी टावर देश में अनोखा होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टेंडर कर लिए हैं, वर्क आर्डर दे दिया है। यह 24 मंजिल का होगा, 1200 काटेज वार्ड होंगे इसमें, 10 आपरेशन थियेटर होंगे और मान लो किसी को अचानक दिल्ली ले जाना हो, मुम्बई ले जाना हो, इसके लिए ऊपर हेलीपैड भी होगा, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप एसएमएस की चिंता कर रहे हैं, एसएमएस की चिंता माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत पहले से ही है। 450 करोड़ इसकी कास्ट है। हेलीपैड पर एयर एंबुलेंस आयेगी, वहीं से वह आपको लेकर जायेगी। (व्यवधान) मैं कालीचरण जी को कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। माननीय नेता महोदय, यह आईपीडी टावर राज्य में सबसे ऊंची इमारत होगी। यह बहुत बड़ा काम है।

आपने एक बात कही थी कि इन नर्सिंग कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने के लिए। इसमें आरपीएससी की रिपोर्ट वगैरह सब आ चुकी है और हमने उसको कैबिनेट को भेज दिया है। हमारा नर्सिंग स्टाफ बार-बार मांग करता है, पंचायत में वीडीओ को कर दिया तो इनके लिए भी हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को कैबिनेट में फाइल मूव कर दी, बहुत जल्दी इनका भी हो जायेगा। (व्यवधान) मैं भी तो दिन भर बैठा हूं, आप भी थोड़ी देर बैठो, क्या दिक्कत है?

कोविड के मामले में आपने पूछा था कि कुल कितने प्रकरण थे। अब तक प्राप्त 17,657, अब तक भुगतान किये गये परिवारों की संख्या 11,558 है। भुगतान योग्य प्रकरण 1,388, रिजेक्टेड 675, पेंडिंग 4,036। इनके लिए

(श्री परसादी लाल)

भी सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट को कहा है कि वह जल्दी भुगतान कर दे। प्रधान मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत सरकार ने भी इसमें मदद की है। 50 हजार का पैकेज उन्होंने दिया है। मुख्य मंत्री जी ने एक लाख का पैकेज दिया है। 18 वर्ष के होने तक उनके बच्चों को पेंशन। भारत सरकार के पैकेज में 75 परसेंट भारत सरकार का, 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का है।

एक बहुत बड़ी बात के लिए हम सब चिंतित हैं कि बहुत सारे डाक्टर, एएनएम डेपुटेशन पर लग जाते हैं और बहुत सारे हास्पिटल खाली रहते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे हास्पिटल खाली हैं जहां डाक्टर नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां डाक्टर सरप्लस हैं। जैसे जयपुर में 300 डाक्टर सरप्लस, अजमेर में 100 डाक्टर सरप्लस, कहीं इतने सरप्लस। हमने तय किया है डेपुटेशन तो हमने समाप्त कर दिया। विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य एक दिन मेरे पास आये कि मेरे 5 डाक्टर विराटनगर से सीएमएचओ फर्स्ट ने लगा रखे हैं। हमने सीएमएचओ फर्स्ट से जानकारी ली, 5 नहीं 70 डाक्टर बैठे हैं। हमने तुरंत उसी रात को उनको रिलीव कराया। अब सरकार ने तय किया है कोई सीएमएचओ, कोई ब्लाक सीएमएचओ, संभागीय अधिकारी सरकार की बिना जानकारी के किसी भी मेडिकल आफिसर का, एएनएम, जीएनएम का अगर अपनी मर्जी से डेपुटेशन करेगा तो उसको 16 सीसीए की चार्जशीट दी जायेगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना है। कटारिया जी कह रहे थे कि हम नहीं कर सके, हम करेंगे। हम तो फकीर हैं, हमारे मीणों के क्या है, हमें किसी की परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि जो डाक्टर जाये वह वहां काम करे। जहां से वेतन ले रहा है, वहां काम करे। जहां ड्यूटी है, वहां पर काम करे। हमारे 2,000 तो एएनएम सरप्लस हैं और हमारे 1,700 सब सेंटरों पर ताले लगे हुए हैं। हम सबको भेजेंगे, हम सब सेंटरों पर सब डाक्टर्स को भेजेंगे।

मैं इस पद पर रहूं या नहीं रहूं, मेरे को इसकी चिंता नहीं है पर माननीय सदस्यों की जो डाक्टर्स की चिंता है, मैंने ऐसी सीएचसी भी देखी है जहां एक भी डाक्टर नहीं है। 6 सीएचसी ऐसी हैं जहां एक भी डाक्टर नहीं है। 200 पीएचसी ऐसी हैं जहां एक भी डाक्टर नहीं है और हमारे यहां सरप्लस बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है यहां। 1,700 सेंटर ऐसे हैं, जबकि हमारी सरकार आने के बाद हमने एएनएम की बहुत भर्ती कर ली। कोई एनएचएम में लगी हुई हैं, अभी 12-13 हजार हमने भर्ती कर लिए, पहले की हैं, फिर भी पता नहीं कहां है। इनका पूरा समानीकरण करके निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि

(श्री परसादी लाल)

हर सेंटर पर हो। पीएचसी पर जब 50 तरह की दवाइयां वहां रहेंगी, निश्चित रूप से इस काम की माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत जल्दी आज्ञा लेकर इसको करेंगे। निश्चित रूप से हम वहां पर डाक्टरों की पोस्टिंग करेंगे। बहुत दयनीय स्थिति है। हम न किसी का डेपुटेशन करेंगे, हम आपसे भी विनती करते हैं कि इन चीजों में आप दबाव मत डालना। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करते हैं। आपके 6 डाक्टर हैं, 6 लगवा लो लेकिन 7वें की बात मत करो। 7वां वहीं जायेगा जहां वेतन ले रहा है। वेतन कहां से ले रहे हैं, काम कहां कर रहे हैं, यह कहां का तरीका है? जहां काम करे, वहीं वेतन लो। हमने सबका वेतन भी रोक दिया, किसी को वेतन नहीं मिलेगा जब तक वहां नहीं जायेगा। उस दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता जाहिर की थी, हम सबकी चिंता है। मैंने सूची देखी है, यह सूची है पूरी। देखने लायक सूची नहीं है, ऐसी सूची है यह। हम इससे चिंतित हैं। मैंने पहले ही दिन यह तय कर लिया था कि चाहे मैं इस पद पर रहूं या ना रहूं पर यह डेपुटेशन वगैरह का सिस्टम बन्द करेंगे। यह पूरी सूची है।

कुछ घोषणाएं हैं, मेडिकल कालेज जोधपुर, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं दौसा में 71.25 करोड़ की लागत से 50 बैड वाले आपातकालीन चिकित्सा इकाई का निर्माण किया जायेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3.75 करोड़ की लागत से एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का निर्माण किया जायेगा।

राज्य में 556 करोड़ रुपये की लागत से 1,112 भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। प्रदेश में बहरापन नियन्त्रण रोकथान की नीति बनाने की घोषणा करता हूं। ये नीति आगामी वित्त वर्ष से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। बाल्यकाल की प्रारम्भिक अवस्था में ही hearing screening (OEAs) auto Otoacoustic Emissions द्वारा की जायेगी एवं बाल्यकाल में बहरापन का सही समय पर इलाज हो जायेगा। कम्युनिटी हैल्थ आफिसर के 3,631 संविदा पदों, प्रबन्धकीय वर्ग में 666 पदों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 4,693 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती को जल्दी ही पूरा कर देंगे। फार्मासिस्ट के 1,799 पदों, नर्स ग्रेड द्वितीय के 1,250 पदों, हास्पिटल केयर के 55 पदों एवं acupressure therapist के 24 पदों पर भर्ती के लिए हमने आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी है। बहुत जल्दी ही हम इनकी भी भर्ती कर देंगे। चिकित्सा विभाग में सीओ के 751 पदों पर भर्ती भी हम बहुत जल्दी ही कर देंगे।

(श्री परसादी लाल)

माननीय सभापति महोदय, हमने आज ही, बहुत समय से, 2018 से एक मामला यहां पर पैंडिंग था प्रयोगशाला सहायकों का। प्रयोगशाला सहायकों का 2018 से एक बहुत बड़ा विवाद था। उसका भी हमने आज समाधान कर दिया है और उसकी भी सूची जारी कर दी है। माननीय न्यायालय के अधीन जो पद रहे हैं, कुछ पद उनके पैंडिंग रह गये हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद हमने 965 लोगों के लिए नियुक्ति का रास्ता खोल दिया है। बहुत जल्दी ही उनको नियुक्ति दे देंगे। प्रयोगशाला सहायकों का मामला बहुत समय से था। हमने जो भी मामले हैं, एनएचएम के बहुत सारे आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। उसमें कोई दस साल से लगा हुआ है और कोई आठ साल से लगा हुआ है। 60 परसेंट पैसा भारत सरकार का है और 40 परसेंट हमारा है। वे बढ़ाने के लिए कहते हैं। यदि भारत सरकार बढ़ाये तो हम भी तैयार हैं, पर उनको परमानेंट भर्तियों में बोनस अंक 10, 20, 30 मिलते हैं। हमने उनको कहा कि जब तक भारत सरकार नहीं बढ़ायेगी तब तक स्टेट गवर्नमेंट उसमें पैसे नहीं बढ़ा सकती। आप नर्सिंग की भर्ती कर रहे हैं। अभी भर्ती हुई है, निश्चित रूप से आप उसमें एप्लाई करें और उसका फायदा करें, आपका पहले होगा। जो भी काम थे, उनको हमने निश्चित रूप से करने की पूरी कोशिश की है।

सभापति महोदय, मेडिकल कालेज वगैरह के बारे में हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी कार्यवाही करेंगे। हम चाहते हैं राजस्थान में तीन मेडिकल कालेज, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं। जालौर के माननीय सदस्य बैठे हैं, तीन की भी पूरी कोशिश करो, हो जायेगा। अभी मुख्य मंत्री जी ने डाक्टर्स के साथ वीसी की थी, सारे डाक्टर्स थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 86 मेडिकल कालेज हैं, हम तो उनसे अभी बहुत पीछे हैं। निश्चित रूप से हमारे यहां नर्सिंग की और डाक्टर्स की कमियां हैं। आज डाक्टर्स गांवों में नहीं जाते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण है। उस कारण को भी माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लायेंगे। जैसे आपने सुझाव दिये। निश्चित रूप से डाक्टर्स गांव में जायें और उनको सुविधाएं मिलें, ये सब चीजें हैं। हम सब चिन्तित हैं, डाक्टर गांव में पीएचसी और सीएचसी में नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री दवा योजना का फायदा कैसे मिलेगा? उसकी जांच कैसे होगी? उसका इलाज कैसे होगा? वहां सीएचसी का भवन बनाया, पीएचसी का बनाया, उसका सदुपयोग कैसे होगा?

निश्चित रूप से सभापति महोदय, आप सबने जो सुझाव दिये, आपके कटमोशन के उत्तर हम कल तक भिजवा देंगे। सबके जवाब आ गये। जो भी

(श्री परसादी लाल)

आपके कामकाज होंगे, निश्चित रूप से आपके अच्छे सुझाव हैं। निश्चित रूप से किसी पीएचसी और सीएचसी में कोई डाक्टर नहीं है, आपके सम्पर्क में कोई डाक्टर हो, वह जाना चाहे तो आप हमको बता दें, हम उसको लगा देंगे। अपन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाली जगह पर कोई स्वेच्छा से जाना चाहे, आप लिस्ट देंगे तो हम उनको लगा देंगे। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम एसएमएस में, मेडिकल कालेजों में, उन्होंने जोधपुर में मेडिकल डेन्टल कालेज खोला।

एसएमएस को भी इतना सुसज्जित कर देंगे, यहां पर हर तरह की सुविधायें हों, लोगों को उसका फायदा मिले। देश में सबसे ऊंचा टावर हमारी आईपीडी बनेगी। राजस्थान में लोग एसएमएस को याद करते हैं, निश्चित रूप से उसको भी याद करेंगे। बहुत अच्छा काम इन तीन सालों में हुआ है।

अब जो बजट घोषणाएं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे हाउस को आश्वस्त करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, सबको तुरन्त करो। जो भी सीएचसी, पीएचसी कर दिया, सबको चालू करो। आपने जो भी सब-सेन्टर खोले, उनको भी जल्दी खोलो। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य के हित में अच्छा काम हुआ है। हमें इसे एप्रिशिएट करना चाहिये। मुख्य मंत्री जी को, हम सबको मिलकर धन्यवाद देना चाहिये कि हैल्थ का इतना काम, इतना अच्छा बजट पहले कभी नहीं आया, जितना अब आया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अनुदान की मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई, मांग संख्या 13 - आबकारी को पारित कराने की कृपा करें।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,20,90,50,000/- (एक सौ बयालीस अरब बीस करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 13 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,80,82,55,000/- (एक अरब अस्सी करोड़ बयासी लाख पचपन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.26 बजे शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

प्रश्न काल में नहीं पुकारे गये/अधूरे/समयाभाव के कारण नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15 फरवरी, 2022)

प्रदेश में मृतक आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

63. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए सरकार ने मृतक आश्रित आवेदक के आवेदन करने के पश्चात् नियुक्ति देने का कोई समय निर्धारित किया है? यदि हां, तो कितने समय में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी विभागीय उदासीनता के कारण आवेदक को निर्धारित समय में अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मृतक आश्रित के अनुकम्पा नियुक्ति की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि से नियुक्ति आदेश जारी करने तक प्रकरणों को बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के लंबित रखने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समय सीमा में आवेदित पूर्ण आवेदन पत्र विभाग स्तर पर प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियत समय में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के निर्देश हैं। (परिपत्र दिनांक 16.07.2021 परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(2) आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है तथा प्रकरण लम्बित नहीं रखा जाता है तथापि कुछ प्रकरणों में चरित्र सत्यापन/पुलिस सत्यापन, मूल विभाग में पद रिक्त न होने तथा आवेदक द्वारा नियमानुसार देय पद पर नियुक्ति न स्वीकार कर अपनी उच्च योग्यता के अनुसार पद पर नियुक्ति चाहने के कारण नियुक्ति में विलम्ब हो सकता है।

अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी विभागों में नोडल अधिकारी/केस प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश

(कार्मिक मंत्री)

जारी किए गए हैं तथा त्वरित कार्यवाही किए जाने हेतु दायित्व निर्धारित किए गए हैं। (परिपत्र दिनांक 16.07.2021 परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(3) अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पूर्ण होने पर समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लम्बित रखने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरीय निकायों में डेयरी बूथों का आबंटन

235. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट 2021-22 में नगरीय निकायों में 5,000 डेयरी बूथ आबंटित किए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कितने लोगों को डेयरी बूथ आबंटित किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट 2021-22 की अनुपालना में प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा आवंटित 2,338 डेयरी बूथों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में पुलिस थानों का सीमांकन

237. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पुलिस थानों का सीमांकन कर नये वृत कार्यालयों का सृजन किया जा रहा है जिसके तहत जिला बाड़मेर के थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्रवार कर नये थाने प्रस्तावित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या इस हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित कर उक्त जिले में थाने प्रस्तावित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिवाना मुख्यालय पर सी.ओ. कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त में कौन-कौनसे पुलिस थानों को सम्मिलित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिवाना पुलिस थाने में सी.आई. का पद सृजित करने व समदड़ी पुलिस थाने के तहत ग्राम पंचायत खण्ड में नई चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पुलिस थानों का सीमांकन कर नये वृत कार्यालय का सृजन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

बाड़मेर जिले में पुलिस थानों का सीमांकन विधान सभा क्षेत्रवार किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। इस हेतु न ही कोई समिति गठित की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बाड़मेर जिले में सिवाना मुख्यालय पर नया वृत कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

नये वृत कार्यालय का सृजन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में सिवाना पुलिस थाने में सी.आई. पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

समदड़ी पुलिस थाना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खण्ड में नई चौकी खोले जाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

कोटा में बायोलोजिकल पार्क का कार्य

238. श्री संदीप शर्मा (कोटा-दक्षिण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा के बायोलोजिकल पार्क का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो इसके कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पार्क में पुराने चिड़ियाघर के वन्यजीवों को भी स्थानान्तरित करने की कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त में देश के दूसरे चिड़ियाघरों से वन्यजीव शिफ्टिंग की कार्ययोजना भी प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक जानवरों को शिफ्ट कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क, कोटा का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है। पार्क का विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री महोदय

(वन मंत्री)

द्वारा 18.12.2021 को किया जाकर उक्त पार्क दिनांक 01.01.2022 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है।

(2) जी हां। कोटा के अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क में कोटा के पुराने चिडियाघर के वन्यजीवों को शिफ्ट करने की कार्य योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 77 वन्यजीवों जैसे की लैपर्ड, हायना, सियार, भेड़िया ब्लैक बक, चिंकारा, चीतल आदि शिफ्ट किये जा चुके हैं। अन्य वन्यजीवों को द्वितीय चरण में शेष एनक्लोजर बन जाने के पश्चात् शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट किये गये वन्यजीवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश एवं देश के दूसरे चिड़ियाघर जैसे कि सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क, उदयपुर, नाहरगढ बायोलोजिकल पार्क जयपुर, नागालैण्ड जूलोजिकल पार्क एवं शक्करबाग जूलोजिकल पार्क, जूनागढ़ से - वन्यजीवों की शिफ्टिंग का कार्य प्रस्तावित है। केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् शिफ्टिंग का कार्य कराया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

झालावाड़ में सहकारी समितियों के माध्यम से बीज वितरण

240. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में वर्ष 2021-22 में किसानों को सहकारी समितियों व अन्य एजेंसियों के माध्यम से खाद व बीज का वितरण सही समय पर नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानियां व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है? क्या सरकार किसानों को अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार आगामी वर्ष 2022-23 में आवश्कतानुसार समय पर किसानों को फसल बुआई के अनुरूप खाद व बीज आदि सुविधा सहकारी समिति व अन्य एजेंसियों के माध्यम से समय पर वितरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। किसानों को अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा किसानों को उन्नत/प्रमाणित बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक जिले के लिए खरीफ एवं रबी

(सहकारिता मंत्री)

मौसम पूर्व कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जोनल कांफ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें प्रमाणित बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजफैड द्वारा कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अनुबंधित कंपनियों के माध्यम से उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण किया जाता है तथा भण्डारित उर्वरक मांग के समय किसानों को उपलब्ध करवाये जाते है। इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर मांग के अनुसार बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

डूंगरपुर में फसल खराबे का मुआवजा

241. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जिला डूंगरपुर में आपदा के तहत 10 पंचायत समितियों में से मात्र तीन पंचायत समितियों में ही काश्तकारों को फसल खराबे का भुगतान हुआ है? क्या सरकार जिले की शेष सात पंचायत समिति के काश्तकारों को भी फसल खराबे की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डूंगरपुर जिले में खरीफ फसल वर्ष 2021 (संवत् 2078) में 3 तहसील साबला, सागवाड़ा एवं गलियाकोट में सूखे से फसल खराबा होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। शेष तहसीलों में सूखे से फसल खराबा नहीं होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। सूखे से प्रभावित किसानों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रभावित पात्र कृषकों को राज्य आपदा मोचन निधि के मानदण्डानुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जायेगा। विभाग द्वारा किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त युवाओं को देय सुविधाएं

243. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्ष में युवा दिवस पर प्रदेश के कितने युवाओं को राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान है? देय सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को पहचान पत्र एवं अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा पुरस्कार की वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष 2017-18 में श्री मनिष कुमार दवे (व्यक्तिगत श्रेणी)

वर्ष 2018-19 में सुश्री दिव्या कुमारी जैन (व्यक्तिगत श्रेणी)

वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई।

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई।

वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई।

(2) विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नही है।

(3) विभाग द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है एवं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अभिशंषा नहीं की जाती है।

भारत सरकार द्वारा आनलाइन आवेदन लिये जाकर युवा पुरस्कार दिये जाते हैं।

सोलर प्लांट लगाने की योजना

244. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बिजली के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों की अनुपयोगी जमीन के उपयोग हेतु सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त योजना से कितना लाभ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना को और प्रभावी ढंग से लागू करने एवं किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या-क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिजली के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु वर्तमान में पी.एम. कुसुम योजना संचालित है। योजना का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों की बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर सोलर प्लान्ट लगाकर विद्युत उत्पादन करने हेतु पी.एम. कुसुम कम्पोनेन्ट-"ए" योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में किसान द्वारा वितरण निगमों के 33/11 केवी सब-स्टेशन के पांच किमी. के दायरे में सोलर प्लान्ट की स्थापना का प्रावधान है। एक मेगावाट क्षमता के प्लान्ट हेतु दो हैक्टेयर भूमि व लगभग चार करोड़ रुपये की लागत आती है तथा वितरण निगम द्वारा किसान अथवा विकासकर्ता को 25 वर्ष तक बिजली का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(3) इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने में आ रही वित्तीय समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा बैंकों के स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

245. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में एक भी सरकारी बालिका महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजकीय उच्च मा. वि. में बालिकाओं की संख्या 500 से अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मापदण्डों के अनुसार बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, वजीरपुर खोले जाने की घोषणा की गई है। घोषणा की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी खोले जाने की घोषणा की गई है। घोषणा की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नव उद्यम प्रवर्तन को प्रोत्साहन देने की योजना

246. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नव उद्यम प्रवर्तन (स्टार्ट अप) को प्रोत्साहन देने के संबंध में क्या प्रावधान एवं योजनायें हैं?

(2) वर्तमान एवं विगत 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक जिले में कितने नव उद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) प्रारम्भ हुए एवं इन्हें कितनी राजकीय सहायता उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान एवं विगत 3 वित्तीय वर्षों में प्रदेश में नव उद्यम

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

प्रवर्तन (स्टार्टअप) से कितना निवेश आया एवं कितना रोजगार सृजित हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नव उद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) को प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रावधान एवं योजनायें अनुलग्नक-1 पर संलग्न हैं।

(2) वर्तमान एवं विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य सरकार के आई-स्टार्ट पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या एवं उपलब्ध करवाई गई राजकीय सहायता की सूचना अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान एवं विगत 3 वित्तीय वर्षों में प्रदेश में नव उद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) से प्रदेश में आये निवेश की सूचना स्टार्टअप्स द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई जाती है।

स्टार्टअप्स द्वारा विभाग को पंजीकरण के समय उपलब्ध करवाये गये आंकडो के अनुसार कुल 1,492 पंजीकृत स्टार्टअप्स में 13,456 लोग कार्यरत थे।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पाली में निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार का बकाया का भुगतान

247. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली के किस-किस निजी विद्यालय को शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब से किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत पाली जिले में सत्र 2019-20 तक प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान, उन सभी विद्यालयों को किया जा चुका है, जिन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व क्लेम कार्यालय को प्रेषित कर दिये थे।

सत्र 2020-21 में पाली जिले में निजी विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त में भुगतान से शेष रहे विद्यालयों की संख्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(शिक्षा मंत्री)

सत्र	किश्त	प्रारम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा
2020-21	प्रथम	15	06
	द्वितीय	34	19

उक्तानुसार भुगतान से शेष रहे विद्यालयों का सत्रवार एवं विद्यालयवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) उक्त बकाया सत्र 2020-21 की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान प्रक्रियाधीन है, जिसका भुगतान 31 मार्च, 2022 तक कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत आवेदक

248. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल कोटा के पास पूर्व में प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को आवास, भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार मण्डल को भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां पर व नहीं, तो क्यों? पंजीकृत आवेदकों की श्रेणी सहित संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि आवासन मण्डल के पास कोटा शहर में प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

भूमि की अनुपलब्धता के कारण आवास आबंटन सम्भव नहीं हो पा रहा है। भूमि की उपलब्धता के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

भूमि के चयन हेतु सर्वे कर यथा सम्भव शीघ्र भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रतीक्षारत पंजीकृत आवेदकों की श्रेणीवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

चित्तौड़गढ़ में भू-जल गुणवत्ता व प्रदूषण की जांच

249. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक लि. के खनन एवं स्मेल्टिंग इकाइयों से आस-पास की पंचायतों में भूजल गुणवत्ता व प्रदूषण की जांच विगत 3 वर्षों में कब-कब की गई? जांच के परिणाम प्रत्येक पंचायत में क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इकाइयों का वायु एवं जलीय वातावरण पर क्या-क्या दुष्प्रभाव है? इनसे जिले की कितनी एवं कौनसी पंचायतें प्रभावित हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त इकाइयों के प्रदूषण से आस-पास की पंचायतों की कृषि भूमि पर एवं कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जांच विगत 3 वर्षों में कितनी बार की गई व उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की कोई खनन इकाई नहीं है। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के स्मेल्टर प्लांट के आस-पास रीको इंडस्ट्रियल एरिया के पास स्थित ग्राम पंचायत आजोलिया का खेडा में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत हैंड पंप के भू-जल की छः माही जांच की जाती है। पिछले तीन वर्षो का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जांच परिणामों के अनुसार भू-जल के अधिकतर मानक (पेयजल हेतु) निर्धारित सीमा के अन्दर है।

भू-जल विभाग से प्राप्त सूचनानुसार मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का चंदेरिया, चित्तौडगढ़ के स्मेल्टर प्लांट के आस-पास के ग्राम सुवानिया (ग्रा.पं. सुवानिया), पुठोली (ग्रा.पं. पुठोली) एवं नगरी (ग्रा.पं. नगरी) के वर्ष 2019, 2020 व 2021 का रासायनिक विश्लेषण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदेरिया से निस्त्रावित प्रदूषक तत्वों की जांच हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर स्टैक मोनिटरिंग व एम्बिएंट एयर क्वालिटी के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट क्रमशः "स" व "द" पर संलग्न है। जांच नमूनों के परिणामों के अनुसार प्रदूषक तत्व सामान्यत निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(पर्यावरण मंत्री)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ग्राम नगरी के पास बेडच नदी के जल नमूने प्रतिमाह एकत्रित किये जाते हैं जिनके परिणाम निर्धारित मानकों के लगभग अनुरूप है। विवरण संलग्नक परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार जिलास्तरीय अधिकारियों की टीम द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के आस-पास के बिलिया, पूठोली, आजोलियों का खेड़ा व नगरी गांवों का वर्ष 2020-21 के दौरान भ्रमण किया गया, जिसमें 5 मिट्टी व 5 पानी के नमूने क्षेत्र से प्राप्त कर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में जांच करवाये गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार सॉयल हैल्थ कार्ड के माध्यम से फसलवार खाद एवं उर्वरक की राय क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध करायी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हरियाणा-भाखड़ा से भादरा-नोहर को कम पानी

250. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विगत एक वर्ष में वाया हरियाणा-भाखड़ा से भादरा-नोहर को कितना प्रतिशत पानी हिस्से से कम मिला? इसके क्या कारण हैं? भविष्य में हिस्से का पानी लेने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विगत 12 माह में नोहर भादरा क्षेत्र को वाया हरियाणा से मिले पानी का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जिसके अनुसार नोहर भादरा के क्षेत्र के लिए निर्धारित पानी 1,65,850 क्यूसेक डेज के विरुद्ध 1,64,180 क्यूसेक डेज पानी मिला है जो निर्धारित पानी से 1.0 प्रतिशत कम है। जब भी प्राप्त जल में उतार-चढ़ाव होता है तो हरियाणा के अधिकारियों से वार्ता, पत्राचार कर तथा हर माह सम्पन्न होने वाली तकनीकी समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाकर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने का प्रयास किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डिफाल्टर किसानों को बिना ब्याज ऋण

251. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के समय

(श्री नरेन्द्र नागर)

के डिफाल्टर किसानों को बिना ब्याज पर ऋण दिये जाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त किसानों को अब कब तक बिना ब्याज ऋण दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

रायसिंहनगर में आपदा प्रभावित किसानों को मुआवजा

252. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 की अवधि में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी, आगजनी आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है? यदि हां, तो वर्षवार आपदावार कराई गई खसरा गिरदावरी, पीड़ित किसानों को दिये गये मुआवजा भुगतान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त पीड़ित किसानों में से कई किसानों को अब तक फसल खराबे का मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? ग्रामवार पीड़ित एवं मुआवजे से वंचित किसानों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनवरी 2019 से दिसम्बर 2021 की अवधि मे ओलावृष्टि से ही किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 से 4 पर संलग्न है।

फसल खराबे से प्रभावित किसानो कों उपलब्ध कराई गई कृषि आदान-अनुदान राशि की वर्षवार सूची परिशिष्ट-5 से 7 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने वाले एवं अन्यत्र निवास करने वाले किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान नहीं हो सका है। उक्त कारणों से शेष रहे किसानों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-8 से 10 पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

खरीफ फसल संवत् 2078 के प्रभावित काश्तकारों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची परिशिष्ट-11 पर संलग्न है।

(3) जी हां। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने पर नियमानुसार कृषि आदान-अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

निजी वाहनों का फिटनेस

253. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की फिटनेस विभाग करता है?

(2) क्या यह भी सही है कि निजी वाहनों की फिटनेस विभाग नहीं करता व निजी सेंटरों पर करवानी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार निजी वाहनों का फिटनेस विभाग द्वारा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि निजी फिटनेस सेंटरों में आटो रिक्शा की फिटनेस जांच के उपकरण नहीं हैं? यदि हां, तो किस आधार पर निजी फिटनेस सेंटरों को आटो रिक्शा की फिटनेस जांच के लिए अधिकृत कर रखा है? क्या सरकार निजी फिटनेस सेंटर्स के स्थान पर आटो रिक्शा का फिटनेस विभाग से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिन राजस्व जिलों में विभाग द्वारा अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर स्थापित हैं, उन जिलों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की फिटनेस नवीनीकरण का कार्य अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर पर होता है एवं जिन राजस्व जिलों में अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं है, उन जिलों में फिटनेस नवीनीकरण का कार्य जिला परिवहन कार्यालय/उप परिवहन कार्यालय स्तर पर संपादित होता है।

(2) जी हां। जिन राजस्व जिलों में विभाग द्वारा अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर स्थापित हैं, उन जिलों में परिवहन वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण का कार्य अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर पर होता है एवं जिन

(राज्य मंत्री, परिवहन)

राजस्व जिलों में अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं है उन जिलों में फिटनेस नवीनीकरण का कार्य जिला परिवहन कार्यालय/उप परिवहन कार्यालय स्तर पर संपादित होता है।

वर्तमान में जिन राजस्व जिलों में अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर स्थापित है, उन जिलों में परिवहन कार्यालयों पर फिटनेस पुन: शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं। आटो रिक्शा वाहन, हल्का मोटरयान श्रेणी में आते हैं एवं परिवहन विभाग द्वारा जिन फिटनेस सेंटरों को हल्का मोटरयान श्रेणी के वाहनों की फिटनेस किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, उन सेंटरों पर समस्त उपकरण स्थापित हैं।

वर्तमान में जिन राजस्व जिलों में अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर स्थापित है उन जिलों में आटो रिक्शा के फिटनेस का कार्य परिवहन कार्यालय से किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित नहीं है।

भोपालगढ़ में पंजीकृत बेरोजगार

254. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जनवरी, 2022 तक कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं व कितने पुरुषों को वर्ष 2020-21 व 2021-22 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है एवं कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना शेष है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के जनवरी 2022 तक कुल 6,985 बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना मे नियमानुसार पात्र स्नातक उतीर्ण कुल 546 महिलाओं एवं 844 पुरुष युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया तथा वर्ष 2021-22 में कुल 715 महिलाओं एवं 1,379 पुरुष युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। वर्तमान में 1,323 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पांचू (नोखा) में सहायक अभियंता का कार्यालय

255. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोखा की पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत सहायक अभियन्ता कार्यालय को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव पांचू में 220 केवी जीएसएस स्वीकृत है? यदि हां, तो इसका कार्य प्रारंभ नहीं होने का क्या कारण है? सरकार उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिला वृत के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने के दृष्टिगत पांच नवीन उपखण्ड खोलने का निर्णय जोधपुर डिस्काम के निदेशक मण्डल द्वारा 31.10.2017 की बैठक में लिया गया था जिसकी अनुपालना में बीकानेर जिला वृत के अधीन पांचू सहित पांच उपखण्ड कार्यालयों का गठन डिस्काम के सचिव प्रशासन के आदेश दिनांक 03.11.2017 द्वारा तदर्थ आधार पर किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जोधपुर डिस्काम के सचिव प्रशासन के आदेश दिनांक 03.11.2017 द्वारा तदर्थ आधार गठित नवीन उपखण्डों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के सक्षम विभाग को प्रेषित किया गया था जिसे स्वीकृत नहीं किया गया। अत: दिनांक 27.09.2021 को जोधपुर डिस्काम के निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में आदेश दिनांक 02.11.2021 के द्वारा पांचू सहित उक्त पांचों उपखण्ड कार्यालयों को भंग कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

पंचायत समिति पांचू में नवीन उपखण्ड कार्यालय खोले जाने के लिये पुन: संशोधित प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा जाना प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोखा में 220 केवी जीएसएस का कार्य प्रारम्भ नहीं होने का कारण व अन्य विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि का आबंटन

256. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि की? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित की जा चुकी है? यदि हां, तो कहां पर व कितनी भूमि आबंटित की गई? यदि नहीं, तो क्यों? आवंटन आदेश की प्रति सदन के मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या भूमि चिन्हित कर ली गई है? यदि नहीं, तो अब कब तक आबंटित कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 4.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.11.2021 को जारी की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जिला कलेक्टर, जालौर के आदेश दिनांक 06.09.2018 राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा के भवन निर्माण हेतु मौजा डोडवाडिया (ग्राम पंचायत आजोदर) तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 08 रकबा 6.15 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ओरण में से 2.0235 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गयी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

उक्त भूमि गैर मुमकिन ओरण होने के कारण इस भूमि के स्थान पर मौजा जालेरा कलां तहसील रानीवाड़ा के खसरा नम्बर 586 रकबा 17.68 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (गोचर) में से 2.58 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 797/586 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (गोचर) में से 0.10 हैक्टेयर कुल 2.68 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (गोचर) भूमि उक्त

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

महाविद्यालय हेतु चिन्हित कर ली गई है। उक्त भूमि के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। उक्त महाविद्यालय, मौजा जालेरा कलां तहसील रानीवाड़ा के खसरा नम्बर 586 रकबा 17.68 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (गोचर) में से 2.58 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 797/586 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (गोचर) में से 0.10 हैक्टेयर कुल 2.68 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (गोचर) भूमि चिन्हित कर ली गई है। उक्त भूमि के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे निकट भविष्य में आबंटित करा ली जायेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा में किराये के भवनों में संचालित पुलिस चौकियां

237. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में कितनी पुलिस चौकियां किराये के भवन में संचालित हैं? उक्त चौकियों को राजकीय भवन में संचालित करने हेतु क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पुलिस थानों एवं चौकियों के लिये भूमि आबंटित होने के पश्चात् भी भवन निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त में भवन निर्माण कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने पुलिस थाने, चौकियां जर्जर व क्षतिग्रस्त भवनों में संचालित हैं? उक्त को सुरक्षित भवनों में संचालन करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में पुलिसकर्मियों के लिये कितने राजकीय आवास निर्मित हैं तथा कितने जर्जर, क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला दौसा में कोई भी पुलिस चौकी किराये के भवन में संचालित नहीं हैं।

(2) दौसा जिले में पुलिस थाना- लवाण व बसवा तथा पुलिस चौकी-तालचिड़ी व सिकराय के लिये भूमि आबंटित हो चुकी है। उक्त थानों एवं पुलिस चौकियों के भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर विचार किया जायेगा।

(3) दौसा जिले में कोई भी थाना या चौकी जर्जर अवस्था में नही चल रहा है। पुलिस थाना बसवा व पुलिस थाना लवाण पुराने चौकी भवन में संचालित है।

(4) जिला दौसा में कुल 60 अपर सबोर्डिनेट एवं 379 लोअर सबोर्डिनेट कुल 439 आवासीय भवन निर्मित हैं। उक्त आवासीय भवनों में से 3 अपर सबोर्डिनेट एवं 55 लोअर सबोर्डिनेट कुल 58 आवासीय भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नकारा घोषित किये जा चुके हैं। वर्तमान में पुलिस लाइन दौसा में आवास/भवन मरम्मत का कार्य चल रहा है।

जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मुक्त कराये गये बाल श्रमिक

238. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 तक कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया? उक्त बाल श्रमिक किन-किन जिलों व राज्यों से लाये गये थे? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही में बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले कितने लोगों के विरुद्ध किस-किस धारा में एफआईआर दर्ज कर क्या-क्या कार्रवाई की गई एवं कितने लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये? थानेवार व प्रकरणवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों से काम करवाने वाले कितने अभियुक्तों के विरुद्ध मानव तस्करी की धारा 370ए के तहत मामला दर्ज किया गया? थानेवार व प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 तक 801 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। यह बाल श्रमिक जिन-जिन जिलों व राज्य से लाये गये थे, उनका थानेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यवाही में बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले 268 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धारा में 205 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई एवं 251 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये जिनका थानेवार प्रकरणवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों से काम करवाने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध मानव तस्करी की धारा 370 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनका थानेवार व प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में पुलिस मित्रों का चयन

239. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पुलिस सहायता के लिए ट्विटर हैण्डल राजस्थान पुलिस हैल्प डैस्क योजना के तहत पुलिस मित्र बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो जिला नागौर में अब तक थानावार कितने पुलिस मित्र बनाये जा चुके हैं? थानावार पुलिस मित्रों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के कितने पुलिस मित्रों का चयन किया जाना प्रस्तावित है? ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत पुलिस मित्र बनाने का क्या-क्या आधार व पैमाने निर्धारित किये गये हैं एवं अपराध नियंत्रण की दृष्टि से योजना कितनी प्रभावशाली रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस सहायता के लिए ट्विटर हैण्डल राजस्थान पुलिस हैल्प डैस्क योजना के तहत नागौर जिले में बनाये गये 1,158 पुलिस मित्र का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत डीडवाना विधान सभा क्षेत्र के 04 पुलिस मित्रों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 09/2019 दिनांक 27.06.2019 में पुलिस मित्र बनाये जाने का आधार/पैमाना निर्धारित किया गया है एवं अपराध नियंत्रण की दृष्टि से योजना के प्रभावशाली होने का विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मकराना पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण

240. श्री रूपा राम (मकराना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पुलिस थाना मकराना (नागौर) में विगत एक वर्ष में कितने प्रकरण दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में कितने अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा व चोरी के मुकदमे में कितनी बरामदगी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपा राम)

(3) उक्त दर्ज मुकदमों में से कितनों में चालान पेश किया गया व कितनों में शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना मकराना (नागौर) में पिछले एक वर्ष में कुल 508 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में कुल 399 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पिछले एक वर्ष में चोरी के कुल 78 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें 13 प्रकरणों में बरामदगी हुई है। बरामदगी का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'ब' के कॉलम संख्या 11 में अंकित है।

(3) पुलिस थाना मकराना में कुल दर्ज 508 प्रकरणों में से 196 प्रकरणों मे न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है तथा 35 प्रकरणों में चार्ज शीट किता की जा चुकी है किन्तु न्यायालय में चालान पेश किया जाना शेष है। कुल दर्ज प्रकरणों में से 243 प्रकरणों में एफ.आर. दी गई है तथा 34 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है, जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवनगर पुलिस थाने (जोधपुर) हेतु भूमि का आबंटन

241. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में संचालित पुलिस थाना देवनगर किराये के भवन में संचालित हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त पुलिस थाना भवन के लिए भूमि का आबंटन कर भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो समयबद्ध कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में स्थित पुलिस थाना देवनगर भवन व भूमि के अभाव में किराये के भवन में संचालित हो रहा हैं।

(2) पुलिस थाना देवनगर हेतु भूमि व भवन आबंटन हेतु पुलिस विभाग द्वारा आवासन मंडल जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम जोधपुर से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। पुलिस थाना देवनगर के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु संबंधित संस्था द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर ही उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर बजट आबंटन किया जाना संभव हो सकेगा।

सरकार पर ब्याज अदायगी का बोझ

242. श्री कालूराम (डग): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान सरकार पर राज्य के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत ब्याज अदायगी का बोझ था? 2014 के उपरान्त यह अब तक प्रतिवर्ष कितना-कितना रहा? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार की योजना के अनुरूप की गई ब्याज दर में विगत वर्षों में राज्य के राजस्व में कितनी बचत की कमी हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक वर्षवार राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं ब्याज भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	**कुल राजस्व**	**ब्याज अदायगी**	**कुल राजस्व से ब्याज अदायगी का प्रतिशत**
2014-15	91326.91	10462.90	11.46
2015-16	100285.12	12008.30	11.97
2016-17	109026.00	17676.93	16.21
2017-18	127307.18	19719.99	15.49
2018-19	137873.02	21695.20	15.74
2019-20	140113.81	23643.27	16.87
2020-21	134307.88	25201.81	18.76

(2) प्रस्तावित उपरोक्त अवधि में भारत सरकार द्वारा ब्याज दरों में कमी करने सम्बन्धी कोई योजना जारी नहीं की गई है।

तारानगर के विद्यालयों के खेल मैदान

243. श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (तारानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में कितने ऐसे उ.प्रा.वि., मा.वि. व उ.मा.वि. विद्यालय हैं जिनके पास खेल मैदान की जमीन उपलब्ध है व कितनों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार उक्त को खेल मैदान की जमीन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नरेन्द्र बुड़ानिया)

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के कितने ऐसे राजकीय विद्यालय हैं, जिनको खेल मैदान हेतु जमीन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है तथा कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास जमीन उपलब्ध है किन्तु स्वीकृत नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त खेल मैदानों को विकसित करने हेतु पृथक् से बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन जिला चूरू में कुल 456 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है, जिनमें से 278 राउप्रावि में खेल मैदान हेतु जमीन उपलब्ध है तथा 178 राउप्रावि में खेल मैदान हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। इन राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान हेतु जमीन उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय तहसीलदार/राजस्व अधिकारी/स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क करने हेतु संबंधित पीईईओ/संस्था प्रधानों को निर्देशित किया हुआ है। उक्तानुसार सूची परिशिष्ट-क एवं ख पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन जिला चूरू में 179 रामावि एवं 353 राउमावि संचालित है, जिनमें से 115 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा 254 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास खेल मैदान की जमीन उपलब्ध है। जिला चूरू में कुल 369 विद्यालयों के पास खेल मैदान उपलब्ध है का नामवार विवरण परिशिष्ट-ग से घ व घ-1 पर संलग्न है।

जी हां। पत्र दिनांक 16.04.2019 एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/साप्र/डी-3/विविध/2016-17/वो-1/2014/117 दिनांक 18.04.2019 एवं दिनांक 15.05.2019 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर खेल मैदान के लिए जमीन आबंटन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। स्थानीय प्रशासन एवं जिला कलेक्टर द्वारा जमीन की उपलब्धता के आधार पर भूमि आबंटन किया जाता है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुल 40 राजकीय विद्यालयों में खेल मैदान हेतु जमीन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है तथा 56 राजकीय विद्यालयों के पास खेल मैदान हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। इन विद्यालयों में खेल मैदान हेतु जमीन उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय तहसीलदार/राजस्व अधिकारी/स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क करने हेतु सम्बन्धित पीईईओ/संस्था प्रधानों को निर्देशित किया हुआ है। सूची परिशिष्ट-ङ एवं च पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन विधान सभा क्षेत्र तारानगर जिला चूरू में संचालित ऐसे 38 राजकीय विद्यालय जिनके खेल मैदान हेतु आबंटित जमीन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है, का विद्यालय नामवार विवरण परिशिष्ट-छ पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र के ऐसे 05 राजकीय मावि/उमावि जिनके खेल मैदान हेतु आबंटित जमीन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है, का विद्यालय नामवार विवरण परिशिष्ट-ज पर संलग्न है।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के खेल मैदान हेतु पृथक से बजट आबंटन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डेगाना में चारदीवारी विहीन विद्यालय

244. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कितने विद्यालय चारदीवारी विहीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें शौचालय एवं पीने के पानी की टंकियां नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में 18 राजकीय प्राथमिक, 02 उच्च प्राथमिक एवं 02 उच्च माध्यमिक विद्यालय चारदीवारी विहीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित समस्त 301 राजकीय विद्यालयों मे शौचालय एवं पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध पेयजल सुविधा के स्रोतों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**विद्यालयों की संख्या**	**उपलब्ध पेयजल स्रोत**
1	43	हैण्डपम्प
2	26	कुआं
3	56	नल कनेक्शन
4	150	टांका
5	24	नल एवं टैंक
6	02	ट्यूबवैल
योग-	301	

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के तिरूपति विहार का नियमितीकरण

245. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार कीर्तिनगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जयपुर (रजिस्ट्रेशन नम्बर : 2446/एल) की आवासीय योजना "तिरूपति विहार" जो ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, के प्लाटधारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा दिलवाने (नियमितीकरण) का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त पट्टे कब तक जारी करवा दिये जाएंगे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त योजना गैर-अनुमोदित है, जिसका नियमानुसार परीक्षण कर नियमन योग्य पाये जाने पर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

पुष्कर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री आवासों की गुणवत्ता की जांच

246. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर में निर्माणधीन मुख्यमंत्री आवास की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की गई है? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार निर्माणाधीन उक्त आवासों की गुणवत्ता की जांच का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुष्कर में मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रारम्भ एवं कार्य पूर्णता अवधि क्या निर्धारित है? क्या कंपनी द्वारा समय पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समयावधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी उक्त आवासों का कार्य कंपनी द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है? क्या सरकार ने उक्त आवासों के कार्यों हेतु कोई समयावधि में विस्तार किया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए कंपनी पर शर्तों के अधीन नियमानुसार अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री आवास की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रारम्भ तिथि 01.08.2018 थी एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 31.07.2021 निर्धारित की गई थी। कम्पनी द्वारा 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कोरोना महामारी की वजह से कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाया है।

(3) जी हां। निर्धारित समयावधि में उक्त निर्माण कार्य कोरोना महामारी के कारण पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। समयावधि बढ़ाये जाने हेतु सक्षम स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अरावली संरक्षण की कार्ययोजना

247. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07.05.1992 को जारी की गई अधिसूचना केवल गुड़गांव तथा राजस्थान के अलवर जिले के लिए जारी की गई है जबकि अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक अस्तित्व में है? क्या सरकार द्वारा शेष राजस्थान की अरावली पर्वतमाला को संरक्षित करने के लिए कोई अधिसूचना, आदेश व परिपत्र तथा नियम जारी किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटिशन संख्या 202/1995 टी.एन. गोदावर्मन थिरूमुलपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया में दिनांक 03.07.2018 को दिये गये फैसले के अनुसार सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की तीन अभिशंषाओं को राज्य में लागू करने के आदेश की अनुपालना किस प्रकार करवाई जा रही है तथा डीम्ड फोरेस्ट वनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का भाग मानते हुए अरावली पर्वतों में क्या-क्या गतिविधियां अवैध हैं तथा क्या-क्या गतिविधियां की जा सकती हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम बोबाड़ी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में वर्तमान खसरा नम्बर 171 गै.मु. पहाड़ में बसे हुए अवैध

(श्री बाबूलाल नागर)

अतिक्रमियों के प्रार्थना पत्र पर गै.मु. पहाड़/गै.मु. तलाई को गै.मु. किया जाकर आबादी नियमन किया गया है? क्या उक्त की तरमीम आदि नियमन पर्यावरण तथा अरावली संरक्षण के लिए सही है? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07.05.1992 को जारी की गई अधिसूचना केवल गुड़गांव तथा राजस्थान के अलवर जिले के लिए जारी की गई है।

जी नहीं। राजस्थान के अन्य जिलों में अरावली पर्वतमाला के लिए सरकार द्वारा कोई अधिसूचना, आदेश व परिपत्र तथा नियम जारी नहीं किये गये हैं।

(2) सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की तीन अभिशंषाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.07.2018 पारित किया गया। इस आदेश की अनुपालना में दिनांक 06.11.2018 को कमेटी का गठन किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में समस्त मुख्य वन संरक्षकगणों को ओरण व देव वन, जो कपूर कमेटी की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं थे, की सूचियां तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये।

रूंध क्षेत्रों में दिनांक 25.10.1980 से पूर्व हुए गैर वानिकी कार्यों के लिए किये गये ऐसे क्षेत्रों के सर्वे व चिन्हीकरण के उपरांत एक सूची तैयार करने के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, भरतपुर एवं कोटा के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

डीम्ड फोरेस्ट के तहत सम्मिलित किये जाने वाले नवीन क्षेत्रों के चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने, देव वन एवं ओरण क्षेत्र से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध करवाने तथा डीम्ड फोरेस्ट में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं हों, इस बाबत समस्त जिला कलेक्टरो को पत्र लिखा गया है।

(3) खान विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी एवं इसके स्लोप क्षेत्र को अरावली पर्वतमाला का भाग मानने के संबंध में निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2006 जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन संख्या 202/1995 टी. एन. गोदावर्मन बनाम यूनियन आफ इण्डिया

(वन मंत्री)

व अन्य में जारी आदेश दिनांक 08.04.2005 की पालना में दिनांक 16.12.2002 के पश्चात् अरावली क्षेत्र में स्वीकृत किये गये 51 नये खनन पट्टों में खनन कार्य बंद करवाया गया। वर्तमान में विभाग द्वारा अरावली हिल्स में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

वन क्षेत्र में स्थित अरावली पर्वतमाला में गैर-वानिकी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। उक्त क्षेत्र में वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी गतिविधियां की जा सकती हैं।

(4) जिला कलेक्टर जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 171 गैर मुमकिन पहाड़ में बसे हुए अवैध अतिक्रमियों के प्रार्थना पत्र पर गैर मुमकिन नही किया जाकर न्यायालय उपखण्ड संख्या 11/2018 उनवान मामलाज बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 08 मई, 2018 की अनुपालना में खसरा नम्बर 171 रकबा 23.72 हैक्टेयर में से 7.00 हैक्टेयर भूमि की किस्म तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा रिकार्ड में गैर मुमकिन अंकित की गई है। उक्त आदेश की अनुपालना में खसरा नम्बर 171 रकबा 23.72 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में 7.00 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन का नवीन खसरा नम्बर 869/171 कायम किया जाकर तरमीम की गई है। प्रशासन गांव के संग अभियान, 2021 में ग्राम पंचायत बोबाडी द्वारा खसरा नम्बर 869/171 रकबा 7.00 हैक्टयेर किस्म गैर मुमकिन में से 2.50 हैक्टेयर भूमि पर आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव दिये जाने पर तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा आबादी भूमि का प्रस्ताव तैयार कर तहसील कार्यालय के पत्रांक 6692 दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ को प्रेषित किया गया है। प्रकरण कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ में विचाराधीन है।

सहाड़ा में बांधों की मरम्मत

248. श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के कई छोटे-बड़े बांधों की स्थिति जर्जर हो गई व भविष्य में उनके टूटने की संभावना बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बरसात के पश्चात् प्रदेश के उक्त बांधों की कोई सेफ्टी ऑडिट तथा मरम्मत करवाने की कोई योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पुराने बांधों के रख-रखाव व जीर्णोद्धार के लिए बजट आबंटित नहीं करने के कारण कई बांध खतरे में हैं? यदि हां, तो वर्ष 2018 से अब तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने बांधों व तालाबों के रख-रखाव के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया तथा किन-किन बांधों की मरम्मत करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों का प्रतिवर्ष मानसून पूर्व एवं पश्चात् किये गये निरीक्षण अनुसार किसी भी बांध के टूटने की संभावना नहीं है।

(2) जी नहीं। आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाये जाने से जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों में से कोई बांध खतरे में नहीं है। विगत वर्षों में सहाडा विधान सभा क्षेत्र में बांधों की मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाई नदी (आहोर) में बजरी दोहन के मापदण्ड

249. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जवाई नदी में खड़े बबूल के पेड़ कटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त नदी में जो बजरी दोहन हो रहा है, उसका विभाग द्वारा क्या मापदण्ड तय है?

(3) उक्त में होने वाले दोहन को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाई नदी में खड़े बबूल के पेड़ काटने हेतु आवश्यकतानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाती है। जालौर जिले में इस हेतु गत वर्ष मानसून पूर्व नीलामी हेतु सूचना प्रसारित की गई थी, परन्तु किसी फर्म द्वारा भाग नहीं लिये जाने से बबूल के पेड़ काटने संबंधित कार्य नहीं किया गया है।

(2) नदी में बजरी दोहन हेतु खान विभाग द्वारा मापदण्ड जारी किये जाने से जल संसाधन विभाग द्वारा अलग से मापदण्ड जारी नहीं किये गये हैं।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) खान विभाग, पुलिस/प्रशासन द्वारा नियम विरुद्ध दोहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती/जानी होती है।

जयपुर में यमुना से पानी दिये जाने की योजना

250. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में नदियों को जोड़ने का कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कब से व अब तक कितना कार्य किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार यमुना से राजस्थान को मिलने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाकर जयपुर जिले को पानी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने के कार्य अन्तर्गत "पूर्वी राजस्थान नहर" एवं "जवाई बांध पुर्नभरण परियोजना" का कार्य प्रस्तावित है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डी.पी.आर. राशि रुपये 37,247 करोड़ की केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। स्वीकृति की अपेक्षा में इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नवनेरा बैराज का कार्य प्रारम्भ कर राशि रुपये 598.76 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अन्तर्गत नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर एवं रामगढ़ बैराज निर्माण हेतु राशि रुपये 9,600 करोड़ के कार्य करवाये जाना एवं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया जाना प्रस्तावित है। जवाई बांध पुनर्भरण परियोजना की संशोधित पी.एफ.आर. 25.11.2019 को केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है तथा वर्तमान में परियोजना की अन्तरराज्जीय परिप्रेक्ष्य संबंधित रिपोर्ट स्वीकृति हेतु लम्बित है। स्वीकृति की अपेक्षा में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अन्तर्गत पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील बुजा व चक सांडमारिया बांधों के निर्माण हेतु राशि रुपये 1,800 करोड़ तथा इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु 1,200 करोड़ के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) राजस्थान को यमुना से मिलने वाली पानी की मात्रा का निर्धारण वर्ष 1994 में हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के मध्य हुए समझौते के तहत हो चुका होने तथा इस पानी की मात्रा का उपयोग अन्यत्र किया जाना प्रस्तावित होने से जयपुर जिले को यमुना का पानी दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

जाखम बांध (प्रतापगढ़) की भराव क्षमता में वृद्धि

251. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रतापगढ़ के जाखम बांध सहित अन्य सभी बांधों में कई वर्षों से भरी मिट्टी के कारण बांधों की जल भराव क्षमता कम हो गई है? यदि हां, तो सरकार उक्त सभी बांधों की मिट्टी निकलवा कर व गहरा करके जल भराव क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ जिले के जाखम बांध सहित अन्य बांधों की मिट्टी निकलवा कर गहरा करके जल भराव क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव लाभ-लागत एवं तकनीकी दृष्टि से उपादेय नहीं होने से विचाराधीन नहीं है।

माण्डलगढ़ में सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

252. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 1 जनवरी, 2019 से अब तक कितनी बार सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां भवन, गोदाम विहीन हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2019 से अब तक कितनी सहकारी समितियों के भवन, गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई व उक्त समितियों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 1 जनवरी, 2019 से अब तक दो बार में कुल 4 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति आदेश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की 06 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गोदाम विहीन हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से अब तक 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन/गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके निर्माण के लिये प्रति समिति 12 लाख रुपये की दर से स्वीकृति जारी की गई है। उक्त 18 समितियों में से 16 समितियों में कार्य पूर्ण हो चुका है व 2 समितियों में कार्य अपूर्ण है।

पूर्ण विवरण पृथक से परिशिष्ट-3 पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

देवली उनियारा की ग्राम सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायतें

253. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली उनियारा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उक्त पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में पिछले 05 वर्षों में 02 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार/गबन की जो शिकायतें प्राप्त हुईं उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. संचालक मण्डल सदस्य घाड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के व्यवस्थापक श्री रामप्रसाद मीणा द्वारा गबन व संस्था के प्रति लापरवाही करने के संबंध में शिकायत दिनांक 05.09.2018 को प्रस्तुत की गई। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक कार्यालय के दिनांक 11.09.2018 के द्वारा अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने प्रकरण की

(सहकारिता मंत्री)

जांच कर जांच रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 को कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके आधार पर दिनांक 18.09.2019 को अधिनियमान्तर्गत जांच परिणाम जारी किये गये तथा दोषी पाये जाने पर संचालक मण्डल के बैठक दिनांक 07.11.2019 के द्वारा श्री रामप्रसाद मीणा, व्यवस्थापक को निलम्बित किया गया। श्री मीणा के विरुद्ध उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.12.2014 के द्वारा निर्णित राशि 1,05,619.60 रुपये दिनांक 01.11.2011 से 18 प्रतिशत ब्याज की दर से समिति में जमा नहीं करवाने की शिकायत थी। उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवस्थापक श्री रामप्रसाद मीणा ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के यहां अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत अपील की है जो प्रक्रियाधीन है।

2. विधान सभा क्षेत्र देवली, उनियारा में रामसागर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. की विशेष साधारण सभा दिनांक 05.07.2021 के प्रस्ताव के अनुसार व्यवस्थापक श्री महावीर प्रसाद गुर्जर के द्वारा समिति में लाखों रुपयों का गबन/दुरुपयोग की जांच करवाने हेतु शिकायत जरिये अध्यक्ष प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत की जांच अधिनियमान्तर्गत धारा 55 में करवाई गई। जांच अधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2021 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक कार्यालय के आदेश दिनांक 07.12.2021 के द्वारा अधिनियम की धारा 57(1) के अन्तर्गत जांच परिणाम जारी किया गया। तत्पश्चात् उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां टोंक कार्यालय के आदेश दिनांक 16.02.2022 के द्वारा प्रकरण धारा 57 में दर्ज किया जाकर धारा 57 के तहत जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) कार्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार करवायी जाकर विधि सम्मत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कपासन में निगम की बसों का संचालन

254. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा संचालित करने के लिए सरकार द्वारा मानदण्ड तय किये हुए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र कपासन में निगम की बसें संचालित हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर कितनी बसों का संचालन हो रहा है? समय सारणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्रामीण मार्ग की स्थिति एवं उपलब्ध होने वाले यात्रीभार को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन विभाग से वाहन संचालन का अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर वाहन संचालन किया जाता है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों की अप/डाउन समय सारणी परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को निगम की बस सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा से घाटोली वाया चेचट के लिए बसों का संचालन

255. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा डिपो की कोटा से घाटोली वाया चेचट के लिए संचालित बस किन-किन कारणों से बन्द की गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के संबंध में स्थानीय विधायक एवं ग्रामीणों द्वारा प्रबन्धक रोडवेज कोटा को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुनः बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोटा से घाटोली वाया चेचट संचालित वाहन को कम यात्रीभार एवं आय प्रति कि.मी. प्राप्त होने के कारण संचालन बन्द कर दिया गया। संचालन अवधि में प्राप्त आय/ यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) स्थानीय विधायक एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य प्रबन्धक, कोटा को उक्त वाहन के संचालन के सम्बंध में लिखे गये पत्रों की प्रति परिशिष्ट 2 एवं 3 पर संलग्न है एवं निगम द्वारा माननीय विधायक महोदय को भिजवाये गये उत्तर की प्रति परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उक्त मार्ग पर निगम बस संचालित किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी में खेल स्टेडियम बनाने की कार्ययोजना

256. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

बीकानेर जिले के पंजीकृत बेरोजगार

257. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुमित गोदारा)

(1) जिला बीकानेर में 30 जनवरी, 2022 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं से सरकारी विभागों में कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो किस विभाग में व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बेरोजगारी भत्ते से वंचित बेरोजगारों को भी भत्ता दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला रोजगार कार्यालय बीकानेर में 30 जनवरी, 2022 तक 41,981 बेरोजगार पंजीकृत हैं। माह जनवरी, 2022 में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत इनमें से पात्र 3,305 युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है।

(2) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को सरकारी विभागों में योजना के नियमानुसार 4 घन्टे इन्टर्नशिप के दौरान आशार्थियों की योग्यतानुसार कार्य करवाया जा रहा है। विभागों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार स्नातक योग्यताधारी पात्र आवेदकों को ही भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में इस योजना में एक समय में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 2 लाख है। 31 जनवरी, 2022 को 1,97,717 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 31 जनवरी, 2022 तक शेष रहे 1,90,641 वेरिफाई किये जा चुके आवेदकों को भी 2 लाख लाभांवितों की अधिकतम सीमा तक अप्रूव कर भत्ता दिया जायेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बून्दी में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की कार्ययोजना

258. श्री अशोक डोगरा (बून्दी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बून्दी के आबादी क्षेत्र में निर्मित मकानों के ऊपर से हाईटेन्शन लाइनें कहां-कहां से गुजर रही हैं? क्या सरकार उक्त लाइनों को

(श्री अशोक डोगरा)

हटवाने अथवा भूमिगत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बून्दी के आबादी क्षेत्र में निर्मित मकानों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी एवं 11 केवी हाईटेंशन लाइनों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

विद्युत लाइनें विद्युत विनियम में निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार रिहायशी मकानों से निश्चित दूरी व ऊंचाई पर स्थापित की जाती है। तथापि विद्युत लाइनें खींचने के बाद शहरी आबादी क्षेत्र का विस्तार होने के कारण लाइनों के समीप व नीचें नियम विपरीत स्थानीय निवासियों द्वारा अनधिकृत निर्माण कर लिया जाता है।

उक्त आबादी क्षेत्रों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों को विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने खर्चे पर हटाने अथवा भूमिगत करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था मानव जीवन या सम्पत्ति के लिये घातक विद्युत लाइनों को हटवाना चाहते हैं तो लाइन को हटाने की तकमीना राशि की 50 प्रतिशत राशि आवेदक/संस्था द्वारा जमा करवाने तथा शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन कर लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रावधान है।

उक्त के अतिरिक्त बून्दी के आबादी क्षेत्र से 132 केवी जीएसएस बूंदी से 132 केवी जीएसएस हिण्डोली तक जाने वाली लाइन, 132 केवी जीएसएस बूंदी के सामने स्थित डाइट रोड, उन्दालियों की डूंगरी कालोनी में से गुजर रही है। उपरोक्त लाइन का निर्माण कार्य 04.01.1984 को पूर्ण होने के पश्चात् विद्युत प्रवाह सुनिश्चित कर दिया गया था। लाइन के निर्माण के पश्चात् कालोनी का निर्माण हुआ तथा लाइन के आसपास लोगों द्वारा मकान बना लिये गये, जिसके लिये निर्माणकर्ताओं को समय-समय पर निर्मित भवनों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्त लाइन को हटाने या भूमिगत करने हेतु कार्य सम्बन्धित आवेदनकर्ता द्वारा जमा राशि (Deposit Work Scheme) योजना के तहत तकनीकी रूप से साध्य होने पर किया जा सकता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

भिवाड़ी में विद्युत के वृत्त कार्यालय की स्थापना

259. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तिजारा के अधीन भिवाड़ी में विभाग का वृत्त कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। भिवाड़ी में वृत्त कार्यालय नवसृजित किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर एक वृत्त कार्यालय सृजित किये जाने बाबत मापदण्डों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुरूप अलवर जिले में वृत्त कार्यालय पहले से ही संचालित है। निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नवीन राजकीय महाविद्यालयों में संकाय

260. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने नये राजकीय महाविद्यालयों में कौन-कौन से विषय खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में 167 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये है, जिनका विषयवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 56 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है जो आगामी सत्र में संचालित होना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

1. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की सभी ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

2. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपीनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के दुलचासर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के सादासर व सोनियासर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. कोविड स्वास्थ्य सहायकों (CHA) एवं सभी चिकित्सा संविदाकर्मियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पूर्ण ट्रोमा सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के डूंगरगढ़ क्षेत्र के चिकित्सालयों में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

8. प्रदेश के प्रत्येक गांव में ए.एन.एम. तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशमी, भादसोड़ा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाश्मा, धमाना के नवीन भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र कपासन के समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

11. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में नवीन सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल कार्यालय में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

14. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित एम्बुलेंस ड्राइवर लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
15. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की जैतसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ट्रोमा सेंटर में आवश्यक उपकरण/ संसाधनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

18. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्षमता को 100 बैड तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. विधान सभा क्षेत्र भादरा के निनाण गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र भादरा के शेरड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. विधान सभा क्षेत्र भादरा के अजीतपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भरवाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

23. डूंगरपुर के हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में एक्स-रे व सी.टी. स्कैन की जांचों में पैसे वसूलने की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति एवं साफ-सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. डूंगरपुर मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों के भवनों में स्टाफ क्वार्टर्स होने के उपरान्त भी चिकित्सकों द्वारा रात्रि ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
26. डूंगरपुर मेडिकल कालेज व सामान्य अस्पताल में संविदा पर लगे कार्मिकों को समय पर वेतन मिले, इस हेतु RMRS में समायोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
27. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पाल देवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व मझोला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

28. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरीणी, पण्डावा, हिगलाड़, पाल, जोलर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र विहीन पंचायतों पर नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की पंचायत समिति पलोट तथा सुहागपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं खेरोट, मोखमुरा (घोडारसी) पानमोडी, गदिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

31. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

32. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

33. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने व सिन्दर, रूपावास तथा दुजाना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों, कानपुरा, भाचुन्दा, रोजड़ा, दौलपुरा, मोरडु, बापूनगर, बालराई, डिगाई, बाणियावास तथा सोनाईमांजी में भवन निर्माण करवाने व क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बांगड़ी, पोईना, अणगौर, वेनपुरा, केरला वड़ेरवास, काणदरा तथा साकदड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पाली से सिरोही के बीच में सांडेराव में NH - 62 पर ट्रोमा सेंटर मय डाक्टर्स व स्टाफ की स्वीकृति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

37. विधान सभा क्षेत्र आहोर के रजियावास, सुमेरगढ़ खेड़ा, वेड़िया आदि गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम पंचायत शंखवाली, ऊण, उम्मेदपुर, डुडसी तथा मेड़ा उपरला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भाद्राजून एवं बागरा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं गुड़ा बालोतान में जहां भवन बना हुआ है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद की नवीन स्वीकृति करवाने, ट्रोमा सेन्टर एवं ब्लड़ बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र आहोर के पावटा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के काणदर, पांवला कस्बा में खण्डहर हो चुके उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

42. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में समुचित चिकित्सा सुविधा एवं दवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में सफाईकर्मियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खमेरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. घाटोल में पडौली राठोड़ में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

47. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर को सैटेलाइट अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कारोई, बरड़ोद को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोकुदा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरिया में भवन निर्माण व अन्य कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

50. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के बान्दर सिंदरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई उपखण्ड पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला अस्पताल में संसाधनों की कमी एवं विशेषज्ञ डाक्टर्स की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में ग्राम पंचायत भामोलाव (अराई) के ग्राम डांग में, ग्राम पंचायत सिरोंज (अरांई) के ग्राम गेहलपुर में, ग्राम पंचायत कालावाड़ा (अरांई) के ग्राम धौलपुरिया में, ग्राम पंचायत कांकलवाड़ा (अरांई) के ग्राम गुन्दली में, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा (अरांई) के ग्राम गुजरवाड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढसूक (अराई), रिकावड़ा (किशनगढ़), आकोडिया (अरांई), खण्डाच (किशनगढ़), भोगादीत (अरांई), छोटा लाम्बा (अरांई), डबरेला (अरांई), बरना (किशनगढ़) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

55. विधान सभा क्षेत्र डग में चिकित्सकों, ए.एन.एम., कम्पाउण्डर आदि के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र डग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेंटर खोलने तथा 50 बैड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र डग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डग, भवानीमण्डी, चौमहला व सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम्बुलेंस के नाकारा होने के कारण मरीजों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र डग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित साफ-सफाई नहीं होने व पानी की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

59. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़ गांव में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ी सादड़ी को 75 बैडेड हास्पिटल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंगलवाड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

62. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र धानोल, पंसेरी, दांतलावास एवं मौखातरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालवाड़ा एवं बड़गांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीवाड़ा में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

66. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में ट्रोमा सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम अमरगढ़ व तलोदा सब सेंटर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर में ब्लड बैंक की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम भवानीपुरा, छाबड़िया, लालकाखेड़ा (NH पर) उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम सवाईपुर, लुहारीकलां, शक्करगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

71. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में एनयूआरएचएम के तहत निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्द्रवरदायी एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, नाका मदार में संविदा चिकित्सकों के पद समाप्त कर नियमित चिकित्सकों के पद सृजित कर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. अजमेर शहर के 100 बैडेड सैटेलाइट हास्पिटल, आदर्श नगर में स्टाफिंग पैटर्न के नियमानुसार पदों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. अजमेर शहर के सैटेलाइट हास्पिटल, आदर्श नगर के चिकित्सालय परिसर में स्थित रिक्त भू-भाग पर चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों के स्टॉफ क्वार्टर्स बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में बाईपास सर्जरी (हृदय) प्रारम्भ करने हेतु विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदस्थापन शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

76. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सैटेलाइट हास्पिटल में सीमेण्ट शैड का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन व चारदीवारी बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. प्रदेश में चिकित्सा विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत संविदा नर्सेज को नियमित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

81. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केन्द्र, जसाई एवं मूढ़ों की ढाणी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने एवं ग्राम सुजानवनगर, ईश्वरपुरा, तिरसिगड़ी इत्यादि स्थानों पर नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

83. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के रानीपुरा व मोजपुर में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावर, गेहुखेड़ी व सरड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

84. राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने में व्याप्त भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

85. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय कन्दोई हास्पिटल को महिला एवं शिशु हास्पिटल के रूप में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र नोहर के तहसील रावतसर के ग्राम पल्लू में चिकित्सालय भवन की चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांव कर्मसाना, लालखा की ढाणी व खरसण्डी में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र नोहर के 1000 से अधिक आबादी के गांवों/चकों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

90. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में बागोड़ा उपखण्ड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम पंचायत कावतरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

91. आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर (कोटा) में विशेषज्ञ सेवाएं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के चिकित्सा संस्थानों के कार्मिकों को अन्यत्र लगाने से चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के पद रिक्त होने के बावजूद अधिशेष कर अन्य जिलों में पदस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में चिकित्सा केन्द्रों के लिए भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

95. न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा में इमरजेंसी एवं ब्लड बैंक भवन के सामने जन सुरक्षा की दृष्टि से बने हुए द्वार को खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव):

96. बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन, रायसर, गडरारोड तथा शिव के चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्सेज के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के गांव नेगरड़ा व बिसकल या बालासर में तहसील चौहटन में रमजान की गफन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

98. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने, वंचित क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

99. विधान सभा क्षेत्र सोजत में शीघ्र ही ट्रोमा सेंटर शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

100. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की तहसील पिण्डवाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में ट्रोमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

102. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गोविन्दपुरा धाभाई, मंढ़ा भांकरी तथा कुहाड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराटनगर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

104. विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लदाना तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र दूदू में संचालित उप जिला अस्पताल व ब्लड बैंक दूदू, उप जिला अस्पताल, फागी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोराज व मौजमाबाद में नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील दूदू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साखून को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा तहसील फागी के मण्डौर एवं तहसील मौजमाबाद के गाड़ोला के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

108. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जनसंख्या को आधार मानते हुए चिकित्सा संस्थानों को खोले जाने तथा चिकित्सा सुविधा विहीन राजस्व गांव एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. बालोतरा जिला अस्पताल में जिला स्तरीय सुविधाएं यथा डायलेसिस आदि उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

113. प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

114. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतसर के ट्रोमा सेंटर को सुव्यवस्थित तरीके से चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन तथा विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों के मरम्मतीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

118. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

119. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने तथा गांवों में उप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों के मरम्मतीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

120. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान व सफाई के लिए स्वास्थ्यकर्मियों के रिक्त पदों को भरने तथा अस्पताल में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

121. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित चिकित्सालयों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों पर पदस्थापन के संबंध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित चिकित्सालयों के परिसर में चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ के लिए आवास गृहों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में स्थित उप जिला अस्पताल के भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के ग्राम लालगढ़, काशीपुरा, पाटन, भटेरी में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसखोह, बड़वा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांभरिया के लिए 108 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

126. न्यू मेडिकल चिकित्सालय, कोटा में नेत्र विभाग की सेवाएं प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. कोटा के न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में आयुर्वेद व होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी भी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सुभाष नगर, कोटा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. न्यू मेडिकल कालेज, कोटा में सुपर स्पेशियलिटी विंग में विशेषज्ञ चिकित्सक व चिकित्साकर्मी लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

130. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों द्वारा नियमित सेवा दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

131. प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

132. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रघुनाथगढ़ को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगड़मेव (अलवर) को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

135. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के चिकित्सालय (नगरपालिका क्षेत्र) को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बसाई नवाब चिकित्सालय को 100 बैडेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ चिकित्सालय को 100 बैडेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय को 300 बैडेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

140. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नाहटा जिला चिकित्सालय में भवन मरम्मत एवं सफाई मद में अधिक राशि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
141. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नाहटा जिला चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर सी.टी. स्कैन मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
142. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
143. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा नगर परिषद् क्षेत्र में चिन्हित 5 स्थानों पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
144. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कुड़ी, सिणली जागीर एवं कानाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

145. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
146. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
147. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
148. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में ट्रोमा सेंटर खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

149. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के अस्पतालों में सफाई व्यवस्था दुरस्त कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
150. प्रदेश के अस्पतालों में संविदाकर्मियों की समस्याओं के निराकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

151. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के गहणकर, शाहबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा गोठड़ा, हिंगवाहेड़ा, थड़ा एवं ग्वालदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

152. पाली जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मृतक आश्रित को एस.बी. रिट संख्या 532/97 दिनांक 16/11/2000 का NO APPEAL प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर विधवा आश्रित को पेंशन का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कोविड महामारी के दौरान कोविड से मरने वाले लोगों को अभी तक आर्थिक सहायता एवं कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण में ब्लड बैंक शुरू नहीं करने एवं भामाशाहों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी हीमोडायलेसिस मशीन की सुविधा शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण व निमाज में रिक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति एवं सभी चिकित्सा केन्द्रों पर ए.एन.एम./जी.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनन्दपुर कालू व लाम्बिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एवं सेन्दड़ा, देवरिया व कलालिया उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

157. विधान सभा क्षेत्र नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्राम गड़ी मेवात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुलपाड़ा को

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

160. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत भवन मेडिकल कालेज चूरू के निर्माण सहित अन्य कार्य अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. चूरू जिला मुख्यालय स्थित डेडराज भरतिया चिकित्सालय सहित उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व सब सेन्टर पर शौचालय नहीं होने व उनकी बदहाली के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र चूरू के जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पूर्व में निर्मित भवनों में चिकित्सालय स्थानान्तरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. मेडिकल कालेज चूरू के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर द्वारा जिला मुख्य चिकित्सालय में आपातकालीन ड्यूटी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

165. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एनेस्थिसिया एवं रेडियोलोजिस्ट के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

166. विधान सभा क्षेत्र मावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मावली व खेमली के पेथौलोजी लेब में सोनोग्राफी व डायलिसिस की सुविधा शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में ट्रोमा सेन्टर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र मावली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घासा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र मावली के उपखण्ड मुख्यालय, मावली पर उप जिला चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र मावली के उपखण्ड मुख्यालय मावली पर आपात चिकित्सा इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

171. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छीपाबड़ौद एवं ग्राम पंचायत झनझनी, मौरवमपुरा व बजारी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छबड़ा व छीपाबड़ौद कस्बे में नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छबड़ा व छीपाबड़ौद में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

174. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला विशेषज्ञ चिकित्सक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. मेडिकल कालेज, कोटा में घोषणानुसार बैडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करवर को पूर्ण व्यवस्था के साथ संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

178. विधान सभा क्षेत्र निवाई में उप स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी एवं ट्रोमा अस्पताल के संचालन एवं भवन हेतु राशि स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

179. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के इड़ाणा, खरका, गुडेल, खैराड़, डालटोड़ा, पीलादर, केवड़ा, नठारा, बलुआ एवं अदवास उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा जावद, देवपुरा, उपरदा, बडगांव,

चाववड, बड़ावली बरोड़ा, पलोदड़ा, सगतड़ा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. विधान सभ क्षेत्र सलूम्बर के जिला हास्पिटल सलूम्बर में सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी, सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. एवं कार्डियोग्राफी की व्यवस्था करने के साथ बैड संख्या 200 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी चिकित्सालयों में समुचित सफाई की व्यवस्था व सफाईकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. राजकीय जिला हास्पिटल, सलूम्बर व सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला हास्पिटल, सलूम्बर में ब्लड बैंक खोलने तथा सोनोग्राफी, एक्सरे मशीनों को ठीक करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

184. विधान सभा क्षेत्र पिलानी की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

185. प्रदेश के चिकित्सालयों में मानवीय संसाधनों में वृद्धि एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

186. विधान सभा क्षेत्र लूणी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणी में मातृ एवं शिशु रोग कल्याण केन्द्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

187. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में आयुष चिकित्सा भवन निर्माण के लिए बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. फलौदी जिला अस्पताल में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. जिला अस्पताल फलौदी में पीएमओ को वित्तीय एवं अन्य अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के वेलनसर में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

192. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नयन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में हाईवे पर स्थित बौंली पर ट्रोमा अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बौंली तथा मित्रपुरा के लिए भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

196. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र, नीमला, बूज, डांगरवाडा, फूटोलाव, नेवर, बिलोद, माथासूला एवं धामस्या को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत सायपुर, देवीतला, खरड, मानोता, श्रीनगर, सरजोली, बाडियावाला, नामावाला, हरिकिशनपुरा तथा छापर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा जमवारामगढ़ की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायतसर तथा ताला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर):

200. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम बायला व आसपालसर बड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम दुलरासर, बुकनसर बड़ा, हामूसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम राजास, छाजूसर, नैयासर, कामासर, कालूसर, चम्पावासी, गोपालपुरिया, बाढा की ढाणी में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा सरदारशहर के ग्राम पुनुसर, उदासर चारणान, बणियासर, ढाणी रायकान, मांगासर, ढाणी ईसरदास, पनपालिया, हालासर, खुण्डिया तथा राजासर चोर्डिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला अस्पताल में सभी संवर्गों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

205. विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत हिंगोटा, हुडला, बालाहेडी, सामिलपुर, नाहिड़ा एवं पारकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र महवा की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पावटा तथा लोटवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

207. नोखा तहसील में पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर एक अतिरिक्त ब्लाक सीएमएचओ कार्यालय खोलने व जिला अस्पताल नोखा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांचू, जसरासर, कक्कू में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. नोखा तहसील के सब सेंटर भादला, भामटसर, जयसिंहदेसर मगरा,

किसनासर, बिलनियासर व सूरपुरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. नोखा तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकाम, जांगलू को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. नोखा में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर, बीएसी नर्सिंग कालेज तथा डीएमएलटी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. प्रदेश में नर्स ग्रेड द्वितीय व एएनएम की नई सीधी भर्ती निकालते हुए संविदा एवं प्लेसमेंट नर्सेज को 10, 20, 30 बोनस अंक व मैरिट बेस पर नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

212. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त स्टाफ व सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के प्रत्येक वार्डों में जनता क्लीनिक नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सैटेलाइट हास्पिटल को खुली जेल की खाली पड़ी जमीन में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

216. विधान सभा क्षेत्र नदबई के सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपखण्ड अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र नदबई में ग्राम पंचायत बरीघा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदनपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम पंचायत बारहमाफी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमर सिंह (बयाना):

220. विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय चिकित्सालय को जिला स्तरीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. राजकीय चिकित्सालय, बयाना में ट्रोमा सेंटर का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र बयाना के उपखण्ड रूपवास के राजकीय चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्ध्ता के संबंध में चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र बयाना को रूदावल राजकीय चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन लगाने तथा महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

224. प्रदेश में सभी स्तर के चिकित्सालयों एवं सेंटर्स में रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. भीलवाड़ा के शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रसव केन्द्र पर मोबाइल यूनिट, 108 एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. भीलवाड़ा जिले के चिकित्सा केन्द्रों पर प्रयोगशालाएं, ड्रग स्टोर, लेबर रूम आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. भीलवाड़ा जिले के सैटेलाइट हास्पिटल शाहपुरा में आवश्यक निर्माण कार्य के साथ चिकित्सकों व कार्मिकों की शीघ्र नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों की जनसंख्या के अनुरूप उप प्राथमिक, सामुदायिक इत्यादि स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

229. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा (टोंक) में 108 व 104 एम्बुलेन्स वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही नर्सिंग कर्मचारी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के रैफरल चिकित्सा संस्थानों द्वारा 108 व

104 एम्बुलेन्स से मरीजों को टोंक स्थान पर सीधे जयपुर रैफर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडारायसिंह, मालपुरा में विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित क्षेत्र के सभी चिकित्सा संस्थानों के सभी कर्मियों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के स्टेट हाईवे SH-12 एवं SH-37A पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने व मालपुरा में ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा व टोडारायसिंह के नवीन भवनों का निर्माण करवाने तथा बैडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

234. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में जिला अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की अलग से भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी अस्पतालों में आवश्यक उपकरणों की पूर्ति जल्दी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी अस्पतालों में खाली पड़े नर्सिंग स्टाफ, डाक्टर आदि पदों की भर्ती शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

239. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पीसांगन ब्लाक के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. नसीराबाद चिकित्सालय में नेत्र आपरेशन थियेटर शुरू करवाकर चिकित्सकों की नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. नसीराबाद उप जिला चिकित्सालय में आई.सी.यू. यूनिट की शुरुआत के लिए टेक्नीकल यूनिट में टेक्नीशियन व आपरेटर की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. नसीराबाद राजकीय चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के मांगलियावास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

244. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खींवसर उपखण्ड व पंचायत समिति मुख्यालय पर BCMO कार्यालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भवन रहित तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों से वंचित राजस्व गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पाचोडी तथा पांचला सिहा में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्डानुसार भौतिक व मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में खरनाल व करनु में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने एवं संखवास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

249. आर.के. जिला चिकित्सालय, राजसमन्द में चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों के बड़ी संख्या में विभिन्न पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में राजकीय चिकित्सालयों, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

251. आर.के. जिला चिकित्सालय, राजसमन्द में गहन हृदय रोग चिकित्सा इकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के आर.के. जिला चिकित्सालय में जल प्रदाय सुविधाओं के विस्तार कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में औषधालयों, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं होने एवं अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक (खण्डार):

254. विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ग्राम पंचायत मुख्यालय सारसोद, आदलवाड़ा कलां, तसावडा, खाजना डूंगर, पाचोंलास, मिनियाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम जुवाड़ (मुई), ग्राम कावड़ (जोला), डूंगरी एवं खिदरपुर जादौन पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भगवलगढ़ में नवीन 108 एम्बुलेंस शीघ्र आबंटन पर चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चौथ का बरवाड़ा में आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि शीघ्र आबंटन करने एवं भवन निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौथ का बरवाड़ा एवं खण्डार को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

258. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावला का पट्टा जारी नहीं होने एवं नये भवन का बजट आबंटन होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ़ को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में देय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की नियमित सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 365 RD (2KLD) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र 22 RJD को क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

263. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के जखराना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) के नव क्रमोन्नत जिला अस्पताल में जिला स्तरीय सुविधाएं तथा स्टाफ का पदस्थापन शीघ्र कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नव क्रमोन्नत माजरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में समस्त सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के चिकित्सा केन्द्रों में समस्त श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

267. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

268. जयपुर शहर के सवाई मानसिंह हास्पिटल पर बढ़ रहे मरीजों के दबाव को कम करने के लिए शहर के R.U.H.S हास्पिटल, कावंटिया हास्पिटल, जयपुरिया तथा गणगौरी हास्पिटल में सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

269. जयपुर के सवाई मानसिंह हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज के मध्य अण्डरपास बनाए जाने के संबंध में विभागीय पहल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

270. प्रदेश में चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा में रिक्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271. प्रदेश में पैरा मेडिकल के ई.सी.जी. टेक्नीशियन संवर्ग के शेष रहे

रिक्त पद एवं नवीन पद स्वीकृत कर भर्ती निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

272. प्रदेश में चिकित्सा विभाग को विधायक कोष से दी जाने वाली एम्बुलेंसों की संचालन व्यवस्था तथा राजस्थान की सभी एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेण्डर की सुनिश्चितता के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

273. प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

274. प्रदेश में उपलब्ध समस्त बेरोजगार एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को राजकीय सेवा में नियोजित कर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाझड़ व जेजूसर को तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र, डूमरा व कसेरू को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

276. प्रदेश में प्रत्येक पंचायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

277. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सभी सुविधाएं व एम्बुलेंस तथा सिंघाना व बुहाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बैडों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सभी अस्पतालों में जांच उपकरण व टेक्निशियन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279. मेडिकल कालेज, झुंझुनूं का निर्माण अतिशीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सिंघाना, कुहाना (सूरजगढ़) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैड बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

282. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ततारपुर व शाहजहांपुर स्वास्थ्य केन्द्रों में नये ट्रोमा सेन्टर खोले जाने व राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों की कमी से हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

283. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर को 50 बैड से 100 बैड तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

285. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. व जी.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

286. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के प्राइवेट स्वास्थ्य केन्द्रों में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लागू न होने व आमजन को हो रही परेशानी एवं राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

287. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नये भवन का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

288. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीविजयनगर तथा रायसिंहनगर में अल्ट्रा साउण्ड मशीन लगाने, उसके संचालन तथा तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

289. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीविजयनगर में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

290. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

श्रीविजयनगर में चिकित्सकों, सर्जन, एम.डी., हड्डी रोग व शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में ट्रोमा सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

292. सोजत (पाली) के मगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुडाकलां में उपजिला चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

293. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर चिकित्सालय को शहरी क्षेत्र से हटाकर नजदीक ग्रामीण क्षेत्र में स्थान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में चिकित्सा हेतु विशेष प्रावधान कर 100 बैड का चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

295. विधान सभा क्षेत्र सोजत उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा सेन्टर का निर्माण अतिशीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

296. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर उचित साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

297. जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में न्यूरो सर्जन, कार्डियोलोजिस्ट एवं लिवर से संबंधित रोग विशेषज्ञ पदस्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

298. जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में उच्च स्तरीय दंत चिकित्सक, दंत सर्जन व दंत चिकित्सा की आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

299. जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में एमआरआई जांच मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

300. जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में कैथ लैब की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

301. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कोविड काल में घोषित एवं विधायक फण्ड से जारी स्वीकृति के उपरांत ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

302. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृतशुदा पदों के रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

303. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर एवं मण्डार क्षेत्र की 108 कण्डम एम्बुलेंस के नवीनीकरण एवं नियमित संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

304. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के दूर-दराज इलाकों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

305. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की आबूरोड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला अस्पताल में क्रमोन्नति एवं गांधी नगर में एक अतिरिक्त नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

306. सिरोही जिले में कार्यरत चिकित्सकों व विभाग के अन्य कार्मिकों को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक न हटाने के मुख्य सचिव के आदेश की चिकित्सा विभाग द्वारा पालना न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

307. सिरोही व शिवगंज तहसील के भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु आवश्यक राशि की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

308. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावाल व सिलदर के नवीन भवन के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के जिला चिकित्सालय, शिवगंज के नवीन भवन के निर्माण हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

310. आबूरोड के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में विभाग द्वारा 50 बिस्तर

क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की व्यवस्था न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

311. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के राजकीय उप जिला चिकित्सालय को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सड्डू बड़ी को क्रमोन्नत करने एवं क्षेत्र में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

312. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बावड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेंटर खोलने, भोपालगढ़, आसोप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ लगाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालावां कलां एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बुड़किया साथिन को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

313. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में परानियों, कस्बा थाना तथा रेलावन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

314. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नवीन पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

315. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

316. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में लैब टैक्नीशियनों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

317. आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर के सामने संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों के धरने को समाप्त कराते हुए प्रदेश में कार्यरत समस्त संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

318. अजमेर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में हृदयरोग पीड़ित मरीजों के लिए स्थाई बैडों एवं ट्रोलियों की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

319. अजमेर में करोड़ों की लागत से ट्रोमा सेंटर बनाए जाने संबंधी पिछले

बजट में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा को तत्काल अमलीजामा पहनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

320. अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ठेका सफाई कर्मचारियों का सम्पूर्ण वेतन एवं पीएफ का भुगतान शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

321. प्रदेश के समस्त आयुर्वेद चिकित्सालयों में योग प्रशिक्षक (1 महिला व 1 पुरुष) लगाये जाने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

322. विधान सभा क्षेत्र डग की ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

323. उप जिला चिकित्सालय अटरू का भवन जीर्ण-शीर्ण होने एवं वर्षा का पानी भरने के कारण नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

324. बारां जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से निकले अपशिष्ट (कचरे) के निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

325. बारां जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुन्जेड को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

326. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की नगर परिषद् बारां की पुरानी आबादी श्रीजी चौक में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने से नई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

327. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नयी 5 ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

328. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में जावली व सांखरी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

329. आर.जी.एच.एस. योजना में निजी अस्पतालों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण एवं अंकेक्षण व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

330. आर.जी.एच.एस. योजनान्तर्गत एसव्यासा बैंगलुरू (SVYASA BENGLURU) को योग थैरेपी और नैचुरोपैथी केन्द्र के रूप में सूचीबद्ध करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

331. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, मसुरिया को पंचकर्म केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

332. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के जिला अस्पताल, प्रताप नगर एवं सैटेलाइट अस्पताल, चो.हा. बोर्ड में चिकित्सालय स्तर के मानक अनुरूप पदस्थापन, जांच सुविधाएं एवं अन्य समस्त संसाधन उपलब्ध करवाकर संस्थागत प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

333. प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में ट्रोमा सेंटर और आपातकालीन इकाइयों को रेजिडेंट्स के भरोसे छोड़ने की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की ड्यूटी पर रहने की अनिवार्यता सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

334. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के बधाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

335. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरैना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भैंसलाना के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

336. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा तथा किशनगढ़ रेनवाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ हेतु आवासीय क्वार्टर्स निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

337. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के नोसाल (ग्राम पंचायत राजपुरा नोसाल) के उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

338. प्रदेश में नर्स ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों को नई भर्ती कराकर भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

339. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने तथा नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

340. श्रीगंगानगर शहर के जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा केन्द्रों में डाक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

341. श्रीगंगानगर शहर की कुंज विहार प्रथम आवासीय योजना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342. श्रीगंगानगर शहर की आबादी विस्तार को देखते हुए पुराने चिकित्सालय भवन में भी चिकित्सा सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

343. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जनता क्लीनिक खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

344. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव प्रेमनगर व ढाकावाली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

345. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय, रतनगढ़ में बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार सीटी स्कैन व एमआरआई मशीन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

346. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजलदेसर में सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

347. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव गौरीसर, खारिया कनिराम, परसनेऊ, मैणासर व रणधीसर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

348. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर को उप जिला अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

349. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जालसू एवं आमेर को विधायक कोष से उपलब्ध कराई गई एंबुलेंस के प्रभावी

संचालन हेतु नियमित रूप से वाहन चालक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

350. विधान सभा क्षेत्र आमेर के चिकित्सा केन्द्रों के जर्जर भवनों की शीघ्र मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

351. विधान सभा क्षेत्र आमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजदा के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलदपुरा के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

352. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर एवं आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जालसू में ब्लड बैंक की स्थापना एवं नियमित ब्लड उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

353. डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोचरी, गंदवा व करावाड़ा का भवन नहीं होने के कारण डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ के नहीं होने की वजह से आम नागरिक को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

354. डूंगरपुर जिले में सिलिकोसिस व कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षणग्रस्त मरीजों की समय-समय पर शिविर लगाकर जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

355. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय में तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र, सांसरपुर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

356. डूंगरपुर जिले के राजकीय अस्पतालों में सफाईकर्मियों को ठेकेदार द्वारा सफाई सामग्री व उचित भुगतान नहीं दिये जाने की वजह से जिले के सभी राजकीय अस्पतालों में सफाई व्यवस्था गड़बड़ाने व इसमें जिले के अधिकारियों की मिलीभगत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

357. डूंगरपुर जिले के राजकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क जांच नहीं होने के कारण गरीब आदिवासी मरीजों से निजी लैब द्वारा जांच हेतु मोटी रकम वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

358. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना पर चर्चा के लिए।

359. प्रदेश के अस्पतालों में उचित संसाधन नहीं होने से उतपन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

360. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

361. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पंचायत मुख्यालय लाम्बा जाटान, जारोड़ाकलां व बडायली के उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता रोड व जसनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

362. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता शहर में पुराना अस्पताल भवन में सिटी डिस्पेंसरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

363. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

364. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़ता सिटी को 100 बैड (पीएमओ) में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

365. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता सिटी में स्वीकृत ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 13 - आबकारी पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-13 मुख्य शीर्षक आबकारी के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

1. प्रदेश में शराब की दुकानें नियत समय पर बंद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

2. प्रदेश में नकली व जहरीली शराब बनाने वालों पर पूर्ण पाबन्दी लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।
3. प्रदेश में अवैध शराब बनाने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश में शराब की दुकानें रात्रि आठ बजे के बाद भी खुली रहने व शराब की मनमानी कीमत वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश में अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों को तुरन्त बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश में शराब बंदी लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

7. प्रदेश में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की गारण्टी राशि कम करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

8. प्रदेश में आदिवासियों को देशी शराब रखे जाने का अधिकार दिये जाने तथा आबकारी विभाग द्वारा गरीब आदिवासियों को परेशान नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

9. प्रतापगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों को अनावश्यक रूप से परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

10. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में संचालित आबकारी थाने के लिए जमीन आबंटन करवाने व भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

11. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आहोर उपखण्ड पर आबकारी निरीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. जालौर जिले में बिकने वाली शराब में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
13. विधान सभा क्षेत्र आहोर में चल रहे अवैध शराब के ठेकों को बंद करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

14. विधान सभा क्षेत्र डग में अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
15. प्रदेश में नई आबकारी नीति से सरकार को मिलने वाले राजस्व में कमी होने तथा संवेदकों को भारी नुकसान होने पर चर्चा के लिए।
16. प्रदेश में शराब बंदी लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

17. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा पर आबकारी निरीक्षक का पद सृजित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर):

18. प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर आबकारी की दुकानें खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
19. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त संचालित अवैध दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत विजयगढ़ में शराब की दुकानें बंद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
21. प्रदेश में चल रही अवैध शराब की दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. प्रदेश में अवैध शराब (नकली शराब) पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिए उपखण्ड स्तर पर जांच लैबोरेट्री खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

23. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के नगरपालिका क्षेत्र अकलेरा में संचालित शराब की दुकानों को नियमानुसार समय पर खोलने व बंद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में संचालित आबकारी दुकानों का समय निर्धारण करने, शराब को अंकित मूल्य पर विक्रय करने एवं धार्मिक स्थलों से हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

25. प्रदेश में दलित बस्तियों, स्कूलों एवं मौहल्लों के आस-पास शराब की दुकानें नहीं खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

26. भीनमाल एवं जालौर जिले में संचालित अवैध शराब के ठेके बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

27. घाटोल आबकारी थाने में सी.आई. स्तर का अधिकारी पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
28. आबकारी थाना, घाटोल को बोलेरो गाड़ी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. घाटोल आबकारी थाने में पर्याप्त स्टाफ लगाने व अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

30. कोटा जिले के क्षेत्र इटावा में अवैध शराब की दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग का वृत्त कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
31. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में शराब की दुकानों पर मूल्य सूची अंकित नहीं होने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
32. प्रदेश में शराब की दुकानों की लोकेशन गैर विवादित स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. कोटा जिले में निर्धारित लोकेशन के अतिरिक्त संचालित अवैध शराब की दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्थित शराब की समस्त दुकानों का वर्ष 2021-2022 के दौरान नियमित निरीक्षण किये जाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता एवं लापरवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

35. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में आबकारी थाना खुलवाने एवं शराब की दुकानों के आबंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

36. आबकारी विभाग द्वारा दुकान आबंटित करते समय लोकेशन बनाये जाने पर आबादी क्षेत्र को दृष्टिगत नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए

37. प्रदेश में सभी अंग्रेजी शराब विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली शराब की दुकानों की लोकेशन में स्थानीय संस्था यथा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. प्रदेश में अवैध शराब उत्पादन को रोकने के लिए विशेष दलों के गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

40. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों के अतिरिक्त संचालित अवैध दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सुबह दस बजे से पहले एवं रात्रि आठ बजे के बाद भी शराब की दुकानों पर बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के धार्मिक स्थानों, स्कूलों व अन्य सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित शराब की दुकानों को अन्यत्र दूर स्थानों पर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

43. बाड़मेर जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोकथाम लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

44. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में संचालित शराब की अवैध दुकानों को बंद कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
45. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में लाइसेन्सधारी शराब की दुकानों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
46. प्रदेश में शराब माफियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में हथकड़ देशी शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

48. जिला अलवर में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

49. प्रदेश में मदिरा की दुकानों को देवस्थान एवं विद्यालयों से दूर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
50. प्रदेश में अवैध रूप से बिक रही शराब को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

51. आबकारी विभाग में बनाई जा रही नीति के संबंध में चर्चा के लिए।
52. आबकारी विभाग में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

53. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में आबकारी विभाग के नये भवन की स्वीकृति के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
54. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित अवैध शराब की दुकानों, निर्धारित समय पश्चात् शराब की बिक्री व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा आबंटित शराब दुकानों को स्कूलों, पंचायतों, मंदिरों एवं गौशालाओं सहित अन्य सार्वजनिक/धार्मिक स्थानों से हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

56. राजस्थान में शराब बंदी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

57. ब्यावर क्षेत्र की स्वीकृत शराब की दुकानों के अलावा आबकारी एवं पुलिस की मिलीभगत से संचालित की जा रही अवैध शराब की दुकानों को बंद कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

58. कोटा व बून्दी में स्कूलों व मंदिरों के नजदीक शराब की दुकानों का आबंटन नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में संचालित अवैध शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर लेकर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

60. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित हथकड़ शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शराब की दुकानों से अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62. प्रदेश में संचालित शराब के ठेकों को मंदिरों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, राजकीय कार्यालयों व बस्तियों के पास एवं भीड़-भाड़ आदि स्थानों से दूर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में शराब की दुकानों की लोकेशन स्वीकृति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने वाले आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

64. राज्य की आबकारी नीति में कृषि भूमि पर व आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें न खोलने का भी नियम शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

65. नई आबकारी नीति में देशी व विदेशी मदिरा का निर्गम आर.एस.जी.एस.एम. से लेकर प्राइवेट सप्लायर्स को दिये जाने से सरकार को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. अजमेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 36, 37, 38, 40, 41 व 42 की आवासीय कालोनियों में स्थित शराब की दुकानें देर रात तक खुले रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

67. प्रदेश में शराब ठेकेदारों द्वारा शराब की अधिकृत एक दुकान के लाइसेन्स के आधार पर अन्य कई स्थानों पर अवैध दुकानें संचालित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

68. अजमेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 48 के कनुआ बाबा मंदिर, वार्ड 27 के रोजमेल प्रेस रोड, वार्ड 25 के रामबाग चौराहे एवं वार्ड 23 के सांसी बस्ती में हथकड़ अवैध शराब पुलिस की मिलीभगत से वर्षों से बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वाजिब अली (नगर):

69. विधान सभा क्षेत्र नगर के सभी गांवों को आबकारी थाना सीकरी में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

70. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में धार्मिक स्थानों, विद्यालयों के पास, हाईवे से निर्धारित दूरी से कम दूरी पर एवं गांवों में अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने तथा अवैध शराब बिक्री के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

72. सवाई माधोपुर जिले में शराब के ठेकों की अवैध रूप से संचालित ब्रांचों को बंद करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

73. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों को बंद करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. जमवारामगढ़ में आबकारी निरीक्षक स्तर का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

75. जयपुर शहर में नालों की जमीन, अवासीय बिल्डिंग, कियोस्क व कच्चे अस्थायी शैड (स्ट्रक्चर) आदि स्थानों पर नियमों के विरुद्ध मापदण्ड पूरे किये बिना अधिकारियों की मिलीभगत से शराब बेचने एवं शराब की दुकानों की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
76. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में आबकारी विभाग की मिलीभगत से देशी व कच्ची शराब/दारू की खुलेआम हो रही बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
77. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद भी शराब की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
78. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में आबकारी विभाग की जानकारी व मिलीभगत से नकली शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

79. प्रदेश में देशी व विदेशी मदिरा की प्रत्येक ब्राण्ड की दरों को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
80. प्रदेश में शराब बंदी नीति के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
81. भीलवाड़ा जिले में अवैध व नकली शराब की रोकथाम के लिए लगातार पुख्ता निगरानी एवं कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
82. भीलवाड़ा जिले में देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें खोलने में नियमों की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
83. प्रदेश में देशी व विदेशी शराब के अन्तर्देशीय एवं अन्तरराष्ट्रीय तस्करों और माफियाओं पर पुख्ता निगरानी रखने और सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

84. प्रदेश में बढ़ते अवैध रूप से नशीले कारोबार को रोकने के लिए विशेष कठोर कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
85. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
86. प्रदेश में अवैध रूप से बिक रही नकली शराब को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में शराब व अन्य नशे की आदत छुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों को बंद करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

89. प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा संवेदकों को समय पर लिखित में विभागीय सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90. प्रदेश में नई आबकारी नीति के लागू होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 व 2021-2022 के लिए शराब व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के संबंध में चर्चा के लिए।

91. प्रदेश में आबकारी शुल्क बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. गंगानगर शुगर मिल से खुदरा व्यापार आर.एस.बी.सी.एल. को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. प्रदेश के आबकारी संवेदकों को आर.एम.एल. मदिरा का उठाव किये जाने के लिए जबरन बाध्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

94. प्रदेश में मदिरा के अवैध विक्रय एवं तस्करी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. प्रदेश में मदिरा में अपमिश्रण एवं जहरीली शराब से जनहानि के बढ़ते प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में मंदिरों एवं विद्यालयों के नजदीक चल रही शराब की दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. उदयपुर संभाग में ड्रग्स सेवन के बढ़ रहे प्रकरणों एवं इस पर नियंत्रण करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में डोडा चूरा नष्ट करने में विभागीय विफलता और राज्य में डोडा चूरा की खुले रूप से बिक्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

99. घड़साना उपखण्ड जिला श्रीगंगानगर में नया आबकारी थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. राज्य में मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश तथा नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग की जांच चौकियां स्थापित करने तथा नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. श्रीगंगानगर जिले की शराब की दुकानों में निर्धारित समय सीमा के पश्चात् भी बिक्री किये जाने की नियमित जांच नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में आबकारी विभाग का स्वयं का कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन के प्रभावी रोकथाम हेतु समुचित उपाय कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

104. प्रदेश में सरकार द्वारा रात्रि 8.00 बजे पश्चात् शराब की दुकानों को बंद किये जाने के आदेश के बावजूद भी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्धारित समय पश्चात् भी दुकानें खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

105. सरकार द्वारा जारी आबकारी नीति में शराब दुखान्तिका जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से कार्यवाही करने के आदेश के बावजूद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

106. प्रदेश में अत्यधिक अवैध शराब की दुकानों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर सरकार द्वारा घोषित आदर्श गांव में की गई नशामुक्ति की शर्त की आबकारी विभाग द्वारा अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

108. प्रदेश में मिलावटी शराब की बिक्री पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

109. अलवर जिले के भिवाड़ी में आबकारी विभाग द्वारा किराये पर ली गई गोदाम की जमीन को खाली नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. प्रदेश में शराब की दुकानें स्टेट व नेशनल हाईवे के नजदीक होने से आये दिन हाईवे पर घटित हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमर सिंह (बयाना):

111. विधान सभा क्षेत्र बयाना में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
112. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में बन रही अवैध शराब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
113. विधान सभा क्षेत्र बयाना में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
114. विधान सभा क्षेत्र बयाना में शराब विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

115. प्रदेश में देशी हथकड़ शराब पर रोक लगाने व हथकड़ शराब निकालने के लिए पैरामीटर तय करके लाइसेन्स दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
116. प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा आबंटित की गई दुकानों पर ही शराब की बिक्री किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
117. प्रदेश में विद्यालय, मंदिर, गुरुद्वारा व आबादी के बीचों-बीच शराब की दुकानें संचालित नहीं करने एवं गांव से कम से कम 1/2 किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

118. रायपुर उप खण्ड मुख्यालय पर आबकारी थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
119. विधान सभा क्षेत्र सोजत में अवैध शराब की बिक्री बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

120. चित्तौड़गढ़ आबकारी थाना के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
121. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में शराब विक्रताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

122. नोखा में चल रहे आबकारी विभाग के वृत निरीक्षक कार्यालय के लिए नगरपालिका नोखा परिक्षेत्र में जमीन आबंटन व भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. प्रदेश में मिलावटी शराब पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

124. सिरोही जिले में आवासीय बस्तियों में शराब की अवैध दुकानें संचालित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

125. सिरोही जिले में नेशनल व स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों की गलत लोकेशन स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

126. सिरोही में गोइली चौराहे से शिवगंज रोड एवं अनादरा चौराहे से बारीघाटे तक शराब की दुकानों की गलत लोकेशन स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

127. सिरोही जिले में शराब विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. गंगानगर शुगर मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

129. सुजानगढ़ में संचालित अवैध शराब की दुकानों को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

130. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद व किशनगंज में आबकारी निरीक्षक स्तर का थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में देशी कच्ची शराब की अवैध बिक्री रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विदेशी मदिरा का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

134. प्रदेश में अवैध शराब बिक्री वाली दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. अजमेर सहित पूरे प्रदेश में एम.आर.पी. से अधिक कीमतों पर शराब बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने एवं संबंधित शराब विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. प्रदेश में चल रहे अवैध हथकड़ शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. प्रदेश में आबकारी टीम पर शराब माफियों द्वारा किये जाने वाले हमलों पर अंकुश लगाने एवं इस संबंध में कठोर नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. प्रदेश में धार्मिक स्थलों एवं विद्यालयों के पास (200 मीटर से कम दूरी) अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

139. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शराब की दुकानें अनुसूचित जाति की बस्तियों से दूर संचालित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के ग्रामों में अवैध रूप से संचालित शराब की दुकानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. नगरपालिका अटरू की हरिजन बस्ती के मध्य में स्थित शराब के गोदाम पर चौबीस घण्टे शराब की ब्रिकी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

142. कठूमर में आबकारी कार्यालय खोलकर इसके अधीन कठूमर क्षेत्र की 32 एवं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की 3 शराब की दुकानें संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

143. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. प्रदेश में मद्यपान के विरुद्ध जनजागृति के समुचित प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. प्रदेश में आबकारी विभाग में लम्बित अंकेक्षण, भ्रष्टाचार एवं गबन प्रकरणों को प्राथमिकतापूर्वक निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश में अवैध हुक्का बार के नाम चल रहे घातक मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए अभियानपूर्वक एवं समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. प्रदेश में एक दुकान के अनुज्ञा पत्र से शराब की अनेक दुकानें संचालित करने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने और समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

148. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में शराब तस्करी में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों तथा आबकारी विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में गत 5 वर्षों के दौरान शराब तस्करी में पकड़े गये वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अवैध शराब की दुकानों को बंद करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पकड़े गये शराब तस्करों, संरक्षण देने वाले पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के गुजरात बोर्डर से लगने वाले आबकारी थाना क्षेत्रों से हो रही शराब तस्करी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

153. विधान सभा क्षेत्र आमेर में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक पार्कों के आस-पास देशी-विदेशी शराब की दुकानों को बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. प्रदेश में देशी मदिरा/आर.एम.एल. मदिरा तथा अंग्रेजी मदिरा की थोक बिक्री का एकाधिकार राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स को दिये जाने हेतु आबकारी नीति में आवश्यक संशोधन करने से राज्य सरकार के राजस्व की बढ़ोतरी हो सके, के संबंध में चर्चा के लिए।

155. प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच एवं इसकी प्रभावी रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. सीमावर्ती राज्यों से शराब माफियाओं द्वारा प्रदेश में की जा रही शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इससे राज्य के राजस्व में हो रही हानि के संबंध में चर्चा के लिए।

157. राज्य में अवैध शराब की बिक्री के कारण राजस्व में हो रही हानि तथा अवैध शराब की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

158. डूंगरपुर जिले में राजकीय विद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों के पास शराब की दुकानें खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के आदिवासी बहुल क्षेत्र में पारम्परिक घरेलू महुआ का पेय पदार्थ बनाकर घरेलू उपयोग पर आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम में कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. डूंगरपुर जिले के सरकारी शराब के ठेकों पर मूल्य सूची नहीं लगाने व निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. डूंगरपुर जिले में आबंटित शराब की दुकानों द्वारा पोइन्ट नाम से अन्य कई स्थानों पर अवैध दुकानें संचालित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

162. प्रदेश में हथकड़ शराब बनाने वाली बावरी जाति को इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु नवजीवन योजना में जोड़कर लाभान्वित करने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में शराब की दुकानें आबादी क्षेत्र, विद्यालय व सार्वजनिक स्थानों से दूर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में शराब बनाने में लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु आर्थिक सहायता करके नवजीवन योजना में जोड़ने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई तथा मांग संख्या 13-आबकारी पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री सुदर्शन सिंह रावत (भीम)

सभापति महोदय,

मांग संख्या 13-आबकारी पर आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये आभार।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में तीन पंचायतों में शराबबंदी के लिये मतदान हुआ एवं उसमें तीनों पंचायतों की विजय हुई। अतः आपके माध्यम से सरकार को अपील करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत थानेटा, बरार व हामलो की वेर में आगामी वित्तीय वर्ष में शराब के ठेके का विज्ञापन नहीं किया जाये।

आपसे अनुरोध है कि आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से निर्देशित करने की कृपा करें ताकि वे आगामी वर्ष में इन सभी तीन पंचायतों थानेटा, बरार व हामलो की वेर में शराब की दुकानों की विज्ञप्ति जारी नहीं हो एवं जन भावना का सम्मान हो एवं कानून पालना सुनिश्चित हो सकें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग 26-चिकित्सा स्वास्थ्य सफाई व लोक कल्याण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपका आभार।

किसी भी देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास व उत्थान हेतु बेहतर स्वास्थ्य बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूकता तथा बजट में चिकित्सा को दी गई प्राथमिकता तय करती है कि हमारी स्वास्थ्य सेवायें कितनी सुदृढ़ हैं।

वैश्विक महामारी कोराना ने सम्पूर्ण विश्व को झकझोर के रख दिया। इस वैश्विक महामारी के चलते विश्व में 50 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सही होने के उपरान्त भी पोस्ट कोविड से अभी तक लोग परेशान हैं।

हमारे देश और प्रदेश में कोराना महामारी ने तांडव मचाया लाखों लोग संकमित हुए और इस महामारी के चलते बड़ी संख्या में मृत्यु के शिकार हुए। परन्तु केन्द्र की सरकार द्वारा कुशल प्रबंध और सार्थक प्रयासों के चलते देश में कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण की ओर है। भारत सरकार की उत्कृष्ट भूमिका की सम्पूर्ण विश्व के देशों ने सराहना की।

हमारे प्रदेश में इस संकट पूर्ण घड़ी में केन्द्र सरकार द्वारा दिल खोलकर मदद की। चिकित्सकीय उपकरण से लेकर दवाइयां, ऑक्सीजन व आर्थिक आवश्यकताओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को सहारा प्रदान किया तथा नि:शुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराकर प्रदेश वासियों की जान बचाते हुए संकट मोचन की भूमिका निभाई।

इस महामारी का खतरा नये वैरियंट के रूप में आज भी सर पर मंडरा रहा है। सचेत रहने की आवश्यकता है जो रूह कंपा देने वाले दृश्य हमने दूसरी पीक में देखा था, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस ओर सरकार को आगाह रहने की आवश्यकता है।

मैं बात करूं राजस्थान में चिकित्सकीय तंत्र की तो वर्तमान में आप अपनी पीठ जरूर थपथपा लें लेकिन बडी आवश्यकता है चिकित्सकीय तंत्र को निचले स्तर तक सुदृढ करने की। प्रभावी कदम उठाने होंगे तब जाकर प्रदेश का आमजन चिकित्सा में राहत प्राप्त कर पायेगा और ये सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं दायित्व भी है।

जिस तरह से आपने 2021-22 में निरोगी राजस्थान का संकल्प किया था यह संकल्प सिर्फ कागजी संकल्प निकला।

आज प्रदेश में मात्र 53 हजार से लेकर 54 हजार रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं जो 9 करोड़ प्रदेश वासियों को चिकित्सा दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री और अधिक चिकित्सक होने चाहिए इस बात को कहते तो हैं परन्तु उसके लिये और अधिक संख्या में मेडिकल कालेज और मेडिकल छात्रों की सीट्स में बढ़ोतरी के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है।

आज छोटे मेडिकल कालेज में मात्र 100 व बड़े मेडिकल कालेज में 250 सीटों की संख्या है। इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है।

1. 2021-22 की निरोगी राजस्थान करने का संकल्प बेबुनियाद निकला। कागजी संकल्प निकला।

2. राजस्थान प्रबंध कोष की आपकी 100 करोड़ की घोषणा सिर्फ प्रचार-प्रसार और संगोष्ठियों में सिमट कर रह गई।

3. प्रत्येक संभाग पर पब्लिक हैल्थ कालेज खोलने की आपकी घोषणा भी फेल साबित हुई।

कोरोना में जिन सरकारी कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिये आपने 50 हजार मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी जिसमें 120 शिक्षक, 118 विद्युतकर्मी जिन्होंने सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्हें आप कोरोना वारियर नहीं मान रहे है।

प्रत्येक संभाग पर पब्लिक हैल्थ कालेज खोलने की घोषणा भी थोथी घोषणा निकली।

दिल्ली की तर्ज पर मौहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा बुरी तरह से फैल हो गई।

कोटा में जिला चिकित्सालय की घोषणा आपकी अधूरी रह गई है उसमें कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

राजस्थान फार्मेसी द्वारा फार्मासिस्ट का कोर्स बी.फार्मा और डी.फार्मा करने के उपरान्त भी उनका संबंधित अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है।

आप पुरानी बजट घोषणाओं को साकार रूप नहीं दे पाये और 2022-23 के बजट में आपने नई घोषणाओं का अम्बार लगा दिया।

चुनाव से पूर्व आपका संविदाकर्मियों को स्थायी करने का वायदा कमेटियों की मीटिंगों तक सीमित रहा है।

केन्द्रीय सरकार की अंधता निवारण योजना में प्रदेश सरकार सिर्फ 34.4 प्रतिशत ही लक्ष्य प्राप्त कर सकी है।

केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना का नाम परिवर्तित कर आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर आप लगातार प्रदेशवासियों को यह समझाने का प्रयास कर रहे है कि यह योजना आपकी है।

आज प्रदेश में बच्चे को जन्म देने वाली जन्मदात्री मां के प्रति आप लापरवाह हैं। 3200 छोटे अस्पतालों में से मात्र 2000 अस्पतालों में प्रसव सुविधा है और सालाना 25000 हजार नवजात शिशुओं की मौत जन्म के साथ मिले कुपोषण, कोख में संक्रमण और मां की प्रसव पूर्व जांच नहीं हो पाने के कारण हो रही है।

हमारे प्रदेश में 75 प्रतिशत ग्रामीण है। इस आधार पर 500 शिशु रोग इकाइयों की आवश्यकता है और इनकी संख्या मात्र 60 है और नीचे तो 20 ही है।

हमारे प्रदेश में 3000 से अधिक प्रसूति रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है पर मात्र 1100 ही उपलब्ध है, जिनमें से भी 80 प्रतिशत बड़े शहरों में है।

सभापति महोदय, आज भी शिशु मृत्यु दर 30 प्रतिशत है। हमारे प्रदेश में 50 प्रतिशत महिलाएं बच्चियां एनीमिया और कुपोषण की शिकार हैं। यदि प्रदेश में महिलाओं को स्वस्थ नहीं रख पाये तो प्रदेश कैसे खुशहाल और स्वस्थ हो सकता है।

आज प्रदेश में मेडिकल बायोवेस्ट प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। इसका निस्तारण न हो पाने की वजह से गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा सदैव बना रहता है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर जहां के न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में सम्पूर्ण संभाग से लोग चिकित्सा हेतु आते हैं वहां के चिकित्सकीय तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक

150 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ए.एस.बी. आपकी लापरवाही से पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा है। ए व बी दोनों ब्लाकों में बना यह परम विशेषज्ञ चिकित्सालय में मात्र 4 विभाग के ही जे.एन. इन्डोर डोर प्रारम्भ हो पाये, 9 में से 8 परम विशेषज्ञ चिकित्सक की सैंक्शन पोस्ट है, 5 की आपने इस बजट में घोषणा कर दी। 90 नर्सिंग स्टाफ सैंक्शन हैं जिसमें आप 21 को ही ज्वाइनिंग दे पाये है। बिना नर्सिंग स्टाफ व पैरा मेडिकल के यहां कैसे सेवाएं प्रारम्भ की जायेंगी।

और यह जो सैंक्शन है वो ए ब्लाक शुरू करने के लिये है बी ब्लाक के लिये इतने ही नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी और सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक को आप कोई अतिरिक्त बजट नहीं दे रहे हो।

कार्डियक विभाग में कार्डियक थोरोसिक सर्जन व कार्डियो सर्जन को कब लगायेंगे जिसमें हृदय के गंभीर रोग का कोटा में इलाज हो पाये।

हृदय रोग विभाग के 6.5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आपके पास प्रस्तावित हैं इन्हें स्वीकृत करें जिसमें हृदय रोगियों का उपचार हो सके।

न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलोजी विभाग

ही नहीं है। एम.बी.एस. में एक न्यूरोसर्जन के ऊपर कोटा संभाग इलाज करवा रहा है। यू.टी.बी. के दो न्यूरोसर्जन चिकित्सक आपके द्वारा गये हैं। आप दो चिकित्सक आर.पी.एस.सी. से दो न्यूरो सर्जन स्थाई तौर पर लगायें जिससे न्यू चिकित्सालय में यह विभाग प्रारम्भ हो पायेगा।

नये चिकित्सालय में ई.एन.टी. सेवायें और नेत्र विभाग की चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है।

संसाधनों के अभाव में पीडियाट्रिक्स विभाग कभी बंद हो सकता है।

3 साल से कैथ लैब है परन्तु कैथ लैब में कॉर्डियक सर्जन आज तक नहीं लगा पाये।

किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित है परम विशेषज्ञ चिकित्सक भी है परन्तु सरकार द्वारा ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ व चिकित्साधिकारी नहीं लगा पाने के कारण विभाग शुरू ही नहीं हो पाया है।

सम्पूर्ण कोटा में सरकारी तौर पर कैंसर की उच्च स्तरीय तो क्या सामान्य चिकित्सक भी संभव नहीं, बरसों पुरानी कोबाल्ट थैरेपी मशीन से रोगियों को थैरेपी दी जाती है। मरीजों के लिये लीनियर एक्सीलरेटर मशीन की वर्षों से आवश्यकता है।

कोटा में कैंसर रोगियों का सरकार तो इलाज कर नहीं पा रही जो धर्मादा संस्थान कैंसर रोगियों के इलाज में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। भारत विकास परिषद् कैंसर अस्पताल और कोटा कैंसर सोसायटी इनको भी आपके द्वारा कोई मदद प्रदान नहीं करना चाहते।

न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में गत सरकार के समय बना द्वितीय तल तैयार खड़ा है परन्तु स्टाफ व चिकित्साधिकारियों के अभाव में प्रारम्भ नहीं हो पाया।

वर्तमान में एन्ट्री गेट छोटा है अत: इमरजेन्सी कारणों से इसे बड़ा करने की आवश्यकता है।

कोरोना के नये वैरियंट का खतरा अभी भी बरकरार है अत: उच्च स्तरीय श्वसन रोग विभाग व संक्रमण रोग निवारण संस्थान की भी महती आवश्यकता है।

होम्योपैथी में कई असाध्य रोगों का उपचार संभव है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम माध्यम रहा है। सरकार इन दोनों पद्धतियों के प्रति लापरवाह सिद्ध हुई। इसमें कार्यरत चिकित्सक वेतन विसंगतियों से जूझ रहे हैं। इनकी विसंगति दूर कर सरकार को इन पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए।

साथ ही न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में एक ही छत के नीचे यह विभाग खोलने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर)

माननीय महोदय,

मांग संख्या 26+13 पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया. इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, पिछले दो वर्षों में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना जैसी भयंकर महामारी के विभिन्न रूपों ने मानवता को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन हम सब के लिए यह गौरव का विषय है कि विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य सभी हैल्थ वर्करों ने अपनी जान को भारी जोखिम में डालकर मानवता को सर्वोपरि रखते हुए कोरोना पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। करोड़ों लोगों को फ्री वैक्सीन से बचाया।

महोदय, प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीजों को महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। अगर सरकारी चिकित्सालय में स्टाफ पूरा होगा और समय पर मरीज को इलाज मिलेगा तो मजबूरन उसे प्राइवेट अस्पताल नहीं जाएगा।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के 384 पद स्वीकृत हैं जबकि 282 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। 102 पद रिक्त होने के कारण यहां से रोजाना मरीजों को अजमेर सहित अन्य अस्पतालों के लिए रैफर किया जा रहा है। सरकार से मेरी मांग है कि एकेएच ब्यावर में चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की पूर्ति की जाए।

महोदय यह चिकित्सालय कई वर्षों से संचालित है। यहां पर प्रतिवर्ष करीब 5 लाख मरीज ओपीडी में आते हैं तथा प्रतिवर्ष 9000 प्रसव (सामान्य एवं सिजेरियन) 25 हजार के करीब अन्य सर्जरी की जाती है। महोदय, इस चिकित्सालय में 300 बैड ही स्वीकृत होने के कारण मरीजों को अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए रैफर किया जा रहा है। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि आज ही राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में 300 की जगह 500 बैड स्वीकृत कर मरीजों को राहत प्रदान करें।

महोदय, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर का भवन करीब 100 वर्ष पूर्व बना हुआ है। जो कि वर्तमान में जर्जर अवस्था में हो गया हैं। यह मै नहीं कर रहा हूं। यह अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर एवं सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. ब्यावर के निरीक्षण एवं पत्र एवं जिला कलेक्टर अजमेर के पत्र क्रमांक 13392 दिनांक 21/12/2021 द्वारा दिये गये अनुमति पत्र से साबित हो रहा है कि इस भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाना नितान्त ही आवश्यक है। मेरी सरकार से मांग है कि इस जर्जर भवन को तुरन्त तोड़कर नया भवन बनाने हेतु आवश्यक बजट जारी कराये ताकि भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।

इस चिकित्सालय में हृदय रोग एवं न्यूरोलोजी से संबंधित मरीज भी काफी संख्या में दूरदराज के क्षेत्रों से इलाज कराने आते हैं मगर यहां पर कार्डियोलोजी यूनिट एवं न्यूरोलोजी यूनिट नहीं होने के कारण मरीजों को यहां से रैफर किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोगों को काफी मानसिक एवं आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि ब्यावर के एकेएच में कार्डियोलोजी यूनिट व न्यूरोलोजी यूनिट स्वीकृत करते हुए चिकित्सक नियुक्त करें ताकि मरीजों को राहत मिल सके।

साथ ही निवेदन है कि यहां पर सोनोग्राफी और सीटी स्कैन मशीनों की संख्या मरीजों के लिए नाकाफी हो रही है। यहां पर सोनोग्राफी और सीटी स्केन की संख्या बढाई जाए।

महोदय, यहां पर चार जिलों अजमेर, पाली, राजसमंद तथा भीलवाड़ा जिलों के मरीज इलाज कराने आते हैं। साथ ही यह चिकित्सालय राजमार्गों से घिरा होने के कारण तथा सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां होने के कारण यहां पर मरीजों की संख्या अधिक रहती है। इस बाबत यहां पर मेडिकल कालेज खोलने के लिए कई बार सरकार से निवेदन कर चुका हूं। अब और निवेदन है कि ब्यावर में मेडिकल कालेज खोलने की कृपा करें।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सन् 2018 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराखन स्वीकृत हुआ जो क्षेत्र की जायज मांग थी। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां के लोगों को काफी राहत मिली। लेकिन बड़े ही अफसोस और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने उक्त केन्द्र के भवन निर्माण के लिए अभी तक बजट स्वीकृत नहीं किया, जबकि अधिकारियों ने कई बार प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा हुआ है। साथ ही इसके बाद स्वीकृत हुए केन्द्रों पर

सरकार ने बजट जारी कर दिया। मेरी सरकार से मांग है कि उक्त केन्द्र के लिए शीघ्र बजट जारी कर भवन निर्माण करावे।

साथ ही निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाखेड़ा जो कि उपखण्ड टाटगढ़ के मध्य में स्थित है। यहां पर मरीजों की अधिकता रहती है। साथ ही उपखण्ड टाटगढ़ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां से अन्य स्थानों पर जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाखेड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमोन्नत करें।

महोदय, कोरोनाकाल के दौरान पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की मौत हो गई तथा कइयों की जान जोखिम में आ गई। मैंने विधायक कोष से एकेएच ब्यावर के लिए 60 लाख तथा सीएचसी जवाजा के लिए 30 लाख तथा सीएचसी टाटगढ़ के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत किये थे, लेकिन टाटगढ़ में लगाये गये ऑक्सीजन प्लान्ट में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। क्षेत्र के सरपंच और आम लोगों ने शिकायत की है कि संबंधित फर्म को जांच होने पर ही भुगतान किया जाए। अत: टाटगढ़ में लगाये गये ऑक्सीजन प्लान्ट की जांच की जावे।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर)

माननीय सभापति महोदय, सदन में आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहते हुए सर्वप्रथम मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में आमजन की सुविधाओं हेतु कुछ आवश्यकताएं हैं उनके लिए मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में जो सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है यह बहुत ही पुरानी है तथा पीपीपी मोड पर सशुल्क 1100/-रुपये पर संचालित है। इस सीटी स्कैन मशीन के स्थान पर नई मशीन की आवश्यकता है इसलिए नई सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत की जाए तथा सीटी स्कैन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। इसके अलावा वहां पर डायलेसिस मशीन पीपीपी मोड पर सशुल्क 1100/- रुपये पर संचालित है। वहां पर डायलेसिस मशीन व संसाधन सरकारी है। अतः यह सुविधा भी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाये।

सभापति महोदय, श्रीगंगानगर के जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी

मशीन (कलर डोपलर) एक ही है जिससे रोगियों की नियमित जांच नहीं होती और मशीन की कमी के कारण रोगियों को वेटिंग में रखा जाता है इसलिए एक नई सोनोग्राफी मशीन (कलर डोपलर) शीघ्र स्वीकृत कर उपलब्ध करायी जाये। साथ ही एसएनसीयू में नवजात शिशुओं की संख्या को देखते हुए 25 नये रेडियन्ट हीट वार्मर की भी आवश्यकता है। वर्तमान में जो रेडियन्ट हीट वार्मर उपलब्ध हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है इसलिए संख्या में वृद्धि की जाये।

उक्त अस्पताल में एक नई डेंटल चेयर तथा आपरेशन थियेटर में अस्थि रोग विभाग के लिए नई ओ.टी. टेबल की भी आवश्यकता है। इसके लिए रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन मय संसाधन की भी बहुत आवश्यकता है ताकि मौसमी बीमारियों के दौरान रोगियों को एसडीपी व आरडीपी की सुविधा उपलब्ध हो सके। सभापति महोदय, हमारे वहां पर पैथोलोजी लैब में पैथोलोजिस्ट का पद रिक्त है तथा एक ऑटो एनालाइजर मशीन की भी आवश्यकता है। साथ ही यहां पर एक्स-रे विभाग में एक डी.आर. की आवश्यकता है ताकि उच्चतम गुणवत्ता के एक्स-रे कम समय में उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त यहां पर एम.आर.आई. मशीन की भी बहुत जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारे वहां जिला अस्पताल में बहुत से चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी काफी समय से खाली हैं जिससे रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां पर वर्तमान में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के 11 पद रिक्त हैं, जिनमें पैथोलोजिस्ट, शिशुरोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है। इसके अलावा वर्तमान में लैब टैक्नीशियन संवर्ग के 31 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 17 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता है, ताकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का सफल संचालन हो सके। साथ ही वहां पर नर्सिंग संवर्ग के 15 पद भी रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाये। सहायक कर्मचारियों के 47 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 34 पद रिक्त हैं, जिन पर शीघ्र नियुक्तियां करवाई जायें।

माननीय सभापति महोदय, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा कुंज विहार प्रथम आवासीय योजना, श्रीगंगानगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 176.57 वर्गफीट भूमि आरक्षित की गयी है। आपसे प्रार्थना है कि आम जनता की सुविधा को देखते हुए श्रीगंगानगर की कुंज विहार प्रथम

आवासीय योजना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इसके अलावा श्रीगंगानगर शहर की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है तथा शहर का भी विस्तार हो रहा है। इस विस्तार को देखते हुए सुविधाएं कम हैं इसलिए मेरी मांग है कि पुराने चिकित्सालय भवन में भी चिकित्सा सुविधा शुरू की जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

समूह जाने के क्षेत्र से बाहर

आर एम एल (RML) देसी - उठाव के लिए जबरन बाध्य करने पर रोक लगे

स्कूल = मन्दिर-पाणी- खुर्द=सभी

मेरी विधान सभा-बून्दी कोटा जिला एक भी गांव व नदी कालोनी नहीं जहां शराब जहां भी शिकायत मिलती है। प्रशासन शराब की दुकान की स्वीकृति नही दी जाये

शराब की दुकानों में मिलावट

कोटा शहर चाहे बून्दी-24 घण्टे शराब मिलती है

थाने-गोदामों=2 बजे

सभी सब ब्रांचों को बन्द किया जाये

गांजा भांगकोटा-हर कालोनी स्कूलों के आसपास गांजा स्मेक

शराब व भांग की दुकानों का औचक निरिक्षण किया जाता है- सब लीपापोती

आबकारी विभाग जब चाहे जिसका अवैध शराब बेचने का केस बना सकते जब कि जो अवैध है, उसी का बनाये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन)

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

1. RGHS स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई बड़े अस्पताल प्रदेश के अभी भी इस योजना से नहीं जुड़े हैं जैसे कोटा शहर के मैत्री अस्पताल, सुधा अस्पताल, जयपुर शहर के इटरनल अस्पताल आदि। सरकार इन अस्पतालों को क्यूं छोड़ रही है? सरकारी कर्मचारी इन अस्पतालों में इलाज से वंचित है। अपने तनख्वाह से RGHS कटौती कराने के बाद

भी। इन अस्पतालों और सभी बड़े अस्पतालों को कब जोड़ेगी सरकार RGHS में।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

2. RGHS में सरकारी कर्मचारियों में भी भेदभाव किया जा रहा है. 2004 से पहले लगे कर्मचारियों को अनलिमिटेड कैश less की सुविधा दी गई इंडोर और आउटडोर इलाज की। जबकि 2004 के बाद लगे कर्मचारियों की आउटडोर लिमिट 20 हजार सालाना और इंडोर की लिमिट 5 लाख सालाना कर रखी है। जब पेंशन सबको देने की घोषणा कर दी है तो RGHS में ये भेदभाव क्यों?

3. एक अस्पताल, एक जांच करने वाले डाक्टर और स्टाफ भी वोही फिर RGHS में लगने वाला शुल्क भामाशाह और अन्य स्कीम से दुगना क्यों।

आंकड़े बढ़ाने को लेकर या फिर कर्मचारियों की लिमिट जल्दी खतम करने को। सरकार नीयत बताएं।

जैसे दिल की जांच एंजियोग्राफी का भामाशाह स्कीम में शुल्क 5300 रुपए है जबकि इसी जांच का शुल्क RGHS में 11000 है।

2019, दिसम्बर में जेके लोन अस्पताल कोटा में शिशुओं की हुई मृत्यु के मामले में हमारे सामने आये कई ब्लड का प्लाज्मा फार्मा कंपनियों को विक्रय हो रहा है इसकी जांच करवाई जाये। लापरवाही के कारण जिस तत्कालीन अधीक्षक डाक्टर एच.एल. मीणा को हटाया गया था, ऐसी क्या मजबूरी थी जो उस लापरवाह अधिकारी को फिर एक-डेढ़ साल बाद फिर इसी अस्पताल का अधीक्षक बना दिया।

डाक्टर एचएल मीणा बिना उच्च अधिकारियों के आदेश के स्वयंभू प्रभारी अधिकारी बनकर बैठा है। कोटा के एमबीएस चिकित्सालय के ब्लड बैंक का उसकी शिकायत लिखित में कोटा मेडिकल कालेज के ब्लड बैंक के विभागाध्यक्ष कर चुके हैं। प्रिंसिपल और कलेक्टर को तो 6 महीने से ज्यादा होने के बाद भी अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? डाक्टर एचएल मीणा गैर कानूनी तरीके से प्रभारी बनकर जो ब्लड बैंक में किट, रीजेंट्स, मशीनें खरीद रहा है, ब्लड का प्लाज्मा फार्मा कंपनियों को विक्रय हो रहा है, इसकी जाँच करवाई जाये।

4. नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कालेज कोटा के 11-12 वर्ष बाद भी अभी तक शुरू हुए होने के बाद भी यहां आजतक ENT WARD, नेत्र रोग विभाग, कैंसर विभाग की भर्ती सुविधा तो छोड़ो, ओपीडी तक चालू नहीं हुई। आम जनता को कब इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा? मेडिकल कालेज स्तर का अस्पताल होने के बाद भी ये मूलभूत सुविधाएं भी ना मिल पाना दुर्भाग्य है।

5. जब मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सभी कुछ फ्री होगा अस्पतालों में तो CT scan, एमआरआई स्कैन के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं मरीजों से/जो कि मूलभूत जांचें हैं?

थैलीसीमिया की तरह ही कैंसर और डायलिसिस के मरीजों को भी ब्लड बैंक से ब्लड हमेशा बिना रिप्लेसमेंट के दिए जाने के आदेश देंगे तो गरीबों को लाभ मिल पायेंगे क्योंकि इन मरीजों को भी बार-बार ब्लड चढ़ने की दिक्कत आती है। इनके परिजन कहां से लाएं रक्त देने वाले बार-बार?

6. इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट ब्लड बैंक शुरू करने के लाइसेंस क्यों दिए जा रहे हैं? अकेले कोटा में 8 ब्लड बैंक है। hen, एक दो को और परमिशन देने वाले आप हैं इससे सरकारी ब्लड बैंकों को रक्त संग्रहण में दिक्कत आने वाली है। रक्तदान शिविर कैसे मिलेंगे? सरकारी अस्पतालों को क्या इतने प्राइवेट अस्पताल ब्लड बैंक क्वालिटी कंट्रोल कर पाएंगे? कहीं-छोटी जगह हास्टल के नीचे।

कर्मचारी-अधिकारी बनने पर Calegey.

कैंसर विभाग लीनियर एक्सीलरेटर मशीन के लिए बजट = आवश्यकता

RM SCL OMFT = विधायक,

RMSC की सप्लाई नहीं

कोटा MBS

टिटनेस इंजेक्शन नहीं और जरूरी सिरिन्ज भी नहीं है

CMHO कोटा ग्रामीण से शहरी क्षेत्र से अनेकों डाक्टर्स नर्स प्रथम द्वितीय महिला (काम कार्यकर्ता पेरामेडिकल स्टाफ, सीएचए सीएचओ को - व्यवस्थार्थ - अन्य स्थानों

मेडिकल कालेज कोटा - चार दीवारी = दरारें परिसर घाटी

नवीन चिकित्सालय में कई स्थानों पर पानी टपकने की परेशानी

नवीन चिकित्सालय में परेशानी

नवीन चिकित्सालय कोटा एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में संचालित वार्डों की अपेक्षा में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।

मेडिकल कालेज मे सुरक्षा सुपरवाइजर का मुख्यालय प्रशासनिक ब्लाक किया हुआ है, जबकि अन्य कालेजों में सुरक्षा सुपरवाइजर का मुख्यालय मुख्य द्वार होता है।

मेडिकल कालेज कोटा में लगे भूतपूर्व सैनिक श्रमिकों को

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य हेतु मंत्री महोदय को मेरे द्वारा निम्न मांग बिन्दु-

1- महिला चिकित्सा कर्मियों के लिये कार्य स्थल पर ही breast feeding women को शिशु पालना गृह (cretch) की व्यवस्था करना।

2- महिला चिकित्सा कर्मियों को self defence के लिए ट्रेनिंग करवाना।

3- icu स्टाफ के लिये hard duty allowance प्रतिदिन के हिसाब से हो।

4- सभी चिकित्साकर्मियों के लिये सबसे पहले सभी मुफ्त "जीवन रक्षक टीकों" की व्यवस्था होनी चाहिए।

5- प्रत्येक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र पद आम नागरिक को उचित सलाह देने हेतु councelor पद स्थापित होना चाहिए।

6- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करना।

7- जिला चिकित्सालयों में रैफरल वाहनों को दुरुस्त करवाना।

8- बूंदी जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिशु प्रजनन अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त चल रहा है, उसे भरना।